राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 226

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 23 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

राजनाथ बोले– जम्मू–कश्मीर के बच्चे राष्ट्रवादी, भटकाने वाले दोषी

>> 3

आरटीआइ के दायरे में सीजेआइ

जीवन का संघर्ष इंसान को हर कदम ताकतवर बनाने के साथ ही हक के लिए आत्मबल के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल की। पेज–11

शीर्ष अदालत से केंद्र की अपील, डेथ वारंट के सात दिन के अंदर हो फांसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की मृत्युदंड के मामले में पूर्व के आदेश को स्पष्ट करने की मांग
- कोर्ट से दुर्दांत अपराध के पीड़ितों के पहलू को भी ध्यान रखने का अनुरोध

कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर मौत को धता बता रहे फांसी की सजा पाए दोषियों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन के भीतर डेथ वारंट जारी कर दिया जाए और उसके बाद सात दिन के भीतर उन्हें फांसी दे दी जाए। इस पर उनके साथी सह अभियुक्तों की पुनर्विचार याचिका, क्यूरेटिव याचिका या दया याचिका लंबित रहने का कोई असर नहीं पड़े। केंद्र सरकार ने न्याय का इंतजार करते दुर्दांत अपराध के पीड़ितों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से इस बारे में दिशा-निर्देश तय करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने शत्रुघ्न चौहान मामले में दिए गए फैसले में फांसी के लिए तय की गई 14 दिन की समय सीमा को घटा कर सात दिन करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को शीर्ष अदालत में यह अर्जी दाखिल की गई। दिल्ली के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषियों के मामले को देखते हुए यह अर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले के चारों दोषियों को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। घटना को सात साल बीत चुके हैं लेकिन दोषी एक के बाद एक याचिका दाखिल कर कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठा रहे हैं और मौत की सजा को धता बता रहे हैं। इस मामले में चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके बाद दो दोषियों की क्यूरेटिव याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ठुकरा चुका है। एक दोषी मुकेश की दया याचिका भी राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। निचली अदालत ने चारों को फांसी देने के लिए एक फरवरी की तारीख तय कर रखी है। लेकिन अभी तक दो अभियुक्तों ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल नहीं की है जबकि तीन ने दया याचिका नहीं दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अंतिम मौके पर कोई अभियुक्त दया याचिका या क्यूरेटिव दाखिल कर देता है तो फांसी फिर टल जाएगी।

केंद्र सरकार ने अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2014 को शत्रुघ्न चौहान मामले में फांसी की सजा पाए दोषियों के पहलू से विचार करते हुए फैसला दिया था और दिशा निर्देश जारी किए थे। जिसमें यह कहा गया था कि दया याचिका खारिज होने के बाद अभियुक्त को 14 दिन का समय दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि कोर्ट ने उस फैसले में यह भी कहा था कि फांसी की सजा पाए दोषी का मामला लटका रहना उस पर मानसिक अत्याचार है।

सरकार का कहना है कि देश में दुष्कर्म, हत्या आदि के दुर्दांत अपराध बढ़ रहे हैं। फांसी की सजा पाए दोषी एक-एक कर अर्जी दाखिल कर मामला लटकाते रहते हैं। कोर्ट को न्याय का इंतजार कर रहे अपराध के पीड़ित परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार की मांग है कि कोर्ट आदेश दे कि पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के ही भीतर दोषी को क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने की इजाजत होगी। कोर्ट यह भी आदेश दे कि अगर दोषी दया याचिका दाखिल करना चाहता है तो वह डेथ वारंट जारी होने के सात दिन के भीतर ही ऐसा कर सकता है। यह भी मांग है कि कोर्ट सभी सक्षम अथारिटी जैसे राज्य, जेल अथारिटी तथा अन्य को आदेश दे कि वे दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन के भीतर डेथ वारंट जारी करेंगे और उसके बाद सात दिन के भीतर दोषी को फांसी दे दी जाएगी। उसके केस पर इस बात का कोई असर नहीं होगा कि उसके सह अभियुक्तों की पुनर्विचार, क्यूरेटिव या दया याचिका लंबित है।

जागरण विशेष

नया कश्मीर देसी–विदेशी सैलानियों से गुलजार

जम्मू : 'जन्नत' कहा जाने वाला कश्मीर पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। बर्फ से लकदक होने के बावजूद पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ जुट रही है। जम्मू के विभिन्न धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं की कतार लग रही है। (पेज–6)

न्यूज गैलरी

राज–नीति ▶ पृष्ठ 4

27 जनवरी से मुंबई में 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल, सिनेमा घर

मुंबई : मुंबई की नाइटलाइफ पर बुधवार को आधिकारिक मुहर लग गई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 'मुंबई 24 घंटे' नीति को हरी झंडी देते हुए इसके पहले चरण के तहत गैर आवासीय इलाकों के मॉल में स्थित थिएटर, दुकानें, खानपान के आउटलेट और मॉल परिसरों को 27 जनवरी से 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने फैसले की जानकारी दी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में खलल की आतंकी साजिश

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को और गति देने के लिए शुरू किए गए केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में खलल डालने की साजिश रची जा रही है। खबर है कि तीन आतंकी संगठन आउटरीच प्रोग्राम के लिए केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में हैं। खुफिया अलर्ट के बाद सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों ने प्रभावी सुरक्षा रणनीति बनाई है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

जलवायु परिवर्तन पर ग्रेटा और ट्रंप फिर आमने–सामने

दावोस : स्विट्जरलैंड में मंगलवार से शुरू हुए डब्ल्यूईएफ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग फिर आमने–सामने आ गए। इस सम्मेलन में 17 साल की ग्रेटा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है। उनके निशाने पर सीधे तौर पर ट्रंप का भाषण था, जिसमें उन्होंने एक लाख करोड़ पेड़ लगाने की बात कही थी।

सीएए पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इन्कार

सख्त रुख ▶ सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब, एनपीआर टालने की मांग भी ठुकराई

अदालत ने 80 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा सरकार का पक्ष सुने बिना एकतरफा फैसला नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने के दिए संकेत
- सभी हाई कोर्ट को सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से भी रोका
- प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने दिए आदेश

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार को सुने बगैर एकतरफा कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा। यहां तक कि कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की प्रक्रिया तीन महीने के लिए टालने की मांग भी ठुकरा दी।

कोर्ट ने सीएए को चुनौती देने वाली करीब 80 नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही मामला सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने के भी संकेत दिए। साथ ही सभी हाई कोर्ट से कहा है कि वह सीएए के मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। मामले में चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने बुधवार को उक्त आदेश दिए। सीएए पर रोक नहीं लगने का मतलब है कि उसके जरिये 31 दिसंबर, 2014 तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के चलते भागकर आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खुला हुआ है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर कुल 144 याचिकाएं सुनवाई पर लगी थीं जिनमें से 60 याचिकाओं पर कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका था। केंद्र सरकार की स्थानांतरण याचिका भी लंबित है। ज्यादातर याचिकाएं सीएए कानून के खिलाफ हैं। हालांकि दो पक्ष में हैं। मामले की शुरुआत में केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कुल 144 याचिकाएं हैं। पिछली बार कोर्ट ने 60 याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था उस पर सरकार का जवाब तैयार है। उसी समय सीएए का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की मांग की। उनसे सहमति जताते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामला पांच जजों को भेजा जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि इस बीच कोर्ट एनपीआर और एनआरसी की प्रक्रिया पर 2-3 महीने के लिए रोक लगा दे, वह कानून पर रोक की मांग नहीं कर रहे हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि सीएए के नियम जारी होने के पहले ही प्रदेश सरकार ने 40 हजार लोगों को चिह्नित कर लिया है। अगर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई तो भरपाई न हो सकने वाला नुकसान होगा। सिंघवी ने कहा कि जो चीज 17 साल से नहीं हुई है वो अगर तीन महीने और नहीं होगी तो क्या हर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट इतना ही आदेश दे दे कि सरकार फिलहाल नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं जारी करेगी। लेकिन कोर्ट ने कोई भी आदेश नहीं दिया। पीठ ने कहा कि वह मामले पर सुनवाई की तिथि तय करेगी और अगर मामला पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाता है तो अंतरिम आदेश पर भी वही पीठ विचार करेगी।

वकील विकास सिंह ने असम का मामला उठाते हुए कहा कि असम की स्थिति अलग है। सीएए के प्रावधान असम समझौते का उल्लंघन करते हैं। असम में 1971 की सीमा रेखा तय है जिसे सीएए में बढ़ा कर 2014 कर दिया गया है। करीब 40 लाख लोग हैं जो 1971 से 2014 के बीच आते हैं ऐसे तो असम का भौगोलिक परिदृष्य ही बदल जाएगा। त्रिपुरा का भी मामला उठा। कोर्ट ने कहा कि असम और त्रिपुरा की श्रेणी अलग है। कोर्ट ने अटार्नी जनरल वेणुगोपाल से कहा कि वह असम के मामले में दो सप्ताह में जवाब दें। और सिब्बल से असम से संबंधित सारी याचिकाओं की सूची मांगी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस बीच वह एक दिन चैंबर में सुनवाई करके आगे की सुनवाई के लिए रूपरेखा तय कर सकते हैं।

सीएए के समर्थन में बलूचिस्तान हिंदू पंचायत पहुंची सुप्रीम कोर्ट

बलूचिस्तान हिंदू पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उसे भी पक्षकार बनाने की मांग की है। वकील अरधेंदु मौलि कुमार की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अर्जी पर नोटिस जारी किया। अर्जी में कहा गया है कि वे लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आए हैं उन पर वहां धार्मिक आधार पर बहुत जुल्म ढाए गए जिसके कारण उन्होंने भाग कर भारत में शरण ली है। वे पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यक हैं। सीएए से उन्हें राहत मिलेगी। यहां लंबित याचिकाओं में ज्यादातर में कानून को चुनौती दी गई है जिसका असर उन पर पड़ेगा इसलिए कोर्ट उन्हें भी पक्षकार बनाए और उन्हें भी सुने।

एनपीआर से विवादित सवालों को हटा सकती है सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गैर भाजपा शासित राज्यों के विरोध को देखते हुए सरकार ने दिए संकेत
- कल्याणकारी योजनाओं के लिए गरीबों का आंकड़ा जुटाना पहली प्राथमिकता
- राज्यों के मुख्य सचिवों ने भी पिता के जन्म स्थान जैसे सवाल का औचित्य पूछा था

गैर भाजपा शासित राज्यों के बढ़ते विरोध के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से विवादित सवालों को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि यदि सभी गैर-भाजपा राज्यों ने एनपीआर के आंकड़े जुटाने से इन्कार कर दिया, तो इसका पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ध्यान देने की बात है कि जनगणना और एनपीआर पर बैठक के दौरान गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्य सचिवों ने भी पिता के जन्म स्थान जैसे सवाल का औचित्य पूछा था।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार एनपीआर का पूरा उद्देश्य गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आंकड़े जुटाना है। ताकि हर जरूरतमंद को उसकी जरूरत के मुताबिक मदद की जा सके। लेकिन यदि कई राज्यों में एनपीआर के आंकड़े नहीं मिलते हैं तो फिर गरीबों के लिए देशव्यापी कल्याणकारी योजना बनाना और उन्हें जरूरतमंद तक पहुंचाना संभव नहीं होगा। यही नहीं सरकार सिर्फ एनपीआर कराने वाले राज्यों में कल्याणकारी योजना लागू करने का भेदभाव भी नहीं कर सकती है। इससे नुकसान अंतत वंचित गरीबों को ही होगा। यही कारण है कि सरकार एनपीआर में विवादित सवालों को हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

दरअसल एनपीआर में माता-पिता का जन्म-स्थान और जन्मतिथि जैसे सवालों पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं और इसी कारण इसे एनसीआर से जोड़कर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। इसीलिए सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले गैर-भाजपा शासित राज्य एनपीआर के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। पिछले शासनकाल में देश के 60 करोड़ गरीबों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाली मोदी सरकार मौजूदा कार्यकाल में इन्हें और आगे बढ़ाना चाहती है। यदि इसके रास्ते में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कुछ सवाल आड़े आ रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए भी तैयार हो सकती है। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश देश में हर व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक हालात की सटीक जानकारी जुटाना है।

'सिम के लिए भी बताना होता है नाम–पता, फिर अब परहेज क्यों'

नई दिल्ली : एनपीआर हो–हल्ला मचा रहे लोगों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल फोन का सिम लेने पर भी नाम और पता बताना होता है और उसके प्रमाण देने होते हैं, तो फिर एनपीआर को लेकर विरोध क्यों। वैसे भी एनपीआर तैयार करने का फैसला कांग्रेस का है। (पेज–3)

आतंकियों की मदद से घटी पाक की विश्वसनीयता

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी नेतृत्व के पास सीमित विकल्प हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि आतंकवादी समूहों की चोरी-छिपे मदद करने के लंबे इतिहास के चलते इस्लामाबाद के पास इस मुद्दे पर थोड़ी सी विश्वसनीयता बची हुई है।

छह महीने से भी कम समय में जारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) की दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य कार्रवाई के जरिये कश्मीर की स्थिति बदलने की पाकिस्तान की क्षमता में हाल के वर्षों में कमी आई है। इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान मुख्य रूप से इस मामले में कूटनीति पर ही निर्भर रहेगा। सीआरएस अमेरिकी कांग्रेस की स्वतंत्र अनुसंधान शाखा है, जो अमेरिकी सांसदों के लिए रिपोर्ट तैयार करती है, ताकि वे कांग्रेस के अंदर निर्णय ले सकें। वर्तमान में दो प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लंबित हैं, जिनमें से एक की प्रायोजक भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल हैं।

सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच अगस्त के बाद पाकिस्तान कूटनीति के मोर्चे पर अलग-थलग पड़ गया है। तुर्की अकेला ऐसा देश रहा, जिसने उसके रुख का ठोस और स्पष्ट समर्थन किया। बताते चलें कि भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और इसे दो भागों में विभाजित करने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में और कड़वाहट आ गई। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। पाकिस्तान इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करना चाहता है। 25 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। परिषद ने बंद कमरे में 16 अगस्त को कश्मीर पर पांच दशकों से अधिक समय में पहली बार चर्चा की। हालांकि, इसके बाद कोई औपचारिक बयान नहीं जारी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक के मुख्य सहयोगी चीन की मानवाधिकार के मुद्दे पर सीमित अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता है। ऐसे में इस्लामाबाद की उम्मीद इस बात पर टिकी हो सकती है कि भारत अपनी प्रतिष्ठा को खुद नुकसान पहुंचाए। कश्मीर पर लंबे समय से अमेरिका की स्थिति यह है कि कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को भारत और पाक के बीच बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट

- जम्मू–कश्मीर पर इस्लामाबाद के पास सीमित विकल्प
- सैन्य कार्रवाई के जरिये स्थिति बदलने की क्षमता नहीं

कश्मीर नहीं, पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से है चिंता पेज>>13

मिलिए गगनयान की लेडी रोबोट व्योममित्र से

- अगले साल दिसंबर में पहले मानवरहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है हाफ–ह्यूमनॉयड
- व्योममित्र अंतरिक्ष में मानव की तरह ही सारे कामों को अंजाम दे सकती है

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अगले साल दिसंबर में अपने पहले मानवरहित गगनयान में 'लेडी रोबोट' व्योममित्र को भेजेगा। जीती जागती आधुनिक महिला दिखने वाली यह मशीन भारतीय अंतरिक्ष अभियान के लिए बेहद अहम साबित होगी। यह हाफ ह्यूमनॉयड अंतरिक्ष में मानव गतिविधियों को अंजाम देगा। साथ ही वहां के पर्यावरण से तालमेल बिठाने के साथ ही जीवन रक्षक प्रणाली को नियंत्रित करेगा।

उद्घाटन सत्र में सबके आकर्षण का केंद्र रही लेडी रोबोट का संस्कृत नाम व्योममित्र (यानी अंतरिक्ष मित्र) रखा गया है। हाफ ह्यूमनॉयड व्योममित्र के पैर नहीं बनाए गए हैं। इसलिए वह केवल आगे या बगल में झुक सकती है। व्योममित्र ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपना परिचय खुद देकर चौंका दिया। उसने कहा, 'सबको हैलो। मैं व्योममित्र हूं। हाफ ह्यूमनॉयड की प्रोटोटाइप। मुझे पहले मानवरहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है।' मिशन में अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए उसने बताया, 'मैं मॉड्यूल पैरामीटर की निगरानी कर सकती हूं। आपको सतर्क कर सकती हूं। पैनल ऑपरेशन शुरू करने जैसी गतिविधियों को अंजाम दे सकती हूं। मैं एक सहयोगी हूं और अंतरिक्ष यात्रियों से बात भी कर सकती हूं। मैं उनको पहचान कर उनकी मांगी जानकारियां भी उन्हें दे सकती हूं।' व्योममित्र के अपना परिचय खुद देने के बाद सिवन ने बताया कि यह अंतरिक्ष में मानव की तरह ही सारे कामों को अंजाम दे सकती है।

इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली हाफ ह्यूमनॉयड 'व्योममित्र' की पहली झलक देखने को मिली। एएनआइ

गगनयान दूसरे ग्रहों पर मानव मिशन भेजने में भी मदद करेगा

बेंगलुरु, प्रेट्र : इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में नया स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि गगनयान अभियान का मकसद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान से भेजना है। अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान–3 मिशन के लिए भी काम शुरू कर दिया है। इसरो के चेयरमैन के. सिवन ने बुधवार को बताया कि दिसंबर 2021 में भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष अभियान से पहले भी दो मानवरहित अभियान क्रमशः दिसंबर 2020 और जून 2021 में भेजे जाएंगे। (पेज–16)

दो टूक

नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को जोकर और मनोरोगी कहा था, इस पर खेर ने कहा–आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद कुंठा में गुजारी है

अनुपम का नसीरुद्दीन को जवाब, कहा मेरे खून में हिंदुस्तान है

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

अनुपम खेर

नसीरुद्दीन शाह (दोनों फाइल फोटो)

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के अभिनेता अनुपम खेर को 'जोकर' कहे जाने का करारा जवाब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दिया है। दरअसल, अनुपम इन दिनों अमेरिका में अपने शो 'न्यू एम्सटर्डम' की शूटिंग कर रहे हैं।

अनुपम खेर ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब के लिए मेरा प्यार भरा पैगाम। वह मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। मैं हमेशा से उनकी कला की इज्जत करता आया हूं और करता रहूंगा। पर कभी-कभी कुछ बातों का दो टूक जवाब देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये है उनको मेरा जवाब।

फिर वीडियो में अनुपम खेर ने कहा, 'मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूं। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की। आपको भला-बुरा नहीं कहा। अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद कुंठा में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना साहब, शाहरुख खान, विराट कोहली की आलोचना कर सकते हैं, तो मुझे इस बात का यकीन है कि मैं अच्छी संगत में हूं। इनमें से किसी ने भी आपके बयान को गंभीरता से नहीं लिया। वर्षों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही पता नहीं लगता है। मेरी बुराई करके अगर आप एक-दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको यह खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखें। आपका शुभचिंतक अनुपम। आप जानते हैं कि मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो।

दरअसल, फिल्म इंडस्ट्री में नीतियों और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ फिल्म जगत के रुख को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि इन नीतियों का विरोध करने वाले लोग कम होते हैं। इस बारे में बोलने वाले लोग ट्विटर पर हैं। मैं ट्विटर पर नहीं हूं। अनुपम खेर ट्विटर पर बहुत मुखर हैं। उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वह जोकर हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआइआइ) और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के उनके समकालीन लोग उनके साइकोपैथिक (मनोरोगी) स्वभाव से वाकिफ हैं। यह उनके खून में है। वह किसी की मदद नहीं कर सकते हैं।

वैसे यह पहला मौका नहीं है जब नसीरुद्दीन शाह और अनुपम के बीच तकरार हुई है। इससे पहले मॉब लिंचिंग और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर पर दिए गए नसीरुद्दीन के बयान पर अनुपम खेर ने कहा था देश में इतनी आजादी है कि सेना को अपशब्द कहे जा सकते हैं, एयर चीफ की बुराई की जा सकती है और सैनिकों पर पथराव किया जा सकता है। आपको इस देश में और कितनी आजादी चाहिए? कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी।

एनआरसी के लिए तथ्य जुटाने की अफवाह, मुस्लिम युवती का घर फूंका

जागरण संवाददाता, वीरभूम

- बंगाल में पुलिस के संरक्षण में है पीड़ित का परिवार
- एनजीओ के लिए कांट्रेक्ट पर काम करती है पीड़िता

मुस्लिम युवती द्वारा घर-घर जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनआरसी) के लिए तथ्य एकत्र करने की अफवाह का बाजार गर्म होते ही असामाजिक तत्वों ने उसके घर को फूंक दिया। दहशतजदा परिवार को पुलिस की संरक्षण में जाना पड़ा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार बंगाल में वीरभूम जिले के मयूरेश्वर-1 नंबर ब्लाक अंतर्गत मल्लारपुर थाना क्षेत्र के गौरबाजार निवासी 20 वर्षीय चुमकी खातून एक एनजीओ के लिए कांट्रैक्ट पर काम करती हैं। एक ऑनलाइन फर्म की साझेदारी में एनजीओ, ग्रामीण महिलाओं को स्मार्टफोन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। चुमकी भी घर घर जाकर कुछ सामान्य तथ्य एकत्र कर रही थी, जो प्रशिक्षण का हिस्सा था। लेकिन, इसी बीच अफवाह फैल गई की एनजीओ के माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने बीते मंगलवार रात चुमकी खातून के घर में आग लगा दी। घटना से दहशत में आया चुमकी का परिवार जान बचाने के लिए वहां से भाग कर थाने जा पहुंचा। अभी उसका परिवार पुलिस के संरक्षण में है। उधर, सूचना पर पहुंचे रामपुरहाट के उप विभागीय पुलिस अधिकारी सौमजीत बरुआ ने स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने कहा की चुमकी का परिवार सुरक्षित है। घटना के साथ एनआरसी का कोई संबंध नहीं है। इस बारे में अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस का प्रदर्शन उसके बाद लगातार खराब रहा और वह 2019 के लोकसभा में भी जारी रहा। यहां भी उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 23 जनवरी 2020

चुनावी हलचल

कांग्रेस के प्रचारकों की सूची में सिद्धू भी, प्रचार पर संशय

चंडीगढ़ : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को भी शामिल किया गया है। हालांकि, उनके प्रचार करने पर संशय है। वह सात महीने से घर पर बैठे हैं और किसी राजनीतिक सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले रहे। सिद्धू ने पिछले साल जुलाई में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हरियाणा विस चुनाव में भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन वह किसी रैली में नहीं गए। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। (राब्यू)

अकाली का एलान, नहीं होने देंगे कमलनाथ की रैली

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाए जाने का शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) व दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) ने विरोध किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कमलनाथ की एक भी चुनावी सभा नहीं होने दी जाएगी। (राब्यू)

पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़े 14.77 लाख मतदाता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के साथ ही मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने इस चुनाव के लिए मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार ली है। सीईओ कार्यालय के मुताबिक, एक करोड़ 47 लाख 86 हजार 389 मतदाता मिलकर इस बार दिल्ली की सरकार चुनेंगे। इस तरह पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार करीब 14.77 लाख अधिक मतदाता हैं। इस चुनाव में इन मतदाताओं की भूमिका अहम हो सकती है।

सीईओ रणबीर सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में अब कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नए नाम जोड़ने व काटने का काम 21 जनवरी के बाद बंद कर दिया गया है। छह जनवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन मतदाता सूची के आंकड़े जारी किए गए थे। तब दिल्ली में एक करोड़ 46 लाख 92 हजार 136 मतदाता थे। इसके बाद भी 11 जनवरी तक काफी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, जिनका सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया चल रही थी। इस तरह छह जनवरी के बाद 94,246 मतदाता जुड़े हैं जिसमें 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता अधिक हैं।

22 जनवरी 2020 तक फाइनल मतदाताओं के आंकड़े

कुल मतदाता : 1,47,86,389	100 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता : 690
पुरुष मतदाता : 81,05,236	दिव्यांग मतदाता : 50,473
महिला मतदाता : 66,80,277	एनआरआइ मतदाता : 498
थर्ड जेंडर : 869	मतदाताओं का अनुपात : 73.40
सर्विस मतदाता : 11,608	मतदाताओं का लिंगानुपात : 824
पहली बार मतदान करने वाले मतदाता (18 से 19 साल के) : 2,32,815	लोकसभा चुनाव के बाद बढ़े मतदाता : चार लाख 69 हजार 929
80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता : 2,04,830	कुल मतदान केंद्र : 2689
	कुल मतदान बूथ : 13,750

70 मॉडल मतदान केंद्र संभालेंगी महिला अधिकारी

दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक मॉडल मतदान केंद्र होंगे। इनमें अन्य मतदान केंद्रों की तुलना में अधिक सुविधा होगी। खास बात यह है कि इन 70 मतदान केंद्रों के सभी बूथ पिंक बूथ होंगे। इसका मतलब यह है कि उसकी कमान पूरी तरह महिला अधिकारियों के हाथ में होगी। इसका मकसद महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हर जिले में एक मतदान बूथ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी संभालेंगे। ऐसे मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों की इच्छा से तैनात किया जाएगा।

इस्तेमाल नहीं होगी डिजिटल मतदाता पर्ची

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

चुनाव में इस बार 11 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की पहचान के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल तो होगा लेकिन अब डिजिटल मतदाता पर्ची का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित होगा। हालांकि लोग वोटर हेल्पलाइन एप से डिजिटल मतदाता पर्ची डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं।

दरअसल, इस बार दिल्ली के सभी 70 सीटों पर चुनाव अधिकारियों द्वारा बूथ एप के इस्तेमाल करने की तैयारी थी। इसके तहत सभी मतदाताओं की पर्ची पर क्यूआर कोड का प्रावधान किया गया है ताकि मतदाता केंद्र पर चुनावी ड्यूटी में जुटे अधिकारी बूथ एप के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर मतदाताओं की पहचान कर सकें। बाद में चुनाव आयोग ने सिर्फ 11 विधानसभा क्षेत्रों में ही इसका इस्तेमाल करने की इजाजत दी। तब यह कहा गया था कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर क्यूआर कोड युक्त मतदाता पर्ची पहुंचाएंगे। किसी वजह से यह पर्ची खो जाने पर मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र पर जा सकेंगे ताकि क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए डिजिटल पर्ची का इस्तेमाल हो सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि इस प्रावधान पर कई लोगों ने सवाल उठाए। चुनाव में गोपनीयता सबसे अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए बूथ में मोबाइल ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी।

करीब चार हजार मतदाता व बुजुर्ग घर बैठे करेंगे मतदान : 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं को इस बार घर बैठे मतदान की सुविधा दी जा रही है। ऐसे कुल 2,55,303 मतदाता हैं लेकिन इसमें से सिर्फ करीब चार हजार लोगों ने ही इस सुविधा के लिए आवेदन दिया है।

सीईओ कार्यालय के अनुसार मतदान के दिन चुनाव अधिकारी बैलेट लेकर उनके घर जाएंगे और मतदान कराएंगे। यह मतदान भी पूरी तरह गोपनीय होगा। उसकी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी और उम्मीदवारों के एजेंट भी वहां मौजूद रह सकते हैं। घर पर मतदाता के नहीं मिलने पर अधिकारी कुछ देर बाद दूसरी बार भी बैलेट लेकर जाएंगे।

पिक एंड ड्रॉप की सुविधा

80 वर्ष से अधिक उम्र वाले जिन बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं ने घर बैठे मतदान के लिए आवेदन नहीं दिया है उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 25 जनवरी से सीईओ कार्यालय को अनुरोध भेजा जा सकेगा और 31 जनवरी तक अनुरोध स्वीकार होगा। वोटर हेल्पलाइन नंबर (1950) पर कॉल या मैसेज (7738299899) भेजकर सुविधा मांगी जा सकती है। मतदाताओं को मैसेज बॉक्स में वोटर कार्ड नंबर व स्पेस देकर पिक लिखकर मैसेज करना होगा

कोई और जीता तो अच्छे काम होंगे खराब

बोले केजरीवाल ▶ हमें एक बार मौका और दीजिए, बाकी बचे कार्य भी पूरे कर देंगे

मुख्यमंत्री ने पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में किया रोड शो

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो निकालकर प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि पांच साल तक जनता की खुशहाली के लिए काम किया है। एक बार मौका और दीजिए बचे कार्य भी पूरे कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई और दल सत्ता में आया तो किए हुए अच्छे काम भी खराब हो जाएंगे। रोड शो के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।

बुधवार को मुख्यमंत्री ने बादली, आदर्श नगर, शाहदरा और कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के साथ रोड शो कर प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। रोड शो में सभी जगह भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए मैंने एक परिवार की देखभाल में बड़े बेटे की तरह भूमिका निभाई है। परिवार में बड़े बेटे के ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। उसको परिवार में सबका ध्यान रखना होता है। बहन की शादी से लेकर घर के अन्य खर्चे तक वह सबकी देखभाल करता है।

70 साल से अटके हैं काम : मुख्यमंत्री ने बाहरी दिल्ली में रोड शो की शुरुआत बादली के स्वरूप विहार स्थित विजय चौक से की और आदर्श नगर विधानसभा के जहांगीरपुरी स्थित कुशल सिनेमा पर समापन किया। इस दौरान वह अलग-अलग जगहों पर रूक कर जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 70 साल से अटके कामों को पांच साल में पूरा करने का प्रयास किया। कुछ काम पांच साल में पूरे नहीं हो सकते, इसके लिए और समय चाहिए। इसलिए हम जनता से पांच साल और मांगने निकले हैं। हमने दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों से भी अपील करता हूं कि वे स्कूलों और अस्पतालों की बेहतरी के लिए आप को ही वोट दें। रोड शो के दौरान बदली विधानसभा से आप उम्मीदवार अजेश यादव व आदर्श नगर विधानसभा से पवन कुमार शर्मा मौजूद रहे।

गीता कॉलोनी में प्रत्याशी एसके बग्गा के साथ रोड शो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हरीश कुमार

शाहदरा में गोयल के साथ मांगे वोट

मुख्यमंत्री ने कृष्णा नगर से आप प्रत्याशी एसके बग्गा के साथ मिलकर गीता कॉलोनी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय से अपने रोड शो की शुरुआत की। यह रोड शो न्यू लाहौर, गीता कॉलोनी ,रशीद मार्केट , होते हुए जगतपुरी में समाप्त हुआ। लोगों ने अपने घरों की छत से मुख्यमंत्री पर फूल भी बरसाए और कुछ लोगों ने रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री को रोककर अपनी लिखित शिकायतें भी दी। परवाना रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए और काले गुब्बारे भी छोड़े। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी व दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के साथ रोड शो किया। यह रोड शो भोलानाथ नगर से शुरू हुआ और बाबूराम स्कूल, अनाज मंडी, ज्वाला नगर से होते हुए कस्तूरबा नगर समाप्त हुआ। रोड शो में प्रचार के कई रंग भी देखने को मिले। कार्टून कलाकारों ने मनोरंजन करके और बच्चों ने नृत्य पेश करके आप के लिए वोट मांगे।

आप के लिए बागी पड़ न जाएं भारी, सुलह के प्रयास जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- टिकट काटे जाने से बागी विधायकों ने आप प्रत्याशियों के खिलाफ ठोकी ताल
- आप ने पिछली बार की तुलना में इस बार 15 विधायकों का टिकट काटा है

राजधानी के महासमर में आम आदमी पार्टी के लिए अपने ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से खफा कई विधायकों ने पार्टी प्रत्याशियों के सामने ताल ठोक दी है। वहीं कुछ विधायक अंदरखाने प्रत्याशियों की जड़ें काटने में जुटे हुए हैं। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बगावत को थामने की है। यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व टिकट वितरण से नाराज विधायकों और अन्य कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि जिन लोगों ने आप प्रत्याशियों के सामने पर्चा दाखिल किया है। वे सभी लोग नामांकन वापस ले लेंगे।

टिकट काटे जाने से बागी हुए विधायकों ने आप प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोक दी है। इसमें सीलमपुर से विधायक हाजी इशराक, गोकलपुर से चौधरी फतेह सिंह, कोंडली से मनोज कुमार, हरी नगर के जगदीप सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। वहीं दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह कमांडो ने एनसीपी से, बदरपुर से एनडी शर्मा ने बीएसपी से पर्चा भरा है।

टिकट न मिलने से नाराज आदर्श शास्त्री ने द्वारका सीट से कांग्रेस के टिकट पर नामांकन कराया है। हालांकि, पार्टी ने कोशिश करके हाजी इशराक और कालकाजी से विधायक अवतार सिंह कालका को मना लिया है। उन्होंने पर्चा नहीं भरा है, मुंडका सीट से नाराज विधायक सुखबीर सिंह दलाल को भी पार्टी ने मना लिया है। उन्होंने भी पार्टी के प्रत्याशी के सामने पर्चा नहीं भरा है। इसके बाद भी छह से अधिक विधायक चुनाव मैदान में हैं। पार्टी नहीं चाहती है कि कोई भी विधायक बागी रह कर उनके प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़े।

इसे देखते हुए पार्टी की तरफ से बागियों को मनाने की जिम्मेदारी पार्टी के दिल्ली प्रभारी संजय सिंह को सौंपी गई है। बुधवार को भी वह हाजी इशराक और सुखबीर दलाल के साथ पार्टी आफिस में देखे गए। हालांकि, तीन दिन पहले भी संजय सिंह ने सुखबीर सिंह दलाल और कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ पार्टी आफिस में प्रेसवार्ता की थी। इसके बाद भी वह कमांडो को नहीं मना सके और उन्होंने दिल्ली कैंट से नामांकन करा दिया है।

आप ने 15 विधायकों का टिकट काटा है। पार्टी ने जिन विधायकों का टिकट काटा है, उनसे पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में लगने के लिए कहा है। साथ ही उन्हें अहसास भी कराया गया कि पार्टी ने भी उनके लिए सब कुछ किया है। आगे भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी।

भाजपा और आप का नापाक गठजोड़ फिर उजागर : सुभाष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां इतनी हताश हो गई हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों को लक्ष्य बनाकर स्क्रूटनी के समय उन पर अनाप-शनाप आरोप लगा रही हैं। इससे भाजपा और आप का नापाक गठजोड़ फिर उजागर हुआ है। वह बुधवार को प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के विरुद्ध नई दिल्ली से 74 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। इतनी बड़ी संख्या में उनके विरुद्ध नामांकन दिल्ली की जनता का उनकी जनविरोधी नीतियों और कामों के प्रति विरोध प्रकट करता है। केजरीवाल का इतिहास काम करने का नहीं बल्कि केवल प्रचार करने का है। इसे दिल्ली की जनता समझ चुकी है।

इस दौरान उन्होंने रोहतास नगर एवं मुस्तफाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं, पदाधिकारियों और सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर रोहतास नगर से कांग्रेस प्रत्याशी विपिन शर्मा, मुस्तफाबाद से पार्टी प्रत्याशी अली मेंहदी, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रो रतन जैन भी उपस्थित थे।

मोदी, शाह और नड्डा होंगे भाजपा के स्टार प्रचारक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली विधानसभा चुनाव में कलाकार भी उतरेंगे प्रचार में
- भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में बहाएंगे पसीना

दिल्ली विधानसभा में भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री व भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा से जुड़े फिल्मी कलाकार भी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे।

भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाएगा। दिल्ली के सभी सांसदों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। कला जगत से राजनीति में आने वाले भाजपा नेता भी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए रोड शो करेंगे।

सूची में ये भी शामिल : केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावडेकर, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, सोम प्रकाश, गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर, नित्यानंद राय व हरदीप पुरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा नेता श्याम जाजू, तरुण चुघ, मनोज तिवारी, हर्षवर्धन, विजय गोयल, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मीनाक्षी लेखी, हेमा मालिनी, हंस राज हंस, गौतम गंभीर, अनिल जैन, दुष्यंत कुमार गौतम, सिद्धार्थन, सनी देओल, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ।

भाजपा के लिए आसान नहीं जजपा से समन्वय

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

- जजपा के चुनाव नहीं लड़ने से हतोत्साहित हैं दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता
- भाजपा प्रत्याशियों का साथ देने से पहले दुष्यंत चौटाला को अपने कार्यकर्ताओं को मनाना होगा

हरियाणा सरकार में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी अपनी तैयारियों के बावजूद इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। पार्टी नेता और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इसके पीछे यह कारण बताते हैं कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चाबी निर्दलीय प्रत्याशियों को दे दिया है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

इससे पहले दुष्यंत ने पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक कर दम भरा था कि चाहे जो हो जाए जजपा दिल्ली में चुनाव अवश्य लड़ेगी। इसके लिए दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कुछ सीटों पर समझौते का प्रस्ताव भी रखा था। दुष्यंत चौटाला भाजपा के तत्कालीन कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इस सिलसिले में मिले थे।

इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संभावना जताई थी कि भाजपा दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जजपा का सहयोग ले सकती है। चुनाव नहीं लड़ने के निर्णय के साथ दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा है कि दिल्ली में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशियों की मदद करेंगे। हालांकि दुष्यंत चौटाला की इस बात से जमीनी स्तर पर जजपा के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं। उनमें साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। इन कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रत्याशियों के साथ लगाना आसान नहीं होगा। जानकारी के अनुसार भाजपा की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री डॉ.अनिल जैन ही दुष्यंत के साथ समन्वय करेंगे।

दुष्यंत चौटाला। फाइल

हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को समझाएंगे दुष्यंत

जजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी पार्टी का दिल्ली में भाजपा के साथ चाहे जिस भी कारण से समझौता नहीं हो पाया मगर अब पार्टी कार्यकर्ताओं पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आने वाले दिनों में जजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में भाजपा का साथ देगा और हरियाणा से भी जजपा कार्यकर्ता भाजपा के प्रचार में उतारे जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं कि बाहरी दिल्ली की पांच सीटों पर तो जजपा कार्यकर्ता अथवा नेता इस बार तय मानकर चल रहे थे कि भाजपा से उनका समझौता होगा। मगर समझौता नहीं होने से वे काफी निराश हैं। अब पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला इन नाराज व रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का काम भी करेंगे। हालांकि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का तो यहां तक कहना है कि वे चौधरी देवीलाल नहीं है कि जो कहेंगे और मतदाता आंख बंद करके मान लेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बाहरी दिल्ली में केवल दुष्यंत के प्रत्याशी ही टिक सकते थे।

नेशनल कैपिटल

ग्रेटर नोएडा में आए बिना जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी मेट्रो

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- जेवर एयरपोर्ट से सीधे नोएडा सेक्टर 142 को जोड़ने की योजना
- डीएमआरसी से जल्द तैयार कराई जाएगी डीपीआर

जेवर एयरपोर्ट मेट्रो को सीधे नोएडा सेक्टर 142 से जोड़ा जा सकता है। यमुना प्राधिकरण इसके लिए जल्द ही दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। 142 से बोटेनिकल गार्डन को मेट्रो से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इसके निर्माण से जेवर एयरपोर्ट आइजीआइ एयरपोर्ट से मेट्रो से जुड़ जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट को मेट्रो कनेक्टिविटी देने के लिए यमुना प्राधिकरण ने डीएमआरसी से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई थी। इसके तहत नॉलेज पार्क दो एक्वा मेट्रो स्टेशन से यमुना एक्सप्रेस वे के समानांतर हरित क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो ट्रैक बनाने का सुझाव दिया गया था। मेट्रो निर्माण की धनराशि जुटाने के लिए इस रिपोर्ट को शासन को भेजा गया था। इसी बीच जेवर एयरपोर्ट मेट्रो के लिए एक नए रूट पर विचार शुरू हो गया है। इसके तहत नोएडा के सेक्टर 142 से सीधे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है।

यह रूट एक्सप्रेस वे के दूसरी ओर नोएडा के सेक्टरों से होकर सीधे जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगा। 142 सेक्टर से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो ट्रैक के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इसकी रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। इसके बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट मेट्रो सेक्टर 142, बोटेनिकल गार्डन होते हुए शिवाजी स्टेडियम पर आइजीआइ एयरपोर्ट (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) मेट्रो से जुड़ जाएगी। दोनों एयरपोर्ट के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बन जाएगी।

परिवारवाद

तीनों ही प्रमुख दलों ने दिग्गज नेताओं के पुत्र-पुत्रियों को टिकट देकर अगली पीढ़ी को विरासत सौंपने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं

विरासत संभालने को चुनावी मैदान में उतरे लाडले

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

परिवारवाद को लेकर राजनीतिक दलों में भले ही कितने भी सियासी दावे किए जाएं, लेकिन हकीकत यही है कि हर चुनाव में नेता अपनी विरासत पुत्र-पुत्रियों को सौंप रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार भी तीनों ही प्रमुख दलों ने दिग्गज नेताओं के पुत्र-पुत्रियों को टिकट देकर अगली पीढ़ी को विरासत सौंपने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं।

चुनाव में इस बार कई नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाने में सफलता पाई है। इसमें भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के भतीजे विक्रम विधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। बिधूड़ी 2014 में दक्षिणी दिल्ली से पहली बार सांसद चुने गए थे। इससे पहले वो तीन बार तुगलकाबाद सीट से विधायक चुने जाते रहे। हालांकि 2015 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने बड़ा उलटफेर करते हुए इनके भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विक्रम बिधूड़ी को 33,701 वोटों से शिकस्त दी थी। दक्षिणी दिल्ली की एक और सीट कालकाजी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आप ने यहां से आतिशी को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट पर इन्हें भाजपा के गौतम गंभीर से करारी शिकस्त मिली थी। भाजपा ने उनके सामने धर्मवीर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस से सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा मैदान में हैं। 2013 के चुनाव में चोपड़ा इस सीट से हार गए थे। 1998 से 2008 तक सुभाष ही इस सीट से विधायक रहे थे। 2015 में आप के उम्मीदवार अवतार सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। आरकेपुरम विधानसभा सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री की बेटी प्रियंका सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। योगानंद ने हाल में कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। 2015 में यहां से आप की प्रमिला टोकस ने जीत दर्ज की थी। अगली पीढ़ी की इस फेहरिस्त में अगला नाम मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का आता है। यहां से पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिमी जिले की हॉट सीट द्वारका में भी मुकाबला दिलचस्प है। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वो आप के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। महाबल मिश्रा द्वारका सीट से विधायक रह चुके हैं और 2015 में भी इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके थे। पिछली बार यहां से आप के आदर्श शास्त्री जीते थे। बवाना से बीजेपी के रविंद्र कुमार इंद्राज चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पिता नरेला से विधायक रह चुके हैं।

कांग्रेस में परिवारवाद की लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस ने अंबेडकर नगर से पूर्व विधायक प्रेम सिंह के बेटे यदुराज सिंह को टिकट दिया है। वहीं नांगलोई जाट से पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह के बेटे मंदीप सिंह को टिकट दिया है। मंदीप सिंह वर्तमान में निगम पार्षद हैं।

रोहतास नगर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम बाबू शर्मा के बेटे पूर्व विधायक विपिन शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो देवली सीट से वरिष्ठ नेता बूटा सिंह के बेटे पूर्व विधायक अरविंदर सिंह को टिकट दिया गया है।

आप उम्मीदवार तोमर की पत्नी को मिला टिकट

दिल्ली की त्रिनगर विधानसभा सीट से आप के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर का टिकट काटकर उनकी पत्नी प्रीति तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र सिंह तोमर को अयोग्य घोषित किया था। कांग्रेस ने भी कभी बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कीर्ति आजाद की पत्नी चुनाव मैदान में उतारा है। वे संगम विहार से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यहां आप ने एक बार फिर अपने वर्तमान विधायक दिनेश मोहनिया पर भरोसा जताया है।

शाहीन बाग प्रदर्शन को भाजपा ने बताया सुरक्षा के लिए खतरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

शाहीन बाग में प्रदर्शन को भाजपा ने सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उसका कहना है कि सीएए को लेकर आप और कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह से सड़कें बंद हैं। लोगों का कारोबार ठप हो गया है। दहशत का माहौल है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किया '39 दिन हो गए शाहीन बाग के कारण यातायात ठप, लाखों लोग परेशान। बच्चे परीक्षा के समय भी 2-2 घंटे सड़कों पर बर्बाद कर रहे हैं। ऑफिस जाने वालों को परेशानी। व्यापारियों को नुकसान। क्या ये जायज है?' राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति में दिल्ली व राजधानी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़कें बंद हैं। एंबुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो गए हैं। लोगों का कारोबार बंद कर दिया गया है। फ्रेंड्स कॉलोनी में लोगों के घरों में तोड़ फोड़ की गई थी जिससे लोग डरे हुए हैं।

भाजपा नेताओं ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को गुमराह करके हिंसा के लिए भड़का रही है। मुस्लिमों के मन में डर पैदा किया जा रहा है।

2004 में आखिरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड के लिए निमंत्रित किया गया था। तब ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डि सिल्वा थे। इससे पहले 1998 में भी ब्राजीली राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर विशेष अतिथि शामिल हुए थे।

जम्मू-कश्मीर के बच्चे राष्ट्रवादी भटकाने वाले दोषी : राजनाथ

रक्षा मंत्री बोले ▶ सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, भारत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर के बच्चों को राष्ट्रवादी करार देते हुए साफ कहा कि कभी-कभी इन्हें गलत दिशा में भटका दिया जाता है इसीलिए इन बच्चों को हमें किसी दूसरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा आखिर युवा होते हैं और इसलिए उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए दोषी मानने के बजाय उन लोगों को दोषी माना जाए जो इन्हें भटकाते हैं।

रक्षा मंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए आए एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए यह बात कही। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में 10 से 12 साल के बच्चों को कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित किए जाने के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के बयान के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह टिप्पणी मायने रखती है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों के बीच राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि भारतीय मूल्य सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और इसीलिए भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र किए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने तय किया था कि हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी (पाकिस्तान) ने अपने राष्ट्र का एक धर्म घोषित कर दिया और उसने खुद को एक धर्मशासित देश बना लिया। यहां तक की अमेरिका भी एक धर्म प्रधान देश है मगर भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे संत-महात्माओं ने न केवल राष्ट्र की सीमाओं में रहने वाले सभी लोगों को एक परिवार माना बल्कि हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं।

नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने (दाएं से चौथे) एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप में कैडेटों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों को संबोधित भी किया। एएनआइ

पीएम ने तीन मंत्रालयों के नौ लंबित प्रोजेक्ट की समीक्षा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस साल की पहली 'प्रगति' बैठक में तीन मंत्रालयों के नौ प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के ये प्रोजेक्ट नौ राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में फैले हुए हैं।

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि नौ में से तीन प्रोजेक्ट रेलवे के, पांच सड़क परिवहन और राजमार्ग और एक प्रोजेक्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का है। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के कार्यों की भी समीक्षा की।

ई-गवर्नेंस के जरिए प्रभावी पुलिसिंग के लिए व्यापक व एकीकृत प्रणाली क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर को 'प्रगति' कार्यक्रम के तहत 12.30 लाख करोड़ के 269 प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी।

जावडेकर बोले, पिछड़ी जातियों का पता लगाने में अभी लगेगा और वक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आरक्षण के बाद भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की पिछड़ी रह गई जातियों का पता लगाने और उन्हें आरक्षण का समुचित लाभ दिलाने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल सरकार ने एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 31 जुलाई, 2020 तक इससे जुड़ी रिपोर्ट सरकार को देगा। आयोग के कामकाज का दायरा भी बढ़ाया गया है। वह ओबीसी जातियों के नामों की अशुद्धियों का पता लगाने व सही करने की सिफारिशें भी देगा।

केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि आयोग को यह विस्तार उन्हें दिए गए नए कामों को देखते हुए लिया गया है। ओबीसी की कई जातियों के नामों में ब्रिटिश काल से ही अशुद्धियां चली आ रही थीं, जिसे अब ठीक करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल इस काम का जिम्मा आयोग को सौंपा गया है। आयोग की सिफारिश मिलने के बाद इसे ठीक करने का काम किया जाएगा। आयोग का मौजूदा कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा था। ओबीसी की पिछड़ी जातियों का पता लगाने और इसके उपवर्गीकरण को लेकर सरकार ने जस्टिस जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर, 2017 को इस आयोग का गठन किया था। उस समय आयोग को सिर्फ 12 हफ्ते के भीतर ही इसे लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन यह काम पूरा नहीं हो पाया और सरकार आयोग के कार्यकाल को लगातार विस्तार देते चली आ रही है।

कैबिनेट का फैसला

- सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया, अब 31 जुलाई, 2020 तक करेगा काम
- अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़ी जातियों के नामों की अशुद्धियां भी परखेगा आयोग

नई दिल्ली में बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर। एएनआइ

नए एनआइटी में स्थायी परिसर निर्माण के संशोधित लागत अनुमान मंजूर

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय कैबिनेट ने नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआइटी) के स्थायी परिसरों की 2022 तक स्थापना के लिए 4,371.90 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमानों को बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इन एनआइटी की स्थापना 2009 में की गई थी और इन्होंने अकादमिक वर्ष 2010-11 से सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे वाले अपने-अपने अस्थायी परिसरों में कामकाज शुरू कर दिया था। कैबिनेट ने नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के मुख्यालय के रूप में दमन को स्वीकृति दी है। संसद ने पिछले महीने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया था। मंत्रिमंडल ने जहाजरानी मंत्रालय द्वारा तैयार मॉडल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी मंजूरी दे दी। इससे मंत्रालय को दूसरे देशों के साथ एक दूसरे के प्रमाणपत्रों को मान्यता देने संबंधी समझौता करने का अधिकार मिल गया है।

न्यूज गैलरी

एनएच के विकास को लेकर आज से मंथन

गुरुग्राम : देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से लेकर नए राजमार्ग बनाने के बारे में गुरुवार से मानेसर में दो दिवसीय मंथन शुरू होगा। इसमें पूरे देश से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों के साथ ही केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव, एनएचएआइ के चेयरमैन सहित सभी आला अधिकारी भाग लेंगे। मंथन के दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही सड़क परिवहन राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। आगामी दिनों में क्या कुछ करने की आवश्यकता है, इस बारे में सुझाव लेंगे। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बैठक तय समय पर शुरू हो। इसके लिए सभी को बुधवार रात तक ही पहुंचने का निर्देश दिया गया था। दो दिवसीय बैठक के दौरान तीन विषयों पर बारीकी से मंथन किया जाना है - कहीं परियोजना को तेजी से पूरा करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जो परियोजना तैयार है उसमें क्या सुधार या विस्तार हो सकता है और भविष्य में कहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने की आवश्यकता है। (जासं)

संसदीय समिति का दो दिनों का महाराष्ट्र दौरा आज से

नागपुर : केंद्रीय बजट से पहले बड़ी उम्मीदें जगाते हुए 31 सदस्यीय संसदीय समिति गुरुवार से महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेगी। यह समिति किसानों के मुद्दों का अध्ययन करेगी। कृषि पर स्थायी समिति के अध्यक्ष पर्वतगौड़ा सी. गद्दिगौदर इस दल की अगुआई करेंगे और इसमें राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 21 सदस्य शामिल होंगे। सांसदों को नागपुर में पांच सितारा रेडिसन ब्ल्यू होटल में ठहराया जा सकता है जहां वे विभिन्न भागीदारों और कृषि विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। पूर्व में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या शीर्ष अधिकारी किसानों से जुड़े मुद्दे पर पांच सितारा होटल में बैठक करने से बचते रहे हैं। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी माने जाने वाले इस शहर में दूसरी कोई सुविधाजनक और चर्चा से दूर रहने वाली जगह तलाशी जाती थी। संसदीय समिति के फाइव स्टार होटल वाले कदम से राजनीतिक हलकों में त्योरियां चढ़ गई हैं। कुछ दिनों पहले भाजपा के कई नेता और सरकार सांसदों को पांच सितारा सुविधा का त्याग करने और लोगों के करीब जाने की सलाह दे चुकी है। 2019 से सरकार नवनिर्वाचित सांसदों को स्टार होटलों में ठहराने की प्रथा बंद कर चुकी है। (आइएएनएस)

भाजपा बोली, जिन्ना बनने की राह पर चल रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एआइएमआइएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान पर भाजपा ने तीखा प्रहार किया है। मुसलमानों के 800 साल तक देश पर शासन करने के बयान को विभाजनकारी बताते हुए भाजपा ने कहा कि ओवैसी नया जिन्ना बनने की राह पर चल रहे हैं। इसके साथ भी भाजपा ने कांग्रेस को भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आड़े हाथों लिया।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आजादी के समय से अभी तक कांग्रेस नेताओं के बयान उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की पुष्टि करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण के मुसलमानों से पूछकर शिवसेना के साथ सरकार बनाने के बयान पर हमला करते हुए पात्रा ने कहा कि इससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। बयान को आपत्तिजनक करार देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के अपमान के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पात्रा ने 1946 से कांग्रेसी नेताओं के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वह सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन, मुसलमानों का कोई भला नहीं करती है।

पात्रा बोले

- मुसलमानों से पूछकर शिवसेना से समझौते का कांग्रेस का बयान हिंदुओं का अपमान
- लोकतंत्र के नाम पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ जहर बोया जा रहा है

संबित पात्रा फाइल फोटो

पात्रा ने बताया कि किस तरह कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा था। उसी समय कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन में मंत्री और कांग्रेसी नेता जेडए खान ने देश के हर जिले में शरिया कोर्ट बनाने की वकालत की थी। पात्रा ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग, दिग्विजय सिंह के मुंबई हमले के पीछे आरएसएस का हाथ होने और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन के देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों के होने के बयान का भी हवाला दिया।

पात्रा के अनुसार, इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में वंदे मातरम को राष्ट्र गान बनाने और 1951 में कॉमन सिविल कोड के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रस्ताव का विरोध किया था। दिल्ली के शाहीन बाग में छोटी बच्चियों के मन में प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर भरे जाने का विरोध करते हुए पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश में हिंदुओं के खिलाफ जहर बोया जा रहा है।

सरकारी भवनों से रिसेप्शन काउंटर बाहर ले जाने पर हो रहा विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र की प्रमुख निर्माण एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी सरकारी भवनों के भीतर स्थित रिसेप्शन काउंटरों को परिसर से बाहर ले जाने की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। सीआइएसएफ द्वारा सुरक्षा को लेकर चिंता जताने के बाद यह कदम उठाया गया है। सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार के अधिकांश भवनों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र में सीआइएसएफ ने कहा है कि कार्यालय भवन के भीतर स्थित रिसेप्शन काउंटर 100 फीसद पहुंच की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। देश के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सीआइएसएफ ही करता है। अपने पत्र में बल ने कहा है कि सरकारी भवनों के परिसर के भीतर रिसेप्शन काउंटरों के होने से अनधिकृत व्यक्ति वहां प्रवेश कर सकते हैं। हाल ही में यह पत्र सीपीडब्ल्यूडी को भेजा गया है। सीपीडब्ल्यूडी महानिदेशक प्रभाकर सिंह ने कहा, 'सीआइएसएफ द्वारा जताई गई सुरक्षा चिंता को देखते हुए एजेंसी (सीपीडब्ल्यूडी) शीघ्र ही सरकारी भवनों से रिसेप्शन काउंटरों को बाहर ले जाने की संभावना का पता लगाएगी।'

तारपीडो आपूर्ति के लिए फ्रांसीसी और जर्मन कंपनी दौड़ में

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय नौसेना को करीब 100 हेवीवेट तारपीडो की आपूर्ति के लिए जर्मनी की कंपनी 'एटलस इलेक्ट्रॉनिक' और फ्रांस की कंपनी 'नेवल ग्रुप' अंतिम रेस में हैं। बता दें कि इन तारपीडो को स्कॉर्पीन श्रेणी की पारंपरिक और अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों में लगाया जाना है।

रक्षा सूत्रों ने बताया, 'निविदाओं का जवाब देने की आखिरी तारीख 17 जनवरी थी और इस संबंध में सिर्फ दो कंपनियों जर्मनी की एटलस इलेक्टॉनिक और फ्रांस की नेवल ग्रुप ने जवाब दिया है।' ये निविदाएं इसलिए अहम हैं क्योंकि फ्रांसीसी स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है और अभी तक इनमें नए तारपीडो नहीं लगाए गए हैं।

स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों को अब कलवरी श्रेणी नाम दिया गया है। आइएनएस कलवरी नामक इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी नौसेना में शामिल की जा चुकी है और संचालन में है। परियोजना के विवरण के मुताबिक, नौसेना के लिए हेवीवेट तारपीडो की तात्कालिक जरूरतों को विदेश से खरीद के जरिये पूरा किया जाएगा, लेकिन दीर्घकालिक जरूरतों को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के जरिये पूरा किया जाएगा। नौसेना ने वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से यह आश्वासन हासिल कर लिया है कि उनके देश की सरकारें उनके तारपीडो को अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों में लगाने की अनुमति प्रदान करेंगी।

- नौसेना की स्कॉर्पीन और अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए होनी है खरीद

बता दें कि नौसेना के लिए हेवीवेट तारपीडो के लिए फ्रांस, स्वीडन, रूस और जर्मनी के वैश्विक निर्माताओं को निविदाएं जारी की गई थीं, लेकिन सिर्फ दो कंपनियों ने ही इसका जवाब दिया।

इससे पहले नौसेना ने इटली की कंपनी 'वास' के ब्लैक शार्क तारपीडो का चयन किया था, लेकिन यह कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में फंसी दागी कंपनी फिनमैकेनिका ग्रुप का हिस्सा थी। लिहाजा विवाद के चलते नौसेना को अपना चयन निरस्त करना पड़ा।

भगोड़े नित्यानंद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ

नई दिल्ली, प्रेट्र : नाबालिगों के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप के बाद देश से फरार नित्यानंद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि गुजरात पुलिस ने सीबीआइ से अपील की थी। सीबीआइ ही अंतरराष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल से किसी की तलाश या गिरफ्तारी के लिए अपील करती है। अहमदाबाद (ग्रामीण) के पुलिस उपाधीक्षक केटी कमरिया ने बताया कि इंटरपोल ने भगोड़े नित्यानंद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। उसके खिलाफ गुजरात पुलिस ने अपहरण मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। नित्यानंद पिछले साल से फरार चल रहा है। इसके अलावा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रकिया भी शुरू कर दी गई है।

बुधवार को गुजरात पुलिस ने कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में कहा कि पिछले साल कर्नाटक में दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद के बाद नित्यानंद देश छोड़कर फरार हो गया था। गुजरात पुलिस ने नित्यानंद के खिलाफ यह आरोपपत्र अहमदाबाद आश्रम से दो लड़कियों के गायब होने के मामले में दाखिल किया है। इन लापता लड़कियों ने कोर्ट में जमैका के किंग्सटन से हलफनामा भी दायर किया है। अहमदाबाद आश्रम से दो लड़कियों के गायब होने के बाद पिछले साल नवंबर में नित्यानंद के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। ब्लू कॉर्नर नोटिस ऐसे व्यक्ति पता लगाने के लिए जारी किया जाता है, जो अपराधी है और लापता है। वहीं, रेड कॉर्नर नोटिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। गुजरात पुलिस ने कहना है कि नित्यानंद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाल ही में गुजरात पुलिस ने नित्यानंद को वांटेड घोषित कर दिया था।

नित्यानंद फाइल फोटो

रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी प्रक्रिया शुरू

हाल ही में नित्यानंद ने दावा किया था कि उसने इक्वाडोर से खरीदे गए द्वीप पर एक हिंदू राष्ट्र-कैलाशा का निर्माण किया है। नित्यानंद का असली नाम राजशेखरन है और वह तमिलनाडु का रहने वाला है।

'मोबाइल सिम के लिए भी बताना होता है नाम-पता, फिर अब परहेज क्यों'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एनपीआर और सीएए पर हो-हल्ला मचा रहे लोगों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल फोन का सिम लेने पर भी नाम और पता बताना होता है और उसके प्रमाण देने होते हैं। तो फिर एनपीआर को लेकर विरोध क्यों। वैसे भी एनपीआर तैयार करने का फैसला कांग्रेस का है। यह फैसला कांग्रेस ने 2010 में ही ले लिया था, लेकिन उस समय किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। हालांकि उन्होंने साफ किया, इसमें मांगी गई किसी भी जानकारी का ब्योरा देना जरूरी नहीं है।

केंद्रीय मंत्री जावडेकर बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के बाद सीएए, एनआरसी और एनपीआर से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने साफ किया कि असम के जिस एनआरसी को विपक्ष और कांग्रेस मुद्दा बना रही है। वह यह क्यों भूल रही है कि इसे लाने की फैसला उन्हीं का ही था। जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया। जावडेकर से इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बल्कि उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इसे समझना चाहिए।

गोगोई पर दुराचार के आरोप लगाने वाली कर्मचारी बहाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व महिला कर्मचारी को सेवा में बहाल कर दिया है, जिसने पिछले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाया था।

सूत्रों के मुताबिक, महिला ड्यूटी पर वापस आने के बाद छुट्टी पर चली गई है। उसकी बकाया राशि भी उसे दे दी गई है। गौरतलब है कि जस्टिस एसए बोबडे (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय इन-हाउस जांच समिति ने पिछले साल मई में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को आरोपों से बरी कर दिया था। जांच समिति को महिला कर्मचारी के आरोपों में कोई आधार नहीं मिला था।

एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में महिला कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला बंद कर दिया था। इस मामले में पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए हरियाणा के झज्जर निवासी नवीन कुमार ने कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

बता दें कि नवीन कुमार की तरफ से तिलक मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पिछले साल तीन मार्च को महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

- ड्यूटी पर वापस आने के बाद छुट्टी पर चली गई महिला कर्मचारी, उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला भी बंद
- जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय इन-हाउस जांच समिति ने गोगोई को आरोपों से बरी कर दिया था

नवीन कुमार ने आरोप लगाया था कि महिला ने उसे सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उससे 50,000 रुपये ठग लिए। इस आरोप के बाद 10 मार्च को महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले दिन एक अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 12 मार्च को उसे जमानत मिल गई। अप्रैल 2019 में महिला ने सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों को हलफनामा देकर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था। बाद में उसने दावा किया कि पहले उसका तबादला किया गया और बाद में नौकरी से हटा दिया गया।

गृह मंत्रालय की चेतावनी, आक्रोशित व्यक्ति उठा सकते हैं कठोर कदम

नई दिल्ली, एएनआइ : गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के डीजी, आइबी निदेशक और एसपीजी प्रमुख एवं अन्य को पत्र भेजकर नए खतरे के संबंध में सावधान किया है। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली अपमानजनक टिप्पणियों और फोटो आदि से खतरा जुड़ा बताया है।

गणतंत्र दिवस परेड पर सभी आतंकी समूहों से खतरे की आशंका के संबंध में किए गए पत्राचार के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का विस्तृत प्रभाव दिख सकता है। मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में बेनामी धमकी भरे पत्रों, संदेशों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रधानमंत्री एवं उच्च पदों पर आसीन अन्य लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और फोटो की बाढ़ आ गई है। ऐसे में इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि आक्रोशित व्यक्ति कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं। पिछले सप्ताह जारी पत्र में प्रधानमंत्री पर हवाई खतरे का भी उल्लेख किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बार दिल्ली को अतिरिक्त बल दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं।

तैयारी

विभिन्न राज्यों झांकी में दिखेगी सांस्कृतिक-धार्मिक विविधता, जयपुर की छटा और उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल भी आएंगे नजर

राजपथ पर सुनाई देगी गुरबाणी, दिखाई देगा कुल्लू का दशहरा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस परेड में इस बार राजपथ पर गुरबाणी भी सुनाई देगी और अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा भी दिखाई देगा। विश्व प्रसिद्ध जयपुर और उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों की छटा भी मन को लुभाएगी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में वहां की सांस्कृतिक-सामाजिक-धार्मिक विविधता का खासा मिश्रण देखने को मिलेगा। पंजाब की झांकी गुरु नानक देव के 550 वें प्रकाश पर्व पर आधारित है। इसके तीन खंड हैं- किरत करो, नाम जपो और वंड छको। इनके जरिये विश्व को संदेश दिया जाएगा कि ईमानदारी से आजीविका चलाएं, ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करें और श्रम के फल को आपस में बांटे। इस झांकी के साथ चलती सिख संगत गुरबाणी भी गाती रहेगी।

छत्तीसगढ़ की झांकी में वहां के लोक जीवन का कलात्मक सौंदर्य देखने को मिलेगा। जनजातीय शिल्प कला के जरिये आभूषणों, तरह-तरह की प्रतिमाओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं तक को देखा जा सकेगा। झांकी के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा, मध्य में पारंपरिक गहनों से सुसज्जित एक युवती और आखिर में धान की कोठी बनाई गई है। झांकी के दोनों ओर लोक नर्तकों का नृत्य देखा जा सकेगा।

गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर की झांकी कुछ इस तरह राजपथ पर दिखाई देगी। ध्रुव कुमार

उत्तर प्रदेश की झांकी में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को प्रदर्शित किया गया है। इसमें सर्व धर्म सम्भाव भी दर्शाया गया है। झांकी के अग्र भाग में भारतीय संगीत से जुड़े वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि प्लेटफार्म के नीचे काशी से बहती अविरल गंगा और वहां की संस्कृति का नजारा होगा। झांकी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तबला सम्राट पंडित सामता प्रसाद, गायिका गिरिजा देवी की प्रतिकृतियां भी प्रदर्शित होंगी। कथक नृत्य करते कलाकार झांकी को सजीव बनाएंगे।

हिमाचल प्रदेश की झांकी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कुल्लू दशहरा महोत्सव प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के अग्रभाग में स्थानीय देवता के मोहरों से सुसज्जित देवरथ, बीच में जमीन पर रखी एक देव पालकी तथा आखिर में कुल्लू के अधिष्ठाता देव रघुनाथ के रथ को खींचते देवलू दर्शाए गए हैं। झांकी के साथ दोनों ओर कुल्लू के पारंपरिक वाद्ययंत्री देवधुन बजाते नजर आएंगे।

जम्मू कश्मीर की झांकी गांव की ओर चलने का संदेश देगी। झांकी के सामने का भाग कश्मीर की अनूठी परंपरा की समृद्धि के प्रतीक शॉल बुनकर की विशाल मूर्तिकला को दर्शाएगा। इसके बाद वहां की संस्कृति का चित्रण करने के लिए पारंपरिक लोक संगीतकारों के साथ विभिन्न कलाकृतियों से जुड़े कारीगरों का प्रदर्शन होगा। पारंपरिक बसोली चित्रकला झांकी का अहम घटक है।

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ की झांकी निरस्त

दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने इस बार राजधानी की धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक विरासत पर झांकी तैयार करने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें दर्शाया जाना था कि दिल्ली में सभी धर्म-संप्रदायों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और यहां सभी धर्मों के अनुयायियों के धार्मिक स्थल भी हैं। विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली के इस प्रस्ताव को चार राउंड तक विचाराधीन रखा, लेकिन उसके बाद अस्वीकृत कर दिया। इसी तरह से हरियाणा सरकार की ओर से राज्य की झांकी के पांच प्रस्ताव भेजे गए थे। मेरी फसल- मेरा ब्योरा, मेरा परिवार-मेरी पहचान, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, अंत्योदय सरल केंद्र एवं महिला सुरक्षा- नारी शक्ति एप। लेकिन विशेषज्ञ समिति ने राज्य सरकार के प्रचार से जुड़े उक्त सभी प्रस्तावों को रद कर दिया। चंडीगढ़ की झांकी का प्रस्ताव जेलों की थीम पर था, वो भी समिति को पसंद नहीं आया।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

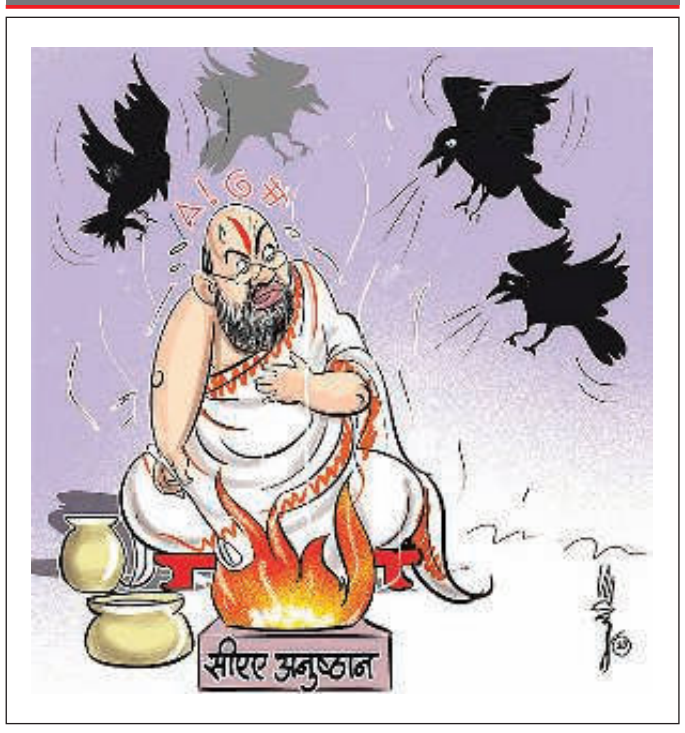

26 जनवरी से महाराष्ट्र के स्कूलों में रोजाना सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यमंत्री वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक, छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे, ताकि वे इसका महत्व जान सकें।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 23 जनवरी 2020

27 जनवरी से मुंबई में 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल, सिनेमा घर और दुकानें

फैसला ▶ महाराष्ट्र कैबिनेट ने 'मुंबई 24 घंटे' नीति पर लगाई मुहर

आदित्य ठाकरे ने कहा, इससे पुलिस पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई की नाइटलाइफ पर बुधवार को आधिकारिक मुहर लग गई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 'मुंबई 24 घंटे' नीति को हरी झंडी देते हुए इसके पहले चरण के तहत गैर आवासीय इलाकों के मॉल में स्थित थिएटर, दुकानें, खानपान के आउटलेट और मॉल परिसरों को 27 जनवरी से 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया के साथ फैसले की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि लंदन की नाइट इकोनॉमी (रात्रिकालीन कारोबार) पांच बिलियन पौंड (करीब 46,710 करोड़ रुपये) है। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र में फिलहाल पांच लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सरकार राजस्व व रोजगार सृजन के जरिये और लोगों की मदद करना चाहती है। हालांकि, दुकान, मॉल व खानपान के आउटलेट को रात में खोलना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा, 'जो लोग यह महसूस करते हैं कि रात में प्रतिष्ठान खोलकर वे और अच्छा कारोबार कर सकते हैं, उन्हें यह सुविधा प्रदान की गई है।'

प्रतिष्ठानों के रात में खुलने से कारोबार बढ़ने की उम्मीद। प्रतीकात्मक

आदित्य ने बताया, 'बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स और एनसीएपी के करीब नरीमन प्वाइंट पर खान-पान वाले वाहनों के लिए एक लेन खोली जाएगी। खानपान निरीक्षक इस पर नजर रखेंगे। अगर कोई ठोस कचरा निस्तारण, आवाज की सीमा या कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आजीवन प्रतिबंध भी लग सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पुलिस पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात 1:30 बजे के बाद भी उनकी ड्यूटी रहती है और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई दुकान खुली तो नहीं है। अब वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि महानगर में बड़ी संख्या में लोग रात की ड्यूटी करते हैं। पर्यटक देर रात तक घूमते हैं। कई बार उन्हें रात में दुकानें बंद होने के कारण भूखे रहना पड़ता है।

इन परेशानियों को देखते हुए 'मुंबई 24 घंटे' नीति लाई गई है। मॉल व मिल परिसरों की सुरक्षा के भी बंदोबस्त किए गए हैं। वैसे तो सभी मॉल व मिल परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन किसी को अगर अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है तो वह भुगतान करके सरकार से सुविधा ले सकता है।

भाजपा युवाओं के खिलाफ : नाइटलाइफ को लेकर भाजपा की टिप्पणी के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर आदित्य ने कहा, 'महाविकास अघाड़ी सरकार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। भाजपा युवाओं के खिलाफ है। देखा जा सकता है कि वह दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करती है।'

देर रात 1:30 बजे बंद हो जाएंगे पब व बार

आदित्य ने बताया कि नई नीति को अमल में लाते हुए आबकारी नीति को नहीं छेड़ा गया है। पहले की तरह महानगर के बार व पबों को अब भी देर रात 1:30 बजे बंद करना होगा।

महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या जाएंगे सीएम उद्धव

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- राउत ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे सहयोगी दल भी आएं साथ
- भाजपा ने मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को स्टंट कहा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी। भाजपा उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को स्टंट करार दे रही है।

राउत ने कहा है कि सरकार पूरे जोश से काम कर रही है। यह पांच वर्ष पूरे करेगी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे। श्रीराम के दर्शन कर आगे की दिशा तय करेंगे। राउत ने यह सूचना देने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार में अपने सहयोगी दलों कांग्रेस एवं राकांपा को भी आमंत्रित करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं हमारे सहयोगी दल भी साथ आएं। राहुल गांधी कई मंदिरों की यात्रा करते ही रहते हैं।

बता दें कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 24 नवंबर को ही अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन तब सरकार बनने की अनिश्चितता में उन्हें यह योजना स्थगित करनी पड़ी थी। अब वह सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे इससे पहले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जून 2019 में अपनी पार्टी के 18 सांसदों के साथ अयोध्या गए थे।

उद्धव ठाकरे फाइल

भाजपा की ओर से उद्धव की इस प्रस्तावित यात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है जबकि दिल्ली की भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी शिवसेना की चुटकी लेते हुए पूछा है कि क्या शिवसेना कांग्रेस के साथ अयोध्या जाएगी? भाजपा नेता ने प्रश्न किया है कि जिस कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा किया था, उस कांग्रेस को भी क्या आप अयोध्या ले जाएंगे? महाराष्ट्र की भाजपा नेता सायना एनसी ने भी शिवसेना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि शिवसेना की विचारधारा क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा है। उनके अनुसार ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र विनाश अघाड़ी है।

वैचारिक द्वंद्व के दौर से गुजर रही शिवसेना

पिछले वर्ष 28 नवंबर को अपने वैचारिक विरोधी दलों कांग्रेस एवं राकांपा के साथ सरकार बनाने के बाद से ही शिवसेना वैचारिक द्वंद्व के दौर से गुजर रही है। कभी सावरकर तो कभी नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर उसे कांग्रेस के सुर से सुर मिलाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि ऐसे में उद्धव अयोध्या में श्रीराम का दर्शन कर अपनी हिंदूवादी छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यूज गैलरी

कल हो सकता है झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार

रांची : झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार 24 जनवरी को हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार सुबह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय राजभवन से मांगा है। इस मुलाकात के क्रम में वह नए मंत्रियों के नाम राज्यपाल को सौंप सकते हैं। चर्चा है कि इसी दिन शाम में राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर भी बातें फाइनल हो चुकी हैं। इधर, मंत्री पद के बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। बताया जाता है कि कांग्रेस को मंत्रियों के तीन पद और मिल सकते हैं। इसके साथ कांग्रेस के पांच मंत्री हो जाएंगे। झामुमो के खाते में मंत्रियों के कुल पांच पद मिले हैं। राजद को एक पद पहले से ही दे दिया गया है। कांग्रेस कोटे से राजेन्द्र सिंह, दीपिका पांडेय तथा बन्ना गुप्ता को मंत्री बनाने की चर्चा है। झामुमो से स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, जगरनाथ महतो, दीपक बिरुआ तथा मथुरा महतो के नाम की चर्चा है। (राब्यू)

पीएमसी बैंक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली : पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों को उनके रुपये निकालने की अनुमति देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 21 अप्रैल तक टाल दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मंगलवार को हलफनामा दाखिल कर निकासी पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई को सही ठहराया था। उसने कहा था कि यह प्रतिबंध बैंक की स्थिति और उसके जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा भुगतान करने की क्षमता के आधार पर लगाया गया था, लेकिन यह जमाकर्ताओं के प्रति बैंक के दायित्व को समाप्त नहीं करता है। (जासं)

भोपाल मेमोरियल अस्पताल के 12 डॉक्टरों का इस्तीफा

भोपाल : भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) के 12 डॉक्टरों ने बुधवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज थे। डॉक्टरों ने बीएमएचआरसी की डायरेक्टर डॉ. प्रभा देशिकन को इस्तीफा सौंपा है। हालांकि, ये डॉक्टर अगले एक माह तक सेवाएं देते रहेंगे। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि एक महीने के भीतर उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया तो वे सेवाएं देना बंद कर देंगे। दरअसल, बीएमएचआरसी में इन दिनों प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर भर्तियां चल रही हैं। (नईदुनिया)

ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन एचसीएफसी-141बी का इस्तेमाल बंद

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन (एचसीएफसी)-141बी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। फोम निर्माता कंपनियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था और ओजोन की परत को कमजोर करने वाला रसायन है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपर बहुत कम मात्रा में ओजोन मौजूद है। यह धरती को सूर्य के अल्ट्रावायलट विकिरणों से बचाती है। मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है, 'एचसीएफसी-141बी का देश में उत्पादन नहीं होता था और आयात से घरेलू जरूरतें पूरी की जाती थीं। 31 दिसंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के साथ ही एक जनवरी से एचसीएफसी-141बी का आयात प्रतिबंधित हो गया है। देश ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन को पूरी तरह बाहर कर दिया है।' इसी प्रकार फोम निर्माता उद्योग द्वारा एचसीएफसी-141बी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। यह कदम ओजोन समाप्त करने वाले पदार्थ (नियमन एवं नियंत्रण) संशोधन नियम 2014 के तहत उठाया गया है। एचसीएफसी-141बी का इस्तेमाल मुख्य रूप से पोलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में किया जाता था।

गुजरात में भाजपा विधायक केतन ईनामदार का इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▶ रूपाणी सरकार और अफसरों से नाराज थे विधायक केतन

भाजपा सांसदों के बाद अब विधायक भी गुजरात की रूपाणी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा विधायक केतन ईनामदार ने जनता के काम नहीं होने व उपेक्षा से तंग आकर विधायक पद से ही इस्तीफा सौंप दिया। प्रदेश की राजनीति में इसे मुख्यमंत्री रुपाणी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा मिलने से इन्कार किया है।

वडोदरा जिले की सावली विधानसभा से चुने गए विधायक केतन ईनामदार ने विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को भेजे गए अपने इस्तीफे में कहा हैकि सरकार व प्रशासन में संकलन का अभाव है। मंत्री व अधिकारी उनके क्षेत्र के विकास व जनता के कार्यों को लेकर उदासीन हैं। उनकी सिफारिश के बावजूद उनकी व उनके कामों की उपेक्षा की जाती रही है। ईनामदार ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनका सम्मान नहीं रखा जाता है। विधायक के इस्तीफे से एक बार पिफर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा कि भाजपा सरकार में विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं। मंत्री व अधिकारी विधायकों की नहीं सुनते, सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है। सरकार के सेवा सदन अब मेवा सदन बन गए हैं, जहां पैसों के बिना काम नहीं होते।

गौरतलब है सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, भर्ती प्रकिया में अनियमितता, सांसदों व विधायकों की सिफारिश के बावजूद जनता के काम नहीं होने की बात को लेकर पहले सांसद व अब विधायक भी सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न उठाने लगे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने जहां केतन ईनामदार का इस्तीफा नहीं मिलने की बात कही वहीं भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी व प्रवक्ता भरतभाई पंड्या ने मीडिया के माध्यम से इस्तीफे जानकारी मिलने की बात कही है। पंड्या ने कहा कि सरकार व प्रशासन में कौन अधिकारी उनके कामोंकी उपेक्षा कर रहे हैं इसकी जानकारी ली जाएगी।

बंगाल में बैलेट पेपर से होगा नगर निकाय चुनाव

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में नगर निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को इस बाबत जानकारी दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि 10 फरवरी के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है।

तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर बैलेट पेपर के इस्तेमाल की हिमायती रही हैं। बीते साल 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली में उन्होंने घोषणा की थी कि बंगाल में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव अब ईवीएम से नहीं, बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। अब चंद महीने में राज्य में विभिन्न 110 नगर निकायों के चुनाव होने हैं, जिसमें बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सचिवालय नवान्न सूत्रों के अनुसार इस बाबत राज्य चुनाव आयोग को सरकारी की ओर से इत्तला किया जा चुका है।

10 फरवरी के बाद नगर विकास मंत्रालय की ओर से चुनाव तारीखों की जानकारी साझा की जाएगी। इस बीच, चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकार के समक्ष बैलेट पेपर वापस नहीं लाने को लेकर कई दलील दी जा रही हैं।

आजम खां की मुश्किलें बढ़ीं जौहर विवि की दो इमारतें कुर्क

जागरण संवाददाता, रामपुर

- अनुसूचित जाति के लोगों से खरीदी 104 बीघा जमीन भी प्रशासन ने कब्जे में ली
- इमारतों के निर्माण में सेस का भुगतान नहीं किया गया

सांसद आजम खां की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन ने बुधवार को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की दो इमारतों को कुर्क कर लिया। दोनों इमारतों में 50-50 क्लास रूम बने हैं। इसके अलावा डीएम की इजाजत लिए बिना अनुसूचित जाति के लोगों से खरीदी 104 बीघा जमीन भी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। एसडीएम ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय में इन भवनों के निर्माण में सेस का भुगतान नहीं किया गया। इस पर श्रम विभाग की ओर से एक करोड़ 37 लाख रुपये की आरसी जारी की गई। इसका भुगतान न किए जाने पर प्रशासन ने सील कर दिया।

एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद-प्रयागराज ने 10 मुकदमों में आजम के खिलाफ फैसला सुनाया था। आरोप है कि आजम ने सपा शासनकाल में मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए अनुसूचित जाति के 10 लोगों से बिना डीएम की अनुमति के जमीन खरीदी। यह जमीन जौहर विवि में शामिल है। नियमानुसार जिलाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी था। राजस्व परिषद ने फैसला सुनाया था कि जमीन की खरीदारी में नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए जमीन सरकारी घोषित की जाए। राजस्व परिषद का आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने कार्रवाई के लिए उप जिलाधिकारी सदर को भेज दिया। एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी बुधवार को राजस्वकर्मियों व पुलिस के साथ जौहर विवि पहुंचे और 104 बीघा जमीन की पैमाइश कराई। एसडीएम ने बताया कि जमीन पर सरकारी कब्जा कर लिया गया है।

आजम खां फाइल

प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर कार्रवाई के संकेत

राज्य ब्यूरो, पटना

▶ पार्टी की बैठक में कार्रवाई की सिफारिश करेंगे जदयू प्रदेश अध्यक्ष

पार्टी के फैसले की सार्वजनिक आलोचना करने वाले दो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के खिलाफ जदयू ने कार्रवाई का संकेत दिया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बुधवार को पटना में कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय महासचिव पवन कुमार वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश वह पार्टी की बैठक में करेंगे। मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से बातचीत भी करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि अगली बैठक कब होगी। सिंह ने कहा कि इन दोनों के बयान से पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों ने कहीं जाने का मन बना लिया है तो वे स्वतंत्र हैं।

मालूम हो कि प्रशांत किशोर लगातार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। जबकि जदयू ने संसद के दोनों सदनों में इसके पक्ष में मतदान किया था। पवन वर्मा की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जदयू ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा के साथ सीटों का तालमेल क्यों किया। इस सवाल पर वर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है। कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पवन वर्मा का पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। पार्टी के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। इसके बावजूद उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। आज वह जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह कहीं से उचित नहीं है। आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसी हालत में करता है, जब उसकी बातचीत किसी दूसरे दल से चल रही हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि नया कानून किसी को नागरिकता से वंचित करने के इरादे से नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एनआरसी के बारे में भी केंद्र सरकार की ओर से संतोषप्रद स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। इसके बाद भी इन विषयों को मुद्दा बनाने का कोई तुक नजर नहीं आता है। सिंह ने इशारे में कहा कि पीके और वर्मा कांग्रेस या किसी अन्य दल के संपर्क में हैं।

विवाद के बाद एमपी पीएससी ने उप परीक्षा नियंत्रक को हटाया

नईदुनिया, इंदौर : मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने उप-परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुशांत पुणेकर को हटा दिया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भील जाति को लेकर पूछे गए आपत्तिजनक सवाल से पैदा हुए विवाद के बाद पीएससी में हुआ यह पहला बड़ा बदलाव है।

अधिकारी को हटाने के तरीके पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हटाए गए अधिकारी की पदस्थापना सैट यानी राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ में थी, लेकिन राज्य सेवा परीक्षा के मामले को लेकर उन्हें हटाया गया। इससे अधिकारी से नियम विरुद्ध काम लेने के मामले में भी एमपी पीएससी संदेह के घेरे में आ गया है। एमपी पीएससी ने तीन दिन पहले डॉ. पुणेकर को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि परीक्षा होने के बाद उनके लिए कोई कार्य नहीं बचा, लिहाजा उन्हें रिलीव किया जाता है। डॉ. पुणेकर को मूल विभाग भेज तो दिया गया, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने भी फिलहाल उन्हें कहीं नियुक्ति नहीं दी है। मामले में डॉ. पुणेकर का कहना है कि विभाग से नई पदस्थापना के आदेश का इंतजार कर रहा हूं।

रेल इंजनों से उत्सर्जन के लिए दिशानिर्देशों पर रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से जानना चाहा कि रेल इंजनों से उत्सर्जन के मानकों के दिशानिर्देश संबंधित उसके आदेश का कितना अनुपालन हुआ है।

एनजीटी के प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीपीसीबी से एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने रेलवे द्वारा संचालित लोकोमोटिव इंजनों से होने वाले प्रदूषण पर विचार करते हुए लोकोमोटिव मानकों को शामिल करते हुए दिशानिर्देश बनाने और उसे सीपीसीबी की वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। पीठ ने पर्यावरण व वन मंत्रालय, सीपीसीबी समेत सभी हितधारकों को दिशानिर्देशों का अध्ययन करने के बाद लोकोमोटिव इंजनों के लिए अंतिम मानकों की मंजूरी के लिए प्रयास तेज करने और उसे अधिसूचित करने के लिए भी कहा है।

पीठ ने उपरोक्त दिशानिर्देशों पर सीपीसीबी से ई-मेल के जरिए एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी देने को कहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर पीठ ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि रेलवे के डीजल इंजनों से हानिकारक उत्सर्जन हो रहा है। ट्रिब्यूनल ने साल 2017 में लोकोमोटिव मानकों को शामिल करते हुए दिशानिर्देश बनाने और उसे सीपीसीबी की वेबसाइट पर डालने और सभी हितधारकों को लोकोमोटिव इंजनों के लिए आखिरी मापदंडों को मंजूरी देने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

'भारतीय रेलवे के डीजल इंजनों के निकास उत्सर्जन मानक' शीर्षक से सीपीसीबी ने अंतरिम रिपोर्ट पेश की है, जिसका उद्देश्य इस सेक्टर के लिए मानकों और प्रोटोकाल को ठीक करना है। ताकि, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत भारत द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। वैश्विक स्तर पर परिवहन के साधनों से होने वाले प्रदूषण में रेलवे सेक्टर का हिस्सा 3.5 फीसद है।

एनजीटी ने सीपीसीबी से एक महीने के भीतर मांगी रिपोर्ट

पैरों पर गिर गुहार लगाती रही महिला, मप्र के मंत्री बोले-नाटक बंद करो

नईदुनिया, रीवा : रीवा दौरे पर आए मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल विवादों में घिर गए हैं। बुधवार को नगर निगम की एक संविदा कर्मी महिला उनके पास अपनी फरियाद लेकर आई थी। वह मंत्री पटेल के पैरों पर गिरकर अपनी गुहार लगाने लगी, लेकिन महिला की बात को अनसुना करते हुए मंत्री ने बेरुखी से कहा, 'नाटक बंद करो।' घटना तब हुई जब मंत्री पटेल पत्रकार वार्ता को संबोधित करने रीवा के एक होटल में पहुंचे थे। नगर निगम की संविदा कर्मी मुन्नी पटेल का कहना था कि उसे एक माह से वेतन नहीं मिला है। जब मंत्री ने झिड़क दिया तो महिला की आंखों से आंसू बह निकले। इस पर मंत्री ने कहा, 'रोना-गाना बंद करें। नाटक-नौटंकी यहां नहीं चलने वाली है। अभी मैं पत्रकार वार्ता करने आया हूं। बाद में बात करूंगा।' महिला के पक्ष में निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने मंत्री से बात करनी चाही तो वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि, मंत्री पटेल ने महिला को आवेदन पत्र देने की बात कही। इसके बाद मामला शांत हो सका। मंत्री पटेल ने पार्षद नम्रता सिंह पर पूरी घटना को प्लान करने का आरोप लगाया है।

रखी बात

गुजरात के राज्यपाल बोले, गो आधारित प्राकृतिक खेती ही बचाव का बेहतर उपाय, उर्वरक पोषित फसलों से 30 फीसद तक बढ़े कैंसर रोगी

रासायनिक खेती की फसलें दे रहीं कैंसर : आचार्य देवव्रत

जागरण संवाददाता, कानपुर

दो लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का पाठ पढ़ाने वाले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती की फसलें लोगों को बीमार कर रही हैं। पीजीआइ चंडीगढ़ और देश के बड़े अस्पतालों की रिपोर्ट बताती हैं कि इसकी वजह से कुछ वर्षों में 25 से 30 फीसद कैंसर रोगी बढ़े हैं। प्राकृतिक खेती ही बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय है। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गाय आधारित प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक रासायनिक खेती करने के दौरान इसके दुष्परिणाम जाने। इसके बाद पद्मश्री सुभाष पालेकर की प्राकृतिक खेती अपनाई। इससे उत्पादन बढ़ा और फसलें भी स्वास्थ्यवर्द्धक हुईं। गाय आधारित खेती से हम बंजर जमीन को फिर उपजाऊ बना सकते हैं। एक देसी गाय के गोबर-गोमूत्र से 30 एकड़ जमीन के लिए 'बीजामृत', 'जीवामृत' और 'घन जीवामृत' मिलते हैं। जैविक खेती में तीन साल कम उत्पादन मिलता है, लेकिन प्राकृतिक खेती से पहले ही वर्ष फसलें लहलहाने लगती हैं। एक एकड़ में 32 क्विंटल उत्पादन किया जा सकता है वह भी महज 250 रुपये के खर्च पर। उन्होंने बताया कि गुजरात में आठ से दस हजार किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2022 तक गुजरात के सौ फीसद किसान यह खेती करेंगे।

गंगा तीरे प्राकृतिक खेती योजना : केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब-हरियाणा ने धान व गेहूं की खूब पैदावार होती है। वह अपना अनाज बेचते हैं लेकिन खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमे विचार करना होगा कि अनाज तो हो पर रसायन मुक्त। गंगा किनारे पांच किमी तक प्राकृतिक खेती की योजना तैयार की गई है।

कानपुर के चंद्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि गोष्ठी को संबोधित करते गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। जागरण

गौ आधारित कृषि प्रशिक्षण

कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और जमीन अधिक उपजाऊ बनाने के लिए प्रदेश सरकार अब गौ आधारित खेती को बढ़ावा दे रही है। प्रत्येक किसान को मास्टर ट्रेनर के जरिए इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। 27 से 31 जनवरी के बीच निकलने वाली गंगायात्रा से इसकी शुरुआत की जाएगी। यह यात्रा कानपुर की 1038 ग्राम पंचायतों से गुजरेगी। इस दौरान किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती व जीवामृत बनाने व उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गंगायात्रा का समापन कानपुर में होगा।

अश्लील मैसेज भेजने पर इंदौर के उपायुक्त निलंबित

राज्य ब्यूरो, भोपाल

▶ पीड़िता ने मप्र के मंत्री गोविंद सिंह को दिखाए थे मैसेज

मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग ने अधीनस्थ महिला अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने पर इंदौर में पदस्थ उपायुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजेश क्षत्री को निलंबित कर दिया है। यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला अधिकारी प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के पास पहुंची थी। महिला ने मंत्री डॉ. सिंह को क्षत्री द्वारा उन्हें भेजे गए मैसेज दिखाए तो मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दे दिए।

आरोपित क्षत्री लंबे समय से अपने अधीनस्थ महिला अफसर को परेशान कर रहा था। उसे वॉट्सएप पर अश्लील मैसेज भेज रहा था। महिला ने इसकी शिकायत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मामलों की रोकथाम और सुनवाई के लिए विभागीय स्तर पर गठित समिति से की, लेकिन समिति कुछ नहीं कर पाई, तो पीड़ित महिला संबंधित अफसर के खिलाफ एसएसपी इंदौर के पास गई। वहां से भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़िता वॉट्सएप मैसेज के प्रिंट आउट लेकर बुधवार सुबह मंत्री डॉ. सिंह के भोपाल स्थित बंगले पर पहुंच गई। पीड़िता ने मंत्री को आरोपित अफसर द्वारा भेजे गए मैसेज दिखाए और आपबीती सुनाई। मैसेज देखने के बाद मंत्री ने सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अफसरों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

विभाग के अफसरों ने पीड़िता के मोबाइल में भेजे गए मैसेज देखने के बाद प्रथम दृष्टया उपायुक्त क्षत्री को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है।

261 प्रदर्शन नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भारत भर में हुए हैं। इनमें से 230 प्रदर्शन सीएए के विरोध में हुए, जबकि कानून के समर्थन में 31 प्रदर्शन हुए हैं।

लोकतंत्र सूचकांक में 10 पायदान नीचे खिसका भारत

नई दिल्ली, आइएएनएस : इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) के 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 पायदान नीचे खिसककर 51वें स्थान पर पहुंच गया है।

ईआइयू की ओर से बुधवार को जारी इस वैश्विक रैंकिंग के मुताबिक भारत का कुल स्कोर (0-10 के पैमाने पर) 2018 के 7.23 के मुकाबले 2019 में 6.90 रह गया है। जबकि वैश्विक औसत स्कोर 2018 के 5.48 के मुकाबले घटकर 5.44 रह गया है। ईआइयू ने इसे 2006 में लोकतंत्र सूचकांक शुरू होने के बाद का सबसे खराब स्कोर करार दिया है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर गिरने का कारण जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के मद्देनजर वहां बड़ी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती, स्थानीय नेताओं की नजरबंदी, असम में एनआरसी लागू होने से बड़ी मुस्लिम आबादी का उससे बाहर होना, नागरिकता संशोधन कानून से बड़ी मुस्लिम आबादी की नाराजगी, जेएनयू में छात्रों के आंदोलन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई और शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को बताया गया है। सूचकांक में चीन 2.26 के स्कोर के साथ 153वें और हांगकांग तीन पायदान गिरकर सिंगापुर के साथ 75वें स्थान पर है। चीन और हांगकांग की स्थिति का कारण क्रमशः झिंगजियांग प्रांत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को बताया गया है।

चरमपंथियों के हमले से सहमे एक और सिख नेता ने छोड़ा पाकिस्तान

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दिनोंदिन और खराब होती जा रही है। मुस्लिम चरमपंथियों की धमकी और हमले से सहमे एक और सिख नेता अपने परिवार के साथ पकिस्तान से पलायन के लिए मजबूर हो गए। सिख नेता राधेश सिंह टोनी पर कुछ सप्ताह पहले हथियारबंद चरमपंथियों ने हमला कर दिया था। इसके बाद उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके पेशावर से लाहौर भागना पड़ा। पाकिस्तान छोड़ने के बाद वह अपने परिवार के साथ भारत में पनाह ले सकते हैं।

इस्लामाबाद के सूत्रों के अनुसार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सिख नेता राधेश सिंह टोनी खैबर पख्तूनख्वा से पलायन कर चुके हैं। वह मुस्लिम चरमपंथियों के निशाने पर थे और उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी थीं। राधेश पाकिस्तान की खराब होती कानून-व्यवस्था के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) सरकार की आलोचना करते रहे हैं। गुरु नानक के जन्मस्थान पवित्र गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले के बाद से अल्पसंख्यक सिख समुदाय को चरमपंथियों ने निशाने पर ले लिया है। ननकाना साहिब पर हमले के बाद सिख समुदाय के एक युवक की हत्या भी हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर निवासी राधेश सिंह टोनी वहां अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज माने जाते थे। वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। स्थानीय चुनाव में उन्होंने अल्पसंख्यक सीट से किस्मत आजमाई और भारी बहुमत से जीते थे। बाद में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

उल्लेखनीय है इससे पहले भी कई सिख नेता पाकिस्तान से पलायन करके भारत समेत दुनिया के कई देशों में पनाह ले चुके हैं। पिछले ही साल पीएम खान की पार्टी पीटीआइ के नेता व पूर्व विधायक बलदेव सिंह परिवार समेत भारत आ गए थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए पाकिस्तान सरकार पर हमला बोला था।

राधेश की टिप्पणी पर हिना रब्बानी खार घेर चुकी हैं इमरान खान को : सिख नेता राधेश की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-क्यू) की नेता व पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार हाल ही में प्रधानमंत्री इमरान खान को घेर चुकी हैं।

सीएए आने से 'कई लोगों' के सपने टूट गए : तारिक

साक्षात्कार

पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक व मशहूर विचारक **तारिक फतह** की टिप्पणियां पाकिस्तान की नींद उड़ा देती हैं। अयोध्या के डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित एक संगोष्ठी में शामिल होने आए तारिक से **नवनीत श्रीवास्तव** ने सीएए के साथ ही तमाम विषयों पर बात की। प्रस्तुत हैं वार्ता के प्रमुख अंश–

पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह की फाइल फोटो। जागरण

● सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की क्या वजह है?

- ये सारा सिलसिला बंगाल का है। वहां नॉन बंगाली-बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम काफी संख्या में हैं। ये लोग वर्षों से प. बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने का सपना पाले हुए हैं। जब सीएए आया तो इन्हीं लोगों का सपना टूटा और इन्होंने ही विरोध शुरू किया। इसे ऐसे भी समझिए कि बंगाल में 1971 के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू आए। वे 20-30 साल से वहां रह रहे हैं, लेकिन नागरिक नहीं हैं। जब सीएए से यह तय हो गया कि 2015 से पहले आए हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी तो इन्हीं नॉन बंगाली-बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिमों ने इसका विरोध शुरू किया। इन्हीं नॉन बंगाली-बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिमों को ये लगा कि यदि बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता मिली तो उनका अपना वोट बैंक कम पड़ जाएगा और बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य राज्य बनाने का सपना भी टूट जाएगा। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है।

● आंदोलन तो दिल्ली और लखनऊ तक में हो रहे हैं?

- सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही और ये बात खुद मुस्लिम भी जानते हैं पर वर्षों से बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य राज्य बनाने जो सपना था वो सीएए से टूट गया है। इसीलिए इसका विरोध जामिया से शुरू हुआ, जो खुद धर्म के नाम पर बना विश्वविद्यालय है।

● पर अब तो महिलाओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली है?

- मुस्लिम औरतों को ज्यादती सहन करनी पड़ती है। उन्हें रटे रटाए नारे के साथ आंदोलन में उतारा गया।

● पर ये भ्रम दूर कैसे होगा?

- ये खुद ब खुद आंदोलन खत्म करने को मजबूर होंगे। एक मुस्लिम होने के नाते मुझे दुख ये है कि ये लोग अपनी जिद के चक्कर में अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। लोगों में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। ये नफरत किसी हिंदू के कहने से नहीं बढ़ रही, बल्कि इनकी खुद की करनी से बढ़ रही है।

● रामजन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं?

- मैं मानता हूं कि ये ऊपर वाले का फैसला है और सबक भी कि आईंदा किसी मंदिर या गिरिजाघर को तोड़कर मस्जिद बनाने की जुर्रत न हो। आवश्यकता इस बात मुस्लिम भी ये मानें कि उनके पूर्वजों ने गुनाह किए थे।

● आपको इमरान खान से पाकिस्तान की बेहतरी की कुछ उम्मीद है?

- नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ आता-जाता ही नहीं।

● देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसी उम्मीद है?

जवाबः सबके लिए एक कानून यानी कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में कदम अवश्य उठाएंगे।

सिंहदेव बोले– सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी छग सरकार

नईदुनिया, रायपुरः छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जल्द छत्तीसगढ़ सरकार एक प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव लाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सिंहदेव ने यह बातें केरल और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन विचार किया जा रहा है। सीएए को लेकर मंत्री सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही सिंहदेव पहले भी एनआरसी और सीएए का विरोध कर चुके हैं। चर्चा है कि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। इसके लिए केरल और पंजाब विस में पारित प्रस्ताव का भी अध्ययन किया जाएगा।

उपद्रवियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगी पीढ़ियां : योगी

सीएए का समर्थन ▶ देशप्रेम ही सबसे बड़ा पुण्य और राष्ट्रविरोध ही पाप

जागरण संवाददाता, कानपुर

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएए के विरोध में तोड़फोड़ करने वालों को सख्त तेवर दिखाए। कहा कि इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। बुधवार को कानपुर मे सीएए के समर्थन में हुई जनसभा में योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में गरीब कल्याण और देश का ढांचा दुरुस्त किया। दूसरे कार्यकाल में वह सीएए जैसे बड़े फैसले ले रहे हैं। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता का रास्ता बन गया है। देश विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस इसका समर्थन कर अपने पाप धो सकती थी, लेकिन कांग्रेस व वामपंथी देश के दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने महर्षि अरविंद के हवाले से राष्ट्रप्रेम को पुण्य और राष्ट्रविरोध को पाप बताते हुए कहा कि देश विभाजन के समय वंचितों के बड़े नेता डॉ.आंबेडकर ने सारे लालच ठुकरा कर भारत का रास्ता चुना और दूसरे नेता जोगिंदर सिंह मंडल पाकिस्तान जाकर वहां कानून मंत्री बने। मंडल तो तीन साल बाद भागकर भारत आए और यहां गुमनाम मौत मरे, जबकि डॉ.आंबेडकर भारत रत्न बने और पूजे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में किदवईनगर के कामर्शियल ग्राउंड में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान आपस में बात करते केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

सीएए से एनआरसी और एनपीआर का लेना देना नहीं : केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सीएए से एनआरसी और एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है। 1986 में तो राजीव गांधी ने ही असम में एनआरसी का वादा किया था। आगे कहा, सीएए का विरोध करने वाले वामपंथी तिरोहित, कांग्रेस अप्रासंगिक, तथाकथित बुद्धिजीवियों को सरकार से मिलने वाली रोटी बंद हो चुकी है।

'एनपीआर न भरने की गलती न करें अखिलेश': उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि एनपीआर नहीं भरेंगे, लेकिन वह ऐसी गलती हरगिज न करें क्योंकि उनके चचा आजम खां के बेटे ने कागजात में ऐसी ही गलती की थी और उनकी विधायकी चली गई।

एनआरसी आ भी जाए तो आपत्ति क्या है : राजनाथ

रवि प्रकाश तिवारी, मेरठ : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के पक्ष में रैली करने बुधवार को मेरठ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) की चर्चा छेड़ गए। जनता की ओर सवाल उछालते हुए पूछा, एनआरसी अगर आ भी जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? जनता ने भी उसी गर्मजोशी से उनका समर्थन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हालांकि अभी एनआरसी की कहीं कोई चर्चा नहीं है, फिर भी विपक्ष बेवजह यह कहकर माहौल खराब कर रहा है कि मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा। ऐसे लोगों को सरकार का संदेश है कि जो भी मुसलमान देश का नागरिक है, उसे कोई छू नहीं सकता। कोई माई का लाल आंख उठाकर उनकी ओर देख नहीं सकता। उन्होंने एनपीआर के बारे में कहा कि 2010 में कांग्रेस ही इसे लेकर आई, अब हम इस पर काम कर रहे हैं तो वे विरोध कर रहे हैं। सीएए की बात करते हुए राजनाथ बोले कि पड़ोसी देशों में अपमान की जिंदगी जी रहे जो शरणार्थी भारत आए हैं उनमें अधिकांश दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं। ऐसे लोगों को नागरिकता देना भारत का धर्म है।

'धर्मनिरपेक्ष' थे जिन्ना, नहीं चाहते थे विभाजन : बोस

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष ने फिर पार्टी लाइन से इतर दिया बयान

▶ कहा–कांग्रेस के सांप्रदायिक नेताओं के कारण हुआ देश का विभाजन

बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने फिर पार्टी लाइन से इतर बयान दिया है। इस बार उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया है। बोस ने बुधवार को दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक 'सेक्युलर' नेता थे, क्योंकि वह कभी भी विभाजन नहीं चाहते थे। कांग्रेस के सांप्रदायिक नेताओं के कारण भारत विभाजित हुआ। जिन्ना 1935 में कोलकाता के दरभंगा हॉल में आए थे। उस दौरान उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले बोस ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर कहा था कि किसी कानून को डर पैदा कर लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि भाजपा इस कानून के समर्थन में राज्य ही नहीं देशभर में जागरूकता अभियान चला रही है। इसी बीच पार्टी के इस प्रदेश उपाध्यक्ष ने उक्त बयान दिया है। उन्होंने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा, 'जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे और वह कभी भी विभाजन नहीं चाहते थे।

उन्हें कांग्रेस द्वारा मजबूर और विमुख कर दिया गया था। उन्होंने महसूस किया कि वह भारत में सत्ता साझा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ 1940 में बाध्य होकर लाहौर सम्मेलन में पाकिस्तान मुद्दे को उठाया था। उससे पहले वह पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे। बोस ने कहा 'कांग्रेस शासन के दौरान सांप्रदायिक नेताओं के कारण भारत विभाजित हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहां तक कि महात्मा गांधी भी, जिन्होंने विभाजन को अनिच्छा से स्वीकार किया।

1955 तक पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। दुर्भाग्य से जिन्ना का निधन हो गया और इसके बाद पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहा और यही भारत की आत्मा है।' बोस ने कहा, भारत दुनिया के एक मात्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चंद्र कुमार बोस ने यहां तक कहा कि जिन्ना को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं होता तो आज कश्मीर और जिहादी जैसी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती।

पाकिस्तान बनने से ही आज देश को कई गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। इस तरह के बयान भाजपा के आदर्शों के विपरीत होने के सवाल पर बोस ने कहा कि इतिहास को नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये विचार उनके व्यक्तिगत हैं। इसे पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

भाजपा की प्राथमिकता में विकास नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना है : थरूर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद शशि थरूर ने बुधवार को कोलकाता में कहा कि विकास का कोई एजेंडा नहीं होने के चलते भाजपा अब एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। उन्होंने कोलकाता साहित्य सम्मेलन में दावा किया कि असली 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' सत्ताधारी पार्टी है, जो देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांट रही है। थरूर ने दावा किया, सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने एजेंडे को पूरी तरह लागू कर रही है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार के पास विकास की मानसिकता ही नहीं है। उन्होंने कहा, असली टुकड़े-टुकड़े गैंग सत्ताधारी पार्टी है, जो देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांट रही है। बांटों और राज करो की तर्ज पर पार्टी हमें उसी तरह बांट रही है, जैसा कि ब्रिटिश राज में किया गया। 'टुकड़े- टुकड़े गैंग' इस शब्दावली

शशि थरूर। फाइल

का इस्तेमाल अक्सर दक्षिणपंथी दल की तरफ से विपक्ष पर हमला करने के लिए किया जाता है, खासतौर से वाममपंथी दलों और समर्थित संगठनों के लिए। उन्होंने कहा, क्या राष्ट्रीयता का आधार धर्म होना चाहिए? महात्मा गांधी ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत की बात की, पाकिस्तान की तरह नहीं जो इस्लामिक देश बन गया। थरूर ने कहा, हमारा संविधान सभी के लिए गरिमा और सम्मान को दर्शाता है। संविधान इसे दर्शाता है और साथ ही उसने धर्म आधारित नागरिकता के विचार को अनिवार्य रूप से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार नागरिकता तय करने के लिए धर्म को आधार माना जा रहा है और एक धर्म, इस्लाम को इससे बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, हम भारत के नागरिक हैं, यह साबित करने की जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हमेशा स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का जिक्र करते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया गया था, लेकिन भाजपा ने इसे छह धर्मों और तीन देशों तक सीमित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने तुगलकी अंदाज में नोटबंदी लागू की और अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में भारी बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है।

मप्र में थप्पड़ कांड के बाद दिग्गज भाजपा नेताओं की ललकार

नईदुनिया, राजगढ़

मध्य प्रदेश के ब्यावरा में राजगढ़ कलेक्टर द्वारा भाजपा कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के विरोध में बुधवार को राज्य के चार दिग्गज पार्टी नेताओं ने ब्यावरा में आयोजित सभा के मंच पर आकर कमलनाथ सरकार को ललकारा। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीधी चेतावनी देते हुए कह कि प्रदेश में ऐसा ही चलता रहा तो राज्य के मंत्रियों को सड़कों पर घूमने नहीं देंगे। उनका विरोध किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, विस में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव व पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ सरकार व अधिकारियों को चेताया।

जेएनयू के वायरस राजगढ़ में आ गए–विजयवर्गीयः भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सभा में राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता पर तंज करते हुए कहा, 'मुझे पता लगा है कि जेएनयू के वायरस राजगढ़ में भी आ गए हैं। कलेक्टर महोदया जेएनयू में पढ़ी हैं। उसी वायरस के कारण यह सब हुआ है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से वायरस को खत्म करेंगे।'

ब्यावरा में बुधवार को भाजपा की सभा में जनता का अभिवादन करते महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। मंचासीन हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपाध्यक्ष राकेश सिंह और विस में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव। नईदुनिया

...तो घर में चौका-चूल्हा कर रहीं होतीं–भार्गवः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने राजगढ़ की कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'जिस संविधान के तहत कलेक्टर-डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति हुई है, उसे सभी को मानना चाहिए। संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। यदि संविधान नहीं होता तो ये घर में चूल्हा-चौका कर रहीं होती।'

थप्पड़ आखरी कील–राकेश सिंहः प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, 'भाजपा तब नहीं डरी, जब उसके दो सांसद थे। अब 16 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। रवि बड़ोने (कलेक्टर के थप्पड़ के शिकार) यह थप्पड़ आपके गाल पर नहीं पड़ा है, बल्कि ऐसा करके कांग्रेस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है।'

अहंकार को माटी में मिला देंगे– शिवराजसिंहः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने कहा, 'सरकारें आती हैं, जाती हैं। संविधान सदैव रहने वाला है। आप एक प्रक्रिया के तहत काम करो, नहीं तो अहंकार पीसकर माटी में मिला दिया जाएगा। मैं भी 10 चुनाव जीता हूं। ऐसा कलेक्टर कभी नहीं देखा।'

अशोभनीय शब्दों का प्रयोग

पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने कलेक्टर को लेकर अशोभनीय व आपत्तिजनक शब्द कहे। साथ ही बार-बार यह भी कहा कि इन शब्दों को आप गलत तरीके से मत लेना।

मप्र हाई कोर्ट ने राजगढ़ कलेक्टर से मांगा जवाब

राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता द्वारा एक भाजपा कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का मामला मप्र हाई कोर्ट पहुंच गया। एक जनहित याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन और कलेक्टर से विस्तृत जवाब मांगा है। हालांकि, तत्काल एफआइआर दर्ज करने की मांग की खारिज कर दी।

अखिलेश व मायावती ने स्वीकारी सीएए पर बहस की चुनौती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सीएए के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई बहस की चुनौती को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वीकार कर लिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग जगह और मंच तय कर लें हम विकास के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। भाजपा के लोग बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते हैं। सपा अध्यक्ष ने अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनेताओं की भाषा संयमित होनी चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भी बुधवार को ट्वीट किया, सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर बहुजन समाज पार्टी बहस करने की चुनौती को किसी भी मंच पर और कहीं भी स्वीकार करने को तैयार है।

मंगलवार को लखनऊ में सीएए के समर्थन में आयोजित रैली में अमित शाह ने कहा था, 'मैं सबके सामने कहने आया हूं। ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश या कोई विपक्ष का नेता, चर्चा करने के लिए मंच ढूंढ़ लो, हमारा दल चर्चा के लिए तैयार खड़ा है।'

जागरूक जनता सब समझती है : प्रियंका

राब्यू, लखनऊ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती पर कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा के अलावा बिना नाम लिए सपा बसपा पर निशाना साधा। बुधवार को उन्होंने ट्वीट किया, 'अजीब दास्तां है ये..कहां शुरू कहां खत्म.. गृह मंत्री जी उप्र में उन्हें चुनौती दे रहे हैं जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए घर से बाहर तक नहीं निकले और जिन्हें गृह मंत्री जी को चुनौती देनी चाहिए वे दूसरे प्रदेशों की समस्याओं की बातें कर रही हैं। उप्र की जागरूक जनता सब समझती है।'

अमित शाह पहले सीएए की धाराओं पर दें स्पष्टीकरण : ममता बनर्जी

जागरण संवाददाता, दार्जिलिंग

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) की धाराओं पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ ममता ने बुधवार को चार किलोमीटर पैदल यात्रा कर जुलूस को नेतृत्व किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा।

जुलूस के बाद रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार केवल गैर-भाजपा शासित राज्यों में सीएए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के भय से बंगाल को छोड़कर सभी राज्य नई दिल्ली में एनपीआर को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए थे।

असम में एनआरसी से लाखों हुए बेघर

ममता ने कहा,'असम में एनआरसी के कारण लाखों गोरखा बेघर हो गए। हम दार्जिलिंग में ऐसा होने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि मैं यहां हूं।' उन्होंने कहा कि इस कानून से एक भी गोरखा प्रभावित नहीं होगा। गोरखा अगर एक हो जाए, तो देश का कानून कुछ नहीं कर सकता है। देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। गोरखा देश के नागरिक हैं। उनकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है।

ममता बनर्जी। फाइल

ममता ने की सीएए के विरोध में चार किलोमीटर लंबी पदयात्राः सीएए के खिलाफ ममता की चार किलोमीटर लंबी पदयात्रा रार्बट्सन रोड से शुरू होकर गांधी रोड, डी बी गिरि रोड, एनएच 55 होते हुए दार्जिलिंग मोटर स्टैंड में खत्म हुई। यहां सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और भाजपा देश को बांटने की साजिश कर रही है।

शाह दे रहे हर दिन नए-नए उपदेशः तृणमूल प्रमुख ने हिंदी में रैली को संबोधित करते हुए कहा,'हर दिन केंद्रीय गृह मंत्री नए उपदेश दे रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि हम (विपक्षी पार्टियां) लोगों को गुमराह कर रहे है। मैं उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहना चाहूंगी कि क्या किसी व्यक्ति को पहले विदेशी घोषित किया जाएगा और उसके बाद सीएए के तहत आवेदन की अनुमति होगी।'

एटलस साइकिल कंपनी के ज्वाइंट वीपी की पत्नी की संदिग्ध मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

साइकिल कंपनी एटलस के ज्वाइंट वाइस प्रेसिडेंट (वीपी) संजय कपूर की पत्नी नताशा कपूर (57) की मंगलवार दोपहर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन स्थित घर में उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला। शुरुआती जांच में पुलिस इसे खुदकशी बता रही है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से पुलिस इसे संदिग्ध मानकर विभिन्न दृष्टिकोण से मामले की जांच कर रही है। पुलिस को कमरे के अंदर बने मंदिर से एक पत्र मिला है। इसमें लिखा है कि वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं थीं। नई दिल्ली के तुगलक रोड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगाराम अस्पताल में बुधवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद स्वजन ने लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

पुलिस को मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे घटना के बारे में सूचना मिली थी। बेटे सिद्धांत ने पुलिस को बताया कि उसने मां के मोबाइल पर कई बार फोन किया था। वह दोपहर के भोजन के लिए डाइनिंग हॉल में आने के लिए बुला रहे थे। जब वह उनके कमरे के पास गए, तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे में उनका शव दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका हुआ था।

डीसीपी (नई दिल्ली) ईश सिंघल ने बताया कि आत्महत्या के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए पूछताछ शुरू की गई है। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम सबूत एकत्र करने के लिए मौके पर पहुंची। मौके से पुलिस को हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। नताशा कपूर के पति संजय भी उसी घर में रहते हैं, लेकिन घटना के समय वह घर में मौजूद नहीं थे।

पुलिस अब नताशा कपूर के मेडिकल इतिहास के बारे में और परिजन से उनकी अंतिम बातचीत के बारे में पूछताछ करेगी। उनके फोन को यह पता लगाने के लिए स्कैन किया जाएगा कि उन्होंने आत्महत्या करने से पहले किसी से बात की थी या नहीं।

01 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली निजी किट दी गई है सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात प्रत्येक भारतीय जवान को। इसके अलावा जवानों को खुद की रक्षा और कहीं आने-जाने के लिए 1.5 लाख रुपये से ज्यादा के उपकरण भी दिए गए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 23 जनवरी 2020

इन बच्चों के साहस को सलाम

ये देश के ऐसे बच्चे हैं जिनके साहस से बड़े-बड़ों को सीखने और समझने की जरूरत है। इनके अदम्य साहस और वीरता को सबका सलाम है। भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार (2019) 12 राज्यों के 22 बच्चों को दिया गया। जिसमें 10 लड़कियां, 12 लड़के रहे।

करीब चालीस लोगों की जान बचाई

केरल के आदित्य कुमार ने साल 2019 में नेपाल में बस में आग लग जाने पर करीब चालीस लोगों की जान बचाई थी। आदित्य ने हथौड़े से बस की पिछली खिड़की को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला था।

दो बच्चियों को डूबने से बचाया

रायपुर के धमतरी जिले के कानीडबरी ग्राम निवासी जगदीश निर्मलकर की बेटी **भामेश्वरी निर्मलकर** ने 12 साल की उम्र में दो बच्चियों को तालाब में डूबने से बचाया। गांव की सोनम और चांदनी स्कूल से छुट्टी होने के बाद गांव के तालाब में नहाने गईं थीं। अचानक डूबने लगीं। भामेश्वरी ने इस बात की परवाह किए किए बिना कि उसे तैरना तक नहीं आता है, तालाब में छलांग लगा दी। किसी तरह वह बच्चियों को खींचकर बाहर ले आई।

हाथियों के दल से बचाई जान

रायपुर के सरगुजा जिले के मोहनपुर गांव की रहने वाली सात साल की **कांति सिंह** ने पिछले साल जंगली हाथियों से अपनी तीन साल की छोटी बहन की जान बचाई थी।

जोखिम में डाल थी अपनी जान

जम्मू-कश्मीर के बड़गाम जिले के 18 वर्षीय मुदासिर अशरफ ने दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर की चपेट में आए एक ग्रामीण को बचाने का प्रयास किया। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद ग्रामीण को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने ग्रामीणों को भी बचाव दल की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया।

परिवार को गोलीबारी से बचाया

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले 16 साल के सरताज मोहिद्दीन मुगल का परिवार पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में आ गया था। सरताज ने माता-पिता और दो बहनों को किसी तरह से घर से बाहर निकाला था।

बचाई थी मां, दादा व चालक की जान

पालमपुर की **अलाइका** 1 सितंबर, 2018 को कार में माता सविता व दादा सेवानिवृत्त कैप्टन के के अवस्थी के साथ खैरा जा रही थी। भारी बारिश के बीच कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से 50 मीटर नीचे लुढ़क गई। गनीमत रही कि कार पेड़ के साथ फंस गई। अलाइका ने कार का दरवाजा खोला और सड़क तक पहुंची। लोगों की मदद से सभी की जान बचाई।

गुलदार से डरी नहीं

पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 10 साल की **राखी** को गुलदार से अपने छोटे भाई राघव की जान बचाई थी। इस दौरान वो बुरी तरह घायल भी हो गईं थीं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसका 15 दिनों तक इलाज चला और उसके सिर में 45 टांके लगे।

लंबी है फेहरिस्त

इसके अलावा केरल के मुहम्मद मोहसन, उड़ीसा की श्रीमतीबदरा, पूर्णिमा गिरी व सबिता गिरी, मणिपुर की लारेंबम याईखोंबा मंगांग, मिजोरम की लालियानसांगा, कर्नाटक के 11 वर्षीय बेंकटेश, कर्नाटक की 9 वर्षीय आरती किरण शेट, मिजोरम की 11 वर्षीय कैरोलिन मलसामतुआंगी, मेघालय के पौने 11 वर्षीय एवरब्लूम के नोंगरम, असम के पौने 11 वर्षीय कमल कृष्णा दास, केरल के सवा 13 वर्षीय फतह पीके, मिजोरम के पौने 13 वर्षीय बनलालरियातरेंगा, महाराष्ट्र के पौने 11 वर्षीय जेन सदावरते व 15 वर्षीय आकाश मच्छिंद्रा खिल्लारे शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने 49 बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : दो लुटेरों से रूसी पर्यटकों को बचाने वाले इशान शर्मा, दुनिया में सबसे कम उम्र के व्यावहारिक लेखक का विश्व रिकार्ड रखने वाले ओमकार सिंह और सबसे कम उम्र की पियानो वादक गौरी मिश्रा बाल शक्ति पुरस्कार 2020 पाने वालों में प्रमुख हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पांच से 18 वर्ष आयु वर्ग के 49 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया।

हर साल बच्चों को आविष्कार, समाज सेवा, स्कूली शिक्षा संबंधी, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी के लिए बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत एक मेडल, एक लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

पुरस्कृत 49 बच्चों में दुनिया भर में 50 से ज्यादा मैजिक शो करने वाला 12 वर्षीय दर्श मालिनी और तबला वादन में महारत रखने वाला 11 वर्षीय मनोज कुमार लोहार भी शामिल हैं। भारत की सबसे कम उम्र की पियानो वादक गौरी मिश्रा के अलावा 50 फीसद बौद्धिक अक्षमता और कमजोर लक्षण का पता लग जाने के बावजूद नृत्य में उल्लेखनीय प्रतिभा प्रदर्शित करने वाला कोरोक विस्वास भी पुरस्कृत हुए हैं।

पुरस्कार पाने वालों में शामिल पंद्रह वर्षीय इशान शर्मा ने एक रूसी महिला पर्यटक को लुटेरों से बचाने के साथ ही उसे दबोचने में पुलिस की मदद की थी। मणिपुर के 10 वर्षीय लाल्कांसुंग ने एक बड़े तालाब में डूबने से तीन लड़कियों को बचाया था। पेमा ने भारी बारिश और भूस्खलन में ढह गई स्कूल की चाहरदीवारी से दो लड़कियों की जान बचाई थी।

अलर्ट जारी ▶ खुफिया तंत्र ने सुरक्षा एजेंसियों को किया सतर्क, आतंकी डाल सकते हैं बाधा

मंत्रियों के दौरे में खलल की साजिश

आतंकियों ने कथित तौर पर टारगेट भी चुन लिए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को और गति देने के लिए शुरू किए गए केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में खलल डालने की साजिश रची जा रही है। खबर है कि तीन आतंकी संगठन आउटरीच प्रोग्राम के लिए केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में हैं। खुफिया अलर्ट के बाद सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों ने प्रभावी सुरक्षा रणनीति बनाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जम्मू कश्मीर में आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए 36 केंद्रीय मंत्रियों के 24 जनवरी तक दौरे हैं। पांच अगस्त 2019 के बाद लगातार सुधरते हालात के बीच केंद्रीय मंत्रियों के दौरों का यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। खुफिया सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन न सिर्फ कश्मीर में, बल्कि जम्मू संभाग में भी गणतंत्र दिवस पर या उससे पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मौका तलाश रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर अपने टार्गेट भी चुन लिए हैं। दरअसल, एक सप्ताह पहले ही श्रीनगर में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के पांच सदस्यीय मॉड्यूल को पकड़ा है। उनसे आत्मघाती आतंकियों द्वारा पहनी जाने वाली विस्फोटकों से लैस जैकेट भी बरामद हुई है।

15 आतंकियों के तीन से चार ग्रुप बनाए गए: साजिश को अंजाम देने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा ने करीब 15 आतंकियों के तीन से चार गुट बनाए हैं। इन आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक अभियान चला रखा है। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। सभी संवेदनशील इलाकों, सुरक्षा शिविरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

ये ठिकाने हैं निशाने पर: आतंकी संगठनों के निशाने पर शोपियां के शादीमा-अहगाम स्थित सेना की 44 आरआर का शिविर, बड़गाम में ओल्ड एयरफील्ड की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की 43वीं वाहिनी का कैंप और श्रीनगर के भीतर कुछ खास जगह हैं। आतंकियों ने कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं, पंच-सरपंचों और कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या की साजिश रची है। आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस पर जम्मू और उसके साथ सटे किसी इलाके में भी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देना चाहते हैं।

श्रीनगर में आतंकी गतिविधियां बढ़ीं: सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के भीतर और साथ सटे इलाकों में भी बीते कुछ दिनों में आतंकियों की गतिविधियों में इजाफा देखा गया है। डांगरपोरा, करालपोरा, माच्छुआ, गुंड, चकपोरा, वाथूरा, सुठसु, कलां, कोठीपोरा, नौगाम जैसे इलाकों में आतंकियों की आवाजाही देखी गई है। श्रीनगर के हारवन, जकूरा, हजरतबल और छत्ताबल व डाउन-टाउन के कुछ हिस्सों में भी आतंकियों के छिपे होने के संदेह पर तलाशी ली गई है।

> आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है। वादी के सभी जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह को सुरक्षित, शांत और विश्वासपूर्ण माहौल में पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां की जा चुकी है।
>
> **-दिलबाग सिंह, पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर**

खुशहाली का पैगाम लेकर लालचौक पहुंचे नकवी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

समय- सुबह के 11.30 बजे, स्थान- लालचौक से सटा किताबघर मौलाना आजाद मार्ग श्रीनगर। यहां सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवान अन्य दिनों की तरह सड़क पर एक दूसरे से करीब 15 से 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं।

सड़क के दूसरी तरफ चाय-पकौड़े की दुकानें खुली हैं। वहां सुबह घर से बिना खाए काम पर निकले लोग नाश्ता कर रहे हैं। अचानक सायरन बजा और पुलिस की गहमागहमी शुरू हो गई। एक बुलेट प्रूफ काली एक्सयूवी और सुरक्षाबलों के एस्कार्ट वाहन अचानक रुके। काली गाड़ी का दरवाजा खुला और कराकुली टोपी व ओवरकोट पहने एक व्यक्ति बाहर निकला। उसे देखकर सब हैरान रह गए। एक ने कहा यह तो मुख्तार अब्बास नकवी है। यह यहां कैसे? इतने में दूसरे ने जवाब दिया कि आजकल यहां मंत्री आ रहे हैं, अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर। यह उसी सिलसिले में यहां आएं हैं।

विकास की आस जगा रहे मोदी के मंत्री

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के विकास और लोगों में बेहतर भविष्य की आस जगाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम के तहत बुधवार को नौ और केंद्रीय मंत्री पहुंचे। इनमें से छह मंत्री जम्मू और तीन मंत्रियों ने कश्मीर संभाग में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के 14 कार्यक्रम हुए। खराब मौसम के कारण केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का ऊधमपुर जिले के मानसर में होने वाला कार्यक्रम रद हो गया। वह अब गुरुवार को होगा। आउटरीच कार्यक्रम के 5वें दिन 11 ब्लॉकों में कार्यक्रम हुए, जो जम्मू, ऊधमपुर, रामबन, राजौरी, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल में हैं। अब तक चालीस से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऊधमपुर के मजालता, कैलाश चौधरी ने सांबा के रामगढ़, पुरषोत्तम रूपाला ने जम्मू के आरएसपुरा, सोमप्रकाश ने जम्मू के भलवाल, संजय धोत्रे ने राजौरी के नौशहरा, संतोष गंगवार ने रामबन के चंद्रकोट व दानवे राओसाहेब ने राजौरी के मंजाकोट में कार्यक्रम किए।

अब धंधा चलने लगा है

मंत्री को अपने बीच में पाकर सभी हैरान रह गए। नकवी ने जब वहां अपना सामान सजा रहे यूसुफ के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा कि कहो कैसा चल रहा है? यूसुफ तो पहले घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा अब धंधा चलने लगा है। नकवी ने स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की, वहां मौजूद कुछ खरीदारों ने भी उनसे सवाल किए। उन्होंने सभी को यकीन दिलाया कि शांति और विकास का दौर शुरू हो चुका है।

बदलाव का मजबूत माहौल बना रहे हैं : नकवी

मंत्री के आने की खबर सुनते ही वहां से चंद की कदमों की दूरी पर प्रेस एन्क्लेव, सेंट्रल मार्केट में खड़े मीडियाकर्मी भी पहुंच गए। उन्होंने मंत्री से सुरक्षा, विकास और सियासत से जुड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। मंत्री ने मुस्कराते हुए सहज ढंग से सवालों को टालते हुए कहा कि पूरे कश्मीर में सकारात्मक माहौल है। हम यहां लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं।

'370 पर पूर्व के फैसलों में विरोध हो तभी मामला सात जजों की पीठ को'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह अनुच्छेद 370 के मामले को सात जजों की बड़ी संविधान पीठ को तभी भेजेगी जब सर्वोच्च अदालत के दो पूर्ववर्ती फैसलों के बीच सीधे तौर पर विरोधाभास होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर याचिकाकर्ता वर्ष 1959 के प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर के फैसले और 1970 में संपत्त प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर के फैसले में अगर कोई गंभीर विरोधाभास दिखा सकेंगे, तभी अनुच्छेद 370 के मामले को सात जजों की बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। इन दोनों ही फैसलों में पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बुधवार को जम्मू और कश्मीर की बार एसोसिएशन ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद-370 को अवैध बताते हुए हटा दिया था।

इस खंडपीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल, आर.सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत ने कहा कि आपको हमें दिखाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों के बीच विरोधाभास है। तभी इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए फैसलों में विपरीत बात साबित होनी चाहिए।

वकीलों के संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जफर अहमद शाह ने कहा कि भारतीय संविधान और जम्मू व कश्मीर का संविधान एक-दूसरे के समानांतर थे। इन दोनों को आपस में अनुच्छेद 370 से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के संपत्त प्रकाश के फैसले में कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को जारी रखा जाए। शाह ने कहा कि दोनों ही संविधान साथ-साथ चल रहे थे। अनुच्छेद-370 की उपधारा (2) इसीलिए थी, ताकि दोनों संविधानों में कोई संघर्ष न हो। इसलिए उन्होंने इस मामले को विचार के लिए सात जजों की संविधान पीठ को सौंपने का आग्रह किया।

चौबीस घंटे में लिया शहादत का बदला, मार गिराया आतंकी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सुरक्षाबलों ने बुधवार को 24 घंटे के भीतर अपने दो साथियों की शहादत का बदला लेते हुए खियू (पुलवामा) से करीब दो किलोमीटर दूर भागे जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया। फिलहाल, उसके दो से तीन अन्य साथियों को मार गिराने के लिए सुरक्षाबलों का अभियान जारी है।

सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के एक संयुक्त कार्यदल ने मंगलवार सुबह खियू, अवंतीपोर, (पुलवामा) में जैश के तीन से चार आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया था। जामतराग इलाके में छिपे आतंकियों ने जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सेना के जवान राहुल रैयनसवाल निवासी रियासी वामनगांव (उत्तराखंड) और एसपीओ (स्पेशल पुलिस आफिसर) शहबाज अहमद निवासी राजौरी (जम्मू कश्मीर) शहीद हो गए थे। सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए घेराबंदी का दायरा बढ़ा दिया। इसके साथ ही उन्होंने खियू व साथ सटे इलाकों में आतंकियों के पुराने ओवरग्राउंड वर्करों और कुछ कैमिस्टों की भी निगरानी शुरू कर दी। दोपहर करीब बारह बजे जमतराग से करीब दो किलोमीटर दूर नगींदर में उन्होंने आतंकियों को घेर लिया। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, लेकिन उसके दो से तीन साथी भाग निकले।

न्यूज गैलरी

जम्मू-कश्मीर के पहले दौरे पर पहुंचे सेनाध्यक्ष

जम्मू : थलसेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने सुरक्षा हालात का जायजा लेने बुधवार शाम जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर पहुंचे। नरवाने ने कमान मुख्यालय ऊधमपुर में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुवार को वह सीमावर्ती राजौरी जिले के कुछ अग्रिम इलाकों का दौरा करेंगे। राजौरी, पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों के सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। जनरल नरवाने गुरुवार को सेना की 16 कोर मुख्यालय नगरोटा जाएंगे। वह कोर मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक में जम्मू संभाग की सुरक्षा चुनौतियों और उनका सामना करने के लिए जारी अभियान पर भी विचार-विमर्श करेंगे। वह उप राज्यपाल जीसी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। (राब्यू)

शबाना की हालात में सुधार जल्द हो सकती छुट्टी

मुंबई : सड़क हादसे में घायल हुई अभिनेत्री शबाना आजमी की हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। यह जानकारी उनके पति जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने शबाना आजमी की सेहत की दुआ मांगने के लिए सभी शुभचिंतकों और मित्रों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शबाना आजमी की हालात में तेजी से सुधार हो रहा है, और संभव है कि गुरुवार को उन्हें आइसीयू से बाहर लाया जाएगा। (एंटरटेनमेंट ब्यूरो)

हजारों करोड़ का हो सकता है रेलवे ई-टिकटिंग रैकेट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे के टिकटिंग रैकेट में वित्तीय लेनदेन का पैमाना हजारों करोड़ रुपये में हो सकता है। शुरुआती जांच में अकेले दुबई के सरगना हामिद अशरफ के व्यक्तिगत खातों में इससे हर महीने 15-16 करोड़ रुपये की आमद होती पाई गई है, जबकि अन्य हजारों एजेंटों के बैंक खातों में जाने वाली रकम का आकलन अभी बाकी है।

रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार के अनुसार, जैसे-जैसे जांच बढ़ रही है, रैकेट के वित्तीय मुनाफे का पैमाना बढ़ता जा रहा है। जब अकेले हामिद अशरफ को हर महीने 15-16 करोड़ रुपये की कमाई हो रही है तो पूरे नेटवर्क की कमाई का फिलहाल सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए इसका पूरा आकलन करने में अभी वक्त लगेगा। संदेह होता है कि कहीं न कहीं रेलवे के ही कुछ लोग नेटवर्क को भीतर की सूचनाएं पहुंचाते हैं। कई वर्ष पहले इसके प्रमाण भी मिले थे, जब आइआरसीटीसी के आधिकारिक एजेंट को मुंबई में टिकटों की दलाली नेटवर्क के लिए काम करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद सामने आए ऐसे ही कुछ अन्य मामलों को देखते हुए आइआरसीटीसी की वेबसाइट की क्षमता बढ़ाने के साथ कई एहतियाती प्रावधान किए गए थे। इनमें रजिस्ट्रेशन, लॉगइन और बुकिंग तथा 10 सेकंड से पहले भुगतान करने का प्रयास करने वाले यूजर के लिए कैप्चा का प्रावधान शामिल है। कोशिश रही कि एक टिकट बुक करने में कम से कम ढाई-तीन मिनट लगे और दलालों के लिए थोक में बुकिंग करना मुश्किल हो। इसके अलावा व्यवस्था की गई कि कोई एक व्यक्ति महीने में छह से ज्यादा टिकट बुक नहीं करा पाए। नेटबैंकिंग भुगतानों में ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) को अनिवार्य किया गया। इससे ज्यादा 12 तक टिकट बुक कराने के लिए आधार वेरीफिकेशन जरूरी कर दिया गया, लेकिन इसमें एक खामी रह गई कि एक से अधिक लोगों के टिकट में केवल एक व्यक्ति का आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य किया गया। इससे रैकेट के लिए आसानी हो गई। रैकेट ने एएनएमएस सॉफ्टवेयर तथा फर्जी आधार के जरिये इस सुरक्षा कवच को भी भेद लिया है।

बिहार से भी जुड़े तार, झारखंड से भी दो गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय ई-टिकटिंग रैकेट

जागरण टीम, पटना

अंतरराष्ट्रीय ई-टिकटिंग रैकेट के काले कारोबार में गिरफ्तार झारखंड के गिरिडीह निवासी गुलाम मुस्तफा के तार बिहार से काफी पहले से जुड़े हैं। गुलाम मुस्तफा 2015 से ही उप्र के बस्ती निवासी हामिद अंसारी से जुड़ा है। हामिद ने कुछ दिनों तक पटना में रहकर ई-टिकट बुक करने वाले अपने सॉफ्टवेयर को बेचने का कारोबार शुरू किया था। गुलाम मुस्तफा के माध्यम से ही उसने बिहार में नेटवर्क शुरू किया था। बस्ती के हामिद अंसारी को पहले भी टिकट की दलाली में आरपीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। जेल से छूटने के बाद उसने तत्काल टिकट बुक करने वाले सॉफ्टवेयर निर्माण की कोशिश शुरू कर दी।

इंटरनेट के माध्यम से इजरायल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के संपर्क में आया। उसने सबसे पहले ब्लैक टीएस के नाम से डोमेन बनाया। इससे एक बार में 500 टिकट बुक होने लगे। शुरू में इसकी मार्केटिंग बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, मुंबई व दिल्ली में करने लगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नेपाल से धंधा संचालित करने लगा। गुलाम मुस्तफा उसके धंधे को भारत में देखने लगा।

उधर रैकेट में शामिल गिरिडीह से तीन आरोपितों मो. कलीम, शमीम अख्तर और अमित गुप्ता बुधवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों से जब्त लैपटॉप, मोबाइल और डोंगल को टीम खंगाल रही है। आधा दर्जन लोगों पर अभी भी विभाग की नजर है। आरपीएफ ने बताया गुलाम मुस्तफा की पत्नी सबीना खातून का काम क्षेत्र में सॉफ्टवेयर बेचने का है।

ब्लैक टीएस के साथ ही रेड मिर्ची : गुलाम मुस्तफा के गिरोह में जहानाबाद के महबूब और दाउद भी आ गए। उसने ब्लैक टीएस के साथ ही रेड मिर्ची के नाम से सॉफ्टवेयर बनाकर इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। 2018 में ही हामिद अंसारी चर्चा में आया। मुंबई आरपीएफ की विशेष टीम भी उसके गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार करने पटना पहुंची थी। महबूब और दाउद को गिरफ्तार कर दोनों को अपने साथ मुंबई ले गई। दोनों ने नेपाल में बैठे आका मो. हामिद अंसारी और गुलाम मुस्तफा का नाम बताया। मुस्तफा की निशानदेही पर भागलपुर से मो. जुनैद राज और मो. इमरान को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने बताया कि रेड मिर्ची से मिले सारे पैसे गुलाम मुस्तफा के बैंक खातों में डाले जाते थे। 2019 में रेड मिर्ची काफी चर्चा में आ गई। आरपीएफ यह मानकर चल रही है कि हामिद अंसारी ही हामिद अशरफ के नाम से नेपाल के बाद दुबई में जाकर बैठ गया है। इसके बाद उसने रेड मिर्ची को बंदकर इजरायल की सॉफ्टवेयर कंपनी से ही एएनएमएस नाम से नई कंपनी खोल दी। इसके नाम से सॉफ्टवेयर बाजार में आ गया। उसने देश के कोने-कोने में एजेंट रखे थे।

एक टिकट पर एक हजार : पूछताछ में जुनैद और इमरान ने बताया कि वे एक टिकट (पीएनआर) पर मुस्तफा को एक हजार रुपये दिया करते थे। दोनों अमूमन महीने में सौ से डेढ़ सौ टिकटें काटते थे। गुलाम मुस्तफा ने ही भागलपुर के दोनों साइबर संचालकों को 'एएनएमएस' सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए थे। लेकिन उसके इस्तेमाल का तरीका पता नहीं होने के कारण जुनैद राज और इमरान उस सॉफ्टवेयर से टिकटें नहीं काट सके। उनका मजबूत नेटवर्क कोलकाता में भी है। अकेले कोलकाता में प्रतिदिन 5000 से अधिक तत्काल टिकटों की बुकिंग हो रही है।

तीन आरोपित गिरिडीह से गिरफ्तार

रैकेट में शामिल गिरिडीह के तीन आरोपितों मो. कलीम, शमीम अख्तर और अमित गुप्ता को रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपित धीरेंद्र यादव उर्फ रिंकू के आवास में भी छापा मारा गया, परंतु वह हाथ नहीं आया। आरोपितों के यहां छापेमारी में पुलिस के हाथ चार लैपटॉप, तीन मोबाइल व तीन डोंगल जब्त हुए। जब्त लैपटॉप को तकनीकी सेल की टीम खंगाल रही है। आधा दर्जन लोगों पर अभी भी विभाग की नजर है। इंस्पेक्टर ने बताया गुलाम मुस्तफा की पत्नी सबीना खातून का काम क्षेत्र में सॉफ्टवेयर बेचने का है।

2018 में जहानाबाद के महबूब और दाउद को मुंबई आरपीएफ ने किया था गिरफ्तार

▶ ब्लैक टीएस के नाम से हामिद अंसारी ने शुरू किया था ई-टिकटिंग हैकिंग का कारोबार

जागरण विशेष

बर्फ से ढके होने के बावजूद कश्मीर पर्यटकों की पहली पसंद, एक ओर जहां कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ जुट रही है, वहीं वैष्णो देवी मंदिर सहित जम्मू के मुख्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की कतार लग रही है

बर्फ से लकदक नया कश्मीर देसी-विदेशी सैलानियों से गुलजार

कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जागरण

ललित कुमार, जम्मू

'जन्नत' कहा जाने वाला कश्मीर पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। बर्फ से लकदक होने के बावजूद पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ जुट रही है। वहीं, माता वैष्णो देवी मंदिर सहित जम्मू के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की कतार लग रही है।

बात करें 'नए कश्मीर' की तो अमन की बहार के बीच वादी देसी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। मौजूदा समय में वादी के पहाड़ बर्फ से लकदक हैं। बावजूद इसके पर्यटकों का उत्साह कम नहीं है। कश्मीर पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में होटल खचाखच हैं। विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। इधर, जम्मू के पर्यटन व धार्मिक स्थलों में भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आमद बढ़ रही है।

पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में बीते दो माह से पर्यटकों की भीड़ जुटना शुरू हुआ था, जो थम नहीं रहा है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिन-ब-दिन बढ़ रही है। पर्यटन विभाग मौके का भरपूर लाभ उठा रहा है और पर्यटकों को लुभाने के लिए अन्य राज्यों में रोड शो के जरिये टूरिज्म का प्रचार-प्रसार कर रहा है।

बीते वर्ष अगस्त में जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने से पहले एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों व अमरनाथ श्रद्धालुओं को लौटने की सलाह दी तो एक महीने जम्मू कश्मीर मेहमानों से सूना रहा। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पर्यटकों के कदम फिर घाटी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। विदेशी पर्यटकों का कश्मीर के प्रति लगाव नए सिरे से बढ़ता दिख रहा है। जापान, मलेशिया जैसे देशों से पर्यटक लगातार कश्मीर पहुंच रहे हैं।

पर्यटकों के कश्मीर की तरफ बढ़ते कदमों में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर बाधा बना हुआ है। दिसंबर से लगातार खराब मौसम के कारण पहाड़ों से गिरे मलबे ने रास्ते बंद कर रखे हैं। कश्मीर में हवाई सेवा से काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस तरह से धीरे-धीरे पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यह सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है। इस बार तो हिमाचल पहुंचने वाले पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं।

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देंगे : वीके सिंह: केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग राज्यमंत्री वीके सिंह ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नीटॉप को देसी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने का विश्वास दिलाया है। आउटरीच कार्यक्रम में जम्मू आए सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए विशेष तैयारियां कर रही है। पत्नीटॉप में पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

> कश्मीर हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। यहां हालात सामान्य हो रहे हैं, यह संदेश तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। अक्टूबर के बाद से पर्यटकों के आने का सिलसिला फिर तेज हुआ है। गुलमर्ग में काफी पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए।
>
> **-निसार अहमद वानी, डायरेक्टर, टूरिज्म कश्मीर**

> कश्मीर में गत वर्ष नवंबर के बाद से पर्यटन ने कुछ जोर पकड़ना शुरू किया है। इसका मुख्य कारण वहां हालात का शांत होना ही है। आतंकी हिंसा में बहुत कमी आई है। इसके अलावा इस बार हिमपात खूब हुआ है।
>
> **-रमन शर्मा, प्रबंध निदेशक, इंडिया प्राईड टूर एंड ट्रैवल**

> बीते वर्ष दिसंबर हमारे लिए अच्छा रहा है। कारोबार अच्छा रहा है। आजकल चैनलों में कश्मीर में आतंकी हिंसा को लेकर प्रचार नहीं होता, इसलिए भी पर्यटक यहां आ रहे हैं। इंटरनेट पर जिस तरह से राहत मिली है वह भी पर्यटकों की आमद बढ़ाने में सहयोग कर रही है। आने वाले दिनों में यहां विंटर गेम्स होने जा रही हैं, निवेश सम्मेलन की तैयार है।
>
> **-फिरदौस अहमद, होटल व्यावसायी**

8 लाख से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत देश में हर साल पानी, स्वच्छता, पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से हो जाती है।

आजादी दिलाने का निभा गए वादा

यूनीफार्म वॉलेंटियर कोर के सदस्यों के साथ नेताजी। आर्काइव

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती (23 जनवरी) पर विशेष

आज हम जिस 71वें गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, उसे अलंकृत करने, आकार देने और मजबूत करने में हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी। 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा', अपने इस वायदे के तहत देश को आजादी दिलाने वाले महानायक सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक रहे हैं।

आजादी के सिपाही का जीवन वैसे तो वीरता के किस्सों के साथ याद किया जाता है लेकिन संघर्ष के साथ जीवन रहस्यों के लिए तो नेताजी सुभाषचंद्र बोस का ही नाम आता है। आइए, उनके 123वें जन्मदिन पर उनके जीवन रहस्यों से करते हैं उनके अपनों द्वारा साक्षात्कार

शुरुआती जीवन

उड़ीसा के कटक में आज ही के दिन 1897 में संपन्न बंगाली परिवार में जन्म हुआ। बचपन उड़ीसा में बीता। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद दर्शनशास्त्र में स्नातक के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। देश को आजादी दिलाने के उनके लंबे सफर के बाद आज रहस्यों का अंतहीन सिलसिला कायम है। 2017 में केंद्र सरकार की ओर से भले ही उनकी मौत के कारणों को स्पष्ट कर दिया गया लेकिन ये फैसला उनके परिवार और उनसे जुड़े लोगों के मन और मस्तिष्क में दर्द के साथ कई सवाल भी छोड़ गया।

यूनीफार्म वॉलेंटियर कोर के प्रशिक्षण के दौरान घोड़े पर सवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आर्काइव

क्या आप जानते हैं?

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये सबको मालूम है लेकिन बहुत कम लोगों का पता है कि इससे काफी पहले उन्होंने यूनीफॉर्म वॉलेंटियर कोर नाम से एक और फोर्स का गठन किया था। नेताजी शुरू से ही सैन्य अनुशासन में यकीन करते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1928 में कांग्रेस में यूनीफॉर्म वॉलेंटियर कोर का गठन किया था। नेताजी यूनीफॉर्म वॉलेंटियर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। नेताजी वॉलेंटियर कोर के सदस्यों के साथ सुबह कोलकाता मैदान में लांग मार्च, ड्रिल, घुड़सवारी, बंदूकबाजी, कसरत इत्यादि करते थे। यह बिल्कुल सैन्य प्रशिक्षण जैसा था।

(नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस से बातचीत पर आधारित।)

आइसीएस बने

1919 में ब्रिटेन गए और चौथे स्थान के साथ आइसीएस परीक्षा पास की। विदेशी सरकार के अधीन काम नहीं करने की इच्छा के चलते 1921 में इस्तीफा देकर स्वदेश वापसी।

पार्टी अध्यक्ष : 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी वह चुनाव में खड़े हुए। महात्मा गांधी ने पट्टाभि सीतारमैया को खड़ा किया और चुनाव में सीतारमैया हार गए। कांग्रेस के असहयोग के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।

आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक का गठन : 22 जून, 1939 को इस संस्था का गठन किया। दो जुलाई, 1940 को गिरफ्तार कर कोलकाता के प्रेजीडेंसी जेल में रखा गया।

निर्वासन झेलना पड़ा

- अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ पहुंचे। वहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्टालिन से मदद मांगी लेकिन उसने इन्कार कर दिया।
- 1943 में सिंगापुर पहुंच आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापान ने समर्थन दिया। 1945 में विमान दुर्घटना में मौत की खबर मिली।

23 जनवरी पर आती थी विशिष्ट टीम

शक्ति सिंह (फाइल फोटो)। जागरण

1982 का मार्च महीना। लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग को लेकर उनके कुछ शिष्य गेट के भीतर घुसे। भवन के पूर्वी उत्तरी हिस्से में तीन कमरे के सेट में बुजुर्ग रहने लगे। उनका सामान धीरे-धीरे एक माह तक आता रहा। छह माह बाद उनके नेताजी होने की चर्चाएं शुरू हुईं। ढाई साल घर में रहे लेकिन मार्च महीने की आधी रात की पलक भर झलक को छोड़ दिया जाए तो उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। पड़ोसी जिले बस्ती की सरस्वती देवी ने ही उन्हें देखा था। सरस्वती देवी नेपाल राजघराने के गुरु परिवार से संबंधित थीं। साल में दो बार कोलकाता से विशिष्ट सदस्यों की टीम यहां आती थी। 23 जनवरी और दुर्गा पूजा में।

काली मां का चित्र देखकर ठहर गई ललिता बोस

16 दिसंबर 1985 की रात में गुमनामी बाबा की मृत्यु हो गई। 28 दिसंबर 1985 को नेताजी की सगी भतीजी ललिता बोस मेरे घर रामभवन आई। ललिता ने ताला खोल कर पहला कमरा देखा तो अनमनी सी रहीं लेकिन भीतरी कमरे की दीवार पर काली मां का चित्र देख वह चौक गईं फिर ज्यों ही उन्होंने बक्सा खोला उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बक्से में पुराने पत्र थे। ललिता बोस की निगाह रोलेक्स घड़ी, गोल फ्रेम चश्मा, पार्कर पेन, इंग्लैंड के टाइपराइटर पर भी पड़ी। एक पत्र आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के मुखिया डॉ. पवित्र मोहन राय का भी लिखा हुआ मिला। कोर्ट में केस हुआ। सूची बनाकर सभी सामान मालखाने में सुरक्षित रखे जाने का आदेश हुआ। 2760 वस्तुओं में से 425 आर्टिकल रामकथा संग्रहालय में रखे जा चुके हैं लेकिन अभी तक जनता के दर्शन के लिए उस गैलरी को खोला नहीं गया।

अयोध्या स्थित रामभवन (फाइल फोटो)। जागरण

(अयोध्या (तब फैजाबाद) में रामभवन के स्वामी शक्ति सिंह से बातचीत पर आधारित, जहां गुमनामी बाबा ने जीवन के आखिरी ढाई साल बिताए।)

न्यूज गैलरी

छेड़खानी करने के आरोपित डीआइजी को हाई कोर्ट से राहत

मुंबई : बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआइजी) निशिकांत मोरे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। मोरे पर 17 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। जस्टिस डीपी नाइक ने मोरे को 29, 30 व 31 जनवरी को नवी मुंबई के तालोजा थाने में उपस्थित होकर पुलिस को सहयोग करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपित और पीड़िता के परिवार में अच्छे रिश्ते थे। पीड़िता के पिता ने जब आरोपित से उधार लिए रुपये वापस करने से इन्कार कर दिया तो उनमें खटास पैदा हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि पांच जून 2019 को जब पीड़िता के जन्मदिन पर कथित छेड़खानी हुई, तब उसका परिवार भी वहां मौजूद था। जस्टिस नाइक ने कहा, 'वीडियो में पीड़िता का तौर-तरीका कथित घटना पर संदेह पैदा करता है।' पनवेल सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मोरे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। (प्रेट्र)

बंगाल में थाने से 18 बंदूकें चोरी, सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

खड़गपुर: बंगाल में माओवाद प्रभावित रहे जंगलमहल के झाड़ग्राम जिले के लालगढ़ थाने से 18 बंदूकें चोरी हो गई हैं। मालखाने से बंदूकों की चोरी का राज बुधवार को उजागर हुआ तो सब इंस्पेक्टर समेत मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झाड़ग्राम जिला पुलिस ने आरोपितों को पांच दिनों के रिमांड पर भी लिया है। जानकारी के मुताबिक, लालगढ़ थाने से हुई 18 बंदूकों की चोरी के मामले में पुलिस ने बुधवार को जामबनी के सब इंस्पेक्टर तारापद टुडू को गिरफ्तार किया। तारापद के साथ ही नेशनल वालेंटियर्स फोर्स के कर्मचारी लक्ष्मीराम राणा तथा रिसीवर के तौर पर कार्य करने वाले दो ग्रामीण सुधांशु सेनापति और दिलीप सेनापति को भी गिरफ्तार किया गया। (जेएनएन)

दो फ्लाइटें डायवर्ट होकर अमृतसर पहुंचीं

अमृतसर : गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट नोटम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किए जाने के चलते बुधवार को एक फ्लाइट डायवर्ट होकर अमृतसर पहुंची। लंदन-दिल्ली फ्लाइट ने सुबह 10.30 बजे श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया। नोटम खत्म होने के बाद फ्लाइट ने दोपहर 1.15 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह धुंध के चलते काबुल-दिल्ली फ्लाइट को एसजीआरडी एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया गया। फ्लाइट ने सुबह 6.06 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया। (जासं)

पहले जमकर पीटा, फिर सातों के सिर कर दिए धड़ से अलग

सिंहभूम नरसंहार ▶ सीएम ने गठित की एसआइटी, भाजपा ने बनाई कमेटी

पत्थलगड़ी समर्थक पूर्व मुखिया का विरोध करने पर दिया गया घटना को अंजाम

जागरण संवाददाता, पश्चिमी सिंहभूम

पत्थलगड़ी के विरोध को लेकर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुए नरसंहार में सभी सात शव जंगल से बरामद कर लिए गए हैं। सभी मृतक 25 से 35 वर्ष के बीच के हैं। पहले सभी की जमकर पिटाई की गई, फिर जंगल में ले जाकर सातों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। मृतकों में उप मुखिया जेम्स बूढ़ समेत अन्य ग्रामीण हैं। हत्या से पहले लाठी से इन्हें बुरी तरह पीटा भी गया।

डीआइजी कुलदीप द्विवेदी ने लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय थाना प्रभारी अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि घटना की जांच विशेष जांच दल करेगा। वहीं, हत्याकांड की जांच को भाजपा ने भी छह सदस्यीय कमेटी गठित की है।

पत्थलगड़ी का विरोध कर रहे थे उपमुखिया : डीआइजी ने बताया कि इलाके के पूर्व मुखिया मुक्ता होरो पत्थलगड़ी के पक्ष में थे। एक साल पहले गांव में अभियान चलाकर लोगों से आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा करा लिए थे। ग्रामीणों से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का बहिष्कार करने की शुरू से अपील कर रहे थे। वर्तमान उप मुखिया जेम्स को इस पर एतराज था। वह पत्थलगड़ी का समर्थन नहीं करने की अपील कर रहे थे। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।

नौ लोग लाए गए थे पकड़ कर : पुलिस अधीक्षक के अनुसार, पूर्व मुखिया मुक्ता होरो का आरोप है कि जेम्स बूढ़ ने समर्थकों के साथ उनके तथा पांच अन्य ग्रामीणों के घर पहुंचकर गुरुवार रात सात बजे तोड़फोड़ की। घर के सामान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यही नहीं घर में घुस कर महिलाओं की भी पिटाई की। इसके बाद गांव में रविवार को पंचायत बुलाई गई। इसमें तोड़फोड़ करने वाले नौ लोग पकड़कर लाए गए। इसी बीच मौका देख दो लोग फरार हो गए। पंचायत में विवाद इस कदर बढ़ता गया कि जेम्स बूढ़ समेत सात लोगों की पत्थलगड़ी समर्थकों ने पहले जमकर पिटाई की। इसके बाद पत्थलगड़ी समर्थक सभी को उठाकर गांव से एक किलोमीटर दूर जंगल ले गए। वहां सभी के गले काट दिए।

नहीं मिला ग्रामीणों का सहयोग : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना की जानकारी मंगलवार मिली इसके बाद उन्होंने तुरंत ही सर्च अभियान शुरू करने का आदेश दिया। रात भर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, सूचना के अभाव तथा ग्रामीणों से सहयोग नहीं मिलने के कारण सच्चाई जानने में देरी हुई।

सीएम ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि घटना की जांच एसआइटी करेगी। मुख्यमंत्री ने पूरे घटना की जानकारी ली और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

नड्डा ने एक सप्ताह के भीतर मांगी रिपोर्ट

पत्थलगड़ी का विरोध कर रहे सात आदिवासियों की हत्या को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हत्याकांड की जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह कार्यालय प्रभारी अरूण सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्देशानुसार टीम घटनास्थल का दौरा कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।

गुजरात से शुरू हुआ था आदिवासी आंदोलन

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

- आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई में केसरी सिंह गामित उर्फ कटासवान वाले दादा ने पूरा जीवन बिताया
- खूंटी में चल रहे पत्थलगड़ी और कुटुंब परिवार आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं उनके पुत्र रवींद्र केसरी

रांची के खूंटी जिले के आदिवासी इन दिनों सरकारी व्यवस्था के विरोध में एकजुट हो रहे हैं। इस विचारधारा के पीछे 1930 में बैरिस्टर टेटिया कानजी गामित द्वारा शुरू किया गया सति पति मूवमेंट है। यह मूवमेंट आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार से जुड़ा था। टेटिया कानजी आदिवासियों के 'कटासवान वाले दादा' कुंवर केसरी सिंह के पिता थे। उनके पुत्र रवींद्र केसरी सिंह खूंटी के बागी तेवर को सिरे से खारिज करते हैं।

केसरी सिंह गामित उर्फ कटासवान वाले दादा ने पूरा जीवन आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई में बिता दिया। आदिवासी समुदाय में उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने पिता के सति पति मूवमेंट को आगे बढ़ाया और सूरत के पास तापी-सोनगढ़ में अपनी पकड़ बनाई। आदिवासी उनकी बात सुनते व मानते हैं। अपनी गाड़ी पर भारत सरकार लिखते, पुलिस से सामना होने पर भिड़ जाते, अदालत में अपना केस खुद लड़ते और जीत जाते थे। केसरी सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाले आदिवासी सरकार व प्रशासन को मानने से इन्कार करते हैं। सरकारी बसों में मुफ्त सफर, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र नहीं रखते हैं और कोई कर भी नहीं देते। अपने इलाकों में सफेद रंग का बोर्ड लगाते हैं जिन पर लिखा होता है भारत सरकार। सेवा जोहार इनका प्रमुख नारा है। दावा कि सात जनवरी 1969 में कोर्ट में उन्होंने खुद को भारत की मूल मिट्टी, मूल बीज व मूल वारिस साबित कर दिया था।

खूंटी आंदोलन का समर्थन नहीं : कुंवर केसरी सिंह गामित का नाम लेकर झारखंड के खूंटी में चल रहे पत्थलगड़ी और कुटुंब परिवार आंदोलन का रवींद्र केसरी सिंह समर्थन नहीं करते हैं। वह सरकार व प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन को भी नाजायज मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन अहिंसा व विश्व शांति पर आधारित है। हिंसा के बजाय शांति का मार्ग अपनाने से भी मंजिल मिलती है। हर साल अहिंसा व विश्व शांति पर सम्मेलन करते हैं और यही उनका संदेश है।

हम प्रिवी कौंसिल के अधीन

जमीन के मालिक व खुद की सरकार चलाने के बारे में पूछने पर रवींद्र केसरी सिंह ने कहा कि हम प्रिवी कौंसिल अर्थात भारत सरकार के अधीन हैं। कानून व शासन उन्हें मंजूर नहीं है। नॉन जूडिशियल का अर्थ प्राकृतिक व मुक्त जीवन से है। अपने आंदोलन के जरिये किसी तरह की हिंसा उन्हें बर्दाश्त नहीं।

यह है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1930 में महात्मा गांधी व इरविन के बीच हुए गोलमेज समझौते में आदिवासियों के लिए अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया का उल्लेख किया गया था। टेटिया कानजी आदिवासियों के नेता थे। उनका दावा था कि महारानी विक्टोरिया ने ही आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक सौंप दिया था। ऐसे में आदिवासी जब इस देश के मालिक हैं तो कोई सरकार उनको कैसे आदेश और निर्देश दे सकती है।

गजब कारोबार! दाहिने हाथ से खरीदकर बाएं को 80 अरब रुपये घाटे में बेचा

जागरण संवाददाता, कानपुर

▶ पांच साल में फ्रॉस्ट इंटरनेशनल ने एक कंपनी से 31 हजार करोड़ की खरीद दूसरे को 23 हजार करोड़ में बेची

फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के हाथों धोखाधड़ी का अहसास होते ही कंसोर्टियम के लीडर बैंक ऑफ इंडिया ने फोरेंसिक ऑडिट कराया तो सभी हक्के बक्के रह गए। बैंक की तरफ से सीबीआइ को मिले प्रतिवेदन और सीबीआइ की बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ब्रांच में उदय जे देसाई, सुजय देसाई समेत 15 लोगों पर दर्ज मुकदमे में शामिल 13 बिंदुओं की फोरेंसिक रिपोर्ट कई खेल खोल रही है। ऑडिट रिपोर्ट का मजमून कह रहा है कि फ्रॉस्ट इंटरनेशनल ने दाहिने हाथ से सामान खरीदा और 80 अरब के घाटे में बायें हाथ को बेच दिया।

जनवरी 2018 में लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान न होने और खाते एनपीए होने पर बैंक जागे। अरबों रुपये का ट्रांजेक्शन दिखा रही कंपनी भुगतान क्यों नहीं कर रही है, यह जानने के लिए कंपनी के खातों का फोरेंसिक ऑडिट कराया गया। हरी भक्ति एंड कंपनी ने ऑडिट किया और 5 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, उदय देसाई की फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ने वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक फारेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड (एफडीएलपीएल) से 31398.58 करोड़ रुपये की खरीद की और गफ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (जीडीएल) को करीब आठ हजार करोड़ रुपये घाटे में 23,426.66 करोड़ रुपये में बेच दिया। ये दोनों कंपनियां हांगकांग स्थित तीसरी कंपनी फौस्टा लिमिटेड के जरिए एक-दूसरे से जुड़ी हैं। फौस्टा लिमिटेड, एफडीएलपीएल की सौ फीसद की स्टेक होल्डर है और जीडीएल व फौस्टा का पता एक ही है।

ऑडिट टीम ने एक और मामला खोला। बैट यूनीवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रीज सेल्स ओवरसीज लिमिटेड व मैपल (यूके) लिमिटेड के निदेशक और पूर्व निदेशक आशीष टोडी अप्रैल 2008 तक फ्रॉस्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के भी निदेशक रहे। इस दौरान इन कंपनियों से 4,371.17 करोड़ रुपये की खरीद और 4,411.48 करोड़ रुपये की बिक्री की गई। कई एग्रीमेंट और इनवाइस पर एक ही हस्ताक्षर मिले। रिपोर्ट में है कि माल किसी और को बेचा लेकिन भुगतान किसी और ने किया।

दूसरे दिन भी जारी कार्रवाई : 3,592 करोड़ रुपये के घोटाले में फ्रास्ट इंटरनेशनल के निदेशक, पूर्व निदेशक व गारंटरों के खिलाफ सीबीआइ की जांच दूसरे दिन भी जारी रही। सीबीआइ की बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड शाखा के अधिकारियो ने बैंक से तमाम जानकारियां जुटाईं। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया सारे दस्तावेज पहले ही दे चुका है टीम ने ऋण जारी करने के दौरान लगाए गए कागजात और प्रक्रिया की बारीकी से जांच की। इसके पहले मंगलवार को सीबीआइ ने कानपुर, मुंबई और दिल्ली में कुल 13 स्थानों पर फ्रास्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक उदय देसाई समेत पूर्व निदेशक व गारंटरों के आवास और प्रतिष्ठान पर छापे मारे थे। सीबीआइ के अधिकारी बुधवार को भी दिनभर जांच के साथ बयान दर्ज करते रहे।

नाबालिग की अग्रिम जमानत अर्जी पोषणीय नहीं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में आरोपित नाबालिग को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। हाई कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और अन्य आरोपों में आरोपित साहब अली और अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 10 व 12 के अंतर्गत नाबालिग के मामलों में स्पेशल पुलिस यूनिट एवं चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं। नाबालिग को 24 घंटे के भीतर बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश करना होता है, जिसे जांच करके उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसे में यह कहना कि बोर्ड को अग्रिम जमानत देने का अधिकार नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी की सुनवाई होनी चाहिए, विधिसम्मत नहीं है।

मंगलुरु हवाई अड्डे पर बम रखने वाले ने आत्मसमर्पण किया

▶ इंजीनियरिंग स्नातक है संदिग्ध, इससे पहले बम की झूठी सूचना देने के लिए छह माह जेल की हो चुकी है सजा

बेंगलुरु, प्रेट्र : मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैग में बम रखने वाले 36 वर्षीय संदिग्ध ने बुधवार को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। समर्पण करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में आया। पूछताछ और चिकित्सकीय जांच के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध का नाम आदित्य राव है और वह मनिपाल का रहने वाला है। वह मंगलुरु हवाई अड्डे पर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए व्यक्ति जैसा दिखता है।

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने हवाई अड्डे पर बम रखने की बात स्वीकार कर ली है। सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व मंगलुरु की पुलिस एक टीम बेंगलुरु पहुंच गई है। बेंगलुरु में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में उसे पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड ले लिया गया है। मंगलुरु में उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग की जाएगी।

कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि पुलिस की सक्रियता के कारण उसने समर्पण किया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बम बनाने के लिए सामग्री कहां से जुटाई और उसे कैसे बनाया।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि राव इंजीनियरिंग स्नातक है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वह पोस्ट ग्रेजुएट है। इससे पहले 2018 में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बम की झूठी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और छह माह कैद की सजा सुनाई गई। दो महीने जेल काटने के बाद वह अभी जमानत पर बाहर है। उसने बदला लेने के लिए यह काम किया था। कथित रूप से कुछ दस्तावेज के अभाव के कारण बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उसे सुरक्षा गार्ड की नौकरी नहीं दी गई थी।

राव 2012 में नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आया और एक निजी बैंक में काम पर लग गया। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और मंगलुरु लौट आया जहां छह महीने तक वह सुरक्षा गार्ड रहा और उडुपी के पुतिग मठ में रसोइए का काम किया। इसके बाद वह फिर बेंगलुरु लौटा और एक बीमा कंपनी में काम करने लगा। फिर उसने इस नौकरी को भी त्याग दिया और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी पाने का प्रयास किया। मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टिकट काउंटर के पास सोमवार को एक लावारिस बैग में विस्फोटक पाया गया था।

मेंगलुरु एयरपोर्ट पर विस्फोटक रखने वाला आदित्य राव। एएएनआइ

रंग लाया प्रयास

बेटे को मुंबई ले जाने के लिए छोड़ दी थी हाई कोर्ट की नौकरी, फिल्म 'पंगा' में कंगना के बेटे की भूमिका निभा रहे हैं लक्सर के यज्ञ

बेटे के सपने के लिए पिता ने करियर से लिया 'पंगा'

हिमांशु जोशी, देहरादून

'जो सपने देखते हैं, वो पंगा लेते हैं...' यह केवल फिल्म 'पंगा' की टैग लाइन ही नहीं, बल्कि इसी फिल्म में अभिनेत्री कंगना रनौट के बेटे की भूमिका निभा रहे लक्सर के यज्ञ भसीन की असल जिंदगी की कहानी भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि फिल्म में बेटे ने तो असल जिंदगी में पिता दीपक भसीन ने बेटे के लिए हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी और पूरा परिवार मुंबई जाकर रहने लगा। आखिरकार बेटे को फिल्म 'पंगा' मिली, जो 24 जनवरी को रिलीज हो रही है।

लक्सर (हरिद्वार) निवासी 10 वर्षीय यज्ञ भसीन फिल्म 'पंगा' में कंगना रनौट के बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में जहां मां के सपनों को साकार करने के लिए बेटा आगे आता है, वहीं रियल लाइफ में यज्ञ के सपनों को साकार करने के लिए उनके पिता दीपक भसीन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। दीपक बताते हैं, 'मैं नैनीताल हाई कोर्ट में नौकरी कर रहा था तो मुझे हर कोई कहता था कि बेटे को मुंबई ले जाओ। यह वहां बढ़िया करेगा। हमें भी लगता था कि यज्ञ में आम बच्चों से कुछ अलग है। आखिर हमने मुंबई जाने का निर्णय लिया। मैंने 30 जून, 2017 को हाई कोर्ट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हम परिवार समेत मुंबई आ गए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। पर आज नतीजा सबके सामने है।'

करीब ढाई साल के इस संघर्ष के बीच यज्ञ को फिल्म 'पंगा' के जरिये बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। धारावाहिक 'मेरे साईं' से छोटे पर्दे में एंट्री करने वाले यज्ञ, अब तक 'सीआइडी', 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'कृष्णा चली लंदन' में काम कर चुके हैं। जल्द ही यज्ञ एक नई फिल्म में भी दिखाई देंगे।

हरिद्वार के लक्सर में पिता दीपक भसीन और मां सोनिया भसीन के साथ फिल्म पंगा में अहम भूमिका निभा रहे यज्ञ भसीन। साभार-दीपक भसीन

सेट पर पढ़ाई करते हैं यज्ञ

दीपक बताते हैं कि पढ़ाई और अभिनय के बीच यज्ञ आसानी से सामांजस्य बना लेते हैं। वे बताते हैं कि मैं वाट्सएप में यज्ञ के शिक्षकों से असाइनमेंट लेता हूं और शूटिंग के बीच खाली समय में यज्ञ असानइमेंट पूरा करता है।

कंगना मैम ने किया काफी मोटीवेट

कक्षा पांच के छात्र यज्ञ बताते हैं, 'यह मेरी पहली फिल्म है। इसमें कंगना मैम के बेटे की भूमिका मिली है। इसमें मेरे लिए काफी कुछ करने को था। शुरुआत से ही कंगना मैम ने मुझे इतना मोटीवेट किया कि मैं भूल गया कि यह मेरी पहली फिल्म है। करीब साढ़े आठ माह तक मैंने उनके साथ शूटिंग की। वह एक परफेक्ट एक्ट्रेस होने के साथ-साथ बहुत अच्छी इंसान हैं। इसके अलावा मैंने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, नीना गुप्ता के साथ भी कई सीन किए।'

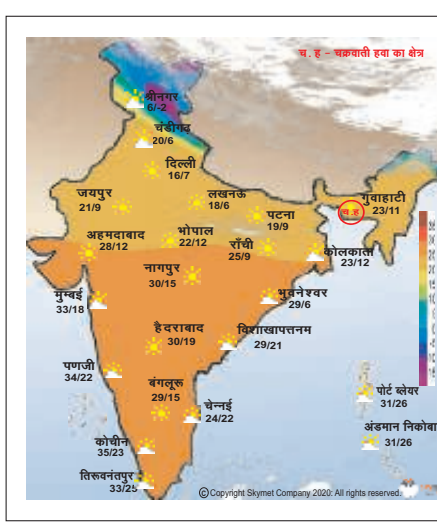

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। आंशिक बादलों के साथ धूप खिली रहेगी। रात के तापमान में गिरावट के कारण कंपकंपाती ठंड जारी रहेगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में शुष्क मौसम जारी रहेगा। रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंडी सुबह में कोहरा छाया रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/19/आंबा	अहमदाबाद	27/14/आंबा
कोलकाता	22/11/सा	बड़ौदा	29/14/सा
चेन्नई	32/24/आंबा	नागपुर	31/14/आंबा
हैदराबाद	30/19/आंबा	इन्दौर	29/13/आंबा
बंगलूरू	30/15/सा	रांची	27/12/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/25/आंबा	पटना	25/13/आंबा
गुवाहाटी	24/13/सा	जबलपुर	28/10/आंबा
गंगटोक	05/-5/सा	पुणे	29/21/आंबा

दैनिक जागरण

ईर्ष्या जिसके भीतर पनपती है उसी का नुकसान करती है

जल्द फैसले की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से इन्कार कर उन लोगों को निराश करने का ही काम किया जो पता नहीं कैसे यह मान कर चल रहे थे कि शीर्ष अदालत को आनन-फानन इस कानून पर रोक लगा देनी चाहिए। निःसंदेह यह एक मुगालता ही अधिक था, क्योंकि सरकार के पक्ष को सुने बिना संसद से पारित और साथ ही अधिसूचित कानून पर रोक लगाना न्यायसंगत नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून पर विचार नहीं कर सका तो इसके लिए इस कानून के विरोधी ही अधिक जिम्मेदार हैं। पहले इस कानून को चुनौती देने के लिए करीब साठ याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या सोचकर तमाम और याचिकाएं दाखिल कर दी गईं। अब उनकी संख्या 140 से अधिक हो गई है। सरकार ने पहले दायर याचिकाओं के जवाब तो तैयार कर लिए थे, लेकिन उसे नहीं पता कि नई याचिकाओं में क्या मांग की गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में उसे इन याचिकाओं का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय और देना पड़ा। क्या जल्द फैसले की उम्मीद लगाने वाले यह समझेंगे कि याचिकाओं का ढेर लगाकर उन्होंने अपनी ही उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया? आखिर किसी एक मसले पर इतनी अधिक याचिकाएं दायर करने की क्या जरूरत थी?

शायद विपक्षी दल नागरिकता कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करने की भी होड़ में शामिल हैं। सच जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट को समय और संसाधन बर्बाद करने वाली इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। इसी के साथ उसे इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस कानून की वैधानिकता का निपटारा जल्द से जल्द करने की जरूरत है। वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि इस कानून के विरोधियों ने धरना-प्रदर्शन का एक उद्योग खड़ा कर दिया है। दुष्प्रचार के जरिये लोगों को न केवल सड़कों पर उतारा जा रहा है, बल्कि उन्हें यह नया पाठ भी पढ़ाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी उनके खिलाफ है। इस सुनियोजित दुष्प्रचार से उपजे भ्रम और भय के माहौल को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकता संशोधन कानून पर यथाशीघ्र दूध का दूध और पानी का पानी हो। यह तभी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जल्द सुनाने की व्यवस्था करे। उसे ऐसा इसलिए भी करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें विधानसभाओं में नागरिकता कानून विरोधी प्रस्ताव यह जानते हुए भी पारित कर रही हैं कि संसद से स्वीकृत कानून को लागू करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी संवैधानिक अराजकता पर लगाम लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला सुनाना चाहिए।

हाथी-मानव संघर्ष

राष्ट्रीय विरासत पशु हाथियों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे उत्तराखंड में गजराज और मानव के रिश्ते में खटास पैदा हो गई है। यमुना से लेकर शारदा नदी तक फैले हाथी परिक्षेत्र में हाथियों के बढ़ते हमले इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। विभागीय आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य गठन से अब तक हाथियों के हमलों में 169 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 175 घायल हुए हैं। 2019 में तो हाथियों ने 12 लोगों की जान ली। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी चिंताजनक हो चली है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलीफेंट डिवीजन की ओर से देहरादून में हुई दो दिवसीय कार्यशाला में भी मानव व हाथियों के रिश्तों में कड़वाहट पर चिंता जताई गई। कार्यशाला में हाथियों से रिश्ते सुधारने को मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया। साफ है कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के अन्य हाथी बहुल राज्यों में स्थिति ऐसी ही है। अब सवाल उठता है कि हाथी व मानव के रिश्तों में आई कटुता की वजह क्या है। तह में जाएं तो जंगलों में बढ़ता मानवीय दखल ही इसका मुख्य कारण है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां भी इसी वजह से हाथी बिदक रहे हैं और आबादी वाले क्षेत्रों में इनकी धमक बढ़ी है। एक दौर में उत्तराखंड के हाथी, बिहार तक स्वछंद विचरण करते थे।

उत्तराखंड में हाथियों और मानव के बीच टकराव थामने को हाथी गलियारों को निर्बाध करने के साथ ही गंभीरता के साथ दूसरे उपायों की दरकार है

इनकी आवाजाही के परंपरागत गलियारे निर्बाध थे। वक्त ने करवट बदली और फिर सिमटते चले गए गलियारे। आज स्थिति ये है कि गलियारे बाधित होने से हाथी दड़बों में सीमित होकर रह गए हैं। कहीं बीच जंगल से हाईवे व रेलवे लाइन गुजर रहे तो कहीं गलियारों में मानव बस्तियां उग आई हैं। ऐसे में एक से दूसरे जंगल में आने-जाने में हाथियों की राह मुश्किलों हो गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व इसका उदाहरण है, जहां हाथी गंगा नदी के एक छोर से दूसरी तरफ नहीं आ पाते। ऐसी ही हाल अन्य क्षेत्रों का भी है। हालांकि, राज्य में 11 हाथी गलियारे चिह्नित हैं, मगर ये बाधित हैं। ऐसे में हाथियों के व्यवहार में बदलाव से विशेषज्ञ इनकार नहीं कर रहे। यदि जल्द ही समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसे मानव व हाथी, दोनों के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा, सरकार और वन महकमे को प्रभावी कदम उठाने होंगे। हालांकि, इस राह में चुनौतियां हैं, मगर ऐसी नहीं कि इनसे पार न पाया जा सके। बस इसमें सफलता के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की दरकार होगी।

अमित शाह की बड़ी लकीर

प्रदीप सिंह

जेपी नड्डा के सामने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की ओर से खींची गई लकीर को बड़ा करने की नहीं, उसे बरकरार रखने की चुनौती है

अमित शाह, एक ऐसी शख्सियत जो पचास की उम्र से पहले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और साढ़े पांच साल में उसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। दुनिया के राजनीतिक इतिहास की यह बहुत बड़ी परिघटना है। चुनावी सफलता, संगठन विस्तार और पार्टी का भौगोलिक विस्तार सब कुछ साढ़े पांच सालों में। राजनीति में पद का मोह सबसे बड़ा होता है, पर 20 जनवरी को नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से ज्यादा खुश अमित शाह ही नजर आ रहे थे। राजनीति में ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं। इसकी तस्दीक उस समय मंच पर विराजमान चार दूसरे पूर्व अध्यक्षों से की जा सकती है। तो अमित शाह की खासियत क्या है? सहज, पर सरल नहीं, दूरदृष्टि पर बारीकियों पर नजर, जीत पर जश्न से परहेज नहीं और हार पर दुख से गुरेज नहीं। वैचारिक निष्ठा अडिग, ईमानदारी रणनीति नहीं स्वभाव है। आशावादी पर यथार्थ से गहारा नाता। सामाजिक समझ और संवेदनशीलता। सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें हमेशा पता होता है कि क्या करना है और क्यों करना है? साल 2013 में उत्तर प्रदेश का प्रभार मिलने से पहले उन्हें गुजरात से बाहर कम ही लोग जानते थे, पर 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी पहली बैठक में जब उन्होंने कहा कि मुझे सीट जिताने वाले नहीं बूथ जिताने वाले चाहिए तो वहां के नेताओं को जोर का झटका जोर से ही लगा। उसी दिन संगठन के लोगों को लग गया कि भाजपा बदलने वाली है।

शाह के साढ़े पांच साल के कार्यकाल का आकलन करते समय यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वह सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर दल और सरकार के बीच की महीन रेखा को बचाए रखना कठिन होता है। जो उन्होंने नहीं कहा कि वह यह कि 1998 से 2004 के बीच यह रेखा मिट गई थी। अमित शाह ने उस विभाजक रेखा को न केवल बनाए रखा, बल्कि और गाढ़ा किया। सत्ता में रहने वाले इससे सहमत होंगे कि सत्ता में रहते हुए पार्टी को बढ़ाना कितना कठिन होता है, क्योंकि दलों का विस्तार अमूमन आंदोलनों से होता है। दूसरी बात यह याद रखने की भी है कि अमित शाह को पार्टी किस हालत में मिली थी। पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश पिछले 65 साल से हो रही थी, पर नतीजे के नाम पर सिफर ही था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों का समर्थन सहयोग तब भी था, पर यह भी तो पता होना चाहिए कि समर्थन और सहयोग किस तरह कब और कहां लेना है?

संगठन में कार्यकर्ता अपने नेता की ओर देखता है। उसके आचार-व्यवहार और कामकाज के तरीके से तय करता है कि

अवधेश राजपूत

कितना काम करना है। जब नेता आराम पंसद हो जाए तो कार्यकर्ता को आराम तलब होने में देर नहीं लगती, पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ कार्यकर्ता के घर जाए, साथ बैठकर खाना खाए तो कार्यकर्ता की छाती चौड़ी हो जाती है। फिर वह काम करने नहीं जान देने को तैयार हो जाता है। शाह ने यही किया। वरना असम और त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा नंबर एक पार्टी नहीं बनती। जिस त्रिपुरा में कभी एक विधायक नहीं रहा वहां बहुमत की सरकार बन गई। जिस महाराष्ट्र में भाजपा चौथे और हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी थी वहां वह नंबर वन बनी। यह मामूली बात नहीं है कि यह स्थिति कायम रही।

जेपी नड्डा की ताजपोशी के वक्त मंच पर पार्टी के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी भी आसीन थे। उन्हें याद होगा कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद उन्होंने कहा कि था कि विचारधारा पर आधारित पार्टियों के विकास की एक सीमा होती है। भाजपा उस सीमा तक पहुंच गई है। इसके बाद ही तय हुआ कि पार्टी अपने कोर मुद्दों से समझौता करेगी। संघ भी इससे मन या बेमन से सहमत हो गया। सत्ता में आने के लिए पार्टी ने अपने तीन मुख्य मुद्दों अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद ही उसे सत्ता मिली। इसी के साथ भाजपा अपने वैचारिक मुद्दों पर बोलने की बजाय आडवाणी जी के शब्दों में छद्म धर्मनिरपेक्ष दल की तरह बोलने लगी। नतीजा यह हुआ कि विचारधारा में पगा भाजपा का कार्यकर्ता और संघ का स्वयंसेवक घर बैठ गया। उसका परिणाम 2004 और 2009 में दिखा।

इस पृष्ठभूमि में अपने कोर वैचारिक एजेंडे पर आक्रामक होकर पार्टी का विस्तार करके अमित शाह ने इस मिथक को तोड़ दिया। साढ़े पांच साल पहले उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला तो उन्होंने इस अवसर को चुनौती की तरह लिया। उन्होंने काम किया ही नहीं, करवाया भी। उन्होंने राजनीति में नैनो टेक्नालॉजी का इस्तेमाल कर लोगों को छोटी-छोटी जिम्मेदारियां सौंपी। काम सौंपकर निश्चिंत नहीं हो गए। उसकी बराबर निगरानी भी की। 2019 का आम चुनाव उनके लिए अग्निपरीक्षा जैसा था जिससे वे कुंदन की तरह तपकर निकले। उन्होंने पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। भारतीय राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं है कि सिर्फ साढ़े पांच साल में वंशवाद के बिना कोई नेता तैयार हो जाए।

अमित शाह के परिश्रम(प्रधानमंत्री के शब्दों में परिश्रम की पराकाष्ठा) निष्ठा, वैचारिक दृढ़ता, सहज बुद्धि और तीव्र गति से फैसला लेने की क्षमता के साथ-साथ मोदी की लोकप्रियता, अद्भुत संप्रेषणीयता और लोगों के विश्वास की पराकाष्ठा का योगदान कम नहीं है। अमित शाह के तप में मोदी का सहयोग प्राणवायु की तरह लगातार प्रवाहमान रहा। इस सबके बावजूद इच्छा, लक्ष्य और योजना को जमीन पर उतारने का काम अमित शाह ने किया। उनकी उम्र और राष्ट्रीय राजनीति में उनके अनुभव को देखते हुए यह उपलब्धि और बड़ी लगती है। समकालीन राजनीति में विरोधी पक्ष के नेताओं की क्षमता पर नजर डालें तो अमित शाह आपको महामानव नजर आएंगे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने कार्यकाल में इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसे बड़ा करना असंभव न हो तो भी बहुत कठिन तो है ही। हालांकि बड़ी लकीर तो उन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी खींच दी है, लेकिन उसकी बात फिर कभी। नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सामने इस लकीर को बड़ा करने की नहीं, उसे बरकरार रखने की चुनौती है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

बुरे नतीजों वाला बेजा विरोध

डॉ. सैयद रिजवान अहमद

सीएए-एनआरसी के विरोध में जो कुछ हो रहा है वह लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत से उपजी कुंठा भी है

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए उन अल्पसंख्यकों का एक अधूरा सपना है जो विभाजन के वक्त इस मुगालते के चलते पाकिस्तान में रह गए थे कि पाकिस्तान भले ही एक इस्लामिक मुल्क हो, लेकिन उसका संस्थापक यानी जिन्ना एक खुले और उदार विचारों वाला मुसलमान है। सीएए एक तरह से उस वचन की पूर्ति है जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यकों को दिया था कि यदि आपको कभी अपने फैसले पर पछतावा हो तो भारत के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। इसी वचन को वर्ष 2003 में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मनमोहन सिंह ने दोहराया भी था। यह भी ध्यान रहे कि 1951 में नेहरू-लियाकत समझौते के तहत दोनों राष्ट्रों ने अपने-अपने देशों में मजहबी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई थी। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त तक अल्पसंख्यकों को कुछ हद तक अधिकार मिले, लेकिन जनरल जिया उल हक का दौर आते-आते वहां वहाबी सोच हावी होने लगी थी। तब संगठित रूप से अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होने लगा। इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों पर पड़ा। उन्हें अगवा करना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना और फिर उनसे निकाह करना एक दस्तूर सा बन गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना तो, लेकिन जल्द ही जनरल इरशाद ने उसे इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके बाद वहां भी अल्पसंख्यकों का ऐसा उत्पीड़न हुआ कि 1971 में कुल आबादी में हिंदुओं की जो आबादी 20 प्रतिशत से अधिक थी वह घटकर 10 फीसद से कम रह गई। यदि पाक और बांग्लादेश ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अपने वादे निभाये होते तो शायद सीएए की जरूरत ही नहीं पड़ती।

मुस्लिम समाज के नेताओं-धर्मगुरुओं को यह सच स्वीकार करना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में वाकई अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ है। उन्हें ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध आदि भाई-बहनों का स्वागत करना चाहिए, साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह हिदायत देनी चाहिए कि इस्लामी राष्ट्र होते हुए भी वे अपने अल्पसंख्यकों के साथ प्यार से पेश आएं। मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने इसकी अनदेखी की और अभी भी कर रहे हैं। यदि सीएए का मामला मात्र

हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा होता तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आए नेपाली हिंदू, तिब्बत से आए बौद्ध और श्रीलंका से आए तमिल हिंदुओं को भी सीएए में प्राथमिकता से स्थान मिलता, जो कि नहीं मिला। यह इसलिए नहीं मिला, क्योंकि ये भारत से अलग होकर बने देश नहीं हैं।

सीएए को समझना और आसान होता यदि सरकार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई न लिखते हुए केवल पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक लिखती। मुसलमानों द्वारा जिस तरह सीएए का विरोध करना गैर जरूरी है उसी एनआरसी का विरोध भी। कुछ स्वयंभू सेक्युलर पार्टियां और नासमझ मुस्लिम नेताओं के चलते देश को इस अनावश्यक विरोध का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। असम के एनआरसी को राष्ट्रव्यापी एनआरसी से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं। उसकी परिस्थितियां और रूपरेखा वर्ष 1985 के असम समझौते और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थीं, क्योंकि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या जटिल थी। गृहमंत्री या सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने यह कभी नहीं कहा कि असम एनआरसी की तर्ज पर ही देश भर में 1971 से पहले के दस्तावेज मांगे जाएंगे। एनआरसी जैसी व्यवस्था तमाम देशों में अलग-अलग नामों से होती है। लोगों को भड़काने वाले दलों और नेताओं से यह पूछना चाहिए कि आपने इस पर दुष्प्रचार करके जनता को क्यों गुमराह किया? उन्हें कम से कम राष्ट्रव्यापी एनआरसी के खाके और शर्तों का इंतजार करना चाहिए था।

इस विरोध के चलते हताहत लोगों के खून के छींटे मौजूदा सरकार पर नहीं, बल्कि विपक्ष, मुस्लिम नेताओं के दामन पर लगे हैं। लगता है कि जब तक आम गरीब या मुसलमान का खून न बहे तब तक उनकी तकरीरों में वह जोश नहीं आता। सीएए-एनआरसी विरोध में जो कुछ देखने को मिल रहा है वह 2019 के आम चुनाव में भाजपा की सफलता से उपजी चिढ़ भी है। इसके साथ ही तीन तलाक, राम मंदिर, अनुच्छेद-370 का दबा गुबार भी उमड़ कर बाहर आया और जाने-अनजाने सामाजिक दृष्टि से 'कौम' का और नुकसान कर गया।

कोई चाहे संविधान के हर पन्ने पर धर्मनिरपेक्ष लिख दे, लेकिन जब तक किसी भी मुल्क का बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा तब तक वह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। पिछले 70 वर्षों के दौरान चाहे 1955 में समान नागरिक संहिता का विरोध हो, एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध हो, 1985 में शाहबानो के समय का विरोध हो, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर रहस्यमय चुप्पी हो, भाजपा के खिलाफ दिए गए मजहबी फतवे हों, अयोध्या विवाद को लेकर नाजायज जिद हो- इन सबके कारण भारत का बहुसंख्यक धीरे-धीरे एकतरफा धर्मनिरपेक्षता से दूर खिसकता जा रहा है। इसका खमियाजा मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है, यदि उन्होंने देश के बहुसंख्यकों के प्रति अपना अहंकार बरकरार रखा। जो तिरंगे आज लखनऊ और हैदराबाद की रैलियों में नजर आते हैं, यदि आज से 20-25 साल पहले भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान मुस्लिम मुहल्लों में दिखते या फिर कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न के समय दिखते तो शायद इतनी अधिक संख्या में तिरंगा उठाने का ढोंग असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों को नहीं करना पड़ता।

यह समय आत्मचिंतन करने का है कि क्यों देश के हिंदू-मुस्लिमों के बीच दरारें बढ़ती जा रही हैं। यदि 1955 में समान नागरिक संहिता न मानकर मुसलमानों ने इस दरार को बढ़ाना शुरू किया था तो अब उनकी नई पीढ़ी इस दरार को पाटने का काम शुरू करे। एकतरफा धर्मनिरपेक्षता अब देश में नहीं चलने वाली है।

(लेखक अधिवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सामाजिक समरसता

सामाजिक समरसता का भाव हमारी संस्कृति के मूल में है। यह हमारी धार्मिक एवं अन्य परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है, परंतु कालांतर में समरसता एवं सौहार्द के इस तानेबाने पर प्रहार हुए हैं। सामाजिक समरसता का तात्पर्य समाज में सभी जातियों एवं वर्गों के बीच सामंजस्य के भाव से है। इसमें ऊंच-नीच के संकीर्ण भाव को समाप्त करना है। जब समाज में सामाजिक समरसता का भाव पुष्पित पल्लवित होगा तभी राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

राष्ट्र की समग्र उन्नति के लिए सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता अत्यंत आवश्यक हैं। यहां तक कि जब भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी सामाजिक समरसता के भावों को बल प्रदान किया है। भगवान श्रीराम द्वारा शबरी के चखे बेरों को स्नेह के साथ चखना, केवट और निषादराज को सीने से लगा लेना, ये सभी दृष्टांत हमारे सामाजिक तानेबाने को मजबूत करने के लिए ही तो थे। जातियों एवं वर्गों के बीच द्वेष एवं श्रेष्ठता के भाव को समाप्त करने के लिए समय-समय पर महापुरुषों ने अनेकों कार्य किए हैं। तमाम महापुरुषों ने समरसता के लिए जीवन को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यही भाव ही भारतीय संस्कृति का मूल चिंतन रहा है। यह भाव जब तक अक्षुण्ण है, तभी तक भारतीय समाज निर्भय और सुरक्षित है।

सामाजिक समरसता को संरक्षित करने के लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए। वर्तमान दौर में इसकी आवश्यकता है। सभी वर्गों के बीच समरसता का भाव ही हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता को भी प्रगाढ़ करता है। हमारा चिंतन हमारे समाज को समरस बनाने के लिए होना चाहिए जिससे विघटनकारी ताकतों को समाप्त किया जा सके। वास्तव में यही हमारा शाश्वत एवं मौलिक चिंतन है। यह चिंतन खंडित न हो, विलुप्त न हो, इसके लिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है। यह इसलिए, क्योंकि आज समाज में अनेक ऐसी ताकतें हैं जो इस भाव को समाप्त करने पर तुली हैं।

ललित शौर्य

समझनी होगी ऊर्जा की महत्ता

सुधीर कुमार

ऊर्जा संसाधनों के साथ मानव समुदाय का अस्तित्व जुड़ा है। अतः इसके संरक्षण के लिए हमें हरपल सचेत रहना होगा

हाल में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2019 जारी किया है। यह सूचकांक 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता पहल की प्रगति के बारे में समीक्षात्मक जानकारी प्रदान करता है। ऊर्जा दक्षता के ताजे सूचकांक में हरियाणा ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का प्रयास प्रशंसनीय रहा है। ऊर्जा दक्षता से तात्पर्य ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपभोग तथा ऊर्जा संचालित उपकरणों पर नियंत्रण रखकर ऊर्जा की बचत करने से है। किसी देश की आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में ऊर्जा संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं-परंपरागत और गैर-परंपरागत। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हजारों वर्षों में तैयार होते हैं। चूंकि परंपरागत ऊर्जा के ये संसाधन धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए इसके अत्यधिक दोहन से ये बड़ी तेजी से समाप्त भी हो रहे हैं। अतः वक्त का तकाजा भी यही है कि ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर खुशहाल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जाए। यह सूचकांक राज्यों को ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण पर बल देने के लिए प्रेरित करता है।

बढ़ती जनसंख्या तथा उच्च आर्थिक विकास की आशा में एक तरफ ऊर्जा की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है तो दूसरी तरफ नागरिकों की लापरवाही से हो रही बर्बादी ने ऊर्जा संकट को अधिक विस्तार दिया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंधाधुंध इस्तेमाल और गैर-परंपरागत स्रोतों की ओर अन्वेषण की अरुचि आने वाले समय में देश के लिए चिंता का सबब बनने वाली है। यही वजह है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का सीमित उपभोग करने तथा उसे भावी पीढ़ी के लिए सहेजने के लिए आज ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। ऊर्जा का संरक्षण करने का मतलब जीवन का संरक्षण करना या कम से कम ऐसी चीजों का संरक्षण करना है, जिससे जीवन आगे बढ़ता है। जाहिर है, ऊर्जा संसाधनों के साथ मानव समुदाय का अस्तित्व जुड़ा है। अतः इसके संरक्षण के निमित्त हमें हरपल सचेत रहना होगा।

2015 के पेरिस जलवायु समझौते में भारत के प्रयास से 122 देशों का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में आगे आना तथा सौर ऊर्जा के विकास का सामूहिक संकल्प कई मायनों में खास रहा। दरअसल जलवायविक विविधता वाले भारत देश में ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों यथा-सौर, पवन, जल एवं भूतापीय ऊर्जा आदि के विकास की अपार संभावनाएं हैं। अगर इनका समुचित विकास होता है तो ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर दबाव निश्चित तौर पर कम होगा। इससे पर्यावरण भी सेहतमंद रहेगा। ऊर्जा संरक्षण खुशहाल भविष्य की अनिवार्य शर्त है। हालांकि जनभागीदारी के बिना इस लक्ष्य का हासिल करना कतई आसान नहीं होगा।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

सही तर्क

महेश जेठमलानी ने अपने लेख 'नागरिकता कानून की मनमानी व्याख्या' में तर्क एवं तथ्यों के साथ इस मांग को अनुपयुक्त सिद्ध किया है कि पाकिस्तानी अहमदियों और शियों को भी पीड़ित समुदाय मानकर नागरिकता कानून के अंतर्गत हिंदू-बौद्ध-जैन-सिख-ईसाई-पारसियों के समान नागरिकता प्रदान की जाए। उनका यह कहना इतिहास-सम्मत है कि इन दोनों समुदायों की भूमिका उक्त छह अल्पसंख्यक समाजों के लिए वैसी ही रही है, जैसी सुन्नियों की। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव (23 मार्च, 1940) के लेखक जफरूल्ला खान एक अहमदिया थे। यही नहीं संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत के खिलाफ जबरदस्त पैरवी भी उन्होंने ही की थी। कई साल विदेश मंत्री रहते उन्होंने हिंदुओं आदि के प्रति खूब घृणा का प्रचार किया। वास्तव में तो पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना ही एक शिया थे। 1934 से पूर्व वह इस्माइली आगाखानी खोजा थे। यह उपपंथ हिंदुओं की तरह दशावतार में यकीन करता था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1866 के फैसले में इसे हिंदू-मुस्लिम विश्वासों का मिश्रण बताया था। इसलिए जब 1934 में जिन्ना ने मुसलमानों को नेतृत्व देने की सोची तो उन्होंने शियों का अस्न-अशारी उपपंथ अपना लिया। किंतु उग्रवादी समाज का नेता बनने के लिए स्वयं और भी अधिक उग्रवादी तेवर दिखाने पढ़ते हैं, जैसा आज एक और कुछ शिया नेता कर रहे हैं। अतः जिन्ना अपने भाषणों में खूब आग उगलने लगे। अंततः जिन्ना ने अपना अभीष्ट पाकिस्तान पा लिया। उसके बाद 1948 के प्रारंभ में कराची में जो हिंदू-सिख आदि का नरसंहार हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी इस शिया नेता पर ही है। 16 अगस्त, 1946 को 'सीधी कार्रवाई' के नाम पर जिन्ना ने कलकत्ता से जो खूनी खेल शुरू किया था, उसने नोआखली एवं टिपरा मिलाकर एक लाख अल्पसंख्यकों के प्राण लील लिए थे। अब एक और शिया की चर्चा की जाए। ये हैं पाक के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, जिन्होंने हॉलैंड के परमाणु प्रतिष्ठान से नाभिकीय बम की विधि चुराई थी। ये आजीवन अहमदियों-शियों को गाली देते रहे, ताकि सुन्नी बहुसंख्यकों में लोकप्रिय रहें, पर जहां तक भारत का प्रश्न है, ये बेहद खतरनाक साबित हुए। इन्होंने शिया ईरान को अपना फॉर्मूला भारत-विरोधी हो जाने की शर्त पर दिया।

अजय मित्तल, मेरठ

युवा शक्ति के प्रणेता नेताजी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ये शब्द सटीक बैठते हैं कि, वो खुद ही जान लेते हैं, बुलंदी आसमानों की। परिंदों को दी नहीं जाती, तालीम उड़ानों की। नेताजी बोस के व्यक्तित्व पर उनकी माता प्रभावती, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थीं एवं उनके शिक्षक बेनी माधव प्रसाद का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। 23 जनवरी 1897 को कटक में पैदा हुए सुभाष चंद्र ने लंदन में आइसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी मेधा के झंडे गाड़ दिए। मातृभाषा के पक्षधर बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका मानना था कि बड़े-बड़े संकल्प युवाओं के त्याग से ही पूर्ण होते हैं। आज भारत के पास युवा शक्ति की उर्जा और ओजस्विता का अभूतपूर्व भंडार है, जिसे सही मार्गदर्शन, सही दिशा और सही बोध एवं विमर्श की आवश्यकता है। भारतीय युवा शक्ति अप्रतिम है, जिसमें साहस कूट-कूट कर भरा है। अगर उसे उसकी शक्ति याद दिला दी जाए तो भारत को विकसित होकर महाशक्ति बनते में देर नहीं लगेगी।

डॉ. मनोज कुमार शर्मा, स्याना

मंदी का प्रचार ज्यादा

दैनिक जागरण के 22 जनवरी के अंक में प्रकाशित विवेक कौल का लेख, भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यथा कथा, पढ़ा। उन्होंने गंभीर तरीके से अपनी बात कही जो सही भी है, परंतु आज बहुत से व्यापारी अपने आर्थिक अपराध को मंदी की आड़ में छिपा रहे हैं। जो भी व्यापारी मंदी में डूबने की कहानी फैला रहे हैं उन्होंने गाहे-बगाहे कोई न कोई आर्थिक अपराध जरूर किया होता है। ऐसे लोग अपनी कंपनी को लाभ कमाने के लिए कर्ज लेकर दूसरे देश में नए-नए कारोबार में नए निवेश कर मालामाल होने में लगे हुए हैं। यहां पर वे एक तरह से मंदी का खौफ ही फैला रहे हैं।

डॉ. सुमनवीर सिंह, पलवल

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र

25 हजार शोध हुए थे वर्ष 2014-15 में देश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी के अनुसार। वहीं 2018-19 में इनकी संख्या बढ़कर 41 हजार तक जा पहुंची है।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल

साहित्यिक मेले से बनती संस्कृति

अनंत विजय

आज अगर पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं या कह सकते हैं कि पूरे देश में जो एक साहित्य महोत्सवों की संस्कृति का विकास हुआ है तो उसके पीछे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सफलता ही है। लगभग सभी साहित्य उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर ही आयोजित होते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो देशभर में साहित्यिक संस्कृति को मजबूत करने में जेएलएफ ने पथप्रदर्शक वाली भूमिका निभाई है

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) एक ऐसा साहित्य महोत्सव है जो पूरी दुनिया के साहित्यप्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर वर्ष जनवरी के महीने में जयपुर के ऐतिहासिक डिग्गी पैलेस में आयोजित होनेवाले इस लिटरेचर फेस्टिवल में देश-विदेश के तमाम मशहूर लेखकों का जमावड़ा होता है जो साहित्य की विभिन्न विधाओं से लेकर राजनीति, खेल और सिनेमा लेखन की नई प्रवृत्तियों पर विमर्श करते हैं। जेएलएफ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखकों के अलावा दुनियाभर के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित लेखकों के विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। आज अगर देश के अलग-अलग हिस्सों में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं या कह सकते हैं कि पूरे देश में जो एक साहित्य महोत्सवों की संस्कृति का विकास हुआ है तो उसके पीछे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सफलता ही है। लगभग सभी साहित्य उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर ही आयोजित होते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो देशभर में साहित्यिक संस्कृति को मजबूत करने में जेएलएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी।

जेएलएफ का आयोजन 23 से 27 जनवरी तक हो रहा है। यह उनके आयोजन का तेरहवां साल है। तेरह वर्षों में जेएलएफ ने अपने आप को इतनी मजबूती से स्थापित कर लिया कि वह अब देश से निकलकर ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी आयोजित होने लगा है। 2008 में पहली बार जब इसका आयोजन हुआ था तो इसकी संकल्पना जयपुर विरासत फाउंडेशन के कर्ताधर्ताओं ने की थी। जयपुर विरासत फाउंडेशन ने राजस्थान की लोक संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। उस वक्त इससे जुड़ी मीता कपूर के मुताबिक 2008 के इंटरनेशनल हेरिटेज फेस्टिवल के तहत ही उसके खंड के रूप में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। 2008 में यह आयोजन तीन दिनों का था और दिग्गी पैलेस के एक ही हॉल में इसका आयोजन हुआ था। उस वर्ष भी नमिता गोखले जेएलएफ से एडवाइजर के तौर पर जुड़ी थीं। मीता कपूर बाद में इस आयोजन से अलग हो गईं, पर एक परंपरा जो उन्होंने पहले संस्करण में शुरू की थी उसका निर्वाह आज तक कर रही हैं। वह जेएलएफ में आने वाले सभी प्रतिभागियों और अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों को अपने घर पर शाम को दावत देती हैं। इस रात्रिभोज में परोसे जानेवाला खाना वह खुद बनाती हैं या उनकी देखरेख में राजस्थानी खाना तैयार किया जाता है।

जेएलएफ के आयोजन की संरचना इस तरह से की गई ताकि वह साहित्यप्रेमियों के अलावा अन्य लोगों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर सके। अलग-अलग भाषा के लेखकों के साथ-साथ सिनेमा और खेल के सितारों को हर संस्करण में नियमत रूप से आमंत्रित करने से भी इसको मजबूती मिली। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में फिल्म से जुड़े लोगों और फिल्मी सितारों को बुलाने को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। ऐसे सवाल सिर्फ जेएलएफ को लेकर ही नहीं उठे हैं, बल्कि दुनिया में जहां भी साहित्य महोत्सवों में फिल्मी सितारों को बुलाया जाता है वहां-वहां ऐसे सवाल खड़े होते रहे हैं। बेस्टसेलर उपन्यास चॉकलेट के ब्रिटिश लेखक जॉन हैरिस ने भी साहित्य महोत्सवों में फिल्मी सितारों को लेकर एक अलग ही तरह का प्रश्न उठाया था। उन्होंने कुछ वर्ष पहले कहा था कि 'कई लिटरेचर फेस्टिवल इन सितारों के चक्कर में लेखकों पर होनेवाले खर्चे में भारी कटौती करते हैं। आयोजकों को लगता है कि सितारों के आने से ही उनको हेडलाइन मिलेगी। उनका मानना था कि इससे आयोजकों को फायदा होता है, पर साहित्य नेपथ्य में चला जाता है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के साहित्यिक आयोजन तभी सफल हो सकते हैं जब इसमें शिरकत करनेवालों में सितारे भी हों, क्योंकि विज्ञापनदाता उनके ही नाम पर स्पांसरशिप देते हैं। विज्ञापनदाताओं की रणनीति होती है कि जितना बड़ा सितारा होगा उतनी बड़ी भीड़ जुटेगी और उनके उत्पाद का प्रचार बड़े उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचेगा, परंतु सवाल यही है कि क्या इस तरह के आयोजनों में साहित्य या साहित्यकारों पर पैसे को तरजीह दी जानी चाहिए। अगर उद्देश्य साहित्य पर गंभीर विमर्श है, अगर उद्देश्य पाठकों को साहित्य के प्रति संस्कारित करने का है तो उसके साथ-साथ इसमें सितारों को बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। गुलजार, जावेद अख्तर, शाबाना आजमी, प्रसून जोशी तो लगभग नियमित तौर पर ही इस आयोजन में आते रहे हैं। उनके अलावा काजोल, करन जौहर, सोमन कपूर, वहीदा रहमान जैसे कलाकार भी जेएलएफ की शान बढ़ा चुके हैं।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में विवादों की भी बड़ी भूमिका रही है। हालांकि इसकी फेस्टिवल डायरेक्टर नमिता गोखले हमेशा से कहती हैं कि उनका उद्देश्य इस आयोजन में किसी तरह के विवाद पैदा करना कभी भी नहीं रहा, पर 2012 में विवादित लेखक सलमान रश्दी के जेएलएफ में आने को लेकर भारी विवाद हुआ था। सलमान पर अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस में ईशनिंदा का आरोप है और उनके खिलाफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई ने जान से मारने का फतवा भी जारी किया था। सलमान रश्दी के विवाद के केंद्र में रहने की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस आयोजन की तरफ लोगों का ध्यान गया था। चार दिनों तक हुए विवाद के बाद आखिरकार सलमान को जयपुर आने की इजाजत नहीं मिली। मामला इतने पर ही नहीं रुका था। उस वक्त की गहलोत सरकार ने वीडियो लिंक के जरिये भी सलमान को सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद भी विवाद रुका नहीं था। सलमान रश्दी के नहीं आने और वीडियो लिंक से सत्र में जुड़ने की अनुमति नहीं मिलने के बाद लेखक जीत थाईल, रुचिर शर्मा और हरि कुंजरू ने सलमान रश्दी की विवादित किताब के अंश पढ़ दिए थे। उसके बाद जीत थाईल पर जयपुर और अजमेर में आठ केस दर्ज किए गए थे। उसके बाद के वर्षों में आशीष नंदी के एक बयान को लेकर आशुतोष की आपत्ति पर भारी विवाद हुआ था। यह विवाद भी काफी दिनों तक चला और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर वहां से निबटा। 2016 में फिल्मकार करण जौहर ने भी अपने बयान से छोटा ही सही, पर विवाद खड़ा किया था। जेएलएफ के आयोजन के पहले ही दिन करण जौहर ने लोकतंत्र को मजाक बता दिया था। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे बड़ा जोक है और लोकतंत्र तो उससे भी बड़ा मजाक है। करण के मुताबिक अगर आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो यह देश सबसे मुश्किल है। इसके अलावा तसलीमा नसरीन के वहां पहुंचने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनमोहन वैद्य के एक बयान को लेकर भी भारी विवाद हुआ था। इन विवादों ने जेएलएफ को चर्चित करने में अवश्य मदद की।

बहरहाल यहां गंभीर साहित्यिक विमर्श भी होते हैं जो पाठकों को संस्कारित करते हैं। राजनीति से लेकर अर्थशास्त्र और औपनिवेशिक संस्कृति के सवालों से भी विद्वान वक्ता मुठभेड़ करते हैं जो पाठकों को उन विषयों को सोचने-समझने की एक नई दृष्टि देते हैं। देश-दुनिया के पाठकों के लिए ये पांच दिन ऐसे होते हैं जिनमें हर तरह की रुचि के विषयों पर विमर्श होता है और पाठकों को भी उसमें हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होता है। पहले संस्करण में एक हॉल से शुरू हुए इस आयोजन में अब पांच स्थानों पर समांतर सत्र होते हैं और श्रोताओं के लिए विकल्प होता है कि वे किस विषय पर किस वक्ता को सुनना चाहते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पिछले तेरह सत्रों में अपने आयोजन के स्वरूप में भी लगातार बदलाव करता रहता है। इसमें सांगीतिक आयोजन जुड़े, जयपुर बुक मार्क के रूप में प्रकाशन जगत की हस्तियों को आपस में विचार विनिमय का एक मंच मिला, जहां पुस्तकों के प्रकाशन अधिकार से लेकर प्रकाशन जगत की समस्याओं पर विमर्श होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसे आयोजन के तौर पर स्थापित हो चुका है जहां गंभीर साहित्यिक विमर्श के अलावा वहां जानेवालों के मनोरंजन से लेकर शॉपिंग तक के अवसर उपलब्ध होते हैं।

खरी-खरी

बजट के पहले का हलवा!

अतुल कनक

बजट के पहले वित्त भवन में हर साल हलवा पकता है। इस हलवे को खाकर अधिकारी बजट पेश होने तक किसी ऐसे स्थान पर चले जाते हैं, जहां उनसे कोई संपर्क नहीं कर सकता। यह हलवा सिर्फ वित्त विभाग के अधिकारियों को मिलता है या मौके पर मौजूद दूसरे लोग भी भविष्य की संभावनाओं का प्रसाद मान ग्रहण कर सकते हैं, यह बात मुझे पता नहीं है। हालांकि अब तक तो देश का हलवा 'वित्त' वालों को ही खाते हुए देखा या पकड़ा गया है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि यह कितना अच्छा हुआ कि सर्दी का मौसम होने के बावजूद देश में बजट तैयार करने के पहले रेवड़ी बनाने और बांटने की परंपरा नहीं है। वरना कुछ आंदोलन तो देश में इस बात पर भी हो सकते थे कि रेवड़ी बांटकर सरकार केवल अपने लोगों का भला करना चाहती है।

हालांकि आंदोलन की संभावनाएं हलवे से भी पैदा होती हैं। कुछ लोगों को यह बहाना मिल सकता है कि जिम्मेदार लोगों को हलवा खिलाने के बाद सरकार गुप्त तरीके से अपनी खिचड़ी पकाती है। यों भी जब देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा दोनों समय भरपेट भोजन नहीं कर पाता हो तो बजट तैयार करने के पहले हलवा खाने और खिलाने की रस्म को गरीबों के खिलाफ साजिश बताया जा सकता है। फिर बजट में जो नए कर लगते हैं, वो तो आम आदमी चुकाता है। ऐसे में सरकार को यदि बजट के पहले हलवा ही खिलाना है तो लंगर लगाकर आम आदमी को खिलाया जाना चाहिए था। यह क्या बात हुई कि कुछ खास लोगों ने हलवा खा लिया और आम आदमी के हिस्से हलवे की कड़ाही के किराये का भुगतान आ गया?

फिर सवाल तो यह भी खड़ा किया जा सकता है कि बजट के पहले हलवा ही क्यों बनाया जाता है? कचौड़ी, साबूदाने की खिचड़ी या मसाला डोसा क्यों नहीं? हलवा बनवाने के पीछे सरकार की सामंती सोच है या वो एक खास संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है। भारत विविधता में एकता का देश है तो बजट के पहले खाना-पीना भी विविधताओं वाला होना चाहिए। किसी साल रसगुल्ला बनवा लिया, किसी साल लिट्टी-चोखा बनवा लिया तो किसी साल बाजरे की रोटी भी बनाई जा सकती है। बजट का संबंध यदि खाने-पीने से ही जोड़ना है तो सरकार को उत्तपम से लेकर ढोकला-बाटी तक विविध संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। हलवा जब परंपरा बन जाता है तो बहुतों को रायता लगने लगता है और व्यवहार में हो या मुहावरे में, रायते को फैलते ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे हलवे और रायते में बहुत रणनीतिक किस्म का संबंध है। जब कोई व्यक्ति हलवा खाने में नाकाम रहता है तो वह उसे रायता बनाकर फैला देता है।

हलवे में बड़ी मात्रा में घी भी डालना पड़ता है और कहते हैं कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। कुछ लोग चाहें तो इस बात को भी सरकार के विरोध का मुद्दा बना सकते हैं कि सरकार पशु-प्रवृत्ति की विरोधी है और घी का हलवा इसलिए बनवाती है, क्योंकि वह कुत्तों को हजम नहीं होता। अब सरकार केवल बिल्लियों या लोमड़ियों के ही लिए थोड़े है। वो तो कुत्तों, गधों, लकड़बग्घों...यहां तक कि इंसानों के लिए भी है। इसलिए उसे सबका ध्यान रखना चाहिए।

बहरहाल सरकार अपने हिस्से का हलवा खाकर बजट बनाने चली गई है। अब देखना यह है कि बजट के थैले से बाहर आते समय इस हलवे का असर आम आदमी को सुख का स्वाद देता है या वो एक बार फिर नए करों के बोझ तले नून-तेल-लकड़ी की चिंता में पड़ जाता है।

ट्वीट-ट्वीट

सीएए पर तत्काल रोक न लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई लोगों का मिजाज बिगाड़ेगा। यह शीर्ष अदालत का एक और निर्णय है जिसमें कपिल सिब्बल जैसे विपक्ष के महंगे वकीलों के बावजूद उनके खेमे को मुंह की खानी पड़ी है।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

मैं अनुपम खेर की विचारधारा का कभी समर्थन नहीं कर कर सकता, लेकिन मेरे आदर्श नसीरुद्दीन शाह ने उन पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा। हमारा देश इसीलिए महान है कि हम सभी के साथ विमर्श की गुंजाइश देते हैं। हम उदारवादी लोग हैं और हमें निजी हमलों से बचना चाहिए।
तहसीन पूनावाला@tehseenp

मुंबई की सबसे अहम मेट्रो रेल परियोजना की कमान संभाल रहीं आइएएस अधिकारी अश्विनी भिडे को हटाना पूरी तरह बदले की कार्रवाई है। आरे को लेकर आदित्य ठाकरे ने उन पर अपनी खीझ ही उतारी है। अब देखते हैं कि मुंबई की इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए भला कौन रहनुमा बन सकता है?
शेखर गुप्ता@ShekharGupta

भारतीय अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से हिचकोले खा रही है तब यह समय आइएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के लिए भी आत्मविश्लेषण का है कि उन्होंने बीते कुछ वर्षों में भारत को लेकर बढ़-चढ़कर अनुमान लगाए। वहीं नोटबंदी जैसे मामलों की अपेक्षित समीक्षा के बजाय उनकी वाहवाही ही करते रहे।
सुहासिनी हैदर@suhasinih

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से कश्मीर की स्थिति में सुधार होगा?

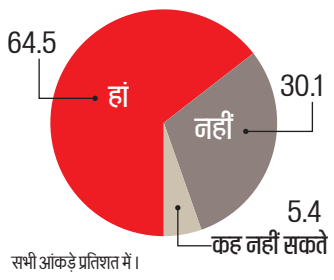

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर के अधिकार की समीक्षा की जानी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बांटो दोनों हाथ से हमें न बिल्कुल हर्ज,
लेकिन किसकी जेब पर जाएगा यह खर्च?
जाएगा यह खर्च जरा हमको समझाओ,
फिर वादे बरसाय वोट पर दांव लगाओ।
मूरख हमें बनाय मलाई अपना चाटो,
काट हमारी जेब 'मुफ्त में' हमको बांटो!
– ओमप्रकाश तिवारी

छत्तीसगढ़ डायरी

तो अब चल पड़ेंगे पग उसी ओर...!

आलोक मिश्रा
राज्य संपादक
नईदुनिया, छत्तीसगढ़

अगर कंक्रीट का बनाना हो तो एक शहर बनाना आसान है, लेकिन उसे बसाना वाकई चुनौती होती है। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर (नवा रायपुर या अब अटल नगर) के साथ कुछ ऐसा ही है। उसमें आकार लेती बेहतरीन बिल्डिंगें, अत्याधुनिक मंत्रालय, हरे-भरे किनारों वाली चौड़ी सड़कें बरबस आंखें रोक लेती हैं। व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन रहने को लोग तैयार नहीं हैं। आम तो आम, सरकारी भी वहां नहीं जाना चाहते। अब खुद मुख्य सचिव वहां रहने को कूच कर गए हैं तो थोड़ी उम्मीद जगी है कि शायद अब वहां के दिन बहुरें।

जब मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो चिंता थी कि राजधानी कहां बनाएं? बिलासपुर का भी नाम चला, पर मुहर लगी रायपुर पर। कसक फिर भी थी एक नई राजधानी बनाने की। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समय ही इस पर काम शुरू हो गया। सरकार बदली तो रमन के जमाने में इसे और पर लगे। आठ हजार हेक्टेयर में बसाने की योजना बनी, 40 सेक्टरों में बांटा गया। जिसमें रहने के लिए 21 सेक्टर बनाए गए। कैपिटल कांप्लेक्स, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस कांप्लेक्स इसके हृदय स्थल में रखे गए, जबकि औद्योगिक हब में ऐसे उद्योगों को जगह दी गई है जो प्रदूषण रहित हों। नया रायपुर का लगभग 39 फीसद हिस्सा हरियाली को समर्पित किया गया है। एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहां पूरी तरह आकार ले चुके हैं। एक ऐसा शहर बस रहा है, जो पूरी तरह से स्मार्ट है। हर आने वाले नाते-रिश्तेदार को जिस तरह दर्शनीय स्थल दिखाए जाते हैं, उसी तरह नया रायपुर भी दिखाया जाता है, लेकिन त्रासदी यही है कि अभी लोग वहां रहने को तैयार नहीं हैं।

इसके लिए अब भूपेश सरकार ने तय किया है कि राज्यपाल सहित सरकार वहीं रहेगी। पहले सरकार एवं सरकारी कर्मचारी वहां बसेंगे, तभी जनता को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। राज्यपाल भवन की डिजाइन अंतिम चरण में है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास तेजी से तैयार हो रहे हैं। मुख्य सचिव ने ठिकाना बसा ही दिया है इसलिए आशा दिखाई देने लगी है। लगता है कि अब मंत्रालय एवं विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर तो दबाव बनेगा ही, देखा-देखी और लोग भी जाने लगेंगे। मंशा तो बेहतर है, अब देखना यही है कि इसमें कितनी सफलता मिलती है?

तेजी से आकार लेता अटल नगर।

दिन न बदले जोगी के

दिन बहुरते हैं। सबके दिन बहुरते हैं। मध्यप्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अजीत जोगी के दिन बहुरे, उनके उतरे तो 15 साल रमन की चांदी रही। अब भूपेश बघेल के दिन हैं, लेकिन ये दिन जोगी को बहुते भारी पड़ रहे हैं। पिता-पुत्र दोनों की ही एक मुसीबत दूर नहीं होती, दूसरी सिर चढ़ कर बोलने लगती है। आजकल एक नई मुसीबत से वे दो-चार हैं। उनके बिलासपुर स्थित बंगले में काम करने वाले एक नौकर ने आत्महत्या कर ली। पिता अजीत जोगी और पुत्र अमित जोगी दोनों ने ही संवेदना व्यक्त की और परिवार के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया, लेकिन घर वालों ने उन पर उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। घर वालों का आरोप है कि मरने से एक दिन पहले उन्होंने चोरी का आरोप लगा उसे काफी जलील किया था। इसी कारण उसने जान दी। इम मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज करने में तेजी दिखाई। जोगी, सरकार को कोस रहे हैं कि बदले की भावना के तहत उन पर केस दर्ज करवाया गया है। वे इसकी न्यायिक या सीबीआइ से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जोगी के आरोप में सरकार की सफाई है कि कानून के तहत कार्रवाई की गई है। अगर वे पाक-साफ हैं तो डर काहे का। बहरहाल जोगी पके खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि ऐसी सरकारी भाषा का अर्थ क्या होता है? पार्टी की जो गत है सो है ही... जाति मामला, अंतागढ़ टेप कांड जैसे मामले दिक्कत किए ही थे अब यह एक और मामला सिर पर आ मढ़ा। अब वे फिर अपने दिन बहुरने के इंतजार में हैं कि ग्रह अनुकूल हो तो बात बनें।

उच्च शिक्षा

शोध की गुणवत्ता का प्रश्न

पीयूष द्विवेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

शोध केवल एक डिग्री प्राप्ति का उपक्रम भर नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा देश और समाज को दिशा देने का काम भी किया जाता है

किसी भी देश की उच्च शिक्षा में शोध का विशेष महत्व होता है। कहीं न कहीं इसी से अमुक देश की उच्च शिक्षा की स्थिति का पता भी चलता है, लेकिन इस मामले में भारत की स्थिति चिंताजनक है। यह चिंता शोध की मात्रा को लेकर नहीं है, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध की मात्रा में कोई कमी नहीं है, बल्कि उसमें तो लगातार वृद्धि ही हो रही है, लेकिन जब प्रश्न शोध की गुणवत्ता और उपयोगिता का आता है तो स्थिति चिंताजनक लगने लगती है। देश में शोध की मात्रा में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जिसके अनुसार वर्ष 2014-15 में देश के विश्वविद्यालयों में जहां कुल 25 हजार शोध हुए थे, वहीं 2018-19 में इनकी संख्या बढ़कर 41 हजार तक जा पहुंची है।

शोध की इस मात्रा-वृद्धि के पीछे के कारणों को समझने का प्रयत्न करें तो इसकी एक प्रमुख वजह इंटरनेट के प्रसार से बीते कुछ वर्षों के दौरान हुई देशव्यापी सूचना क्रांति प्रतीत होती है, क्योंकि इन दोनों का कालखंड लगभग समानांतर ही है। 2014 के बाद से ही इंटरनेट का प्रसार देश में बढ़ने लगा था। सो प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इंटरनेट के द्वारा हर प्रकार की सूचनाओं की सुलभता ने छात्रों के मन में शोध की कठिनाइयों का एक सीमा तक सरलीकरण करने का काम किया है, जिस कारण इसके प्रति उनमें रुझान बढ़ा है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह प्रश्न यथावत है कि क्या मात्रा के अनुरूप शोध की गुणवत्ता और उपयोगिता में भी कोई वृद्धि हुई है? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही है।

इस स्थिति को देखते हुए ही यूजीसी अब ऐसे दिशानिर्देश तैयार करने में जुटा है, जिसके जरिये शोध की गुणवत्ता ही नहीं, उसकी उपयोगिता भी सुनिश्चित की जा सके। इसके जरिये सरकार की कोशिश देश में होने वाले ऐसे तमाम शोधों, जो समाज या उद्योग के हितों की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते और केवल शैक्षिक दिखावे के लिए हो रहे हैं, पर लगाम लगाने की है। अतः यूजीसी जिन नए दिशानिर्देशों को बना रहा है, उनके तहत किसी भी नए शोध को मंजूरी दिलाने के लिए उसे सामाजिक और औद्योगिक उपयोगिता की कसौटी पर खरा सिद्ध होना होगा। जाहिर है इस पहल के जरिये सरकार का प्रयास सही और योग्य छात्रों को अवसर देकर शोध की गुणवत्ता और उपयोगिता में सुधार लाना तो है ही, साथ ही शोध क्षेत्र से संबंधित संसाधनों का अनुचित लाभ लेने वाले दिखावे के शोधार्थियों पर अंकुश लगाना भी है। सरकार का मानना है कि किसी भी शोध का मूल उद्देश्य समाज और आम जनजीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान का मार्ग दिखाना होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो भारत में होने वाले अधिकांश शोध इस कसौटी पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते।

आइआइटी आदि संस्थानों के कुछ शोधों को अपवाद मान लें तो ऐसा न के बराबर ही सुनने में आता है कि देश के किसी शैक्षिक संस्थान में समाज एवं आम आदमी के जीवन की किसी समस्या का समाधान करने वाला कोई शोध हुआ है। देश की पत्र-पत्रिकाओं में भी अक्सर येल, ऑक्सफोर्ड आदि अनेक विदेशी शैक्षिक संस्थानों में हुए विविध शोधों की खबरें दिखती रहती हैं, लेकिन क्या यह सवाल कभी आपके मन में उठा है कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय के शोध की खबर क्यों नहीं दिखाई देती? ये बातें भारतीय विश्वविद्यालयी शोध की गुणवत्ता की वस्तुस्थिति का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं।

वस्तुतः यह समस्या ऐसी है जिसमें किसी एक व्यक्ति, संस्था या कारण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नीति-निर्धारकों की समस्या यह है कि वे छात्रों के प्रति दोष-दृष्टि तो रखते हैं, परंतु व्यवस्था की विसंगतियों पर नजर नहीं डालते। यह नहीं देखते कि विश्वविद्यालय के जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्र शोध करते हैं, वे कितने योग्य हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षकों की अयोग्यता की बातें जब-तब सामने आती रही हैं जो विश्वविद्यालयी शिक्षण एवं शोध से जुड़ी एक बड़ी समस्या है।

दूसरी तरफ छात्रों पर यह आरोप लगता है कि वे शोध के लिए मिलने वाली अनुदान राशि का उपयोग पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह तथा रोजगार खोजने के लिए करते हैं और जैसे ही अच्छा रोजगार मिलता है, शोध को अधूरा छोड़ निकल जाते हैं या फिर जैसे-तैसे पूरा कर लेते हैं। चूंकि शोध करते वक्त छात्र की उम्र पारिवारिक दायित्व उठाने वाली हो जाती है, अतः यदि वह प्राप्त अनुदान राशि का कुछ उपयोग इस रूप में करता है तो गलत नहीं है, लेकिन यदि कोई छात्र शोध अधूरा छोड़कर, अपने विषय से अलग किसी अन्य क्षेत्र में कोई रोजगार प्राप्त कर चला जाता है तो इसे नैतिक रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे छात्रों से अनुदान राशि वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।

इन सबसे अलग शोध की गुणवत्ता में कमी का एक प्रमुख कारण इसके प्रति शोधार्थियों की अगंभीर मानसिकता है। चूंकि स्नातकोत्तर के बाद पीएचडी रोजगार के लिए आवश्यक है, इसलिए बहुत-से छात्र बेमन से भी शोध में संलग्न होते हैं और शोध ग्रंथ की गुणवत्ता से इतर इस प्रयत्न में रहते हैं कि किसी भी तरह शोधकार्य पूरा हो और डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाए। कई बार शिक्षकों की अयोग्यता भी इसमें सहयोगी भूमिका निभाती है। फिर अलग-अलग शोधों और इंटरनेट से लंबी-लंबी नकल उतार लेने से लेकर पैसे देकर थीसिस लिखवाने जैसे कृत्य तक किए जाते हैं। हालांकि शोधकार्य में नकल रोकने के लिए यूजीसी ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं और सॉफ्टवेयर भी लाया गया है, लेकिन शोध के प्रति छात्रों में अगंभीरता और बेपरवाही की मानसिकता तथा शिक्षकों में योग्यता का अभाव जब तक खत्म नहीं होता, इन सब चीजों से बहुत लाभ की उम्मीद बेमानी है।

छात्रों को समझना चाहिए कि शोध केवल एक डिग्री प्राप्ति का उपक्रम भर नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा देश और समाज को दिशा देने का काम भी किया जाता है। अतः यदि शोधकार्य में हाथ डालते हैं तो उसे पूरे मनोयोग से, अपना एक लक्ष्य बनाकर करें। इस प्रकार से किया गया शोध न केवल व्यक्तिगत रूप से उनके लिए, बल्कि देश-समाज के लिए भी हितकारी होगा।

19,434 टेक्नीशियन देशभर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में मौजूद हैं, जबकि जरूरत 31,367 की है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 23 जनवरी 2020

पंजाब

भूजल की चिंता

एक सेटेलाइट सर्वे से पंजाब में भूजल की जो तस्वीर सामने आई है वह चिंताजनक है। इस तस्वीर ने यह भी साबित कर दिया है कि यदाकदा भूजल की चिंता करने से बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए ठोस योजना बनानी होगी और उसे चरणबद्ध तरीके से धरातल पर भी उतारना होगा, तभी सुधार की कुछ उम्मीद की जा सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश में भूजल की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं थी और इसे लेकर योजनाएं भी बनाई गईं, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ। आज हालत यह है कि प्रदेश के 110 ब्लॉक डॉर्क जोन में जा चुके हैं और नौ जिलों के 18 ब्लॉकों में तो ट्यूबवेल लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

विशेषज्ञों ने तो यहां तक चिंता जताई है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो 2037 तक पंजाब रेगिस्तान में बदल जाएगा। किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली और इसके चलते ट्यूबवेल से भूजल के बड़ी मात्रा में दोहन को यदि गिरते भूजल का सबसे बड़ा कारण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में घटता वन क्षेत्र और भूजल रीचार्ज होने की कोई पुख्ता व्यवस्था न होना भी इस समस्या को बढ़ाने का काम कर रहा है। यह अच्छी बात है कि प्रदेश सरकार इसे लेकर गंभीर है और उसने वॉटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार 23 जनवरी को सर्वदलीय बैठक भी करने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक में भूजल बचाने के लिए कोई कारगर योजना सामने आएगी। विपक्षी दलों को भी चाहिए कि वे सियासत से ऊपर उठकर इस मामले में सरकार को उचित सलाह दें।

विपक्षी दलों को भी चाहिए कि वे सरकार को उचित सलाह दें। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी भूजल बचाने की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

प्रदेश के सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी भूजल बचाने की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रदेश के अन्नदाताओं की ही है। उन्हें यह समझना होगा कि यदि हालात इसी तेजी से खराब होते रहे तो बहुत जल्द ट्यूबवेल से भी पानी खींचना कठिन हो जाएगा। जल को ही जीवन कहा गया है, इसलिए यह सबकी जिम्मेदारी है कि इसे बचाने के लिए गंभीरता दिखाएं।

भूजल के अति दोहन ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। दरअसल भूजल का उपयोग बैंक में जमापूंजी की तरह किया जाना चाहिए। अगर बैंक से जमा धन से अधिक धनराशि आहरित होगी तो क्या होगा? चेक सीधे-सीधे बाउंस हो जाएगा। इसी प्रकार धरती के अंदर जितना जल संरक्षित हो, उसी हिसाब से ही निकासी होनी चाहिए। वर्तमान में भूमि के अंदर जल तो कम संग्रहित हो रहा है और विभिन्न माध्यमों से इसकी निकासी अधिक हो रही है। जिस प्रकार टंकी से पानी निकाले जाने पर उसका स्तर कम होता जाता है ठीक उसी प्रकार अति-दोहन से भूजल-स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। भूजल के अत्यधिक दोहन या दुरुपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अति-दोहन के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में कमी तो हो ही रही है साथ ही इससे उथले कुओं के सूख जाने की परेशानी भी उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा इससे भूजल में समुद्री जल के प्रवेश से यह खारा हो रहा है तथा प्रदूषणकारी तत्वों के कारण यह जल दूषित भी हो रहा है।

झारखंड

कड़ा संदेश देना जरूरी

बीते दिनों पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी थाना क्षेत्र में पत्थलगड़ी समर्थकों ने पत्थलगड़ी का विरोध करने वाले सात लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में गुलीकेरा ग्राम पंचायत के उपमुखिया जेम्स बढ़ भी शामिल हैं। हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के बाद शवों को पास के जंगल में फेंक दिया था। गांव के दो अन्य लोग भी गायब हैं, जिनकी भी हत्या की आशंका जताई जा रही है। हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में उनकी सरकार ने फैसला लिया कि पत्थलगड़ी समर्थकों पर लगाए गए देशद्रोह के मुकदमे खत्म किए जाएंगे। माना गया कि पूर्व की सरकार ने गलत तरीके से इन लोगों पर मुकदमा किया था। फैसले के बाद ऐसे लोगों से मुकदमा वापस लिए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा इस घटना के बाद सरकार का क्या रुख होता है।

बहरहाल इस घटना ने यह संदेश दिया है कि आनेवाले दिनों में हेमंत सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। बेशक राज्य की नई सरकार ने साफ मन और पवित्र भाव से हालात को सामान्य बनाने के लिए मुकदमा वापसी का फैसला लिया है। इसका कतई मतलब यह नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग को अपने मन की करने की छूट मिल जाए। पत्थलगड़ी के पक्ष या विपक्ष में तर्क-वितर्क दिए जा सकते हैं। दिए भी जाने चाहिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक तो किसी को नहीं है। इस लिहाज से पश्चिमी सिंहभूम की इस घटना की न सिर्फ तीखे शब्दों में निंदा-भर्त्सना होनी चाहिए, बल्कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों का पता गलाकर सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रतीकात्मक फोटो

पश्चिम सिंहभूम में सात पत्थलगड़ी विरोधियों की हत्या शर्मनाक घटना है। इसके जिम्मेदार लोगों का पता गलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसके साथ ही इस बात की भी गहराई से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं आदिवासियों की पत्थलगड़ी से जुड़ी परंपरा की आड़ में निहित स्वार्थी तत्व अपनी स्वार्थ सिद्धि की गहरी साजिश तो नहीं रच रहे। यदि ऐसा है तो यह राज्य के लोगों के लिए किसी भी नजरिये से ठीक नहीं है। ऐसे तत्व की मंशा को नाकाम करने के लिए जरूरी कदम समय रहते उठाने होंगे। जागरूकता अभियान इस काम में सबसे कारगर हथियार हो सकता है, क्योंकि भोले-भाले आदिवासियों को पत्थलगड़ी के नाम पर गुमराह करने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। जनता को जागरूक करने में प्रशासनिक मशीनरी की तो भूमिका अहम है ही, राजनीतिक दलों और प्रबुद्ध वर्ग को भी महती भूमिका निभानी होगी।

आदिवासियों की परंपरा का पूरा सम्मान करते हुए यह देखा जाना चाहिए कि विकास के रास्ते से उन्हें भटकाने के लिए कोई दूसरा खेल न किया जा सके। इलाके विशेष को वर्जित क्षेत्र में तब्दील कर वहां किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि नहीं होने देने पर भी खासतौर से गौर करना होगा। जिन इलाकों में पत्थलगड़ी की गूंज है वहां की धरती रत्नगर्भा है। वहां की मिट्टी में अफीम जैसी फसल पैदा करने की भी क्षमता है। अवैध खनन की भी काफी गुंजाइश है। लिहाजा सभी पहलुओं पर बारीक नजर रखते हुए सतर्कता के साथ समस्या के समाधान की राह तलाशी जाए। रास्ता ऐसा निकले जिससे जनभावना को बनाए रखते हुए कानून का राज भी बना रहे।

बंगाल

सीएए के खिलाफ प्रस्ताव के निहितार्थ

पिछले डेढ़ माह से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ मुखर हैं। इससे पहले वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर आंदोलन कर रही थीं, परंतु जैसे ही सीएए लागू करने की घोषणा हुई वह सड़क पर उतर आईं। एक दर्जन से अधिक पदयात्राएं कीं, रैली एवं सभाएं आयोजित कीं। धरना शुरू कराया, परंतु उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा था कि वह सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराएंगी। यही नहीं जब पिछले विशेष सत्र में वाममोर्चा एवं कांग्रेस की ओर से केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद मांग की गई कि बंगाल विधानसभा में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया जाए तो तृणमूल सरकार ने ठुकरा दिया था और तर्क दिया था कि एनआरसी के खिलाफ पहले ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है।

परंतु अचानक सोमवार को कोलकाता से दार्जिलिंग के दौरे पर जाते समय एयरपोर्ट पर ममता ने घोषणा कर दी कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

इसके अगले ही दिन मंगलवार को बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने 27 जनवरी को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का एलान कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि अचानक आखिर इस तरह प्रस्ताव पारित होने के निहितार्थ क्या हैं? आखिर ममता सरकार की क्या मजबूरी हो गई कि वह वाममोर्चा एवं कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई और प्रस्ताव पारित करने को राजी हो गई? सीएए के खिलाफ जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई थी तो उसमें ममता नहीं गईं, परंतु अब प्रस्ताव पारित कर साथ होने के संकेत क्यों दे रही हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या आगामी निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर ममता ने यह कदम उठाया है? क्योंकि सीएए के खिलाफ कौन सी पार्टी कितना अधिक मुखर और सक्रिय है इसका श्रेय लेने की होड़ मची है।

माना जा रहा है कि शायद इस श्रेय में माकपा एवं कांग्रेस से वह पीछे न हो जाए, क्योंकि वाम शासित केरल और कांग्रेस शासित पंजाब विधानसभा में पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है। तृणमूल के अंदर भी सांसद सौगत राय जैसे दिग्गज नेता ने यह मांग उठा दी थी। यही वजह जान पड़ती है कि ममता को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने को मजबूर होना पड़ा है। खैर इस प्रस्ताव से हासिल क्या होगा यह तो कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं कानून के बड़े जानकार कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद स्पष्ट कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर

सीमा पर खेल का जोश

मोदी सरकार का आउटरीच कार्यक्रम विकास को बढ़ावा देने के साथ सीमांत क्षेत्र के युवाओं में खेलों के प्रति जोश भी जगा गया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू का पाकिस्तान की गोलाबारी का सामना करने वाले आरएसपुरा के चकरोई में युवाओं को खेल का सामना बांटने की पहल सराहनीय है। सीमांत क्षेत्रों के युवा दमखम रखते हैं, लेकिन वहां पर खेल सुविधाओं की कमी के कारण वह आगे नहीं आ सकते हैं। ऐसे हालात में केंद्रीय मंत्री ने चकरोई में खेल के सामान के साठ किट बांट कर युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया। खेल किटों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड आदि हैं।

जम्मू क्षेत्र में सीमा से सटे इलाकों के युवा क्षेत्र की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे अपनी ताकत सही दिशा में संचालित करें, इसके लिए उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करना समय की मांग है। जम्मू के सीमावर्ती प्लांवाला से जम्मू-कश्मीर के कई वॉलीबॉल खिलाड़ी सामने आए हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि बढ़ावा देने पर ग्रामीण इलाकों में खिलाड़ियों की अच्छी टीमें बन सकती हैं। विशेषतौर पर सीमा के चुनौतीपूर्ण हालात में पले-बढ़े युवा शारीरिक रूप से सशक्त हैं। यही कारण है कि वे सेना, सुरक्षाबलों की भर्ती में सबसे आगे रहते हैं। अब उन्हें खेल सामान देकर उनका हौसला बढ़ाया गया है।

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सीमा से सटे इलाकों के युवा अपनी ताकत सही दिशा में संचालित करें, इसके लिए उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करना समय की मांग है।

पाकिस्तान की गोलाबारी के साए में रहने वाले लोगों की आय के साधन सीमित हैं। अधिकतर परिवार खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में ये परिवार उनके बच्चों को खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने के बार में सोच भी नहीं सकते हैं। सीमा के चुनौतीपूर्ण हालात में सीमांत क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना भी संभव नहीं हो सका है। ऐसे में खेलो इंडिया मुहिम को प्रोत्साहन के लिए दिए गए खेल उपकरण इस सीमांत क्षेत्र के बच्चों को दिशा देंगे। ग्रामीण इलाकों में भी खिलाड़ियों की टीमें बनने से न सिर्फ फिट रहने के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा, अपितु उन्हें खेल के क्षेत्र में प्रतिभा दिखाने के लिए भी बेहतर अवसर मिलेगा। अगर ग्रामीण इलाकों में प्रतिभा को निखारा जाए जो खेल का स्तर बढ़ना तय है।

ऐसे में केंद्र सरकार की इस पहल को जम्मू-कश्मीर के अन्य ग्रामीण इलाकों में भी दोहराए जाने की जरूरत है। शहरों में खेलने के लिए अधिक साधन हैं एवं बुनियादी ढांचा भी बेहतर है। ग्रामीण इलाकों के हालात ठीक इसके विपरीत हैं। ऐसे में प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे खेल विभाग, खेल परिषद आदि को भी शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों को भी पूरा ध्यान देना चाहिए। नई पीढ़ी दिशाहीन न हो, इसके लिए भी जरूरी है कि उन्हें खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाए।

जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा है। आतंकवाद के चलते वहां उद्योग धंधे चौपट हुए ही शिक्षा और खेल जगत की स्थिति भी चिंताजनक हो गई। इससे सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ी। उनकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हुई। इससे उन्हें रोजगार मिलने में समस्या हो रही है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में आने के लिए भी उन्हें सही माहौल नहीं मिल पाया। उम्मीद है 370 के हटने और जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने से इस स्थिति में सुधार होगा।

झारखंड के खूंटी में ताक पर कानून वाट्सएप पर आता आका का निर्देश

जागरण टीम, खूंटी

- ग्रामीणों का रिमोट किसी और के हाथ में, उकसाया जा रहा है सरकार और प्रशासन के खिलाफ

झारखंड में खूंटी जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोग दूर बैठे लोगों के नियंत्रण में हैं। पत्थलगड़ी की ही तर्ज पर आदिवासी भारत और कुटुंब परिवार का प्रचार अब वाट्सएप के माध्यम से तेजी से फैलाया जा रहा है। भोले-भाले ग्रामीणों के मन में वाट्सएप से नियंत्रित करने वाले लोग अपनी बातें समझा रहे हैं और सरकार व प्रशासन के खिलाफ उकसा रहे हैं। वाट्सएप पर ही ग्रामीणों को सारा दिशानिर्देश मिलता है। चौंकाने वाली बात यह भी कि इलाका भले पिछड़ा हो, मगर यहां के युवा स्मार्टफोन से लैस नजर आते हैं। यहां कोई भी बाहरी व्यक्ति आए उसकी फोटो ली जाती है। पहचान पत्र की फोटो लेकर उसे वाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया। एसी नाम से वाट्सएप ग्रुप ऐसे ग्रामीणों में प्रचलित है। एसी का मतलब वे आदिकाल, आदि मानव और आदिवासी भारत बताते हैं। अगर आप उनसे पूछताछ कर कुछ कागज पर नोट भी करते हैं तो वे उसका फोटो खींचकर अपने आका को वाट्सएप करते हैं और वहां से दिशानिर्देश मिलने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं। बहरहाल, यह जांच का विषय है कि इन्हें कौन गाइड कर रहा।

गुरुवार को होती है बैठक, गांव का मसला गांव में ही सुलझा लेते हैं : पत्थलगड़ी और कुटुंब परिवार प्रभावित गांवों का मामला थाने नहीं पहुंचता है। उन्हें थाना-पुलिस व प्रशासन की जरूरत नहीं। न सरकार की जरूरत है और न ही सरकारी व्यवस्था उन्हें चाहिए। गांवों में प्रत्येक गुरुवार को सुबह छह बजे से आठ बजे तक बैठक होती है। बैठक में एक सप्ताह के भीतर होने वाली छोटी-बड़ी घटनाओं की समीक्षा होती है। जैसे किसी की फसल कोई जानवर चर गया, किसी के साथ कोई गालीगलौज कर दिया, किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई। इन सभी समस्याओं को वे गुरुवार की बैठक में निपटाते हैं। इसमें कोई नेता नहीं होता, बल्कि गांव के लोग ही मौजूद होते हैं और मिलजुलकर समस्या का समाधान करते हैं।

अपने अंदाज में व्याख्या : खूंटी के पोसेया तेलाईडीह व मरंगहादा के गुडुबुरू गांव के इस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने भी सरकारी दस्तावेजों की व्याख्या अपने अंदाज में की। आधार कार्ड को जहां बाहरी लोगों व आम लोगों का प्रमाण पत्र बताया, वहीं राशन कार्ड को गरीबी का प्रमाण बताया। खुद को राजा, आदि काल का वंशज बताते हुए सरकार की किसी भी व्यवस्था को मानने से सीधे इन्कार किया।

गाड़ी खरीदनी हो या मोबाइल लेना हो, पहचान पत्र नहीं देते : ग्रामीणों ने पूछताछ में बताया कि उनकी आय का जरिया भी उनकी अपनी खेती है। उन्हें गाड़ी खरीदनी हो या मोबाइल, वे पहचान पत्र नहीं देते हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी पहचान बताने की क्या जरूरत है। वे नन ज्यूडिशियल (गैर न्यायिक) स्टांप पर अपना ब्योरा देते हैं और मोबाइल, गाड़ी आदि खरीदते हैं।

किस प्रमाण पत्र के बारे में क्या है ग्रामीणों का विचार

आधार कार्ड : आधार कार्ड मतलब आम आदमी का अधिकार। यह कार्ड बाहरी व आम लोगों के लिए है। ये ग्रामीण आदि काल से हैं और राजा हैं। इसलिए इनके सेवादार (डीसी-एसपी) इनका आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं।

राशन कार्ड : राशन कार्ड गरीबी का प्रतीक है। राशन कार्ड की उसको जरूरत है, जो भूमिहीन है। ग्रामीण तो जमींदार व राजा हैं, इसलिए उन्हें ऐसे कार्ड की क्या आवश्यकता है। इसकी उन्हें जरूरत नहीं।

मतदाता पहचान पत्र : यह पहचान पत्र बाहरी लोगों के लिए है। बाहरी लोगों को इसकी जरूरत है। आदिवासी राजा मतदान क्यों करेगा। जो खुद नेता, राजा हो वह दूसरे को क्यों चुनेगा।

जॉन हैरिस ने कहा, कहानियां, जादू का सबसे अच्छा प्रकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता : मशहूर अंग्रेजी लेखिका और बेस्टसेलर उपन्यास चॉकलेट की रचनाकार जॉन हैरिस का मानना है कि कहानियां एक बेहतरीन जादू हैं, जिसे पाकर और उस अनुभव का हिस्सा बनकर बहुत खुशी मिलती है। बुधवार को कोलकाता में छह दिवसीय टाटा स्टील लिटररी मीट का उद्घाटन करते हुए हैरिस ने कहा कि जैसे जादू में चीजों को बदलने की शक्ति है, उसी प्रकार कहानियां उस जादुई अनुभव को फिर से बना सकती है। चॉकलेट के अलावा बेस्टसेलर उपन्यास रहे द लॉलीपॉप शूज, पीचेज फॉर फादर फ्रांसिस और द स्ट्रॉबेरी थीफ की लेखिका हैरिस ने कहा कि जब से चॉकलेट बेस्टसेलर बना है उसके बाद से उन्हें पाठकों के हजारों पत्र प्राप्त हुए हैं। हैरिस ने कहा, मुझे नहीं पता था कि कहानियों ने उनको (पाठकों) कैसे प्रभावित किया, लेकिन निश्चित रूप से हर किसी ने खुद के कुछ हिस्से को पहचाना और मेरी कहानी के साथ उनका जुड़ाव हुआ। चॉकलेट के बेस्टसेलर बनने के बाद के अनुभव को याद करते हुए हैरिस ने कहा कि वह बहुत आश्चर्यचकित व पाठकों के प्रति कृतज्ञ हुईं जब उनका शीर्षक कई देशों में हिट हुआ। हैरिस ने कहा कि मेरी मां एक फ्रांसीसी महिला थीं और मेरे पिता एक अंग्रेज थे। दोनों शिक्षक थे और उन्हें किताबें बहुत पंसद थीं। उन्होंने कहा कि हमारे घर में ज्यादा फर्नीचर नहीं था, लेकिन कई किताबें थीं।

अच्छी सेहत का सागर, बहुरंगी हुई गाजर

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी

- भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की देन
- पांच प्रजाति की विकसित, अप्रैल से बाजार में उपलब्ध होगी काली गाजर
- प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण, देश के कई हिस्सों में ट्रायल सफल

जल्द ही आपकी थाली में लाल, काले, पीले, नारंगी ही नहीं बहुरंगी गाजर दिखेगी। इन गाजरों के विभिन्न रंगों के जूस, हलवा, सब्जी का भी आप स्वाद ले सकेंगे। यह गाजर आकर्षक तो होंगी ही, औषधीय गुणों से भी संपन्न होगी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आइआइवीआर) ने आठ साल की मेहनत के बाद लाल, काली, पीली, नारंगी व बहुरंगी गाजर की प्रजाति विकसित की है। काली गाजर अप्रैल से ही बाजार उपलब्ध हो जाएगी। वहीं पीली, नारंगी व बहुरंगी गाजर दो-तीन साल में व्यावसायिक उपयोग में आ सकेंगी। सभी प्रजातियों का देश के कई हिस्सों में ट्रायल हो चुका है।

जैव रसायन प्रचुर, फायदे भरपूर: सभी प्रजाति की गाजर में खनिज तत्व पोटैशियम, कैल्शियम, लौह, मैगनीज प्रचुर मात्रा में हैं। लाइकोपिन, बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन व एंथोसायनिनि जैसे जैव रसायन की मौजूदगी के कारण एंटी-ऑक्सीडेंट व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। गाजर त्वचा को कोमल, आकर्षक बनाने में भी सहयोग करती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है। नियमित सेवन से रतौंधी, हृदय रोग, धूप से होने वाली त्वचा की समस्या से बचाव करेगी। इसमें मौजूद खाद्य-रेशे कब्ज से बचाने के साथ ही कोलेस्ट्राल, उच्च-रक्तदाब को नियंत्रित करेंगे और हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने काली, लाल, नारंगी, पीली और बहुरंगी गाजर विकसित की है। सौजन्य : भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान

लाल गाजर सब्जी, सूप, जूस, हलवा और आचार, काला गाजर से जूस, ड्रिंक व हलवा, नारंगी गाजर सलाद व कैंडी तथा पीला गाजर सूप बनाने के लिए उपयुक्त है। इसका व्यावसायिक उपयोग किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा।

-डॉ. जगदीश सिंह, निदेशक, आइआइवीआर

श्रीकृष्ण संस्कृति पर तैयार होगा ग्रंथ शोध करेगा वृंदावन का संस्थान

विपिन पाराशर, मथुरा : नटवरनागर यानी ब्रज के कन्हैया जितने व्यापक और विविध हैं उतनी ही उनसे जुड़ी कथा, संगीत और भक्ति के रूप हैं। हर राज्य में यह अलग रंग में दिखती हैं। इन्हें एक जगह सहजने का काम पहली बार वृंदावन स्थित वृंदावन शोध संस्थान कर रहा है। अगले पांच साल में विभिन्न राज्यों के अलावा कई देशों से इन्हें एकत्रित कर 'युग-युगीन श्रीकृष्ण व्याप्ति और संदर्भ' नाम के ग्रंथ में सहेजा जाएगा। यह ग्रंथ कई खंडों में होगा।

केरल के त्रिशूर से इसकी शुरुआत की गई है। यहां 19 से 21 जनवरी तक सेमिनार कर ऐसे शोध पत्र एकत्रित किए गए। इनमें मूर्तिकला परंपरा, श्रीकृष्ण मंदिरों में सेवा पद्धति, भक्ति के प्रसार में जगद्गुरु शंकराचार्य का योगदान, वैष्णव संत, मलयालम कविता में श्रीकृष्ण, कांस्य कला में श्रीकृष्ण, ब्रजभाषा के संदर्भ, कथककली और कृष्णाट्टम की परंपरा में श्रीकृष्ण, भित्ति चित्रकला तथा लोक संस्कृति में श्रीकृष्ण के अनेक पक्ष शोधार्थियों ने सामने रखे।

- केरल से हाल ही में की गई इसकी शुरुआत, युग-युगीन श्रीकृष्ण व्याप्ति और संदर्भ में होगा संकलन

श्रीकृष्ण की व्याप्ति से जुड़े सभी संदर्भों को एक पटल पर लाने के लिए संस्थान में संग्रहित तीस हजार पांडुलिपियों तथा देवालयी दस्तावेजों का सर्वेक्षण हो रहा है। देश के अन्य ग्रंथागारों और निजी संग्रहों से भी डिजिटल सामग्री एकत्र की जा रही है। संगोष्ठियां भी आयोजित की जा रही हैं। इन्हें एक पटल पर संकलित किया जा रहा है।

-आरडी पालीवाल, शोध संस्थान अध्यक्ष, वृंदावन।

दक्षिण भारत में श्रीकृष्ण की संस्कृति से जुड़े ऐसे संदर्भ सामने आए हैं, जो केरल और ब्रज के समन्वय की गाथा गा रहे हैं। भागवत में भी कहा गया है कि भक्ति दक्षिण से वृंदावन पहुंची। इन सभी को सहेजा जाएगा। पांच साल में यह काम खत्म कर लिया जाएगा।

-राजेश शर्मा, वृंदावन शोध संस्थान के शोध एवं प्रकाशन अधिकारी

ऑनलाइन सुविधाएं देने में हरियाणा अव्वल अंत्योदय सरल परियोजना को 'गोल्ड अवार्ड'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- सात फरवरी से मुंबई में होने वाले 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में मिलेगा अवार्ड
- प्रदेश में अंत्योदय सरल पोर्टल के जरिये आ रहे 70 लाख से अधिक आवेदन

अंत्योदय सरल परियोजना को 'नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता' की श्रेणी में 'गोल्ड अवार्ड' के लिए चुना गया है। मुंबई में सात से आठ फरवरी तक केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार (डीएआर एंड पीजी) द्वारा आयोजित किए जाने वाले 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में यह अवार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है कि राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण हेतु कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस तंत्र लगाने की प्रक्रियाओं को और बेहतर किया जाएगा।

प्रतीकात्मक

मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की विशाल आइटी क्षमता ने राज्य को देश में एक प्रमुख साइबर हब के रूप में उभरने में मदद की है। राज्य ने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को ई-नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक वर्ष हरियाणा में लगभग एक करोड़ आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं जिनमें से अंत्योदय सरल मंच के माध्यम से 70 लाख से अधिक आवेदन मिलते हैं। अंत्योदय सरल हेल्पलाइन के माध्यम से हर महीने योजनाओं और सेवाओं के बारे में एक लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जाता है। आवेदनों की स्थिति की जानकारी देने के लिए हर महीने लोगों को 15 लाख से अधिक एसएमएस भेजे जाते हैं। हर महीने नागरिकों को किए गए फीडबैक कॉल के माध्यम से औसतन विभागों को नागरिक संतुष्टि के लिए 5 में से 4.3 की रेटिंग मिली है।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि पिछले दो वर्षों में हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 के तहत अधिसूचित समय अवधि के भीतर अपने आवेदनों की 88.2 फीसद डिलीवरी की है।

पंजाब की सड़कों से हटेंगे 15 साल पुराने डीजल ऑटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों से बदलेगी सरकार, रियायती दरों पर मिलेगा लोन

पंजाब में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 15 साल से पुराने डीजल वाले तिपहिया वाहनों (ऑटो) को इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों से बदलने का फैसला किया है। यह फैसला सरकार के 'मिशन तंदुरुस्त पंजाब' के तहत लिया गया है। मिशन के निदेशक काहन सिंह पन्नू ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में 15 साल से पुराने तिपहिया वाहन चल रहे हैं, जबकि पंजाब मोटर व्हीकल एक्ट-1989 के नियम 68सी के मुताबिक कोई भी तिपहिया वाहन या ऑटो रिक्शा 15 साल से अधिक नहीं चलाया जा सकता। सभी बड़े शहरों के डिप्टी कमिश्नरों को पुराने तिपहिया वाहन खत्म करने या इन वाहनों के मालिकों को इन्हें गैस व इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के आदेश दिए हैं।

इच्छुक वाहन चालकों की मदद के लिए सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नर एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जिले की ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट विभाग और जिले के अग्रणी बैंकों के अधिकारियों की कमेटी गठित बनाएंगे।

20 से 25 हजार रुपये देगी सरकार

पन्नू ने बताया कि कुछ बड़ी इलेक्ट्रिक व सीएनजी आधारित ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने पुराने तिपहिया वाहनों को नए वाहनों से बदलने के लिए 20 से 25 हजार रुपये देने का प्रस्ताव दिया है। ये कंपनियां इन पुराने वाहनों को भट्ठियों में पिघला कर खत्म कर देंगी। पुराने वाहनों को नए वाहनों में बदलने के लिए मुद्रा योजना या सरकार की किसी अन्य योजना के तहत रियायती दरों पर बैंक लोन दिया जाएगा। ऐसे आवेदकों की सुविधा के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कैंप भी लगाएगा।

तंत्र के गण

उत्सव गणतंत्र का...

15 जून 2005 को सूचना का अधिकार यानी राईट टू इन्फॉरमेशन अधिनियमित किया गया और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र नागरिकों के लिए अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार 2005 का उद्देश्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।

70 साल के आरटीआइ एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल के संघर्ष के बाद तय हुआ–

आरटीआइ के दायरे में सीजेआइ

91 में पिता के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे से शुरू हुआ संघर्ष आज भी जारी

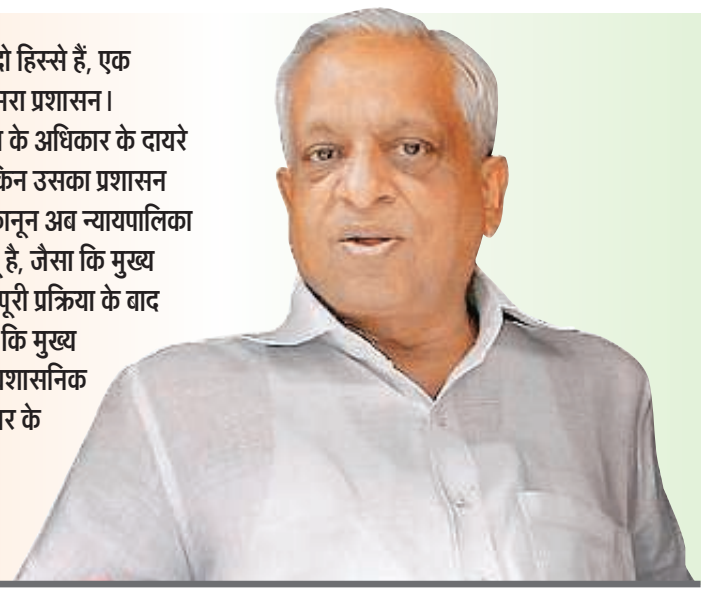

न्यायिक व्यवस्था के दो हिस्से हैं, एक न्यायपालिका और दूसरा प्रशासन। न्यायपालिका पहले भी सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं थी और न अब है, लेकिन उसका प्रशासन अब इसके दायरे में है। यह कानून अब न्यायपालिका के प्रशासनिक अमले में लागू है, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकारा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यह बात एकदम साफ हो गई कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी प्रशासनिक मकसद से सूचना के अधिकार के अधीन है...।

सुभाष चंद्र अग्रवाल, आरटीआइ कार्यकर्ता

विनीत त्रिपाठी ● नई दिल्ली

जीवन का संघर्ष इंसान को हर कदम ताकतवर बनाने के साथ ही हक के लिए आत्मबल के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल की। पिता के खिलाफ दर्ज कराए गए एक झूठे मुकदमे के खिलाफ अदालतों में गुजरे 16 साल के संघर्ष ने उनमें हक के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया।

न्यायिक प्रणाली से मिली पीड़ा से क्षुब्ध सुभाष ने इसके खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी। आखिरकार उन्हें इसमें तब सफलता मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) का कार्यालय भी आरटीआइ के अधीन आता है। जीवन के संघर्षों के बीच सुभाषचंद्र का सफर जारी है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक और फिर मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले सुभाषचंद्र आइएएस बनना चाहते थे, लेकिन परिवार के दवाब के कारण वह पारिवारिक व्यवसाय से ही जुड़ गए।

70 वर्षीय सुभाषचंद्र बताते हैं कि व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर उनका यह संघर्ष पिता के खिलाफ दर्ज हुए एक झूठे मुकदमे के विरुद्ध लड़ाई से शुरू हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक निवासी सुभाषचंद्र के चाचा ने वर्ष 1991 में संपत्ति को लेकर उनके पिता पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। सुभाष के चाचा के दामाद का दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायमूर्ति से करीबी संबंध था। सुभाष चंद्र बताते हैं कि इसी कारण से उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। तीन जनवरी 2005 को सुभाष चंद्र ने संबंधित न्यायमूर्ति के खिलाफ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यवस्था से हताश सुभाष चंद्र को सूचना का अधिकार-2005 के बारे में पता चला। उन्होंने अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट में सूचना के अधिकार के तहत पूछा कि न्यायमूर्ति के खिलाफ उनके द्वारा की गई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इसका जवाब नहीं मिला।

बताते हैं, हालांकि शिकायत की एक प्रति मैंने राष्ट्रपति को भी भेज दी थी। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। इसके बाद कोर्ट ने पहली बार माना कि मेरा वह मामला सूचना के अधिकार के तहत आता है। अखबारों में ये प्रकरण सुर्खियां बना तो वर्ष 2006 में दबाव में आकर सुभाष के चाचा ने उनके परिवार से समझौता कर लिया था। वह कहते हैं, व्यक्तिगत संघर्ष ने अब तक मुझे मानसिक तौर पर और मजबूत करने के साथ ही संघर्ष करने का एक नया हौसला दे दिया था।

क्या सीजेआइ को सभी न्यायमूर्ति अपनी संपत्ति का ब्योरा देते हैं?

सुभाष चंद्र ने नवंबर 2007 में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या सीजेआइ को सभी न्यायमूर्ति अपनी संपत्ति का ब्योरा देते हैं? जब वहां से उन्हें जवाब नहीं मिला तो उन्होंने केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआइसी) के पास अपील दायर की। सीआइसी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार विभाग को कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआइ के अधीन है और इस आधार पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार विभाग ने दी चुनौती

सीआइसी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार विभाग ने जनवरी 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआइसी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय भी सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसे सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार विभाग ने नवंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

13 नवंबर 2019 को आया बड़ा फैसला

मामले की सुनवाई के लिए गठित की गई संवैधानिक पीठ ने 13 नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी आरटीआइ के अधीन आता है। इसके अलावा सुभाष ने राजनीतिक पार्टियों को आरटीआइ के दायरे में लाने में भी अहम भूमिका निभाई। साथ ही उनके द्वारा आरटीआइ में मांगी गई जानकारी के बाद कई घोटाले से लेकर अहम जानकारियां बाहर आईं।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम

वर्ष 1967 से देश के बड़े अखबारों में तीन श्रेणियों में संपादक के नाम पत्र लिखने वाले सुभाष चंद्र अग्रवाल के नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। संपादक के नाम 1,226 पत्र लिखने पर 31 जनवरी 2002 को गिनीज बुक में यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अब तक संपादक के नाम 3,599 से अधिक पत्र लिख चुके सुभाषचंद्र के नाम पर सबसे अधिक संख्या में संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होने का गिनीज रिकॉर्ड भी है। वहीं एक श्रेणी में संपादक के नाम पत्र लिखने वाली उनकी पत्नी मधु अग्रवाल का नाम भी वर्ष 2004 में गिनीज बुक में शामिल हुआ।

नागरिक अधिकारों के सशक्तीकरण की राह

सुभाष चंद्र अग्रवाल ने एक अखबार को पहला पत्र दिल्ली परिवहन निगम के बस कंडक्टर के बारे में लिखा था। इसमें उन्होंने इस बात का रहस्योद्घाटन किया था कि बस कंडक्टर टिकट के बिना यात्रियों से पैसे वसूल कर रहा है।

सुभाष ने रेल मंत्रालय के सामने ताज एक्सप्रेस ट्रेन के अनियमित समय के बारे में भी आवाज उठाई।

अबतक अखबारों को 3700 से ज्यादा पत्र लिखे हैं, कई प्रकाशित भी हुए। सिलसिला जारी।

राजनीतिक पार्टियों को आरटीआइ के दायरे में लाने में भी अग्रवाल की अहम भूमिका थी।

जिराफ हीरो पुरस्कार से भी सम्मनित

अमेरिकी स्वयंसेवी संगठन जिराफ हीरोज प्रोजेक्ट ने 22 जनवरी 2015 को सुभाष चंद्र अग्रवाल को जिराफ हीरो पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया। अग्रवाल को यह पुरस्कार असंख्य चुनौतियों का सामना करते हुए सार्वजनिक भलाई के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रयोग करने के लिए प्रदान किया गया था। जिराफ हीरोज प्रोजेक्ट एक गैर लाभकारी संस्थान है जो जोखिम उठाने वाले अनजान लोगों, जिनमें दुनिया के आम लोगों के लिए जोखिम उठाने का साहस है, उन्हें सम्मानित करता है।

मजदूरी छोड़ शहर में चला रहीं 'पंचायत कैफे'

केके शर्मा ● रतलाम

गरिमा का अधिकार

खेती और मजदूरी के लिए उन्होंने गाहे बगाहे ही गांव से बाहर कदम रखा और समाज ने उन्हें अब तक इसी सीमा में बांध रखा था। इनके घूंघट पर मत जाइए, ये सम्मान का पर्दा है। घर-परिवार, समाज-प्रशासन ने जरा सा भरोसा जताया और उन पांचों ने मिलकर कैफे शुरू कर दिखाया। सुबह किराना लाने से लेकर शाम तक सैकड़ों ग्राहकों के लिए चाय-काफी, नाश्ते का इंतजाम सबकुछ वे मिलकर करती हैं। शाम को कैफे बंद करने से पहले पक्का हिसाब-किताब भी बही खाते में दर्ज कर लेती हैं। अब कुशल व्यवसायी बन चुकी हैं ये ग्रामीण महिलाएं। यह है रतलाम की पंचायत कैफे। महिलाओं का जीवन स्तर उठाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत शुरू किया गया यह नवाचार चंद दिनों में ही लोकप्रिय हो उठा है। रतलाम के जिला पंचायत कार्यालय परिसर में पांच ग्रामीण महिलाओं द्वारा शुरू की गई इस 'पंचायत कैफे' को पांच महिलाएं मिलकर चला रही हैं। कैफे चलाने की जिम्मेदारी गांव के दो अलग-अलग महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई है। जिला पंचायत ने महिलाओं को एक लाख 60 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है।

कैंटीन का काम संभालतीं समूह की महिलाएं। ● नईदुनिया

राजू बाई के पास हाथों का हुनर तो सुशीला का पास हिसाब-किताब

करमदी आजीविका संगठन की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिला सदस्यों को बुलाकर प्रशासन ने जब पूछा तो सभी कैफे चलाने के लिए तैयार हो गईं। जिनमें एक समूह की तीन तो दूसरे समूह की दो महिलाएं शामिल हैं। 28 साल की लक्ष्मी आठवीं पास हैं। वह अपनी तीन व छह साल की बेटी को सास के पास छोड़कर आती हैं। 45 वर्षीय कला और 42 वर्षीय लीला मकवाना पांचवीं तक पढ़ी-लिखी हैं। 45 वर्षीय राजूबाई पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन हाथों के हुनर से रसोई संभाल रखी है। 22 वर्षीय सुशीला मकवाना 12वीं पास हैं, इसलिए हिसाब-किताब का जिम्मा इनके कंधों पर है। सभी सुबह साढ़े आठ बजे घर से निकलती हैं। गांव से जिला पंचायत कार्यालय की दूरी लगभग तीन किमी है। रास्ते में उस दिन का किराना लेते हुए सुबह 9 बजे तक कैफे पहुंचती हैं। फिर शाम साढ़े पांच बजे तक काम-काज कर घर लौटती हैं। एक जनवरी से शुरू हुए इस पंचायत कैफे में चाय, पोहा, कचौरी, काफी, पूड़ी सब्जी सहित अन्य स्वल्पाहार भी मिलते हैं। टिफिन सेंटर भी शुरू कर दिया गया है। सुशीला बताती हैं कि रोजाना 75-100 ग्राहक आते हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ बाहर के लोग भी कैफे में आने लगे हैं।

रोजगार ही नहीं, समाज में पहचान भी दिलाई

कामकाजी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ऐसे समूहों का गठन किया गया है। रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला समूहों के माध्यम से महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिलाया जा रहा है बल्कि समाज में उनकी पहचान भी बनाए जाने का लक्ष्य है।

संदीप केरकेट्टा, सीईओ जिला पंचायत, रतलाम

तिकड़ी से हारा भ्रष्ट तंत्र, कुलपति भी पहुंचे सींखचों के पीछे

चैतन्य सोनी ● सागर

सागर के डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के साथ ही यहां साल 2012-13 में प्रोफेसर से लेकर तमाम स्तर के पदों पर भर्तियों में सारे नियम ताक पर रख दिए गए। 189 पदों पर भर्तियां की गईं। इनमें भाई-भतीजावाद से लेकर भारी भ्रष्टाचार, बिना योग्यता के भर्तियां, बिना विज्ञापित पदों के प्रोफेसर, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां कर ली गई थीं। सागर के व्हिसिल ब्लोअर्स की तिकड़ी ने इस मामले को आरटीआई के माध्यम से उजागर किया था। मामला राष्ट्रपति, एमएचआरडी, सीएजी और सीबीआइ तक पहुंचाया गया। नतीजा, सीबीआइ ने छापेमारी कर मामले की पड़ताल के बाद 10 एफआइआर कीं। सागर का डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां के प्रथम कुलपति को भी सीबीआइ ने सींखचों के पीछे घसीटा है, वे फिलहाल जमानत पर हैं।

डॉ. अनिल पुरोहित

दीपक गुप्ता

अरविंद भट्ट

आरटीआइ एक्टिविस्ट और व्हिसिल ब्लोअर डॉ. अनिल पुरोहित, दीपक गुप्ता और अरविंद भट्ट की तिकड़ी ने डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में साल 2010 से 2013 के बीच में की गई भर्तियों में गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। अनिल पुरोहित ने मई 2013 में आरटीआइ लगाई थी। उन्हें 50 हजार रुपये से अधिक राशि खर्च करने के बाद इसकी जानकारी मिल सकी थी। इस तिकड़ी ने एक के बाद एक आरटीआइ लगाईं और कागजों के अंदर से भ्रष्टाचार के खेल को बाहर निकाला। सीबीआइ को शपथ-पत्र पर शिकायत की गई। इसमें बताया गया कि साल 2010 में विवि में प्रोफेसर, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 89 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थीं, जबकि इसके विरुद्ध 157 पदों पर भर्तियां कर ली गईं। विवि में हुई कुल 189 पदों पर भर्तियों में उन विभागों में भी वरिष्ठ शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई, जिनमें कोई पद ही विज्ञापित नहीं किया गया था। इसमें पत्रकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, इकोनॉमिक्स विभाग, हिस्ट्री, फिलॉसफी विभाग शामिल थे। डॉ. अनिल पुरोहित, दीपक गुप्ता और अरविंद भट्ट ने आरटीआइ के तहत निकाली गई जानकारी को एकत्रित कर विवि प्रशासन, भर्ती कमेटी और तत्कालीन कुलपति डॉ. एनएस गजभिये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीबीआइ ने अक्टूबर 2013 में सागर विश्वविद्यालय में छापेमारी शुरू कर दस्तावेज जब्त किए, पड़ताल प्रारंभ की तो भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने लगीं। सीबीआइ दर्जनों दफा सागर आई और छापेमारी करते हुए जांच-पड़ताल की।

इसमें केंद्रीय विवि के कुलपति से लेकर भर्ती कमेटी, नियुक्ति कमेटी से लेकर तमाम अधिकारी लपेटे में आते गए। मई 2014 में पहली एफआइआर दर्ज की गई। उसके बाद कुल 10 एफआइआर दर्ज की गईं। मामले में कुलपति को सीबीआइ मुख्यालय भी तलब किया गया, वे जेल भी गए। फिलहाल जमानत पर हैं। आरटीआइ एक्टिविस्टों की तिकड़ी की मेहनत के बाद सीबीआइ के अलावा राष्ट्रपति स्तर तक हुई शिकायत के बाद इसे पिटीशन मानते हुए जांच समिति गठित की गई थी।

112वें स्थान पर थे, अब हैं देश में नंबर वन

अबूझमाड़िया मिक्स आचार तैयार कर पैकिंग करतीं ग्राम गुरिया के समूह की महिलाएं। ● नईदुनिया

मो. इमरान खान ● नारायणपुर

नक्सल घटनाओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नारायणपुर जिले की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के बाद इसने ऐसी छलांग लगाई कि वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के क्षेत्र में देश के आकांक्षी जिलों की सूची में 112वें पायदान से सीधे नंबर वन पर पहुंच गया। जिसे देश के पिछड़े जिलों में शामिल किया था, प्रधानमंत्री ने उसकी उपलब्धियां देख यहां के जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई है। यह कमाल संभव हो पाया कलेक्टर के संकल्प, प्रयासों और प्रशासन की जुझारू टीम की बदौलत।

समता का अधिकार

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को यह गौरव यूं ही नहीं मिला। जमीन से आसमान की बुलंदियां छूने के लिए दिन-रात काम हुआ। कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि एक लाख 39 हजार की आबादी वाले इस जिले में एक लाख 52 हजार खाते खोले गए हैं। गांव के 15 से 29 साल तक के अशिक्षित युवाओं को गांवों में ही शिविर लगाकर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे तीन हजार से अधिक युवक-युवतियों को रोजगार मिला। बैंकों से बेहतर तालमेल कर करीब चार सौ युवाओं को मुद्रा लोन योजना के तहत पांच करोड़ 36 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना और जनधन योजना के तहत बेहतर कार्य कर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। इंटरनेट की सुविधाओं का विस्तार करते हुए 44 पंचायतों को हाईटेक बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम किया गया। खेल-खेल में अध्यापन कराने से बच्चों की क्षमता में वृद्धि हुई। नक्सलियों का दंश झेलकर मुख्यालय में शरण लेने वाली आदिवासी महिलाओं और युवतियों को बिहान योजना के तहत स्वसहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आदिम जनजाति को प्रोत्साहित करने के लिए अबूझमाड़ की महिलाओं और युवतियों को साबुन, खिलौने, चूड़ी, सिलाई, कंपोस्ट खाद, बांस के आभूषण, फर्नीचर, ट्री गार्ड, झाड़ू आदि बनाने के साथ ही सीमेंट और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। राजमिस्त्री का काम भी सिखाया गया है। आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।

शिक्षक से प्रशासनिक मुखिया बनने वाले एल्मा ने बताया कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दिलाने को बैंक अकाउंट खोलने, मनरेगा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बैंक खाते, पीडीएस, गैस कनेक्शन, स्कूल-कॉलेज के छात्र- छात्राओं के अकाउंट और आधार सीडिंग करने लोक सेवा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जनसुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कर्मचारी आदि का बैंकों के जरिए बीमा कराया जा रहा है। मल्टी जिम, लेडीज ब्यूटी पॉर्लर, बेकरी, मिनी राइस मिल, होटल व्यवसाय, शॉपिंग सेंटर, सुपर मार्केट, मल्टी कलर प्रिंटिंग प्रेस, छोटे लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण केंद्र से कोदो, कुटकी, कोसरा से चावल बनाकर पैकेजिंग कर मार्केटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि तरक्की की यह रफ्तार अब थमेगी नहीं।

आरटीआइ को हथियार बना अमर हो गए अभिमन्यु

रोषनाथ राय ● भुवनेश्वर (ओडिशा)

देश को दीमक की तरह खोखला करते भ्रष्टाचार पर लोकतांत्रिक तरीके से वार करने के क्रम में अपनी जान गंवा देने वाले अमर सेनानी हैं- अभिमन्यु पांडा। ओडिशा के आदिवासी बहुल कंधमाल जिले के सामान्य परिवार से आने वाले इस लाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) को हथियार बनाया। भ्रष्टाचार के कई केस उजागर किए। माफिया के लोभ-लालच के बावजूद जब नहीं झुके तो हत्या कर दी गई। पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग अब भी जारी है। इसके वाहक बन गए हैं उनके कई दोस्त।

अभिमन्यु पांडा के दोस्त प्रदीप प्रधान भी उन्हीं की तरह सक्रिय आरटीआइ कार्यकर्ता हैं। वे बताते हैं कि अभिमन्यु ने सबसे पहले कंधमाल जिले के बालीगुड़ा में मौजूद जगन्नाथ मंदिर, जो माफिया के कब्जे में था, उसे वर्ष 2016 में सबके सामने लाकर रख दिया। इस मंदिर में मौजूद 32 दुकानों पर माफिया का कब्जा था। सूचना का अधिकारी कानून से मिली जानकारी को आधार बनाकर उन्होंने मंदिर की संचालन कमेटी भंग करने के लिए हाईकोर्ट में केस कर दिया। हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए और कमेटी भी भंग हो गई। फिर बालीगुड़ा क्षेत्र में अवैध शराब दुकानों को अभिमन्यु ने बंद करवा दिया। यही नहीं करीब तीन करोड़ की लागत से निर्मित कंधमाल महाविद्यालय सारंगगड़ हास्टल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को भी सार्वजनिक कर दिया। सफर यहीं नहीं थमा। उन्होंने जनवितरण प्रणाली की दुकानों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एकमुश्त करीब 50 आवेदन दाखिल कर दिए। फिर तो ठेकेदार से लेकर शासन-प्रशासन तब अभिमन्यु के दुश्मन हो गए। जब कोई बस नहीं चला तो साजिश के तहत अभिमन्यु की हत्या कर दी गई। स्व. अभिमन्यु पांडा के दोस्त प्रदीप प्रधान कहते हैं कि लोगों के विरोध एवं हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बालीगुड़ा में शराब की दुकान बंद कर दी गई है। जनवितरण प्रणाली वाले मामले में राज्य सूचना आयोग के पास सुनवाई जारी है। इसी तरह निर्माण में हुए भ्रष्टाचार मामले में सुंदरगढ़ जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी जांच पूरी नहीं हुई है।

प्रदीप प्रधान कहते हैं कि भ्रष्टाचार में शामिल माफिया सत्ताधारी पार्टी बीजद से संबंध रखते हैं। हत्या के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर जब दबाव बनाया तो प्रशासन ने कुछ आरोपितों को तो गिरफ्तार किया। लेकिन पर्दे के पीछे साजिश रचने वाले अबतक हत्थे नहीं चढ़े हैं। वे इतने ताकतवर हैं कि सुपारी देकर हत्या कराते हैं। खुद सामने नहीं आते हैं। ऐसे में इन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआइ या एसआइटी जांच की मांग की जा रही है। हत्या के पीछे कौन लोग हैं, उनका चेहरा आम लोगों के सामने आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आ पा रहा है।

स्व. अभिमन्यु पांडा की पत्नी छवि रानी पांडा कहती हैं कि हत्याकांड के सभी आरोपित पकड़े जा चुके हैं। लेकिन जिन सफेदपोश लोगों के इशारे पर हत्या हुई, उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। क्योंकि वे सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं थे। यदि सीबीआइ जांच होती तो साजिश रचने वाले सफेदपोश भी पकड़े जाते। उनके नाम उजागर होते। यही वजह है कि इस मामले में सीबीआइ जांच की मांग की जा रही है।

14 साल में 40 पर हमला, चार की हो चुकी हत्या: प्रदीप प्रधान बताते हैं कि ओडिशा में आरटीआइ कार्यकर्ता महफूज नहीं हैं। कार्यकर्ताओं पर हमले की तुरंत जांच भी नहीं होती है। राज्य में 14 वर्षों के दौरान 40 आरटीआइ कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं।

आरटीआइ कार्यकर्ता अभिमन्यु पांडा का पत्नी छवि रानी पंडा और अपने दोनों बच्चों के साथ फाइल फोटो। ● फोटो सौ. परिजन

आरटीआइ कार्यकर्ता परशुराम प्रधान।

पति के निधन के बाद परिवार बिखर गया है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। अब आय का कोई स्रोत रहा नहीं। चाहती हूं कि राज्य सरकार दोषियों को सजा दे और बेटा-बेटी की पढ़ाई के लिए कदम उठाए।

छवि रानी पांडा, अभिमन्यु पांडा की पत्नी

जी7सीआर टेक्नोलॉजीज ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली : भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की पहल के तहत दुनिया की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी एवं क्लाउड सेवा प्रदाता कंपनी जी7सीआर टेक्नोलॉजीज ने माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी में एसएसबी 360 प्रोग्राम शुरू करने का एलान किया है। इस पहल से स्टार्टअप एवं छोटे उद्यमियों को 30 लाख डॉलर तक का फायदा होगा। साथ ही उन्हें रणनीतिक सहयोगों का भी लाभ मिलेगा। 100 करोड़ रुपये से कम की राजस्व वाली 10 साल से कम पुरानी कोई भी कंपनी एसएसबी 360 का लाभ उठा सकती है। (जाब्यू)

अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर है। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। बजट में सरकार इसे गति देने के लिए अपना प्लान ऑफ एक्शन सामने लाएगी।

— प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री

सेंसेक्स	41,115.38	निफ्टी	12,106.90	सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 40,688	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 47,285	डॉलर	₹ 71.19	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 63.54
▼ 208.43		▼ 62.95		▼ ₹51		▼ ₹472		▼ ₹0.02			

सिंचाई के बूते खेती को लहलहाने की होगी कोशिश

बजट से उम्मीदें

- जल की किल्लत वाले चिन्हित 256 जिले बजट में हो सकते हैं उपकृत
- 76 लाख हेक्टेयर के तय लक्ष्य का एक तिहाई भी नहीं हो सका है सिंचित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाकर खेती को लहलहाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कृषि की विकास दर को रफ्तार देने के लिए लंबित पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। देश की कई बड़ी व मझोली परियोजनाओं को पूरा करने के साथ माइक्रो इरिगेशन पर विशेष जोर दिए जाने के भी आसार हैं। इस मद में आवंटन भी बढ़ाए जाने की संभावना है। जल की किल्लत से जूझ रहे चिन्हित ढाई सौ से अधिक जिलों के लिए आम बजट में प्रावधान किया जा सकता है।

चार साल पहले हर खेत तक पानी पहुंचाने के घोषित लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई थी। इसके तहत सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने और भूजल संरक्षित करने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।

सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाना कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती। प्रतीकात्मक फोटो

पीएमकेएसवाई के तहत देश की लंबित 99 बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं चिन्हित की गई थीं जिन्हें निश्चित समय में पूरा करना था। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड से रियायती दरों पर कर्ज देने का प्रावधान किया गया था। इनके पूरा हो जाने की दशा में 76 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन के सिंचित होने की संभावना थी। लेकिन परियोजनाओं के पिछड़ने की वजह से दिसंबर, 2019 तक केवल 23.5 लाख हेक्टेयर तक ही सिंचाई सुविधाएं पहुंचाई जा सकी हैं।

चुनौतियों से जूझ रहे कृषि क्षेत्र के लिए उसकी प्राथमिकता सिंचाई है, जिसके लिए पानी की उपलब्धता सबसे जरूरी है। इसमें सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी, समीक्षा और उन्हें समय पर पूरा करने को बजट में उच्च प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें माइक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) जैसी आधुनिक प्रणाली पर विशेष जोर दिया जा सकता है। सिंचाई की इस प्रणाली का प्रसार सिंचित क्षेत्र के साथ असिंचित क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलेगी। सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत 256 जल की किल्लत वाले जिलों को चिन्हित किया गया है, जहां जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आम बजट में ग्रामीण विकास की मनरेगा जैसी योजना की मदद ली जा सकती है। मनरेगा में सूचीबद्ध कार्यों में 46 केवल जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत 2018-19 में 11.58 लाख हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंचा दी गई थी। 2019-20 में लक्ष्य 14 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। इसमें स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन शामिल हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए संसद में पेश होने वाले आम बजट में सिंचाई के लिए विशेष प्रावधान की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसमें जल संरक्षण भी होगा।

बढ़ाई जा सकती है कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन की सीमा

- निजी क्षेत्र के संगठित कर्मचारियों के लिए अभी न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की है मांग
- असंगठित कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के लिए पहले ही 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का एलान कर चुकी है सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का इस बार बजट में एलान संभव है। यूनियनों की लंबे अरसे से यह मांग रही है। माना जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में इसका अवश्य जिक्र करेंगी।

यूनियनों, खासकर भारतीय मजदूर संघ ने कुछ दिन पहले श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ हुई बैठक में ईपीएस के मुद्दे का उठाया था और न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की मांग रखी थी। यही मांग बजट पूर्व चर्चा में वित्त मंत्री के समक्ष भी रखी गई थी। यूनियनों का कहना है कि जब सरकार ने असंगठित कर्मचारियों तथा व्यापारियों तक के लिए अधिक पेंशन का प्रावधान कर दिया है, तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उससे कम पेंशन का कोई मतलब नहीं है।

ईपीएस में पेंशन सीमा बढ़ाने के अलावा बजट में ईपीएस के कम्यूटेशन अथवा अग्रिम आंशिक निकासी का पुराना प्रावधान भी बहाल किया जा सकता है। कम्यूटेशन के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि के साथ पेंशन की कुछ राशि एकमुश्त तौर पर लेने का अधिकार होता है। लेकिन इससे मासिक पेंशन में 15 वर्षों तक एक तिहाई की कमी हो जाती है। 2009 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। पिछले दिनों ईपीएफओ ने इसे बहाल करने की सिफारिश सरकार से की है। इससे साढ़े छह लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने के अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। जिनमें आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी पर सभी की निगाहें हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की भविष्य निधि यानी ईपीएफ तथा स्वास्थ्य बीमा अर्थात ईएसआइ से जुड़े अहम कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसके तहत शेयर बाजारों में ईपीएफ के निवेश के बारे में कोई एलान हो सकता है। नए ईएसआइ अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों के लिए अधिक आवंटन की भी संभावना है।

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए हाल ही में 'संतुष्टि' नाम से एक प्रकोष्ठ बनाया है। इस सिलसिले में 'संतुष्टि' नाम से ही एक पोर्टल लांच किए जाने की भी संभावना है, जिसके बारे में बजट में बताया जा सकता है।

रफ्तार पकड़ने लगी बीएस-6 वाहनों की बिक्री

अच्छे संकेत ▶ मारुति ने छह महीने में पांच लाख कारें बेचीं

टाटा मोटर्स ने अपने सभी मॉडल को बीएस-6 में उतारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कार बाजार की सुस्ती तो अभी दूर नहीं हुई है, लेकिन नए ग्राहकों की तरफ से बीएस-6 वाहनों की मांग बढ़ने लगी है। मारुति सुजुकी ने बताया है कि उसने पिछले छह महीनें में पांच लाख बीएस-6 कारों की बिक्री की है। टाटा मोटर्स ने भी बुधवार को अपनी नई प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज को लांच करने के साथ ही अपनी सभी कारों के बीएस-6 वर्जन को उतार दिया है। कंपनी का कहना है कि बीएस-6 वर्जन में सारे उत्पाद आने के बाद कंपनी के वाहनों की मांग बढ़ने के आसार हैं।

मारुति सुजुकी ने बताया है कि कंपनी अपने तकरीबन सभी प्रमुख मॉडलों (ऑल्टो, इको, एस-प्रेसो, सिलेरिओ, वैगन-आर, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर, अर्टिगा, एक्सएल-6) के बीएस-6 वर्जन उतार चुकी है। अप्रैल, 2019 के बाद से कंपनी ने धीरे-धीरे बीएस-6 वर्जन उतारना शुरू किया था और अभी तक पांच लाख वाहनों की बिक्री कर चुकी है। फरवरी तक कंपनी अपने सभी मॉडल का बीएस-6 वर्जन उतार देगी। कंपनी इससे उत्साहित है कि उसने बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन बनाने के लिए तकनीकी व शोध पर जो समय व पैसे खर्च किए, उसे ग्राहक पसंद कर रहे हैं। देश की एक अन्य प्रमुख कार कंपनी टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हिकल्स के प्रेसिडेंट मयंक पारीक ने दैनिक जागरण को बताया कि आज के बाद हमारी सारी गाड़ियां बीएस-6 में मिलने लगेंगी। यह कार बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने का एक मौका है, जिसे हम गंवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि कंपनी ने बीएस-6 मानकों के आधार पर सिर्फ इंजन ही नहीं बदला है बल्कि अपने बीएस-4 कारों की सारी डिजाइन भी बदल डाली है। टाटा मोटर्स ने बुधवार को अल्ट्रोज के साथ पहली बार प्रीमियम हैचबैक में उतरने का एलान किया। पारीक का कहना है कि अभी देश में जितनी नई कारें बिक रही हैं, उनमें 49 फीसद प्रीमियम हैचबैक हैं। इसमें टाटा मोटर्स अभी तक नहीं थी और इसका असर कुल बिक्री पर भी पड़ रहा था। कंपनी अब एक बडे सेग्मेंट में उतर रही है जिससे उसे मंदी से लड़ने में मदद मिलेगी। बीएस-6 होने के साथ ही अल्ट्रोज को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा के मामले में पांच स्टार की रेटिंग दी है।

मुंबई में बुधवार को टाटा मोटर्स ने नई कार अल्ट्रोज लॉन्च करके हैचबैक प्रीमियम सीरीज में प्रवेश किया। कार लांचिंग के दौरान टाटा मोटर्स के सीईओ व एमडी गुंटर बुश्शेक (बाएं) और प्रेसिडेंट मयंक पारीक (दाएं)। यह कार पेट्रोल और डीजल के पांच-पांच वैरिएंट में उपलब्ध होगी। प्रेट्र

किआ के कार्निवल की जबर्दस्त बुकिंग

किआ मोटर्स ने ग्राहकों के सामने एक दिन पहले अपनी नई एसयूवी कार्निवल के लिए बुकिंग शुरू की। इसके लिए पहले ही दिन 1410 बुकिंग हुई है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। यह भारतीय बाजार में कंपनी की दूसरी लांचिंग होगी। अभी इसे सार्वजनिक तौर पर बाजार में पेश भी नहीं किया गया है। लग्जरी सेग्मेंट में पेश होने वाली इस कार के प्रति ग्राहकों का यह भरोसा कार बाजार में हो रहे बदलाव को भी दर्शाता है।

हुंडई भी पूरे दमखम के साथ तैयार

दैनिक जागरण ने बीएस-6 वाहनों के बारे में हुंडई के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि नवंबर, 2019 के बाद से नए मानकों को लेकर ग्राहकों की तरफ से ज्यादा पूछताछ हो रही है। कंपनी ने मंगलवार को औरा नाम से एक नई कार उतारी है जो बीएस-6 मानकों पर आधारित है। कंपनी सैंट्रो, निओस के पेट्रोल वर्जन के बीएस-6 मॉडल भी लांच कर चुकी है। हुंडई ने बीएस-6 में जो गाड़ियां उतारी हैं, उनकी बिक्री बीएस-4 के मुकाबले ज्यादा है। कंपनी फरवरी, 2020 तक सारे मॉडलों को बीएस-6 में उतारने जा रही है।

पहली अप्रैल से बीएस-6 अनिवार्य

पहली अप्रैल, 2020 से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहनों की बिक्री होगी। अभी कारों की कम बिक्री के लिए वजह यह भी बताई जा रही है कि ग्राहक बीएस-6 वाले मॉडल में इंतजार में हैं।

घरेलू प्लाईवुड उद्योग को सहारे की दरकार

राजीव शर्मा, लुधियाना

केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले अगले वित्त वर्ष के आम बजट को लेकर प्लाईवुड उद्योग में भी उत्सुकता है। प्लाईवुड उद्यमियों का तर्क है कि इस उद्योग को विदेश से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए घरेलू प्लाईवुड उद्योग को सुविधाएं एवं सब्सिडी की दरकार है। साथ ही उद्यमियों ने करों का बोझ कम करने की अपील भी की है।

उद्यमियों का कहना है कि बाजार की चुनौतियों के मुकाबले के लिए विदेश से आ रहे कच्चे माल को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किए जाने और तैयार माल पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की जरूरत है। इन कदमों से यहां प्लाईवुड उद्योग से जुड़ा मैन्यूफैक्चरिंग बेस मजबूत होगा। पंजाब प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान इंद्रजीत सिंह का कहना है कि कृषि आधारित राज्य होने के चलते ही सूबे में प्लाईवुड उद्योग स्थापित हुआ। राज्य में प्लाईवुड बनाने वाली करीब दो सौ यूनिट हैं। इनमें तीन हजार करोड़ सालाना से अधिक का कारोबार हो रहा है। उद्यमियों का कहना है कि अब सूबे में लकड़ी की कमी है। ऐसे में यूपी व हरियाणा से भी लकड़ी की खरीद करनी पड़ रही है। इसके अलावा महंगी बिजली भी परेशानी बनी हुई है। बंदरगाह से दूरी के कारण माल भाड़ा अधिक लग रहा है। सूबे से 75 फीसद प्लाई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में जाती है।

जीएसटी दर पांच फीसद की जाए : इंद्रजीत सिंह का कहना है कि कॉटन, कागज और अन्य एग्रो बेस्ड उत्पाद पांच से 12 फीसद की जीएसटी दर में हैं। वहीं प्लाईवुड को 18 फीसद की स्लैब में रखा गया है। प्लाईवुड आम आदमी की जरूरत है। ऐसे में इस पर जीएसटी की दर पांच फीसद की जाए। इससे इंडस्ट्री के साथ-साथ आम उपभोक्ता को भी लाभ होगा। इससे जहां किसान की आय बढ़ेगी, वहीं इंडस्ट्री को आसानी से कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे विविधिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री का कच्चा माल फेस विनियर मलेशिया, इंडोनेशिया व अफ्रीका से आयात हो रहा है। इसे कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया जाए। इससे इंडस्ट्री की लागत कम होगी।

उद्यमियों की आस

- विदेश से आने वाले कच्चे माल को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने पर सरकार करे विचार
- तैयार माल के आयात पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाकर स्थानीय उद्यमों को दी जाए ताकत
- कृषि आधारित उद्योग होने के कारण प्लाईवुड पर जीएसटी की दर पांच फीसद रखी जाए

विशेष इन्सेंटिव की भी दरकार

पंजाब प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जुनेजा ने कहा कि एग्रो बेस्ड होने के चलते बजट में इस उद्योग को विशेष इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए। साथ ही उद्योग को तीन से पांच फीसद सस्ती ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने की दिशा में भी सरकार विचार करे। बजट में चीन व वियतनाम से आ रही सस्ती प्लाई को नियंत्रित करने के उपाय भी किए जाने चाहिए। आयात पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाए। देश की कुल मांग की करीब 20 फीसद प्लाई विदेश से आ रही है। घरेलू उद्यमियों को सुविधाएं देकर और आयात को नियंत्रित करके ही उद्योग में ग्रोथ का रास्ता साफ होगा।

बजट में फ्रेट सब्सिडी दी जाए

हांडा प्लाईवुड के मैनेजिंग डायरेक्टर हरमीत सिंह ने कहा कि पंजाब पोर्ट से दूर है। यहां बना माल महंगा साबित हो रहा है। इसे मैनेज करने के लिए बजट में फ्रेट सब्सिडी दी जाए। इससे उद्योग को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा विदेशी आयात को दरकिनार करके मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएं। ऐसा करके देश में घरेलू उद्योगों की जड़ें मजबूत की जा सकेंगी। इंडस्ट्री मेक इन इंडिया में काम करने को तैयार हैं, लेकिन सहूलियतें बढ़ाने की दरकार है। बजट में राहत मिलने से ही इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा।

जीएसटी रिटर्न के लिए तीन अलग-अलग अंतिम तारीख

नई दिल्ली, प्रेट्र : अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख अलग-अलग रहेगी। अभी किसी महीने का जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने के लिए उसके अगले महीने की 20 तारीख तक का वक्त रहता है। अब सिर्फ पिछले वित्त वर्ष में पांच करोड़ या इससे ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारी अगले महीने की 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करेंगे।

पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को दो वर्ग में रखा गया है। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को अगले महीने की 22 तारीख और अन्य राज्यों के ऐसे कारोबारियों को 24 तारीख तक रिटर्न की अनुमति होगी।

घाना में भी लागू होगी उज्ज्वला जैसी योजना

- योजना से जुड़ी तकनीकी मदद पाने के लिए अफ्रीकी देश ने भारत से किया करार
- घाना में कई सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर करने में मिलेगी मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

गरीब जनता को किफायती कीमत पर रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन देने की मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना में कई देश अपनी रुचि दिखा चुके हैं। अफ्रीका का घाना पहला देश बन गया है जिसने उज्ज्वला की तर्ज पर ही इस तरह की योजना लागू करने का फैसला किया है। घाना ने इसमें भारत से तकनीकी मदद भी मांगी है। बुधवार को दोनों देशों के बीच इस बारे में एक करार भी हुआ है। समझौते के तहत घाना को एलपीजी से जुड़ी नीति को क्रियान्वित करने में भारत तकनीकी व विशेषज्ञता मुहैया कराएगा। समझौता पत्र पर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और घाना के राजदूत माइकल एर्रॉन की मौजूदगी में सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल और घाना की नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी के बीच हस्ताक्षर किया गया।

घाना की तरफ से उज्ज्वला के व्यापक अध्ययन के बाद इसे लागू करने का फैसला किया गया है। घाना ने भारत को बताया है कि आर्थिक तौर पर कमजोर तबके को उज्ज्वला जैसी योजना से काफी आसानी से गैस कनेक्शन दिया जा सकता है। इससे घाना की कई सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी समाधान निकलेगा। यही वजह है कि घाना ने किसी विकसित देश के बजाय भारत से मदद मांगी है। समझौते से इस बात का भी पता चलता है कि गैस इकोनोमी में भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है।

एक तरफ भारत रूस के सबसे बड़े गैस फील्ड में भारी भरकम निवेश करने का एलान कर चुका है तो दूसरी तरफ घाना जैसे कम विकसित देश को तकनीकी मदद दे रहा है। घाना ने कहा कि भारत की मदद से वह अपनी 50 फीसद आबादी को वर्ष 2030 साफ व स्वच्छ ऊर्जा देना चाहता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने सिर्फ पांच वर्षों में इस योजना के जरिये आठ करोड़ घरों में गैस कनेक्शन दिया है।

घाना को मदद देने से भारतीय तेल कंपनी आइओसी को अफ्रीका के एक बड़े बाजार में प्रवेश का मौका मिलेगा। कंपनी धीरे-धीरे वहां के दूसरे ईंधन बाजार में भी अपनी संभावनाएं तलाश सकती है। अफ्रीका के अधिकांश देश काफी गरीब हैं लेकिन जिस तेजी से उनकी आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए वहां ऊर्जा मांग दुनिया में सबसे तेज होने के आसार हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बाएं से दूसरे) और घाना के राजदूत माइकल एर्रॉन (सबसे दाएं) की मौजूदगी में भारत की तेल कंपनी इंडियन ऑयल और घाना की नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी के बीच करार पर हस्ताक्षर हुआ। प्रेट्र

हालात

208 अंक गंवाकर पांच हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, कंपनियों के उम्मीद से कमतर नतीजे भी बन रहे गिरावट की वजह

बजट से पहले निवेशक सतर्क, शेयर बाजारों में गिरावट

मुंबई, प्रेट्र : आम बजट की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, बाजार में निवेशकों की सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। इसका सीधा असर घरेलू शेयर बाजारों पर देखने को मिला है। बुधवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए 208.43 अंक टूटकर बंद हुआ। दिन के आखिर में यह 41,115.38 के स्तर पर रहा। 16 दिसंबर के बाद से यह सेंसेक्स का निचला स्तर है। यह लगातार तीसरा कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स में गिरावट आई है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 62.95 अंक के नुकसान के साथ 12,106.90 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों में ओएनजीसी का शेयर सबसे अधिक 5.13 फीसद टूटा। एनटीपीसी, मारुति, कोटक बैंक, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, आइसीआइसीआइ बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी ओर, नेस्ले इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एसबीआइ और भारती एयरटेल के शेयर 1.86 फीसद तक चढ़ गए।

प्रतीकात्मक फोटो

विश्लेषकों का कहना है कि आम बजट से पहले ज्यादातर बड़े शेयर बिकवाली दबाव के चलते 'करेक्शन' की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा वैश्विक एजेंसियों द्वारा भारत का विकास दर अनुमान घटाने और कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने की वजह से भी घरेलू निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 0.32 फीसद तक की गिरावट आई। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के प्रेसिडेंट -इक्विटी रिसर्च पारस बोथरा ने कहा, 'घरेलू बाजार ऊंचा खुलने के बाद बढ़त कायम नहीं रख पाए। फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, मेटल और फार्मा कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बाजारों में गिरावट आई। हालांकि, एफएमसीजी और कुछ आइटी कंपनियों के शेयर फायदे में रहे। बजट से पहले अनिश्चितता की वजह से निवेशक सतर्क हैं।' चीन में छह लोगों की जान लेने वाले वायरस का एक मामला अमेरिका में पाए जाने से भी बाजार पर असर पड़ा है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'उम्मीद से कमतर नतीजों के कारण बैंकिंग, ऑटो और मिडकैप कंपनियों के शेयर कंसोलिडेट हो रहे हैं। आइटी और बैंकिंग कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं हैं। इससे बाजार पर असर पड़ रहा है। आगे बहुत कुछ बजट में होने वाली घोषणाओं पर भी निर्भर करेगा।' अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार भी लाभ में रहे। डॉलर के मुकाबले रुपया दो पैसे की बढ़त के साथ 71.19 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

बजट के दिन होगी ट्रेडिंग : बजट के दिन यानी पहली फरवरी को स्टॉक मार्केट में सामान्य दिनों की तरह ही ट्रेडिंग होगी। बीएसई ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, पहली फरवरी को शनिवार होने के बावजूद सामान्य कारोबारी घंटों में ही ट्रेडिंग होगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजारों में ट्रेडिंग नहीं होती है। सूत्रों के मुताबिक, कई मार्केट पार्टिसिपेंट ने अनुरोध किया था कि बजट में बाजार को प्रभावित करने वाली घोषणाओं को देखते हुए उस दिन ट्रेडिंग होनी चाहिए।

चांदी ने लगाया गोता, सोना भी नरम

नई दिल्ली, प्रेट्र : बुधवार को घरेलू सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी ने 472 रुपये का गोता लगाया। दिल्ली में चांदी 47,285 रुपये प्रति किलो पर बोली गई। सोना भी 51 रुपये गंवाकर 40,688 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

सैमसंग ने लांच किया दही जमाने वाला रेफ्रिजरेटर

- भारत की जरूरतों के अनुरूप सैमसंग ने उतारा खास उत्पाद
- फूड प्रोसेस करने वाला दुनिया का पहला रेफ्रिजरेटर है कर्ड मैस्ट्रो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेफ्रिजरेटर बाजार में फिर से नंबर वन पर आने वाली सैमसंग ने भारतीय बाजार में एक ऐसा उत्पाद लांच किया है जिसकी जरूरत संभवतः पूरे देश में है। कंपनी ने कर्ड मैस्ट्रो के नाम से एक नया रेफ्रिजरेटर लांच किया है जिसमें दही जमाने की व्यवस्था है। सैमसंग इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस) राजू पुल्लान ने बताया कि पहली बार दुनिया में इस तरह का रेफ्रिजरेटर तैयार किया गया है जो फूड को प्रोसेस भी करेगा। इसके लिए देशभर में बड़े पैमाने पर अध्ययन व नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ विमर्श किया गया था।

कर्ड मैस्ट्रो रेफ्रिजरेटर में दही जमाने के लिए एक अलग बॉक्स बना हुआ है। दूध को गर्म करके ठंडा करने के बाद इसमें थोड़ी दही डालनी होगी और फिर इसे बॉक्स में रख देना होगा। पांच से छह घंटे में दही जम जाएगी। रेफ्रिजरेटर की कीमत 30,990 रुपये से लेकर 45,990 रुपये तय की गई है। इस रेफ्रिजरेटर की दूसरी खासियत यह होगी कि इस्तेमाल के आधार पर इसमें जगह बनाई जा सकती है। यानी अगर ज्यादा समान फ्रिज में रखना है तो फ्रिजर के इस्तेमाल में बदलाव किया जा सकता है। इसी तरह, किसी घर में फ्रिजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है तो उसके लिए ज्यादा जगह निकाली जा सकती है। कंपनी का कहना है कि 2019 में वह रेफ्रिजरेटर बाजार में 33.9 फीसद हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। नए उत्पादों के साथ कंपनी अगले छह महीने में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 35 फीसद करने का लक्ष्य बनाकर चल रही है।

23 नागरिकों की मौत हो गई है उत्तर-पश्चिमी सीरिया में रूस के हवाई हमले में। यह क्षेत्र विद्रोहियों के कब्जे वाला है। जवाबी कार्रवाई में विद्रोहियों और जिहादियों पर दागे गए रॉकेट हमलों ने पास के सरकारी शहर अलेप्पो में तीन और नागरिकों को मार डाला।

महामारी बन सकती है ये बीमारी

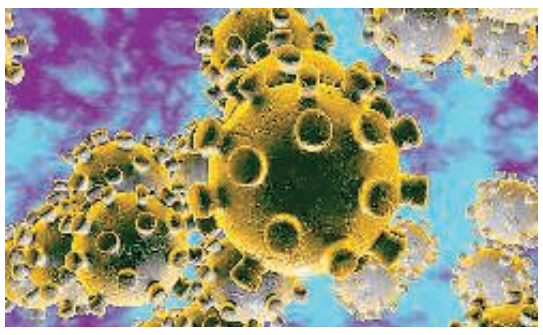

चीन से फैल रहे कोरोना वाइरस से हर देश सतर्क हो चुके हैं। अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लिहाजा सभी देश अपने हवाई अड्डों पर चीन या संक्रमित देशों से आने वाले मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग करने लगे हैं। जिससे संक्रमित लोगों की पहचान करके उन्हें गहन उपचार प्रक्रिया से गुजारा जा सके।

सार्स और मर्स से संबंध

वर्तमान में दुनिया को परेशान करने वाले इस वाइरस का संबंध कोरोनोवाइरीडी फेमिली से है। इस फेमिली के वाइरस से फैली सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पेरेटरी सिंड्रोम) बीमारी ने 2002 में आठ सौ लोगों की जान ले ली थी। यह बीमारी भी चीन से शुरू हुई थी। इसके अलावा 2012 में पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) रेस्पेरेटरी सिंड्रोम कोरोनोवाइरस (मर्स) ने कोहराम मचाया था। उस समय प्रत्येक 10 संक्रमित लोगों में से तीन या चार लोगों को बचाया नहीं जा सका था।

ये हैं शुरुआती लक्षण

इसके बाद ये लक्षण न्यूमोनिया में बदल जाते हैं और श्वसन तंत्र से जुड़े अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं।

क्या है कोरोना वायरस

वायरसों का एक ऐसा बड़ा समूह जो आमतौर पर जानवरों में पाए जाते हैं। अभी तक ऐसे ज्ञात छह वायरस (नये को मिलाकर इनकी संख्या सात हो सकती है।) हैं जो इंसानों को संक्रमित कर रहे हैं।

परहेज ही उपाय

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक परहेज ही इस वायरस से निपटने का एक तरीका है। इसके लिए खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मांस खाने से परहेज और जुकाम व खांसी के दौरान मुंह को ढकना चाहिए।

कहां से आया

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार चीन के वुहान में सी फूड बाजार में इससे प्रभावित जानवरों के जरिए यह वायरस फैला है।

कोई वैक्सीन नहीं

अभी तक इस वायरस से निजात पाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, कोरोना वायरस सी-फूड से जुड़ा है। वैक्सीन तैयार करने की कोशिश हो रही है।

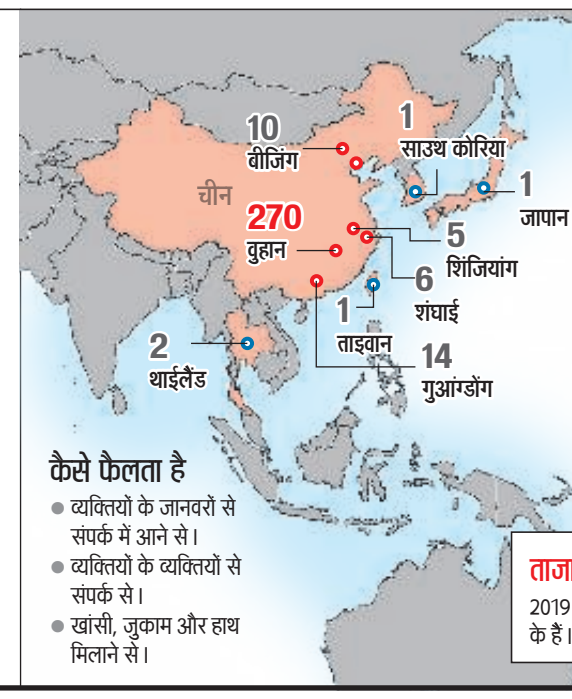

कैसे फैलता है

- व्यक्तियों के जानवरों से संपर्क में आने से।
- व्यक्तियों के व्यक्तियों से संपर्क से।
- खांसी, जुकाम और हाथ मिलाने से।

2012 और उससे पहले

डब्ल्यूएचओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2002 में यह वायरस पहली बार संज्ञान में आया। तब 37 देशों में इसका प्रभाव देखा गया। इसके बाद 2003 में 8098 लोगों इसकी चपेट में आए और 774 लोगों की मौत हो गई। साल 2012 में यूरोप और मध्य पूर्व में इस वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 33 तक पहुंची। इन संक्रमित मरीजों में से 18 की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक वायरस के रोगियों की संख्या सऊदी अरब और जार्डन में ही नहीं अब जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में भी बढ़ रही है।

ताजा स्थिति

2019 से अब तक कोरोना वायरस की चपेट में करीब 300 लोग सिर्फ चीन के हैं। अब यह थाइलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंच चुका है।

न्यूज गैलरी

पुतिन की नई कैबिनेट में नौ उप प्रधानमंत्री

मॉस्को : देश के नए प्रधानमंत्री के रूप पर मिखाइल मिशुस्तीन की नियुक्ति के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नई कैबिनेट का गठन किया है। इसमें उप प्रधानमंत्रियों की संख्या दस से घटाकर नौ कर दी गई है, जिनमें पांच नए चेहरे हैं। राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना के अनुसार, नई कैबिनेट में पुतिन के सहयोगी आंद्रे बेलोसोव को शामिल करते हुए उन्हें प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। जबकि अभी तक इस पद को संभाल रहे एंटोन सिलुआनोव को वित्त मंत्रालय का भार सौंपा गया है। उप प्रधानमंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किए गए दिमित्री ग्रिगोरेंको को रूस सरकार के चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन मंत्रियों के विभागों में कोई फेरबदल नहीं की गई है, उनमें विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू और गृह मंत्री शामिल हैं। (आइएएनएस)

कार दुर्घटना में भारतवंशी पर चलेगा हत्या का मुकदमा

न्यूयॉर्क : अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की तेमेसकल वैली में रविवार रात हुई सड़क दुर्घटना में कार चला रहे भारतवंशी अनुराग चंद्रा (42) पर हत्या का मुकदमा चलेगा। इस हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई थी। दुर्घटना की जांच कर रही पुलिस टीम का कहना है कि अनुराग ने किशोरों की कार को अपनी कार से जानबूझकर टक्कर मारी थी। इस टक्कर से किशोरों की कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई थी। उस कार में छह किशोर थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ा था। तीन किशोरों का इलाज चल रहा है। उन्हें अब खतरे से बाहर बताया गया है। कैलिफोर्निया हाइवे पेट्रोल के लेफ्टिनेंट डेविड योकले ने मीडियाकर्मियों को बताया कि हादसे को जानबूझकर अंजाम दिया गया था। मामले की जांच अब हिट एंड रन के बजाय हत्या के नजरिये से की जाएगी। जांच में पता चला कि कोरोना सिटी में रहने वाले अनुराग पर पहले से आपराधिक मामले चल रहे हैं। (प्रेट्र)

ऑस्ट्रेलिया में फिर भड़की आग, कुछ हिस्से कराए खाली

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा के एयरपोर्ट के पास स्थित जंगलों में आग लगने के बाद शहर के कुछ हिस्से को खाली करा लिया गया है। सड़कों पर आवागमन ठप हो गया है। अधिकारियों ने लोगों से इलाका खाली करने या फिर आग की चपेट में आए उपनगरों से दूर रहने को कहा है। देश में पिछले दिनों हुई बारिश और तापमान में आई कमी से अग्निशमन कर्मचारियों को जंगलों में लगी आग को काबू करने में कुछ सफलता मिली थी। लेकिन तेज हवा चलने और तापमान बढ़ने से फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में राजधानी के उपनगरीय इलाकों के ऊपर धुएं का गुबार दिख रहा है। हाल के दिनों में केनबरा, सिडनी और मेलबर्न विश्व में सबसे खराब हवा की गुणवत्ता वाले शहरों में शीर्ष पर रहे हैं। गत सितंबर से लगी आग की चपेट में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। (रायटर)

कश्मीर नहीं, पाकिस्तान पर ट्रंप के बयान से है चिंता

पेशकश ▶ इमरान से की मुलाकात, कश्मीर में मध्यस्थता का दिया प्रस्ताव

भारत ने किया खारिज, कहा-किसी तीसरे पक्ष की दरकार नहीं

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (दाएं)। रायटर

ठीक चार महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर में मध्यस्थता करने की बात कही है और वह भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सामने। भारत ने तब उनकी मध्यस्थता से साफ मना किया था और बुधवार को भी विदेश मंत्रालय ने मध्यस्थता की किसी भी संभावना से साफ इन्कार किया। लेकिन, भारत की चिंता यह नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार मध्यस्थता की रट लगाए हुए हैं, बल्कि यह है कि उनके इस रवैये से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर बनाया गया दबाव कम हो सकता है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर पर भारत का स्टैंड पुराना है और यह सभी को मालूम है। हम इस मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मदद लेने को तैयार नहीं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर, 2019 में न्यूयार्क में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने यह बात साफ तौर पर कह दी थी। उस मुलाकात के ठीक पहले ट्रंप ने न सिर्फ कश्मीर पर मध्यस्थता करने की बात कही थी बल्कि यह भी दावा किया था कि स्वयं मोदी ने उनसे मध्यस्थता करने को कहा है। यही वजह है कि जब मंगलवार को खान व ट्रंप के बीच मुलाकात में कश्मीर का जिक्र किया गया, तो भारत ने इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत की इस ठंडी प्रतिक्रिया की एक वजह यह भी माना जा रही है कि ट्रंप के अगले महीने नई दिल्ली आने की संभावना है।

इस ठंडी प्रतिक्रिया के बावजूद भारत की चिंता कम नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने, पाकिस्तान के साथ कारोबार करने की बात कही है, वह बताता है कि अमेरिका का नजरिया बदला है। ट्रंप व इमरान के बीच मुलाकात से कुछ ही दिन पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका की यात्रा की है। पाक के उद्यमियों का एक दल भी शीघ्र ही अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर जाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति व इमरान की मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान व ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता में भी द्विपक्षीय कारोबार का मुद्दा उठा है। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान में रुचि दिखा रहा है उसे देखते हुए वैसे देश जो आतंकवाद को प्रश्रय देने के मुद्दे पर पाक से दूरी बना रहे थे वे भी रिश्तों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इससे आतंकवाद के मुद्दे पर पाक पर दबाव बनाने की रणनीति को धक्का लग सकता है। अमेरिका के रुख में आए बदलाव के लिए मुख्य तौर पर उसकी नई ईरान नीति को माना जा रहा है। अगर खाड़ी में फिर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो अमेरिका को पाकिस्तान के सैन्य अड्डों की जरूरत होगी। यही वजह है कि ईरान के जनरल सुलेमानी की हत्या के दिन अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने पाक सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन किया था।

सीनेट ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग सुनवाई के नियमों को दी मंजूरी

वाशिंगटन, एपी : अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई शुरू हो गई। पहले दिन स्थानीय समयानुसार रात दो बजे तक चली कार्यवाही में सदन ने सुनवाई के नियमों को मंजूरी दे दी। साथ ही और गवाहों को बुलाने की डेमोक्रेटिक्स की मांग को खारिज कर दिया।

मंगलवार को सीनेट की कार्यवाही प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में शुरू हुई। सदन में एक तरफ अभियोजन पक्ष के लोग और दूसरी तरफ ट्रंप के वकीलों की टीम बैठी थी। वेल में सीनेटर अपनी सीटों पर शांति से बैठे थे। सदन में किसी को सेलफोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं थी। जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, बहस तीखी होती गई।

प्रधान न्यायाधीश रॉबर्ट्स ने दोनों पक्षों को शब्दों के चयन में संयम बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि वे याद रखें कि वे कहां बोल रहे हैं। चूंकि सीनेट में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी को 53-47 का बहुमत हासिल है, लिहाजा उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के संशोधनों को खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस के अधिवक्ता और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रमुख वकील पैट सिपोलोन ने इस सुनवाई को तमाशा और ट्रंप के खिलाफ आरोपों को हास्यास्पद करार दिया। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि राष्ट्रपति ने कुछ भी गलत नहीं किया है और यह कोई मामला नहीं है।

उधर, दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के लिए पहुंचे ट्रंप ने सदन के डेमोक्रेटिक प्रबंधकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सुनवाई के दौरान पहली पंक्ति में बैठना चाहते हैं और भ्रष्ट चेहरों को घूरना चाहते हैं, लेकिन संभवतः उनके वकीलों को इससे समस्या हो सकती है।

चीन में बढ़ा कोरोना वायरस का प्रकोप, अब तक नौ की मौत

- 440 लोग संक्रमित, 2197 लोग आइसोलेशन में
- कई एशियाई देशों के साथ अमेरिका तक पहुंचा वायरस

बीजिंग, रायटर : चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या नौ हो गई है। इस वायरस से 440 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है, जिनमें 15 चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। संक्रमित लोगों के सपंर्क में आने वाले 2,197 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। फरवरी में वुहान में होने वाले बॉक्सिंग के ओलंपिक क्वालीफाइंग मैचों को निरस्त कर दिया गया है। चीन में 2002 में भी इसी तरह के एक वायरस से सार्स (एसएआरएस) का प्रकोप फैला था। देश के दक्षिणी इलाके से शुरू हुई उस बीमारी की चपेट में आकर दो दर्जन देशों में करीब 800 मौतें हुई थीं।

कोरोना वायरस सेंट्रल चीन के वुहान शहर में सबसे पहले देखा गया। इसके बाद यह हुबेई, बीजिंग, शंघाई, मकाऊ और हांगकांग के साथ ताइवान, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका तक जा पहुंचा है। हुबेई प्रांत में सरकार ने लोगों को सार्वजनिक समारोह से बचने को कहा है। इस वायरस के पूरे विश्व में फैलने का डर है क्योंकि चीनी नववर्ष के चलते कई लोग विदेश यात्राओं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

नेशनल हेल्थ कमीशन के उपमंत्री ली बिन ने मीडिया को बताया कि वायरस के सांस के जरिये फैलने का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रवक्ता तारिक जसारेविक ने कहा कि चीन ने निगरानी बढ़ा दी है, जिसके बाद वायरस के और नए मामले सामने आ सकते हैं।

बिल्लियों से फैला था सार्स : कोरोना वायरस कहां से आया इसका अब भी पता नहीं चल सका है। कुछ लोग इसे वुहान के एक बाजार से आया मानते हैं, जहां वन्यजीवों का अवैध कारोबार होता है। माना जाता है कि चीन में भोजन के लिए बेची जाने वाली सिवेट बिल्लियों से मनुष्यों में सार्स फैला था। कोरोना वायरस का प्राथमिक स्रोत भी जानवर ही माना जा रहा है।

कंपनियों ने कर्मचारियों से वुहान नहीं जाने को कहा : फॉक्सकॉन, हुआवे, एचएसबीसी होल्डिंग सहित चीन की सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को मास्क बांटने के साथ ही वुहान की यात्रा से बचने को कहा है। एपल की सप्लायर फॉक्सकॉन के संस्थापक टेरी गाऊ ने कहा कि वह कंपनी के कर्मचारियों को छुट्टी पर चीन नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं।

ताइवान ने चीन से आंकड़े साझा करने को कहा : ताइवान ने मंगलवार को एक महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की। यह महिला वुहान से लौटी थी। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन के साथ ही डब्ल्यूएचओ से सीधे सूचना साझा करने को कहा है। चीन की आपत्ति के चलते ताइवान डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है।

हांगकांग में पहला मामला सामने आया

हांगकांग में भी वायरस से एक व्यक्ति के संक्रमित होने का पता चला है। वह चीन से आया था। हांगकांग की कैथे पेसिफिक एयरवेज ने कहा है कि वह क्रू सदस्यों को चीन की उड़ान पर जाने के दौरान सर्जिकल मास्क पहनने की अनुमति देगी।

चीन की सीपीईसी परियोजना में पारदर्शिता नहीं : अमेरिका

- काली सूची में डाली गई कंपनियों को मिले सीपीईसी के ठेके
- आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान पर बढ़ेगा कर्ज का बोझ

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक एलिस वेल्स ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की आलोचना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में संचालित चीन की परियोजनाओं में कोई पारदर्शिता नहीं है। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीपीईसी में उन कंपनियों को ठेके दिए गए हैं, जिन्हें विश्व बैंक ने काली सूची में डाल रखा है।

डॉन अखबार के अनुसार, अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों की मुख्य डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी वेल्स ने मंगलवार को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कहा, सीपीईसी में कोई पारदर्शिता नहीं है। चीनी वित्तपोषण के चलते पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह इस परियोजना में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करे। पाकिस्तान के कर्ज के मुद्दे पर वेल्स ने कहा कि चीन से जो धनराशि मिल रही है, वो सहायता नहीं है बल्कि महंगा कर्ज है। वेल्स ने गत नवंबर में भी सीपीईसी पर सवाल खड़े किए थे। उस समय उन्होंने कहा था, 'हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान कर्ज, जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर चीन से कड़े सवाल करेगा। चीन सरकार से यह भी पूछा जाए कि पाकिस्तान में विकास के ऐसे मॉडल को क्यों अपनाया जा रहा है, जो चीन की आर्थिक सफलता से अलग रास्ते वाला है?'

क्या है सीपीईसी प्रोजेक्ट

60 अरब डालर (करीब चार लाख 27 हजार करोड़ रुपये) की लागत वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत चीनी के शिनजियांग क्षेत्र को अरब सागर में स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ा जाना है। इन दोनों को सड़क और रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। भारत को इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति है, क्योंकि यह गुलाम कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 2015 में सीपीईसी को लांच किया था।

नेपाल में मृत आठ भारतीय पर्यटकों के आज आएंगे शव

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल में मृत आठ भारतीय पर्यटकों के शवों को गुरुवार को वापस घर लाया जाएगा। इनमें चार बच्चे शामिल हैं। बुधवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई होगी। नेपाल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है और उससे 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कमेटी यह जांच करेगी कि क्या जिस रिजॉर्ट में यह घटना हुई है, वहां सरकार द्वारा तय मानकों का पालन किया जाता था या नहीं।

बता दें कि केरल के 15 पर्यटकों का दल नेपाल घूमने गया था। उनमें से आठ लोग मंगलवार सुबह एक होटल में बेहोश मिले। उन्हें एयरलिफ्ट कर राजधानी काठमांडू स्थित एचएएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ' सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और गुरुवार सुबह उनके शवों को वापस घर लाया जाएगा।'

प्रिंस हैरी और मेगन ने मीडिया से टकराव के साथ कनाडा में शुरू की नई जिंदगी

- चोरी-छुपे फोटो खींचने पर पत्रकारों को दी कानूनी चेतावनी
- दंपती ने शाही जिम्मेदारियां छोड़कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का किया है एलान

विक्टोरिया, एएफपी : ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने कनाडा में अपनी नई जिंदगी मीडिया से टकराव के साथ शुरू की। चोरी-छुपे फोटो खींचने पर इस दंपती ने मंगलवार को मीडिया को कानूनी चेतावनी दी।

हैरी और मेगन ने गत आठ जनवरी को यह एलान कर चौंका दिया था कि वे शाही जिम्मेदारियां छोड़कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। इस एलान के अगले दिन मेगन कनाडा चली गई थीं। पत्नी और अपने आठ माह के बेटे आर्ची के साथ रहने के लिए हैरी बीते सोमवार को कनाडा पहुंचे। इस दंपती ने कनाडा के वैंकूवर द्वीप के विक्टोरिया में एक आलीशान घर को अपना ठिकाना बनाया है। इस दंपती ने इसी जगह क्रिसमस के दौरान छह हफ्ते की छुट्टियां भी बिताई थीं। कई अखबारों में मंगलवार को मेगन की बेटे आर्ची और अपने कुत्तों के साथ टहलने की तस्वीरें छपी थीं। ब्रिटिश अखबार सन और डेली मेल ने भी इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। बीबीसी के अनुसार, तस्वीरें प्रकाशित होने के बाद हैरी और मेगन के वकीलों ने कानूनी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है, फोटोग्राफरों ने झाड़ियों में छुपकर तस्वीरें खीचीं। वे मेगन की जासूसी कर रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। वे इस परिवार को परेशान कर रहे हैं। शाही दंपती कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल। फाइल/रायटर

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

17 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, एक लाख करोड़ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं को मूर्ख ज्योतिषियों का उत्तराधिकारी बताया

जलवायु परिवर्तन पर ग्रेटा और ट्रंप फिर आमने-सामने

दावोस, रायटर : स्विट्जरलैंड में मंगलवार से शुरू हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग फिर आमने-सामने आ गए। दावोस में आयोजित इस सम्मेलन में 17 साल की ग्रेटा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है। उनके निशाने पर सीधे तौर पर ट्रंप का भाषण था, जिसमें उन्होंने एक लाख करोड़ पेड़ लगाने की बात कही थी। साथ ही जलवायु परिवर्तन पर की जा रही भविष्यवाणियों को खारिज किया था। ट्रंप ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उस दौरान दर्शक दीर्घा में ग्रेटा भी मौजूद थीं।

डब्ल्यूईएफ में अपने मुख्य भाषण में ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं को मूर्ख ज्योतिषियों का उत्तराधिकारी भी करार दिया। जबकि थनबर्ग ने अपने भाषण में एक साल पहले डब्ल्यूईएफ में दिए गए भाषण की टिप्पणियों को दोहराया। उन्होंने कहा, हमारे घरों में आग लगी हुई है और आपकी निष्क्रियता आग की लपटों को हवा दे रही है। उन्होंने जीवाश्म ईंधन के निवेश पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की। विश्व के नेताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन के हित में काम करने के वादों पर सवाल उठाते हुए ग्रेटा ने कहा, आप कहते हैं कि बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए। इतना निराशावादी मत बनिए। इससे पहले पिछले साल भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर ही दोनों आमने-सामने आ गए थे।

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन में लोगों को संबोधित करतीं जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग(दाएं)। रायटर

विज्ञान हो वार्ता का केंद्र बिंदु

ग्रेटा ने कहा, पेड़ लगाना निश्चित रूप से अच्छा कदम है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए जो काम किए जाने चाहिए थे, उसके मुकाबले यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। कम से कम यह वास्तविक प्रकृति की तो जगह नहीं ले सकते। इससे पहले ग्रेटा ने वैश्विक नेताओं से युवा कार्यकर्ताओं को सुनने का आह्वान किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम वह तो अपनी बात नहीं सुने जाने की शिकायत नहीं कर सकतीं। ग्रेटा इस सम्मेलन में उस पैनल का हिस्सा बनकर पहुंची हैं, जिसमें युवा कार्यकर्ता दुनिया को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के परिणाम और योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं।

गृहयुद्ध में लापता लोगों के बारे में जांच चाहते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति

- गोतबाया राजपक्षे की पूर्व स्वीकारोक्ति पर उनके कार्यालय ने दी सफाई

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे गृहयुद्ध के दौरान लापता हुए 20 हजार से ज्यादा लोगों के बारे में जांच चाहते हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को यह स्पष्टीकरण राजपक्षे के उस बयान के बाद जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लापता लोगों की मौत हो गई।

श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों और सरकार के बीच करीब तीन दशक तक गृहयुद्ध चला था। 2009 में कड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद यह युद्ध खत्म हुआ था। इस कार्रवाई की कमान वर्तमान राष्ट्रपति और तत्कालीन रक्षा मंत्री गोतबाया के ही हाथ में थी। उन पर युद्ध अपराध जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे। इस गृहयुद्ध में करीब एक लाख लोग मारे गए थे। गोतबाया ने हाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोआर्डिनेटर हाना सिंगर से मुलाकात के दौरान कहा था कि लापता लोगों के बारे में आवश्यक जांच के बाद उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, राजपक्षे ने संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी को बताया था कि वह मामले की जांच चाहते हैं। उनका कहना था कि जो लोग इस लड़ाई में मारे गए उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता।

वर्ष 2009 में गृहयुद्ध की समाप्ति पर सरकार ने जनगणना कराई थी। उस समय इस बात का पता चला था कि ज्यादातर लापता लोगों को लिट्टे ने अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इसकी पुष्टि उनके परिजनों ने भी की थी। लेकिन लड़ाई के बाद उनका कोई पता नहीं चला। सच्चाई यह है कि लड़ाई के दौरान इन लोगों की मौत हो गई थी। सेना से ताल्लुक रखने वाले चार हजार कर्मचारी भी लापता हैं। इन लोगों की भी लड़ाई के दौरान मौत हो गई लेकिन उनके शव बरामद नहीं हुए।

मैं अगर फिट रहा तो इस साल टी-20 विश्व कप के बाद भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा।
— शोएब मलिक, बल्लेबाज, पाकिस्तान

मैथ्यूज ने टेस्ट में जिंबाब्वे के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक

हरारे, एएफपी : श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने बुधवार को जिंबाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए पहला दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने 468 गेंदों में 16 चौके व तीन छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए। श्रीलंका ने पहली पारी नौ विकेट पर 515 रन बनाकर घोषित की और 157 रनों की बढ़त हासिल की। स्टंप तक जिंबाब्वे ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 30 रन बनाए।

दिल्ली के राणा ने पलटा विदर्भ का पासा

आखिरी दिन नीतिश की 68 गेंदों में 105 रनों की पारी की बदौलत दिल्ली ने विदर्भ को छह विकेट से हराया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: लगातार दो बार की रणजी चैंपियन विदर्भ ने जब दिल्ली के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन 330 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर मेजबान टीम को 347 रनों का लक्ष्य दिया था तो अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद दर्शक, दोनों टीमों के खिलाड़ी, राष्ट्रीय चयनकर्ता और मेजबान टीम के चयनकर्ताओं को भी लग रहा था कि अब मैच बचाना आसान नहीं होगा लेकिन बुधवार को नीतिश राणा ने जो किया उसने सबको गलत साबित कर दिया। दिल्ली की टीम बुधवार की सुबह दूसरी पारी में 10 रन से आगे खेलने उतरी। पहली पारी में 163 रन पर आउट होने वाली इस टीम के लिए यह नई सुबह थी और नीतिश उसके लिए सूरज बनकर आए। उन्होंने सिर्फ 68 गेंदों में सात छक्कों और आठ चौकों की मदद से नाबाद 105 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को हार से ही नहीं बचाया बल्कि सीधी जीत दिला दी। उनकी पारी की बदौलत दिल्ली ने 73 ओवर में चार विकेट पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

प्रतिभा के धनी: इस मैच में पहली पारी में विदर्भ के गेंदबाज अदित्य ठाकरे का बोलबाला रह था जिन्होंने सात विकेट लेकर मेजबान टीम के बल्लेबाजों की एक नहीं चलने दी थी लेकिन बुधवार को नीतिश पर किसी का कोई असर नहीं पड़ा और वह अपने शानदार कट, पुल शॉटों से सभी का दिल जीतते रहे। वह आइपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए खेलते हैं। राणा की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें बीसीसीआइ ने 2018/19 सत्र में घरेलू सीमित ओवरों के क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड खेल के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया था। नीतिश के शतक और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप-ए मैच के चौथे और अंतिम दिन बुधवार को यहां विदर्भ को छह विकेट से हरा दिया। विदर्भ ने पहली पारी में 179 रन बनाए थे जवाब में मेजबान टीम 163 रन पर ढेर हो गई थी और मेहमान टीम ने 16 रन की बढ़त ली थी। विदर्भ ने तीन विकेट पर 330 रनों पर दूसरी पारी घोषित की थी।

नीतिश का दिन: मैन ऑफ द मैच नीतिश जब क्रीज पर आए तो टीम का स्कोर एक विकेट पर 163 रन था और उन्होंने शुरुआत से अपने आक्रामक तेवरों से गत विजेता विदर्भ के खेमे में हलचल मचा दी। नीतिश ने 26 गेंदों में 50 रन पूरे किए। नीतिश को रोकने की विदर्भ की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। जब टीम को जीत के लिए पांच रनों की दरकार थी तो उन्होंने छक्का जड़कर मैच जिता दिया।

नीतिश का विदर्भ से लगाव: नीतिश ने रणजी करियर का पदार्पण 2015 में विदर्भ के खिलाफ ही किया था और उस मैच में उन्होंने 61 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया था। दिल्ली ने वह मैच अपने घर में 10 विकेट से जीता था। राणा ने 2017 के रणजी फाइनल में विदर्भ के खिलाफ दूसरी पारी में 64 रन बनाए थे। जहां तक इस मैच की बात है तो नीतिश ने शानदार स्लॉग स्वीप, कट और ड्राइव लगाए। विदर्भ के कोच चंद्रकांत पंडित ने पहली पारी में दिल्ली के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखकर दूसरी पारी को घोषित करके मैच जीतने के लिए जुआ खेला, लेकिन वह हार गए। नीतिश जब क्रीज पर आए थे तो विदर्भ के कप्तान फैज फजल ने उनके लिए सात खिलाड़ी ऑफ साइड में खड़े किए लेकिन उनकी यह नकारात्मक रणनीति भी फेल हो गई।

मजबूत साझेदारी: दिल्ली 10 रन से आगे खेलने उतरी। कुणाल चंदीला (75) और हितेन दलाल (82) की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 163 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। रजनीश गुरबानी ने 49वें ओवर में हितेन को पवेलियन भेजकर इस साझेदारी को तोड़ा। आदित्य ठाकरे के अगले ओवर में कुणाल भी विकेटकीपर को कैच दे बैठे। राणा ने इसके बाद कप्तान ध्रुव शौरी (44) के साथ तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 14.5 ओवर में 118 रन की साझेदारी करके टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। राणा ने इसके बाद अपना छठा प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया। दिल्ली की यह दूसरी जीत है और उसे छह अंक मिले। टीम के पांच मैचों में 16 अंक हो गए हैं। विदर्भ के इतने ही मैचों में 17 अंक हैं।

रणजी ट्रॉफी

विदर्भ के खिलाफ मैच जीतने के बाद खुश दिल्ली रणजी टीम ● ट्विटर

02 बार रणजी ट्रॉफी के इस सत्र में नीतिश ने शतक लगाया है जबकि वह दो अर्धशतक भी लगा चुके हैं

92 रन नीतिश ने रणजी ट्रॉफी में इससे पहले मैच में बनाए थे। उन्होंने वह अर्धशतकीय पारी पंजाब के खिलाफ मोहाली में खेली थी

35 प्रथम श्रेणी मैच नीतिश अभी तक खेल चुके हैं जिसमें वह नौ अर्धशतक और छह शतक जड़ चुके हैं। वह 43.29 की औसत से 2208 रन बना चुके हैं जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 174 रन है

11 विकेट नीतिश प्रथम श्रेणी मैच में ले चुके हैं। वह कामचलाऊ ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। उनका एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक रन देकर दो विकेट और मैच में सर्वश्रेष्ठ 34 रन देकर चार विकेट है

मैंने हमारे कोच को भरोसा दिलाया था कि 75 ओवर में लगभग 320 रन हमे बनाने हैं तो हम जरूर जीतेंगे। मेरी यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पारी है। मैं इंदौर में 2017 के फाइनल को नहीं भूला हूं जब विदर्भ ने हमसे मैच छीनकर जीत हासिल कर ली थी। मैं जानता हूं कि मैं स्पिनरों के खिलाफ लंबे शॉट खेल सकता हूं। मैं लोगों की सलाह को सुनता हूं जो कहते हैं कि मुझे अपने खेल में बदलाव करना चाहिए लेकिन यह मेरा खेलने का तरीका है और इसे मैं पसंद करता हूं।
नीतिश राणा, बल्लेबाज, दिल्ली

सरफराज का तिहरा शतक

मुंबई, प्रेट्र: युवा बल्लेबाज सरफराज खान के करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 301 रन की पारी से मुंबई ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-बी मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। उत्तर प्रदेश की पहली पारी में आठ विकेट पर 625 रन पर पारी घोषित के जवाब में मुंबई ने बुधवार को मैच के चौथे दिन सात विकेट पर 688 रन बनाकर पारी घोषित की। मुंबई की पारी घोषित होते ही मैच को समाप्त कर दिया गया। सरफराज ने 391 गेंद की नाबाद पारी में 30 चौके और आठ छक्के जड़े। उत्तर प्रदेश के लिए अंकित राजपूत ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। मुहम्मद सैफ को दो सिफलता मिली।

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मनु की अनदेखी पर भड़के पिता

नाराजगी
- सवाल उठाया, विजेताओं के चयन के पीछे क्या मापदंड है
- इस बारे में संपर्क करने पर किसी ने भी जवाब देना उचित नहीं समझा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए विचार नहीं किए जाने के बाद उनके पिता रामकिशन ने बुधवार को चयन मापदंड पर सवाल उठाए।

17 साल की इस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक हासिल किए हैं। वह 2018 में 16 साल की उम्र में मेक्सिको में हुए आइएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वालीं सबसे युवा निशानेबाज बनी थीं। उन्होंने उसके बाद शानदार प्रदर्शन जारी रखा। रामकिशन ने कहा, 'अगर इतने पदक जीतने के बाद उसे इस तरह से नजरअंदाज किया जाता है तो यह वास्तव में निराशाजनक है। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि पुरस्कार विजेताओं के चयन के पीछे क्या मापदंड है? क्या उसका प्रदर्शन इस लायक नहीं है?' रामकिशन ने कहा कि उन्होंने इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'हमने इसके लिए समय से पहले आवेदन किया था। मुझे किसी से पता चला कि मनु का नाम इस साल भी सूची में नहीं है तो मैंने सचिव, संयुक्त सचिव और सहायक सचिव को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जब भी मैंने फोन किया तो उनके निजी सहायकों ने कहा कि वे व्यस्त थे। मैंने उन्हें 25 ईमेल भी भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।' हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्र ने कहा, 'जिस चयनसमिति ने पुरस्कार विजेताओं का चयन किया उसमें खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे।'

मनु ने दिसंबर 2019 में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। कॉमनवेल्थ और यूथ ओलंपिक गेम्स की इस चैंपियन ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग का स्वर्ण जीता। उन्होंने चीन के पुतियान में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ विश्व कप फाइनल्स में भी पीला तमगा हासिल किया। मनु 2020 ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले 15 भारतीय निशानेबाजों में शामिल हैं, जो 10 मीटर और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं के लिए टीम में जगह मिलने पर भाग लेंगी।

इन पुरस्कार विजेताओं को बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। बेंगलुरु के यश अराध्य इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय मोटरस्पोर्ट्स चालक बने। कोविंद ने पांच से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 49 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया।

एक नजर में

रानी को अच्छे खेल की आशा

बेंगलुरु: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी ने बुधवार को कहा कि न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसी ऊंची रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ आगामी मैचों में अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक की बेहतर तैयारी साबित होगा। रानी ने इस सत्र के पहले दौरे के लिए ऑकलैंड रवाना होने से पहले यह बात कही। रानी ने कहा, 'हम न्यूजीलैंड (रैंकिंग छह) और ब्रिटेन (रैंकिंग पांच) जैसी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। इससे ओलंपिक की तैयारी मजबूत होगी। बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छी शुरुआत काफी मायने रखती है।' भारत को न्यूजीलैंड की डेवलपमेंट टीम से 25 जनवरी को खेलना है। इसके बाद 27 और 29 जनवरी को न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीमों से और चार फरवरी को ब्रिटेन से खेलना है। (प्रेट्र)

निखत क्वार्टर फाइनल में

नई दिल्ली: गत चैंपियन निखत जरीन (51 किग्रा) ने बुधवार को बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जब उनकी प्रतिद्वंद्वी सेवडा असेनोवा ने मुकाबला छोड़ दिया। असेनोवा इस टूर्नामेंट की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता हैं। पुरुष वर्ग के पहले दौर में दुर्योधन सिंह नेगी (69 किग्रा) ने पोलैंड के मतेउज पोलस्की को और मुहम्मद हसमुद्दीन (57 किग्रा) ने फ्रांस के एंजो ग्राउ को मात दी। भारत के छह मुक्केबाज हालांकि पहले दौर में बाहर हो गए। पुरुषों में अंकित खताना (75 किग्रा), एशियाई रजत पदक विजेता दीपक कुमार (52 किग्रा), नरेंद्र (+91 किग्रा) और नवीन कुमार (91 किग्रा) पहले दौर में बाहर हो गए। महिला वर्ग में नुपूर (75 किग्रा) और ललिता (69 किग्रा) बाहर हो गईं। शिव थापा को दूसरे दौर में बाई मिला, जहां उनका सामना पोलैंड के पावेल पोलाकोविक से होगा। (प्रेट्र)

भारतीय चुनौती समाप्त

बैंकाक: शीर्ष भारतीय शटलर साइना नेहवाल थाइलैंड मास्टर्स बैडमिंटन के पहले दौर में बुधवार को यहां डेनमार्क की होजमार्क जार्सफेल्ट से हारकर बाहर हो गईं, जिससे इस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती खत्म हो गई। पांचवीं वरीय साइना को 47 मिनट तक चले मुकाबले में 13-21, 21-17, 15-21 से हार मिली। जार्सफेल्ट के खिलाफ विश्व रैंकिंग में 18वें पायदान पर काबिज साइना का रिकॉर्ड इस मैच से पहले 4-0 का था। साइना इंडोनेशिया मास्टर्स के पहले दौर में भी हार गई थीं। पुरुष सिंगल्स में भारत के किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय और समीर वर्मा भी पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। वर्मा को ली जी जिया ने 21-16, 21-15 से हराया। (प्रेट्र)

कोहली सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे : स्टीव स्मिथ

नई दिल्ली, आइएएनएस: प्रतिबंध के बाद लौटकर अपने बल्ले से रन बरसाने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ अपने घर में एक और आइसीसी टूर्नामेंट खेलने को तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस साल टी-20 विश्व कप की मेजबानी करनी है और यह 2015 के बाद दूसरी बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया किसी आइसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। स्मिथ इस विश्व कप को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

स्मिथ ने कहा, 'कोई खास ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा टी-20 क्रिकेट खेलना चाहता हूं और सही लय हासिल करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि खेल के लिए यह मेरे लिए बहुत अहम चीज है। मैं विश्व कप का हिस्सा होना पसंद करूंगा, यह हमारे घर में है। मैंने यहां 2015 में वनडे विश्व कप खेला था और वो मेरे करियर के शानदार छह सप्ताह रहे थे, मैंने हर एक पल का लुत्फ उठाया था। इसलिए घर में एक और विश्व कप खेलना पसंद करूंगा।' भारतीय कप्तान विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा, 'वह शानदार हैं। उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। मुझे लगता है कि वह तीनों प्रारूप में अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि हम उन्हें सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखेंगे। उन्होंने अभी भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आने वाले दिनों में मैं उन्हें कई और रिकॉर्ड तोड़ते हुए देख सकता हूं। उनके पास रनों की भूख है। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह रुकें, यह अच्छा होगा। एक कप्तान के तौर पर उन्होंने भारत को टेस्ट में नंबर-1 बना दिया और जो मैं देख सकता हूं कि उन्होंने टीम के लिए अच्छे पैमाने तय किए। उन्होंने टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है और अविश्वसनीय तरीके से टीम की कप्तानी कर रहे हैं।'

स्टीव स्मिथ ● फाइल फोटो, ट्विटर

भारतीय टीम के मुख्य कोच ने कहा, हम हालात के अनुरूप खेलेंगे, विश्व कप जीतना हमारे लिए जुनून है

न्यूजीलैंड की पिचों को लेकर चिंतित नहीं हैं शास्त्री

नई दिल्ली, प्रेट्र: ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में वनडे सीरीज में हराने के बाद अब भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड को उसके घर में पहली टी-20 सीरीज में हराने के लिए वहां के हालात से भी तालमेल बैठना जरूरी है, लेकिन टीम के कोच रवि शास्त्री वहां की पिचों को लेकर चिंतित नहीं हैं। कोच का कहना है कि हम हालात के अनुरूप खेलेंगे।

कोच शास्त्री ने कहा, 'एक टीम के रूप में हम उस बारे में नहीं सोचते। हमारी कोशिश हालात के अनुरूप खेलने की रहेगी। हम इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे, बल्कि मौजूदा चीजों को ध्यान में रखकर खेलेंगे।'

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी छह वनडे, इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी का जरिया रहेंगे। शास्त्री ने कहा, 'टॉस की बात नहीं करें। हम दुनिया के हर देश में हर हालात और हर टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यही हमारी टीम का लक्ष्य है। विश्व कप जीतना जुनून है और हम उस इच्छा को पूरी करने के लिए सब कुछ करेंगे।' भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर टी-20 के अलावा तीन वनडे और दो टेस्ट खेलने हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज मार्च में होगी। उन्होंने कहा, 'इस टीम में 'मैं' शब्द नहीं है, 'हम' की बात होती है। हम एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाते हैं। जीत टीम की होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमारी मानसिक ताकत और दबाव में खेलने की क्षमता का सबूत थी। वानखेड़े पर बुरी तरह हारने के बाद हमने वापसी की, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। इससे हमारी बहादुरी का पता चलता है और यह साबित होता है कि हम बेखौफ क्रिकेट खेलने से नहीं डरते। यह टीम वर्तमान में जीती है। अतीत में जो हुआ, वह इतिहास है। हम उस लय को भविष्य में भी कायम रखना चाहेंगे।' कप्तान विराट कोहली पहले ही कह चुके हैं कि केएल राहुल से विकेटकीपिंग कराई जा सकती है और शास्त्री ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि टीम में राहुल जैसा प्रतिभा का धनी खिलाड़ी है। वह धवन को लगी चोट से दुखी हैं।

साउथी को भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद: न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउथी ने कहा वह भारत के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज में मिलने वाली चुनौती का इंतजार कर रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। साउथी को हालांकि न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए आखिरी टेस्ट की टीम से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह मैट हेनरी को अंतिम एकादश में शामिल किया गया था। वह हालांकि इससे पहले टीम के चारों मैच में अंतिम एकादश में शामिल थे। वह इंग्लैंड के खिलाफ दो मैचों की घरेलू सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दो टेस्ट में टीम का हिस्सा रहे थे।

ऑकलैंड में लंच के दौरान सेल्फी लेते कप्तान विराट कोहली, (बायें से तीसरे) रवींद्र जडेजा, लोकेश राहुल और मनीष पांडे ● ट्विटर

अंडर-19 विश्व कप जीतेगी भारतीय क्रिकेट टीम : रोहित

ऑकलैंड, प्रेट्र: सीनियर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बुधवार को उम्मीद जताई कि भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप जीतेगी। गत विजेता भारत ने श्रीलंका और जापान को हराकर सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रोहित ने ट्वीट किया, 'भारत की अंडर-19 टीम को शुभकामनाएं। उनकी शुरुआत शानदार रही है और वे खिताब बरकरार रख सकते हैं।' प्रियम गर्ग की कप्तानी में भारत ने जापान को 10 विकेट से हराया था। अब भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारत ने 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में विश्व कप जीता था।

टेनिस महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में नाओमी ने झेंग और कोरी ने क्रिस्टी को हराया, आसान जीत के साथ सेरेना भी तीसरे दौर में पहुंचीं

युवा सनसनी गॉफ के सामने होंगी गत चैंपियन ओसाका

जीत का जश्न मनाती ओसाका ● एएफपी

मेलबर्न, एएफपी: गत चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने चीन की झेंग सेइसेइ को 6-2, 6-4 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका सामना 15 वर्षीय अमेरिका की युवा सनसनी कोरी गॉफ से होगा। सेरेना विलियम्स ने भी बुधवार को अपने मुकाबले आसानी से जीतकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। पहले दौर में सात बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स को अपना शिकार बनाने वाली गॉफ ने दूसरे दौर में भी शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, पहले सेट में उन्हें हार मिली, लेकिन इसके बाद गॉफ ने जोरदार वापसी करते हुए अनुभवी सोराना क्रिस्टी को 4-6, 6-3, 7-5 से हराया।

ओसाका ने फेंका रैकेट: वहीं मार्गरेट कोर्ट एरीना पर ओसाका ने आसान जीत दर्ज की। दूसरे सेट की शुरुआत में सर्विस गंवाने से निराश ओसाका ने अपना रैकेट दूर फेंक दिया। हालांकि, इसके बाद उन्होंने अपने प्रयोजक योनेक्स से माफी मांगी। मैच के बाद ओसाका ने हंसते हुए कहा कि मेरे हाथ से रैकेट छिटक गया और मैं इस पर नियंत्रण नहीं रख पाई। सॉरी योनेक्स।

सेरेना की आसान जीत: सेरेना ने स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक पर आसान जीत के साथ तीसरे दौर में जगह पक्की की। पूरी तरह लय में नहीं होने के बाद भी 38 साल की इस खिलाड़ी को विश्व रैंकिंग में 70वें पायदान पर काबिज जिदानसेक को 6-2, 6-3 से हराने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी की कोशिश में जुटीं आठवीं वरीय सेरेना को अगले दौर में चीन की 27वीं वरीय वांग कियांग से भिड़ना होगा। वहीं, 2019 की उप विजेता रहीं पेत्रा क्वितोवा ने पाउला बाडोसा को 7-5, 7-5 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। कैरोलिन वोज्नियाकी ने यूक्रेन की डायना यास्ट्रेम्स्का को 7-5, 7-5 से मात दी। वहीं दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने बुधवार को तेज हवाओं के बीच खेलते हुए पोलोना हर्कोग को 6-1, 6-4 से हराया। धुएं और बारिश के बाद बुधवार को मेलबर्न पार्क पर तेज हवाओं ने अपना डेरा जमाए रखा।

शरण आगे बढ़े, बोपन्ना बाहर

मेलबर्न : भारत के दिविज शरण और न्यूजीलैंड के अर्टेम सिटाक ने बुधवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष डबल्स वर्ग के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। शरण और सिटाक की जोड़ी ने पुर्तगाल के पाब्लो कारेनो बुस्टा और स्पेन के जोआओ सोउसा को 6-4, 7-5 से हराया। वहीं, बोपन्ना और जापान के यासुताका यूचियामा की जोड़ी को अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन बंधुओं की जोड़ी से 1-6, 6-3, 3-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि, अभी बोपन्ना का इस टूर्नामेंट में सफर समाप्त नहीं हुआ है जिन्हें मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा के साथ उतरना है।

पुरुष सिंगल्स में जोकोविक का जलवा बरकरार

मेलबर्न: पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के गत चैंपियन नोवाक जोकोविक ने रॉड लेवर एरीना पर जापान के वाइल्डकार्ड धारी तत्सुमा इटो को महज 95 मिनट के खेल में 6-1, 6-4, 6-2 से मात देकर तीसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर में जीत के लिए मशक्कत करने वाले जोकोविक ने दूसरे दौर में 16 ऐस और 31 विनर लगाए और आसान जीत दर्ज की। यह 16 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन जोकोविक की मेलबर्न पार्क में 70वीं जीत रही जहां उन्हें महज आठ बार हार झेलनी पड़ी है। यूनान के स्टीफानोस सितसिपास को उनके प्रतिद्वंद्वी फिलिप कोहलश्रबर के चोट के कारण मुकाबले से हटने पर तीसरे दौर में जगह मिली। यूएस ओपन के पूर्व चैंपियन मारिन सिलिक ने फ्रांस के बेनोइट पियरे के खिलाफ पांच सेट तक चले मुकाबले में जीत दर्ज की, जबकि मिलोस राओनिक ने चिली के क्रिस्टियन गारिन को सीधे सेटों में हराया।

वेरेतिनी हुए उलटफेर का शिकार: पुरुष सिंगल्स के पांच सेट तक चले एक मैराथन मुकाबले में अमेरिका के टेनिस सेंडग्रेन ने आठवीं वरीय मातियो बेरेतिनी को 7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5 से हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया।

नोवाक जोकोविक ● एएफपी

हम दोनों एक-दूसरे के खेल से वाकिफ हैं। ओसाका काफी आक्रामक खेल दिखाती हैं। हालांकि, इस बार मैं ज्यादा आक्रामक खेल दिखाऊंगी।
कोरी गॉफ, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी

महिला सिंगल्स के अन्य नतीजे

- सोफिया केनिन ने एन ली को 6-1, 6-3 से हराया
- एकातेरिना एलेक्जेंड्रोवा ने बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-1, 6-3 से हराया
- जूलिया जॉर्जेस ने पेट्रा मार्टिच को 4-6, 6-3, 7-5 से हराया
- एरिना रेबाकिना ने ग्रीट मिनेन को 6-3, 6-4 से हराया
- कार्ल सुआरेज ने आर्यना सबालेंका को 7-6, 7-6 से हराया

अमांडा से सवाल पर भड़के किर्गियोस: ऑस्ट्रेलिया के टेनिस स्टार निक किर्गियोस बुधवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में अमेरिका की युवा खिलाड़ी अमांडा एनिसिमोवा के दिवंगत पिता पर सवाल पूछे जाने पर भड़क गए। पिछले साल यूएस ओपन से ठीक पहले अमांडा के कोच रहे उनके पिता कोंस्टांटीन एनिसिमोवा की अचानक मृत्यु हो गई थी। पहले दौर में अमांडा की हार के बाद उनसे पूछा गया कि अपने पिता के बिना उन्होंने अपना करियर कैसे नियंत्रित किया। अमांडा प्रेस वार्ता के दौरान रो पड़ीं। किर्गियोस ने ट्वीट किया, अगर आपके पास दिल है तो कृपया उसे महसूस करें।

भारत-ए की जीत में चमके शॉ और संजू

लिंकन (न्यूजीलैंड), प्रेट्र: बेजोड़ फॉर्म में चल रहे पृथ्वी शॉ की शानदार पारी के दम पर भारत-ए ने पहले अनधिकृत वनडे में न्यूजीलैंड-ए को पांच विकेट से हराया। शिखर धवन के चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम में चुने गए 20 वर्ष के शॉ ने 35 गेंद में 48 रन बनाए। भारत की टी-20 टीम में धवन की जगह आए विकेटकीपर संजू सैमसन ने 21 गेंद में 39 रन बनाए। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने 19 गेंद में 35 रन का योगदान दिया। जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य भारत ने 20 से अधिक ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया। भारत-ए के लिए मुहम्मद सिराज सबसे उपयोगी गेंदबाज रहे, जिन्होंने 6.3 ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट लिए। वहीं, खलील अहमद और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले। भारत-ए टीम ने न्यूजीलैंड-ए को नौ गेंद बाकी रहते 230 रन पर आउट कर दिया।

न्यूजीलैंड-ए के लिए रचिन रवींद्र ने 58 गेंद में 49 और कप्तान टॉम ब्रूस ने 55 गेंद में 47 रन बनाए। भारत-ए की शुरुआत तेज रही जब शॉ और मयंक अग्रवाल ने अपने मनचाहे अंदाज में रन बनाए। भारत का पहला विकेट 79 रन के स्कोर पर गिरा जब जेम्स नीशाम ने शॉ को पवेलियन भेजा। शॉ ने अभ्यास मैच में 100 गेंद में 150 रन बनाए थे। इस मैच में उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के जड़े। कप्तान शुभमन गिल 30 रन बनाकर आउट हुए। सैमसन ने अपनी पारी में दो छक्के और तीन चौके लगाए। मुंबई के सूर्यकुमार ने भी तीन चौके और दो छक्के जड़े। विजय शंकर ने 20 और क्रुणाल ने 13 रन बनाए।

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...
नई दिल्ली, गुरुवार, 23 जनवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

किताबी अंश

लालकिला से नेहरु ने जताई थी चिंता

गणतंत्र दिवस पर लाल किला में कवि सम्मेलन की परंपरा बहुत पुरानी रही है, एक जमाने में इस कवि सम्मेलन की दिल्ली के साहित्यप्रमियों को प्रतीक्षा रहती थी और वहां श्रोताओं की संख्या काफी होती थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु भी इस कवि सम्मेलन में वहां जाया करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक 'लोकदेव नेहरु' में कई जगह पर जवारलाल नेहरु के लाल किला पर होने वाले कवि सम्मेलन में जाने की बात लिखी है। कई दिलचस्प प्रसंग भी लिखे हैं। एक जगह दिनकर ने 1950 में लालकिला पर आयोजित कवि सम्मेलन के बारे में लिखा है, 'लाल किला का कवि सम्मेलन 26 जनवरी को हुआ था या 25 जनवरी को, यह बात मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है। किंतु उस सम्मेलन में पंडित जी भी आए थे और शायद, उन्हीं की मौजूदगी को देखकर मैंने 'जनता और जवाहर' कविता उस दिन पढ़ी थी। श्रोताओं ने खूब तालियां बजाईं, मगर पंडित जी को कविता पसंद आई या नहीं, उनके चेहरे से इसका कोई सुबूत नहीं मिला। पंडित जी कवियों का बहुत आदर करते थे, लेकिन कविताओं से वे बहुत उद्वेलित कभी भी नहीं होते थे। संसत्सदस्य होने के बाद मैं बहुत शीघ्र पंडित जी के करीब हो गया था। उनकी आंखों से मुझे बराबर प्रेम और प्रोत्साहन प्राप्त होता था और मेरा ख्याल है, वे मुझे कुछ थोड़ा चाहने भी लगे थे। मित्रवर फीरोज गांधी मुझे मजाक में महाकवि कहकर पुकारा करते थे। संभव है, पंडित जी ने कभी यह बात सुन ली हो, क्योंकि दो एकबार उन्होंने भी मुझे इसी नाम से पुकारा था। किंतु आओ महाकवि कोई कविता सुनाओ ऐसा उनके मुख से सुनने का सौभाग्य कभी नहीं मिला।

'दिनकर ने कवियों को लेकर जवाहरलाल के मन में चलने वाले द्वंद्व को भी प्रसंगों के माध्यम से उजागर किया है। दिनकर के मुताबिक पंडित जी उन दिनों लिखी जा रही कविताओं को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहते थे और कई बार अपनी ये अपेक्षा जाहिर कर चुके थे कि हिंदी के कवियों को कोई ऐसा गीत लिखना चाहिए जिसका सामूहिक पाठ हो सके। एक कवि सम्मेलन में जवाहर लाल जी पहुंच तो गए लेकिन खिन्न हो गए। दिनकर के मुताबिक 'सन् 1958 ई. में लालकिले में जो कवि सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष मैं ही था और मुझे ही लोग पंडित जी को आमंत्रित करने को उनके घर लिवा ले गए थे। पंडित जी आधे घंटे के लिए कवि सम्मेलन में आए तो जरूर मगर खुश नहीं रहे। एक बार तो धीमी आवाज में बुदबुदाकर उन्होंने यह भी कह दिया कि 'यही सब सुनने के लिए बुला लाए थे?'

जवाहर लाल नेहरु कवियों की सामाजिक भूमिका को लेकर भी अपनी चिंता यदा कदा प्रकट कर दिया करते थे। चाहे वो कोई गोष्ठी हो या कवि सम्मेलन नेहरु अपनी बात कहने से चूकते नहीं थे। दिनकर ने भी लोकदेव नेहरु में एक प्रसंग में इसका उल्लेख किया है, 'एक बार लालकिले के गणतंत्रीय कवि-सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात भी कही थी कि कवियों का जनता के समीप जाना अच्छा काम है। मगर कवि सम्मेलनों में वो कितनी बार जाएं और कितनी बार नहीं जाएं, यह प्रश्न भी विचारणीय है। 'दरअसल नेहरु की चिंता यह भी थी कि कवि जब अधिक कवि सम्मेलनों में शामिल होने लगता है तो वो फिर रचनात्मकता या उसकी स्तरीयता का ध्यान नहीं रख पाता है और वो उस तरह की कविता लिखने लग जाता है तो तालियां बटोर सके। 1950-60 में कविता को लेकर नेहरु की जो चिंता थी क्या आज वो चिंता दूर हो पाई है, हिंदी साहित्य जगत को विचार करना चाहिए।

-अनंत विजय

संभावनाओं का शहर है दिल्ली

शायद किसी शहर को जीना...उससे लगाव हो जाना इसी को कहते हैं। फिर भले आपका बचपन और युवापन उस शहर में न बीता हो फिर भी रगों में शहर ऐसे बस जाता है...कि उसी शहर की माटी के लगते हैं। हम बात कर रहे हैं आचार्य निशांतकेतु की। यूं तो अध्यापन से सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली आए लेकिन उनका अनुभव... इस शहर के प्रति स्नेह...संस्मरण बहुत कुछ बयां करता है। तभी तो पटना से भी दिल्ली की बैठकियों में...चले आते थे। आज भले उम्र 84 पार कर चुके हैं, अस्वस्थ हैं, बावजूद उनकी यादों में शुरुआती दौर से लेकर अबतक की दिल्ली का अक्स उतर आता है। उनके इसी सफर व दिल्ली के क्रमिक बदलावों पर आचार्य निशांत केतु से प्रियंका दुबे मेहता ने विस्तार से बातचीत की, प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

● दिल्ली गुरुग्राम को बनते देखा होगा, तब और अब कि दिल्ली में क्या अंतर पाते हैं?
दिल्ली का भौतिक विकास तो हो रहा है लेकिन सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अभी बहुत पीछे है। इस दृष्टि से पटना जैसा छोटा शहर समृद्ध हो रहा है। प्रयागराज, बनारस जैसे शहरों में साहित्यक गतिविधियों का सौरव व सुगंध अधिक है। अब दिल्ली और खास तौर पर लेखक वर्ग में एक सामूहिकता, सहयोगशीलता का अभाव है। इसलिए इसमें साहित्यिक सुगंध की कमी महसूस करते हैं। दिल्ली में अब बेगानापन बहुत हो गया है और वह अपनापन कहीं खो गया है।

● दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों की स्थिति को किस तरह से देखते हैं?
मैं इतिहास का छात्र था तो मेरे मन में यहां के इतिहास के लिए आदर है और ऐतिहासिक इमारतों व धरोहरों का अनादर मुझे अंदर से व्यथित कर जाता है। लाल किला से लेकर इंडिया गेट देखने के लिए आने वाले लोगों की संख्या आज भी उतनी ही है। लेकिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर न कोई विचार है, न कोई परामर्श, लोगों में चेतना का अभाव है। जब लाल किला बना था उस समय उसके के अंदर के लोगों को खाने-पीने का सामान खत्म हो जाता था तो लोग लंबे समय तक डर के मारे बाहर नहीं निकल पाते थे। पर्यटकों को इतिहास की उन स्थितियों से रूबरू करवाया जाना चाहिए। वह केवल किला नहीं बल्कि उसका एक प्रस्तर खंड अपने में एक इतिहास समेटे है।

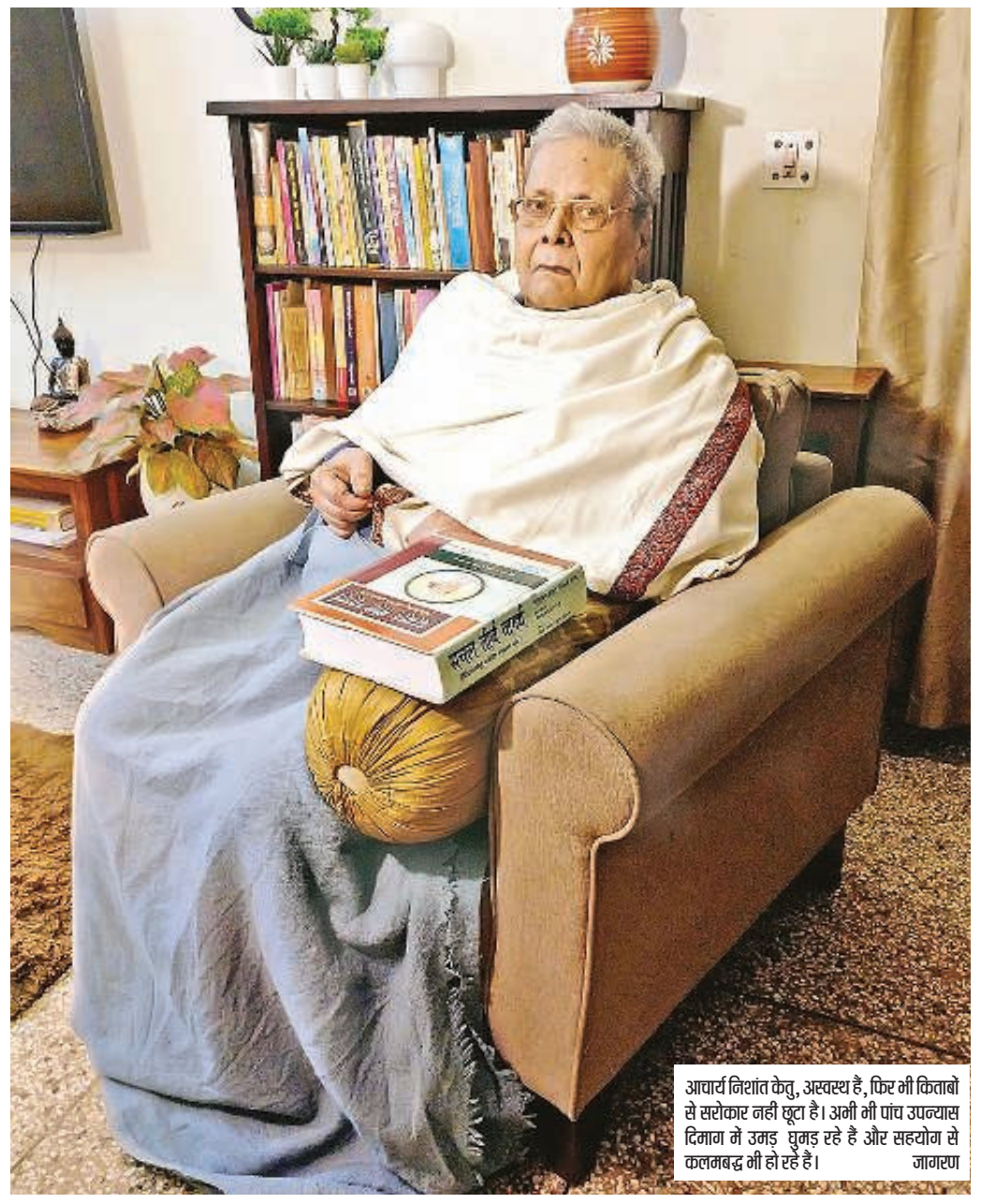
आचार्य निशांत केतु, अस्वस्थ हैं, फिर भी किताबों से सरोकार नही छूटा है। अभी भी पांच उपन्यास दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं और सहयोग से कलमबद्ध भी हो रहे हैं। जागरण

बातचीत

● आप पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे, ऐसा क्या लगा कि दिल्ली आ गए?
वैसे स्थाई रूप से तो मैं सेवानिवृत्ति के बाद यहां आया लेकिन दिल्ली का आकर्षण मुझे पहले से था। पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान भी मैं दिल्ली आया करता था। इस आकर्षण के दो कारण थे उनमें से एक था कि मेरे बच्चे यहां पढ़ते थे। दूसरा कारण यह था यहां पर प्रकाशक थे। दरअसल पटना में पढ़ाई का सत्र बहुत पीछे था ऐसे में बच्चों को दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में दाखिला दिलवाया था। प्रकाशक पटना में भी थे लेकिन इतने नहीं थे जितने की दिल्ली में। दिल्ली आने का एक और कारण बने लेखक मुल्क राज शर्मा 'आनंद'। वे बंटवारे के समय पाकिस्तान में थे। वहां से बच कर बड़ी मुश्किल से यहां आए थे। मैंने उनकी उर्दू की किताबों का अनुवाद कराकर संपादन व प्रकाशन करवाया था। उसके बाद उनके नाती से मेरी बेटी का विवाह हुआ।

● और बाद में ऐसा क्या आकर्षण हुआ इस शहर के ही हो गए?
वैसे हर शहर का अपना मिजाज होता है, इसी तरह दिल्ली का था। पटना में जातीय सीमाएं थीं लेकिन दिल्ली में यह लघुता नहीं थी, उस दौर में। दिल्ली में इतनी उदारता थी कि सभी को एक ही नजरिए से देखा जाता था। दिल्ली अच्छी लगी और अनुकूल भी तो यहां बसने का निर्णय ले लिया।

● फिर तो आपकी रचनाओं में भी इस शहर की छाया मिलती होगी?
हां, दिल्ली की संस्कृति से मैं बहुत प्रभावित था। इस शहर के प्रति मेरा अनुराग मेरे उपन्यास व कहानियों में भी झलकता है। मेरे उपन्यास योषाग्नि का एक खंड तो दिल्ली पर ही है। और भी कई लघु कथाएं हैं जिनमें दिल्ली का प्रभाव दिखता है।

● अच्छा संभावनाओं के नजरिए से इस शहर को कैसे देखते हैं?
दिल्ली में हर वर्ग के लिए हर तरह की संभावनाएं हैं। मेरे बच्चे आज फिल्म निर्देशक से लेकर विदेश में उच्च पदों पर आसीन हैं और हमेशा यही कहते हैं कि अगर वे दिल्ली न आते तो इतना विकास नहीं हो पाता। दिल्ली विकास में हर तरह से सहायक है। व्यक्तित्व विकास से लेकर शिक्षा तक में यहां अपार संभावनाएं हैं। दिल्ली में छोटे छोटे स्थानीय बेल्ट जरूर हैं जिससे अब थोड़ी लघुता जरूर प्रकट होती है लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली व्यापक है।

● शुरुआती दौर में कैसी व्यापकता देखी थी?
सांस्कृतिक स्थली है, राजनीतिक केंद्र है... और भी तमाम आकर्षण हैं जो इस शहर की व्यापकता को दर्शाते हैं। बेहद शांत थी दिल्ली। स्टेशन से लेकर कुतुबमीनार तक जंगल होता था। हम स्टेशन से टैक्सी करते और जब तक दो चार टैक्सियां साथ नहीं चलतीं हम कुतुबमीनार नहीं जा सकते थे। दरियागंज किताबों का मक्का था। जी भर कर किताबें खरीदते थे। कहीं पटरियों पर तो कहीं दुकानों पर... सब जगह पुस्तकें और पुस्तक प्रेमी। उस दौरान जब भी मैं दिल्ली आता था पहाड़गंज में रुकता था और कनॉट प्लेस और पालिका बाजार जाता था।

● यहां की साहित्यिक गोष्ठियों में भी शिरकत करते थे?
हां, दिल्ली में साहित्यिक बैठकी तो खूब होती थीं लेकिन दुख होता है कि अब वह माहौल नहीं रहा। इन गोष्ठियों में हिस्सा लेने के लिए पहले पटना में रहते हुए भी दिल्ली आते थे। हां, मैं क्षेत्रीयता वाली लघु गोष्ठियों का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता था। क्योंकि क्षेत्रवाद या जातिवाद मुझे बिलकुल पसंद नहीं आता है। यहां क्षेत्रीयता की दृष्टि से छोटे छोटे खंड बने हैं मैं कभी उनका हिस्सा नहीं बना। कॉफी हाउस में खूब जाया करते थे। इसके अलावा प्रकाशकों के प्रकाशन संस्थान में भी लेखकों से मिलना जुड़ना होता था।

● उस दौर में समकालीन लेखकों में किन से मुलाकात होती थी?
डॉ. श्याम सिंह शशि से अक्सर मुलाकात होती थी। उन दिनों वे एक पुस्तक संपादित कर रहे थे 'सामाजिक विज्ञान विश्व कोष'। वह पुस्तक दस खंडों में थी। उसमें मदद के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। कादंबिनी के संस्थापक राजेंद्र अवस्थी के साथ घंटों बातचीत होती थी।

● जिस दौर में आप यहां आए थे उस दौरान यहां पर स्थापित लेखकों का बोलबाला था? आपको यहां कितना संघर्ष करना पड़ा?
उस दौर में कम्यूनिस्ट विचारधारा के लेखकों का दौर था। लेखन और प्रकाशक पर उन्हीं की राजनीति का प्रभाव था। हम जैसे साहित्यिक और नॉन कम्युनिस्ट लेखकों को इतनी तवज्जो नहीं मिल पाती थी। प्रकाशक पूरी तरह राजनीति के प्रभाव में थे। उस समय साहित्य हाशिए पर खिसका दिया जाता था। अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इसमें मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में मैं बस लिखता रहता था प्रकाशन के लिए परेशान नहीं हुआ कभी। लगता था कि लिखो, जब छपना होगा, छप जाएगा। हां, प्रकाशक से अर्थराशि के लिए दौड़ धूप करनी पड़ती थी। कई प्रकाशकों ने कई कई बार बुलाया और लौटाया। अर्थराशि की प्राप्ति बहुत कम हुई। इस दृष्टि से पटना की टेक्स बुक कमेटी बेहतर थी। वहां अच्छा पैसा मिलता था।

● लोगों का पाठन और लेखन के प्रति रुझान बढ़ा है लेकिन बावजूद इसके अब साहित्य में गंभीर लेखन की कमी खटकती है?
ये बात तो है, आज गंभीर लेखन नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं। सबसे कटु कारण है वह है कि पूरी तौर पर लेखक होना रोजी रोटी नहीं चला पाता। दिल्ली में लेखन के बल पर आदमी नहीं जी सकता। अब लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। अब हिंदी में लिखना पढ़ना ट्रेंड बन रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ है। आज लेखन में चालू और बिकाऊ चीजों पर ध्यान है। उसके प्रभाव में कणीय लेखक आ रहे हैं जो कि हिंदी के लिए बहुत शुभ नहीं है। अब 'कामायनी' क्यों नहीं लिखी जा रही है। इसका कारण है कि दिल्ली में आने के बाद लोगों को यही लगता है कि आज लिखा और कल यश प्रतिष्ठा व पुरस्कार मिल जाए। लेखक अब लिखना नहीं, प्रशस्ति पाना चाहते हैं। दिल्ली में भाषा की स्वच्छता, स्वछंदता, शुद्धता व प्रांजलता का अभाव शुरुआत से खटकता रहा है। भाषा की शुद्धता की दृष्टि से बिहार और उत्तर प्रदेश का मुकाबला नहीं है। दिल्ली की भाषा पर पंजाब, राजस्थान का प्रभाव है। बहुत ही दुखद है कि दिल्ली में भाषिक आकर्षण नहीं है।

200
से अधिक किताबें व 1000 से अधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं साहित्य भूषण सम्मानित आचार्य निशांत केतु की

● दिल्ली की साहित्यिक संस्कृति के संवर्धन के लिए किस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए?
संस्थाओं की दृष्टि से सहयोग की आवश्यकता है। साहित्यिक संस्थाएं राजनीतिक प्रभावों से मुक्त होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को सहयोग करना चाहिए इसमें। जहां तक अन्य संस्थाओं का सवाल है। उन्हें अपनी लघुताएं भुलाकर हिंदी के लिए सामूहिक दृष्टि से बहुत कुछ करना चाहिए। प्रवासी भारतीय को लेकर तो कुछ काम हुआ लेकिन व्यापक ढंग से नहीं हो पाया। प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य को ज्यादा समृद्ध कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसलिए उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

● उस समय और आज के विश्विद्यालयों की संस्कृति में कितना अंतर पाते हैं?
जेएनयू तो उस दौर से ही राजनीति का अखाड़ा बना रहा है। अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई व साहित्यिक गतिविधियों के प्रति गंभीरता दिखती थी। जामिया मिल्लिया विवि इस मामले में बहुत आगे थी। वहां मुझे अक्सर बुलाया जाता था। वहां एक प्रभाग है जिसमें श्रेष्ठ लेखकों की संपूर्ण पुस्तकें रखी जाती हैं। उसमें मेरी पुस्तकें भी रखी गई हैं। पहला प्रकोष्ठ प्रेमचंद है और दूसरा मेरा है।

● एक दौर था जब लेखन का अंकुर अक्सर विश्वविद्यालयों से फूटता था, आज क्या स्थिति देखते हैं?
आज विश्वविद्यालयों में इतनी साहित्यिक अभिरुचि नहीं रह गई है। मैंने इतनी किताबें खरीदी कि घर किताबें से भर गया। ऐसे में मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर विश्वविद्यालयों तक में संपर्क कर इन पुस्तकों को दान करने का निर्णय लिया। तकरीबन 25 लाख की किताबें थी कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। यह समाज की किताबों के प्रति विरक्ति का ही उदाहरण है। दिल्ली से निराशा मिली तो अंत में मगध विवि के वीसी ने किताबें लेने की इच्छा जाहिर की। वहां मेरे नाम पर एक कक्ष सुरक्षित करके किताबें सजाई गई हैं।

● अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपका लेखन जारी है, यह कैसे संभव हो पाता है?
मैं अब लेखन डिक्टेशन से ही करता हूं। कई उपन्यास मेरे मन में चल रहे हैं और उनके सौ से अधिक पृष्ठ लिखे भी जा चुके हैं। उन्हें पूरा करना चाहता हूं। फिलहाल पांच उपन्यास हैं जिन्हें पूरा करना है। इसमें 'सागर लहरी' उपन्यास को अपने अध्यापन जीवन के अनुभवों के आधार पर कैंपस लाइफ को केंद्र बनाकर लिख रहा हूं।

मिट्टी की मूर्तियां करती हैं बातें

मिट्टी की ये कलाकृतियां इतनी आकर्षक है मानों अब बोल पड़ेंगी। जागरण

काम की दुकान

सिर पर मटकी लिए महिला को देख पास से गुजरते हर शख्स की निगाहें थम जाती हैं। बगल में सिर पर फूलों का टोकरा लिए एक और आकृति, हाथी, घोड़े, दीये लालटेन और लैंप सब कुछ इतना आकर्षक मानो कल्पनाओं की दुनिया में आ गए हों। माताजी मूर्ति कला केंद्र में पहुंच कुछ ऐसा ही तो महसूस करते हैं लोग। वातावरण में मिट्टी की सोंधी खुशबू चारो ओर रंग-बिरंगी कलाकृतियां सब कुछ बेहद आकर्षक। यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सब मिट्टी की बनी हुई हैं। दरियागंज पदमचंद मार्ग स्थित इस दुकान पर हस्तनिर्मित मिट्टी की वस्तुओं का भंडार है। यहां दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान, गुजरात, कलकत्ता व उत्तर प्रदेश के लखनऊ और खुर्जा क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तैयार मिट्टी की मूर्तियां, मटके व अन्य कलाकृतियां घर की सजावट में चार-चांद लगा देंगी।

खुलने का समय
सुबह आठ से रात दस बजे तक कभी आप यहां खरीदारी कर सकते हैं। रोजाना खुलती है।

मां को देख मिली प्रेरणा : कौन गढ़ता है इन्हें, किसके हुनर का है ये कमाल इस बारे में दुकान संचालक विजय कुमार राठौर कहते हैं कि उनकी मां संतरा देवी करीब 50 वर्षों से मिट्टी के दीये व मटके बनाती आ रही हैं। बचपन से ही वे अपनी मां के हुनर को देखते आ रहे हैं। उनको देखकर वे भी इस कला में माहिर हो गए। जब वे 15 वर्ष के थे तभी से मां के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। अब उन्हें भी मिट्टी की कारीगरी करते हुए करीब 27 वर्ष हो चुके हैं। कहते हैं मां ने पहले कारीगरों से यह काम सीखा था फिर खुद ही हाथ से दीये व मटके बनाकर बेचने लगीं। अब तो अन्य राज्यों से भी सामान मंगवाकर दुकान पर बेचा जाता है। सामान की अच्छी गुणवत्ता के कारण दूर-दराज से लोग यहां खरीदारी करने आते हैं।

राजस्थानी मटका से लेकर कोलकाता की मूर्ति तक : घर को देसी मिट्टी से बनी सुंदर व आकर्षक वस्तुओं से सजाने की इच्छा रखते हैं तो यहां एक से बढ़कर एक खुबसूरत दीये, मूर्तियां, मटके व सुराही का भंडार है। यहां आपको राजस्थान के मटके, उत्तर प्रदेश के लखनऊ व खुर्जा के मटके व सुराही और कोलकाता की मूर्तियां मिल जाएंगी। वहीं, विजय और उनकी मां खुद भी घर पर मिट्टी से दीये, गुल्लक, सुराही व मिट्टी के बर्तन की टंकी तैयार करते हैं। अगर आप देवी-देवता की प्रतिमा चाहते हैं तो भगवान विष्णु, लक्ष्मी गणेश, काली मां से लेकर करीब तीन हजार आइटम मिल जाएंगे। महज दस रुपये में पंद्रह प्लेन दीये मिल जाएंगे, वहीं रंग-बिरंगे डिजाइनर दीये की कीमत एक रुपये है। 100 रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं।

-रितु राणा

फुर्सत का ज्ञान

मातृभाषा को संरक्षित करने में जुटा पुस्तकालय

मातृभाषा दुनिया की हर संस्कृति का वो अभिन्न अंग है जिससे प्रत्येक समुदाय की पहचान जुड़ी है। इसीलिए कहते हैं कि मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। ऐसे में कई भाषाएं सीखना गलत नहीं है लेकिन इस होड़ में अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ देना यकीनन सही भी नहीं है। आज के दौर में एक संस्थान ऐसा भी है जो अधिकाधिक बोली जाने वाली मातृभाषा का संरक्षण करने में जुटा है। इसी उद्देश्य को लेकर हिंदी अकादमी द्वारा लखनऊ रोड पर हिंदी प्रसार केंद्र पुस्तकालय व वाचनालय की शुरुआत की गई। यहां हिंदी प्रेमियों के लिए हिंदी साहित्य से जुड़ी सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी यहां हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। पुस्तकालय प्रभारी कहते हैं कि उनका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को पाठकों तक पहुंचाना है। यहां हिंदी साहित्य से जुड़ी कहानी, उपन्यास, कविता व शब्दकोश की पुस्तकों का खजाना है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं।

वर्ष 1983 में हुई थी शुरुआत : छत्रसाल स्टेडियम में हिंदी प्रसार केंद्र पुस्तकालय की नींव तत्कालीन शिक्षा पार्षद व हिंदी अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष कुलानंद भारती वर्ष 1983 में रखी थी। हालांकि वर्ष 2001 में स्टेडियम के पुनर्निर्माण के कारण पुस्तकालय को लखनऊ रोड स्थित शिक्षा विभाग के मंडल कार्यालय परिसर में विस्थापित कर दिया गया। पुस्तकालय के पास ही दिल्ली विश्वविद्यालय होने की वजह काफी बच्चे आते हैं। दो हजार किताबों से शुरु हुआ पुस्तकालय का सफर उन्नति पर रहा। जैसे-जैसे यहां पाठकों की संख्या बढ़ती गई पुस्तकों की संख्या का भी विस्तार हुआ। आलम यह है कि वर्तमान में यहां हिंदी साहित्य से जुड़ी करीब 18 हजार पुस्तकों का भंडार है।

वे किताबें जो हैं आकर्षण का केंद्र : पुस्तकालय में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो खासकर पाठकों को आकर्षित करती हैं। इनमें सचित्र विश्व विज्ञान कोष, संस्कृत हिंदी शब्द कोष, हिंदी पर्यायवाची कोष, मार्क्सवादी सौंदर्यशास्त्र और हिंदी उपन्यास, काम भाव की नई व्याख्या, चरित्र निर्माण, हिंदी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य और कला, अतीत के अवसाद, मैला आंचल, भारत तब से अब तक-भगवान सिंह, आरक्षण का देश-अरुण स्वरी, स्त्रीत्व के बंधन- आशा अरोड़ा, सबसे बड़ा सिपहिया- वीरेंद्र जैन, यथा संभव-शरद जोशी, तीसरी आंख-अमृता प्रीतम, प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र व अन्य रचनाएं, किनारे से किनारे तक- राजेंद्र यादव, अंधे मोड़ से आगे सहित कई रोचक किताबें शामिल हैं।

पहाड़ी संस्कृति का बेहतरीन कोष : इस पुस्तकालय का एक आकर्षण यहां मौजूद उत्तराखंड के साहित्यकारों की पुस्तकें हैं। जिनमें शिवानंद नौटियाल की तपोभूमि गढ़वाल, कुमाऊं भाषा और साहित्य -डॉ. नारायण दत्त पालीवाल, प्राइवेट सेक्टर का व्यंग्यकार, -प्रदीप पंत, निहारिका- गोविंद वल्लभ पंत, अंतिम आवाज- वल्लभ डोभाल, आप मुक्ति तथा अन्य कहानियां-शैलेश मटियानी, बर्फ की चट्टानें, गाए जा- विद्यासागर नौटियाल, थाप -रामशरण जोशी, राष्ट्रीय संस्कृति संपदा- डॉ. जगमोहन जोशी, पर्यावरण और संस्कृति का संकट- डॉ. गोविंद चातक की लिखी किताबें शामिल हैं जो पहाड़ की संस्कृति व जीवन का अद्भुत चित्रण करती हैं।

इसके अलावा यहां कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो अब आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं लेकिन यहां वो भी मिल जाएंगी। इनमें अथर्ववेद संहिता सनातन भाषाएं, अथर्ववेद संहिता मूल पाठ, सारे सुखन हमारे- फैज अहमद फैज, कथा एक प्रांतर की- एस के पोट्टेकाट, भारत के यायावर- डॉ. श्याम सिंह शशि, साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी, सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध- भारतीय ज्ञानपीठ आदि शामिल हैं।

पत्रिकाओं के साथ उम्दा बाल साहित्य भी : आजकल बाल साहित्य की किताबें मिलना भी मुश्किल हैं लेकिन इससे संबंधित यहां करीब 500 किताबों का उम्दा संग्रह है। इन किताबों में चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज, चिल्ड्रंस नॉलेज बैंक, संगठन में शक्ति है, गोरा बादल, नन्हें सैनिक बालगीत, छोटा बड़ा, दक्षिण भारत की कहानियां आदि शामिल हैं।

रितु राणा

लखनऊ रोड स्थित हिंदी प्रसार केंद्र पुस्तकालय...यहां हर दिन ऐसा ही नजारा होता है छात्र आते हैं और दिनभर इसी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। जागरण

18000
पुस्तकों का खजाना है यहां, कभी हिंदी साहित्य से जुड़ी महज 2000 पुस्तकें ही होती थीं

ऐसे लें सदस्यता
पुस्तकालय में सदस्यता लेने के लिए वार्षिक शुल्क 100 रुपये है। इसके लिए एक पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और 500 रुपये सुरक्षा निधि जमा की जाती है जो रिफंडेबल है।

ऐसे पहुंचे
नजदीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ कदम की दूरी पर शिक्षा विभाग के परिसर में पुस्तकालय है।

पुस्तकालय खुलने का समय
सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक यहां पढ़ाई कर सकते हैं। शनिवार व रविवार को पुस्तकालय बंद रहता है।

कांग्रेस का सियासी एकाधिकार खत्म करने वाली जनता पार्टी का गठन

आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को खत्म कर दिया गया। इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए 1977 में आज ही चार विपक्षी दलों ने जनता पार्टी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार हारी और जनता पार्टी 298 सीटें जीती।

20 साल बाद हुआ अमेरिका-वियतनाम में शांति समझौता

अमेरिका और वियतनाम के बीच करीब 19 साल, पांच महीने और चार हफ्ते तक चले युद्ध के बाद आज ही 1973 में शांति समझौता हुआ था। अमेरिका द्वारा लड़े गए अब तक के सबसे लंबे इस युद्ध में 4.80 लाख सैनिक मारे गए।

सियासत में लंबी रेखा खींचने वाले कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे

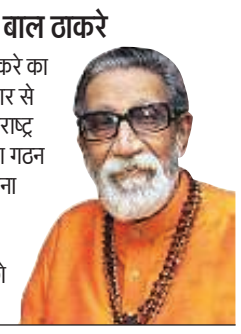

अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले बाल ठाकरे का जन्म 1926 में महाराष्ट्र के पुणे में आज ही हुआ। प्यार से लोग उन्हें बाला साहेब कहकर बुलाते थे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों और वहां की राजनीतिक नब्ज को समझ शिवसेना का गठन किया। बतौर कार्टूनिस्ट अपने करियर शुरू किया। बाद में अपना अखबार भी निकाला। उनका फिल्मी दुनिया से भी गहरा नाता रहा है। सचिन तेंदुलकर को बाल ठाकरे बेहद पसंद करते थे। आपातकाल का उन्होंने समर्थन किया था। 17 नवंबर, 2012 को आखिरी सांस ली।

आर्कटिक महासागर के गर्म होने की बड़ी वजह मानव हस्तक्षेप

- अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने किया दावा
- कहा- ओजोन को क्षीण करने वाले रसायनों के कारण बिगड़ी स्थिति

यह अध्ययन जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि आर्कटिक महासागर में पिछली सदी में जितना तापमान बढ़ा है उसमें मानव हस्तक्षेप की 50 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी है। मानव हस्तक्षेप से मतलब ऐसे रयायनों और गैसों का उत्सर्जन है जो ओजोन परत को क्षीण करते हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि रेफ्रिजरेटर, एसी आदि से होने वाले उत्सर्जन के कारण 1955 से 2005 के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, जिससे इसका बहुत बड़ा क्षेत्र पिघल गया है। जर्नल नेचर में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि ये रसायन क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जैसे हैलोजन तत्वों से बने यौगिक होते हैं और ऊपरी वातावरण में ओजोन की सुरक्षात्मक परत को नष्ट करते हैं।

अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता लोरेंजो पोलवानी ने कहा कि हालांकि इन रसायनों के उत्सर्जन पर धीमी गति से ही सही, पर अब काफी हद तक अंकुश लगा है। उन्होंने कहा, '1987 में ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक समझौता हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तब से इस दिशा में काफी बदलाव आया है।' उन्होंने कहा कि मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें (जीएचजी) में लंबे वायुमंडलीय में बनी रहती हैं, जिसके कारण गर्मी बढ़ती है।

ग्रीन हाउस गैसों ने बढ़ाई चिंता : अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि गर्मी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका निर्विवाद रूप से प्रमुख रही है लेकिन हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि मानवजनित जीएचजी के उत्सर्जन के कारण भी बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा था।

जलवायु मॉडल का किया उपयोग : इस अध्ययन के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए पोलवानी और उनकी टीम ने इन पदार्थों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए एक जलवायु मॉडल का उपयोग किया। उन्होंने दो सिमुलेशन किए- एक जिसमें 1955-2005 के दौरान प्राकृतिक और मानव उत्सर्जन मापा गया था और दूसरे में हैलोजन रसायनों और उनके ओजोन प्रभावों को हटा दिया गया था। दोनों की तुलना में वैज्ञानिकों ने जलवायु प्रणाली पर इन रसायनों का शुद्ध प्रभाव पाया। उन्होंने कहा कि आर्कटिक पर गर्मी के लिए जितनी जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है उतनी ही जीएचजी भी है।

...और कई गुना बढ़ जाती है गर्मी : अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह भी दिखाया कि ओडीएस यानी आजोन को कम करने वाले पदार्थों कारण अन्य कारकों की अपेक्षा गर्मी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि ओजोन की परत में क्षरण होने से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। जिससे गर्मी की दर में कई गुना वृद्धि हो जाती है।

गर्मी को कम करने में मिलेगी मदद : शोधकर्ताओं के अनुसार, आर्कटिक वार्मिंग और समुद्री बर्फ के नुकसान के लिए ओडीएस लगभग आधे से अधिक जिम्मेदार हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि ओडीएस जलवायु प्रभावों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से इन रसायनों के उत्सर्जन को कम करने से आर्कटिक वार्मिंग और समुद्री बर्फ के पिघलने की दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटना है तो प्रभावी कदम उठाने ही होंगे।

गगनयान दूसरे ग्रहों पर मानव मिशन भेजने में करेगा मदद

स्पेक्ट्रम

बेंगलुरु में बुधवार को इसरो के चेयरमैन के सिवन ने अंतरिक्ष में स्टेशन बनाए जाने की भी घोषणा की। एएनआइ

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि गगनयान अभियान का मकसद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्षयान से दूसरे ग्रहों पर भेजना भी है। अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए भी काम शुरू कर दिया है। इसे अगले साल लांच किया जा सकता है।

इसरो के चेयरमैन के. सिवन ने बुधवार को ह्यूमनॉयड की अंतरिक्ष उड़ान और खोज : मौजूदा चुनौतियां और भविष्य के चलन : एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बताया कि दिसंबर 2021 में भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष अभियान से पहले भी दो मानवरहित अभियान क्रमशः दिसंबर 2020 और जून 2021 में भेजे जाएंगे। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का पहला स्वदेशी मिशन ही नहीं होगा बल्कि इसका मकसद लगातार मानव उपस्थिति के लिए एक नया स्पेस सेंटर बनाना भी होगा। उन्होंने कहा, हम यह सब (गगनयान) तीन बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं। पहले बिंदु में-कम अवधि की योजना है। इसमें दिसंबर-2020 और जून-2021 के मानवरहित अभियान होंगे। फिर दिसंबर 2021 में देश का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान होगा। इसके प्रशिक्षण के लिए चार भारतीयों को इस महीने के अंत में रूस में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

दूसरे बिंदु में-मध्यावधि के लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। मानव अंतरिक्ष अभियानों को लगातार जारी रखना और निरंतर अंतरिक्ष में मानव मौजूदगी के लिए अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना अहम लक्ष्य होगा। इस संबंध में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को पूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए बेंगलुरु के पास ही एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। इससे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इसरो की इस संबंध में नासा, अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों और औद्योगिक क्षेत्रों से बातचीत चल रही है। इसरो प्रमुख ने बताया कि तीसरे बिंदु में-लंबी अवधि की योजनाएं शामिल होंगीं। इसमें गगनयान दूसरे ग्रहों पर मानव मिशन भेजने की योजनाओं में मदद करेगा।

ध्यान रहे नरेंद्र मोदी सरकार ने गगनयान परियोजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। गगनयान का मानव अभियान भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर वर्ष 2022 में होना प्रस्तावित है।

इधर-उधर की

कौवे की अनोखी नाराजगी

लंदन, एजेंसी : एक कौवे की नाराजगी यहां के ग्रीनफील्ड्स कम्युनिटी हाउसिंग सोसायटी के लोगों पर भारी पड़ रही है। यहां के ब्रेनट्री एसेक्स के रहने वाले लोगों की कारों के विंडस्क्रीन वाइपर आए दिन क्षतिग्रस्त मिल रहे हैं। लगातार एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद इसकी पड़ताल की गई। जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। दरअसल, एक कौवा पिछले कई महीनों से यहां पार्क की गई कारों के विंडस्क्रीन वाइपर को नुकसान पहुंचा रहा है। जब भी लोग उसे दूर तक भगाकर आते तो वह दोबारा लौटकर आ जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौवे को इससे क्या दुश्मनी है? आलम यह हो गया है कि अब लोग अपनी कारों के विंडस्क्रीन वाइपर को कंबल या किसी मोटे कपड़े से ढककर रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस कौवे के कारनामे काफी वायरल हो रहे हैं और यूजर इससे बचने के लिए तरह-तरह के सुझाव भी दे रहे हैं।

ग्लूकोमा से बचाएगी आनुवंशिक जांच

तलाशी राह ▶ ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खोजी नई विधि

ग्लूकोमा पॉलिजेनिक रिस्क स्कोर से होगी बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन्स की पहचान

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : वैज्ञानिकों ने अंधेपन के इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने ग्लूकोमा (काला मोतियाबिंद) का पता लगाने के लिए एक नई विधि विकसित की है। वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि ग्लूकोमा पॉलिजेनिक रिस्क स्कोर (पीआरएस) के जरिये इस बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके लिए 107 जीन जिम्मेदार होते हैं। नई विधि के जरिये अन्य जीन्स का भी पता लगाया जा सकता है।

ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है, जो आंखों की तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है और इससे धीरे-धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। एक अनुमान के मुताबिक, 2020 के अंत तक विश्व के 7.6 करोड़ लोग इसकी चपेट में होंगे। अभी तक इसका प्रमाणिक इलाज नहीं मिल पाया है। रोकथाम के लिए इलाज की प्रक्रिया काफी धीमी है, इससे उसका असर भी खत्म हो जाता है। यहां तक कि 50 फीसदी मामलों में इससे प्रभावित लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है।

ग्लूकोमा आनुवंशिक बीमारी है। प्रतीकात्मक

लार और रक्त के नमूने से हो सकती है पहचान : मैक्ग्रेगोर ने बताया, 'हमारे अध्ययन से पता चला कि लार या रक्त से एकत्र डीएनए का विश्लेषण करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी में ग्लूकोमा होने की संभावना कितनी है। साथ ही, यह भी कि किन्हें शुरुआती इलाज और मॉनिटरिंग की जरूरत है।'

हर 30 ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से एक है ग्लूकोमा का शिकार : इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के ऑपथेलमोलॉजी विभाग के अकादमिक प्रमुख जेमी क्रेग ने बताया कि अध्ययन से यह उम्मीद बनी है कि भविष्य में ग्लूकोमा के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की जा सकती है। प्रोफेसर क्रेग ने बताया, 'ऐसे कई ऑस्ट्रेलियाई हैं, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले उचित इलाज कराया होता, तो उन्हें अंधेपन का शिकार नहीं होना पड़ता।' उन्होंने बताया, 'हर 30 ऑस्ट्रेलियाई में एक ग्लूकोमा का शिकार है, लेकिन उन्हें यह तभी पता चलता है, जब वे नेत्र-विशेषज्ञ या सामान्यतया आंखों की जांच के लिए जाते हैं। इलाज के लिए शुरुआती स्तर पर पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था में एक बार दृष्टि जाने के बाद उसे वापस लाने का इलाज नहीं है। साथ ही, देर से ग्लूकोमा का पता लगने पर अंधेपन का खतरा काफी अधिक है।'

उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो जाती है बीमारी : क्रेग ने बताया कि ग्लूकोमा किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन इससे अधिकांश पीड़ित लोगों की उम्र 50 या उससे अधिक है। इसलिए हमारा मकसद लोगों को खून की जांच कराने के लिए कहना है, ताकि उस उम्र के लोगों को पता चल सके कि उनमें इसके लक्षण हैं।

शुरुआती स्तर पर इलाज से हो सकता है फायदा

इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता और क्यूआइएमआर बरगॉफर के स्टैटिस्टिकल जेनेक्सि ग्रुप के एसोसिएट प्रोफेसर स्टुअर्ट मैक्ग्रेगोर का कहना है कि जीन की पहचान करने से उन्हें ग्लूकोमा पॉलिजेनिक रिस्क स्कोर (पीआरएस) विकसित करने में मदद मिली, जो यह पता लगा सकता है कि किस व्यक्ति में आंखों की यह बीमारी होने वाली है। मैक्ग्रेगोर ने बताया, 'ग्लूकोमा की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका शुरुआती स्तर पर इसकी पहचान कर इलाज कराना है।' उन्होंने कहा कि आंखें हमें इस दुनिया के दीदार करती हैं। इसलिए इनकी नियमित जांच जरूर करवानी चाहिए। यदि परिवार में किसी को ग्लूकोमा हो तो हमें और तटस्थ रहने की जरूरत है।

पाम ऑयल के पौधे भी बढ़ाते हैं ग्लोबल वार्मिंग

लंदन, प्रेट्र : पाम ऑयल की खेती पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। बड़े पेड़ों की तुलना में इसके छोटे पौधों से ग्रीनहाउस गैसों का दोगुना उत्सर्जन होता है। एक नए अध्ययन में यह दावा करते हुए शोधकर्ताओं ने कहा कि इसका अर्थ है कि इसके पौधे ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हैं।

जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित यह शोध पाम ऑयल प्लांटेशन (पौधरोपण) के विभिन्न चरणों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की जांच करने वाला पहला अध्ययन है। इसे ब्रिटेन की नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मलेशिया के उत्तरी सेलांगोर पीट के जंगल में किया था।शोधकर्ताओं ने कहा कि पाम ऑयल एक वनस्पति तेल है, जिसकी दुनिया में सबसे अधिक खपत होती है। इसकी वैश्विक मांग पिछले अठारह वर्षों में तिगुनी से अधिक हो गई है। जहां वर्ष 2000 में इसका उत्पादन लगभग 20 मिलियन यानी दो करोड़ टन होता था वहीं, 2018 में यह मात्रा बढ़कर सात करोड़ टन हो गई। मलेशिया पाम ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने भूमि उपयोग के चार अलग-अलग चरणों में पांच साइटों का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि परिपक्व पाम ऑयल के पेड़ों की तुलना छोटे पौधे 50 फीसद ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये उत्सर्जन क्षेत्र के लिए कुल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।

फोटो न्यूज

लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में भड़की हिंसा

लेबनान राजधानी बेरुत में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान बुधवार को फिर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर रखकर उनमें आग लगा दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर झड़पें भी हुईं। दरअसल, देश में गहराता आर्थिक संकट लोगों की चिंता का सबसे बड़ा सबब है। लोग नई सरकार के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं। एएफपी

नई सर्जरी से जल्द जुड़ेगी टूटी पसली

शोध अनुसंधान

शोधकर्ताओं ने सर्जरी की एक नई प्रक्रिया विकसित की है। इससे टूटी पसलियों को जल्दी जोड़ा जा सकता है। इसमें दर्द का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा उपचार में टूटी पसलियों को जोड़ने की प्रक्रिया में लंबे समय तक दर्द का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के करीब एक दर्जन मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने सर्जिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ रिब फ्रैक्चर (एसएसआरएफ) प्रक्रिया का परीक्षण किया है। इस प्रक्रिया में फ्रैक्चर के दोनों छोर को एक प्लेट के जरिये जोड़ा जाता है। यह पसली के दुरुस्त होने की पूरी प्रक्रिया के दौरान लगा रहता है। तीन या ज्यादा पसलियों के टूटने के कारण एसएसआरएफ से गुजरने वाले रोगियों ने इस प्रक्रिया में मामूली दर्द होने की बात कही। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के सर्जन एवर्ट एरिकसन ने कहा, 'शोध से जाहिर होता है कि फेफड़ों की समस्या से पीड़ित लोगों को भी इस प्रक्रिया से लाभ हो सकता है।' -एएनआइ

किशोरों में डिप्रेशन के खतरे को भांप सकेगा नया टूल

शोधकर्ताओं ने एक ऐसा टूल विकसित किया है, जो किशोर उम्र के बच्चों में डिप्रेशन (अवसाद) के खतरे को सालों पहले ही भांप सकता है। इस तरीके से किशोरों में मानसिक बीमारियों के खतरे पर नजर रखने के लिए नई विधियां ईजाद करने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रिडिक्टिव टूल उन बच्चों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिनमें 18 साल की उम्र के बाद गंभीर डिप्रेशन का खतरा हो सकता है। यह निष्कर्ष कई हजार किशोरों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन की शोधकर्ता वेलेरिया मोंडेली ने कहा, 'यह शोध टूल विकसित करने की दिशा में ऐसा पहला अहम कदम है, जिससे किशोरों की मानसिक सेहत को दुरुस्त करने में मदद मिल सकती है।' -प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

'मन्नत' के एक कमरे की कीमत 30 साल की मेहनत : शाह रुख

किंग खान यानी शाह रुख खान इन दिनों सोशल मीडिया पर अक्सर अपने प्रशंसकों के सवालों के जवाब देते रहते हैं। अपनी हाजिरजवाबी से वह कई बार प्रशंसकों को चित्त भी कर देते हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर 'आस्क एसआरके' सेशन में उनसे एक प्रशंसक ने पूछा कि सर, आपके आगामी प्रोजेक्ट के बारे में काफी अफवाहें उड़ रही हैं। कृपया आप ही उसके बारे में घोषणा कीजिए? जवाब में चुटीले अंदाज में शाह रुख ने लिखा, 'मैं ही घोषणा करूंगा और कौन करेगा मेरे भाई।' एक अन्य प्रशंसक ने उनसे पूछा कि अगर आप प्रसिद्ध न होते तो क्या करते? इसके जवाब में उन्होंने लिखा, 'मैं वही चीजें करता जो अब कर रहा हूं। प्रसिद्ध होना कोई काम नहीं है। प्रसिद्धि आपके काम के साथ आती है।' सवाल जवाब के क्रम में जब उनसे आने वाले दशक के बारे में पूछा गया तो शाह रुख ने लिखा कि आने वाले दशक को उन्होंने अपने जीवन की बेहतरीन फिल्मों के लिए आरक्षित करके रखा है। पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप होने पर उन्हें कैसा लगता है? शाह रुख ने कहा कि बस आप दुआ में याद रखना। सबसे दिलचस्प सवाल उनसे पूछा गया कि सर, मन्नत (शाह रुख के घर का नाम) में किराए पर एक कमरा चाहिए तो कितने का पड़ेगा। इस पर शाह रुख के जवाब ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने लिखा, '30 साल मेहनत करनी पड़ेगी।' इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जीवन का फलसफा साझा किया। शाह रुख की आखिरी फिल्म 2018 में 'जीरो' रिलीज हुई थी।

'83' में रवि शास्त्री बने धारिया करवा का पोस्टर जारी

फिल्म '83' में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के पोस्टर रिलीज करने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में अगला नाम धारिया करवा का जुड़ गया है। वह फिल्म में रवि शास्त्री की भूमिका निभा रहे हैं। एक बल्लेबाज के रूप में, शास्त्री अपने ट्रेडमार्क 'चपाती शॉट' के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे लोकप्रिय रूप से पैड शॉट के रूप में जाना जाता है, जहां वह अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता होने पर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया करते थे। निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा किया। इससे पहले '83' के निर्माताओं द्वारा सुनील गावस्कर की भूमिका में ताहिर राज भसीन, के.श्रीकांत की भूमिका में जीवा, मोहिंदर अमरनाथ के रूप में साकिब सलीम, यशपाल शर्मा की भूमिका में जतिन सरना, संदीप पाटिल के रूप में चिराग पाटिल, कीर्ति आजाद के रूप में दिनकर शर्मा, रोजर बिन्नी के रूप में निशांत दहिया, मदनलाल की भूमिका में हार्डी संधू, सैयद किरमानी के रूप में साहिल खट्टर, बलविंदर सिंह संधू के रूप में अम्मी विर्क और दिलीप वेंगसरकर के रूप में अदीनाथ एम कोठारे का पहला लुक सामने आ चुका है। यह फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ष 1983 में हरफनमौला खिलाड़ी कपिल देव के नेतृत्व में विश्वकप जीतने पर आधारित है। फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी।

चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म बनाना चाहती हैं कंगना रनोट

पिछले साल फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी' में रानी लक्ष्मी बाई बनीं कंगना रनोट का रुझान अब ऐतिहासिक किरदारों की ओर बढ़ रहा है। कंगना ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की है। यह इच्छा कंगना ने पटना में एक समारोह के दौरान जताई है। बेबाकी से बातें करने वाली कंगना रनोट का कहना है कि अब तक फिल्म इंडस्ट्री ऐतिहासिक दिग्गजों के साथ न्याय नहीं कर पाई है। कंगना से जब समारोह में पूछा गया कि बिहार से किस ऐतिहासिक दिग्गज पर वह फिल्म बनाना चाहेंगी, इस पर कंगना ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया। चरवाहा से सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कंगना अब निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स का उद्घाटन किया है। उनकी बतौर निर्माता पहली फिल्म 'अपराजित अयोध्या' होगी। कंगना आने वाले दिनों में फिल्म 'पंगा', 'थलाइवी' और 'धाकड़' में नजर आएंगी।

'यहां सब ज्ञानी हैं' का किरदार वास्तविक जीवन से प्रेरित : अतुल

मुन्नाभाई एमबीबीएस, बजरंगी भाईजान, स्त्री, टॉयलेटः एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में चरित्र किरदार करने वाले अभिनेता अतुल श्रीवास्तव अब अपने मन का काम करना पसंद कर रहे हैं। ऐसी फिल्में साइन कर रहे हैं, जिसमें वह मुख्य भूमिका में हों। उनकी आगामी फिल्म 'यहां सब ज्ञानी हैं' होगी। फिल्म में अतुल श्रीवास्तव और नीरज सूद मुख्य भूमिका में हैं।

फिल्म का निर्देशन अनंत त्रिपाठी ने किया है। इस फिल्म में कानपुर का फ्लेवर होगा। अतुल का कहना है कि वह फिल्म में जीजा का किरदार निभा रहे हैं, जिसका परिवार उनके पास मौजूद संपत्ति बेचकर अपनी माली हालत सुधारता है। पैसे खत्म होने पर वह फिर अपनी संपत्ति बेचना चाहता है। अतुल ने बताया कि हर शहर में ऐसे लोग होते हैं। उनके एक दिल्ली के दोस्त थे दीक्षित जी। उन्हें लोगों के बीच बैठकर ज्ञान बांटने का शौक था। ब्रीफकेस लेकर आते थे। अपने खर्चे से सबको खिलाते-पिलाते थे। हर बार अपनी जमीन बेचकर फ्लाइट से आते थे, जब पैसे खत्म हो जाते थे, तो पैसेंजर ट्रेन से वापस जाते थे।

पुलिस अधिकारी का किरदार निभाना चाहते हैं रितिक

हिंदी सिनेमा में पुलिस अफसर का किरदार निभाने को लेकर कलाकारों में उत्सुकता रहती है। हाल की बात करें तो खाकी, गर्व, गंगाजल, सिंघम, सिंबा, मर्दानी, दबंग जैसी कई फिल्में पुलिस की बहादुरी, ईमानदारी और काम के प्रति उनके समर्पण पर बनी हैं। हीरोइज्म दिखाने का असली मौका कलाकारों को पुलिस के किरदारों में अक्सर मिल जाता है। ओमपुरी, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा समेत कई कलाकार पुलिस के किरदार में यादगार भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि रितिक रोशन को अभी तक यह किरदार निभाने का मौका नहीं मिला है। 'लक्ष्य' फिल्म में आर्मी अधिकारी का किरदार निभा चुके रितिक पुलिस की वर्दी पहनने के लिए आतुर हैं। यह इच्छा रितिक ने हाल में मुंबई में आयोजित हुए उमंग 2020 समारोह के दौरान कही। उमंग समारोह पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित होता है। फिल्मी सितारे उनके सम्मान में परफॉर्म करते हैं। रितिक रोशन ने भी अपनी फिल्म वॉर के गाने 'घुंघरू टूट गए...' पर डांस किया। मुंबई पुलिस के कार्यों की तारीफ करने के साथ ही रितिक ने इच्छा जताई कि वह पुलिस अफसर का रोल करना चाहते हैं। रितिक ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में कई तरह के रोल किए हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी का किरदार करने का मौका आज तक नहीं मिला है। रितिक ने फिल्ममेकर्स से निवेदन किया है कि पुलिस अफसर का किरदार उनके लिए लिखें। रितिक के मुताबिक यह किरदार उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार होगा।

जोकर बने अर्जुन कपूर...

सितारे अपने स्टाइलिश लुक को अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। वहीं कुछ सितारे अपने अजीबोगरीब पोज वाली फोटो पोस्ट करने से गुरेज नहीं करते हैं। इन दिनों मलाइका अरोड़ा के साथ अपने संबंधों को लेकर चर्चा में छाए अर्जुन कपूर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा किया। इस तस्वीर में वह जोकर बने हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मेरा नाम जोकर'। सोशल मीडिया पर अर्जुन की यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रकुलप्रीत ने लिखा, 'सच्ची बात।' अर्जुन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं है। फिल्म में उनके अपोजिट रकूल प्रीत हैं।